>

Title: Discussion on the Demands for Grants Nos. 80 to 82 under the Control of the Ministry of Rural Development for 2008-09.

श्री काशीराम राणा (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देश के गांवों के गरीब और बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, गांवों में पीने का पानी पहुंचाना और बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से हो सकता है। जो बजट यहां पेश किया गया उसमें बहुत अच्छी राशि मिनिस्ट्री को दी गई है, करीब 42 हजार 400 करोड़ की राशि ग्रामीण विकास मंत्रालय को दी गई है। इस राशि का सही उपयोग हो, जरूरतमंद लोगों को जिसकी जरूरत है, चाहे पीने का पानी हो, चाहे रोजगार हो, वह मिले, इससे बहुत अच्छी सेवा हो सकती है, भारत का अच्छा निर्माण हो सकता है। आजादी के 61 साल के बाद आज जो गरीब पीने के पानी के लिए तरसते हैं और रोजगार के बिना मर जाते हैं, उनको बचाने का अच्छा मौका मिनिस्ट्री के पास है। मैं इसकी अलग-अलग योजनाओं के विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे माननीय सदस्य इस बारे में बोलेंगे।

मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय रोजगार योजना की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। ये ऐसी योजना है जिसके जरिए गांव के लोगों तक रोजगार पहुंचाने का एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। इस बार बजट में 16,000 करोड़ रुपया सिर्फ एनआरईजीपी के लिए एलोकेट किया गया है। मैं मानता हूं कि बेरोजगारों को रोजगार देने की जो गारंटी सरकार ने स्वीकार की है, अगर इसे अच्छी तरह से फुलफिल करना है तो अगर इसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़े तो देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय की कद्र करता हूं कि उनके दिल में गरीबों और गांवों के लिए अच्छी भावनाएं हैं, मैं इसकी सराहना भी करता हूं। उन्होंने समय-समय पर एमपीज़ को प्रपत्र भी भेजे हैं कि आप उस पर निगाह रखें ताकि राष्ट्रीय रोजगार योजना का अच्छी तरह से अमलीकरण हो सके। लेकिन मुझे माफ कीजिए यह अच्छी योजना होते हुए जिस प्रकार से यह योजना चल रही है उसका जो लाभ मिलना चाहिए उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह ठीक किया गया है कि पहले 200 जिले लिए फिर 330 जिले बनाए और 1 अप्रैल से पूरे देश को कवर कर लिया है। यह अच्छा है कि देश के सभी स्टेट्स के गांवों में बसे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए और इसके साथ गांवों का विकास भी हो, जो वहां की छोटी-छोटी योजनाएं हैं, उनके अच्छी तरह से बन पाने की क्षमता इस प्रोग्राम में है। लेकिन इस योजना का लाभ जिस प्रकार से होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। यह मैं नहीं कहता, यह रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि इस योजना में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। उन्होंने हर स्टेट में जो रिपोर्ट दी है, अगर उस रिपोर्ट को देखा जाए तो इसका सही लाभ बेरोजगारों को नहीं मिल पा रहा है। आप जानते हैं हाउसहोल्ड रोजगार देने की नेशनल एवरेज 2006-07 में 43 दिन थी, 2007-08 में कम होकर 38 दिन हो गए यानी एक साल में पांच दिन की कमी हुई, अब 2008-09 में क्या होगा जब चर्चा होगी तब पता चलेगा।[r8] लेकिन जिस प्रकार से एवरेज डेज में कमी होती जाती है, इसके बारे में सरकार को सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए एवरेज डेज कैसे बढ़े, इसके बारे में सरकार को ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इस देश में ऐसे-ऐसे राज्य हैं, जहां बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु आदि प्रमुख हैं। ऐसे राज्यों में बहुत अधिक बेरोजगारी होने के कारण वहां से दूसरे राज्यों में रोजगार पाने के लिए माइग्रेशन होता है। लेकिन फिर भी वहां लाखों-करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं। इसका कारण यह है कि देश में रोजगार की कमी है और खासकर जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जहां रोजगार चाहिए, वहां हमारी योजना का कैसा इम्पैक्ट हैं, उसके बारे में मैं बता रहा था। देश में जो गरीब या पिछड़े हुए राज्यो की श्रेणी में आने वाले जो राज्य हैं, उनमें बिहार का उदाहरण ले लीजिए, वहां एवरेज वेज केवल 22 है। उत्तर प्रदेश में 28 है, झारखंड 47 है, मध्य प्रदेश 58 है। इस तरह से जो गरीब, बैकवर्ड या अविकसित राज्य की कैटेगरी में आने राज्य हैं, जो अविकसित हैं। वहां एवरेज डेज की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वहां यह कम है। इसीलिए एवरेज डेज की जहां जरूरत है, वहां उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। यह बहुत गम्भीर समस्या है। यह कैसे बढ़े, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और रोजगार का दायरा और भी बढ़ाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि यदि इसमें बढ़ते हुए करप्शन को नहीं रोका गया तो आखिर यह योजना फेल हो जायेगी। जैसे कैग ने रिपोर्ट दी है कि हर एक स्टेट में अलग-अलग तरह से किस प्रकार करप्शन की जाती है। वहां कई जगहों पर मजदूरों, वर्कर्स का डुप्लिकेशन हो रहा है। किस प्रकार से अप्रूवल के बिना भी पैसा खर्च किया जा रहा है और कई ऐसे राज्य हैं, जहां आज तक कोई प्लानिंग ही नहीं हुई, जिसकी वजह से वहां काम उपलब्ध नहीं है। मैं एक-दो उदाहरण देना चाहूंगा कि कैसे-कैसे प्रोजैक्ट्स का अमलीकरण हो रहा है। जो कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, उसे आपने भी पढ़ा होगा, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, चूंकि मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं आपको बताता हूं कि चाहे मणिपुर हो, जहां पर लाखों रुपया, जो मजदूरों को देना चाहिए था, वह मजदूरों तक नहीं पहुंचा। आंध्र प्रदेश को भी कम्पैनसेशन मिलना चाहिए था, वहां दो लाख पांच हजार नौ सौ ग्यारह हमारे भाई-बहनें हैं, जो वहां काम करते थे, उन्हें अभी तक वह पैसा नहीं मिल पाया। हरियाणा में भी इसी तरह से फंड का डाइवर्जन हो गया। वहां ट्रैक्टर और कार्ट ओनर को मिट्टी के खनन के लिए पैसा दे दिया गया और कहीं-कहीं पर डिले पेमेन्ट होने के कारण बेरोजगार भाई-बहन रोजगार लेने के लिए नहीं आते हैं। मैं अभी अपने संसदीय क्षेत्र में नवसारी, जलालपुर, चिखली और गंडेवी खासकर इसी योजना का निरीक्षण करने के लिए गया था। सिर्फ इसी योजना को देखने के लिए मैंने दो दिन के लिए वहां का दौरा किया[b9]। सर, जैसे मैंने कहा कि एवरेज डेज जो मिलना चाहिए, वह उनको नहीं मिल पाता। [r10]जो जॉब-कार्ड हम इश्यू करते हैं, मैं एक नवसारी जिले का उदाहरण देना चाहूंगा। जॉब-कार्ड वहां पर इश्यू कर दिये गये लेकिन जॉब-कार्ड से भी 50 या 45 प्रतिशत लोगों को ही जॉब मिल पाता है। यह बात सही है कि फंड की कमी नहीं है। आप जो मांगे, फंड दे देते हैं लेकिन एडवांस प्लानिंग पूरी न होने की वजह से जितने भी लोगों को रोजगार देने की ख्वाहिश है, वह पूरी नहीं होती और इसीलिए मैंने पाया कि बहुत सारी कमियों को तुंत दूर करना चाहिए। कमी नं. एक यह है कि मैंने जो वहां काम करने वाले लोगों से पूछा कि आपको पेमेंट कब मिलती है? वे कहते है कि, हम एक वीक काम करते हैं, दूसरे वीक में वे मेजरमेंट लेने के लिए आते हैं और तीसरे वीक हमें पेमेंट मिलता है। अब जिसको खाना रोज का नहीं मिल पाता है, इसीलिए वे काम करने के लिए आते हैं। इसलिए अगर उनको डेली या दो दिन में या वीकली पेमेंट नहीं मिलेगा तो वह कैसे अपना काम करेगा, कैसे अपने परिवार को खिलाएगा, कैसे अपना पेट भरेगा जिसके लिए यह योजना बनी है? इसलिए आज काम करो और तीसरे वीक में अगर उसे पेमेंट मिलेगा तो इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। पांच दिन के बाद अगर पेमेंट जाता है तो उसके हाथ में उसको पैसा मिल जाए, न कि वह बैंक एकाउंट में जाए। बैंक एकांउट में भी उतनी ही गड़बड़ है। उसे एमाउंट रखना पड़ता है, फिर पैसा उस एकाउंट में जमा रखना पड़ता है। बिना रोजगार वाला आदमी पैसा कहां से लाएगा? इसलिए हमारे सिस्टम में जब तक बदलाव नहीं आएगा, तब तक इस काम में मैं नहीं मानता कि हमारे भाई-बहन जो बेरोजगार हैं, वे इस योजना में आने के लिए तैयार हो जाएंगे।

जो लूपहोल्स हैं, वे ये हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं, मानिए कि जिसने 15 दिन में मजदूरी मांगी और हमने नहीं दी, ऐसे अगर मजदूर हैं या भाई-बहन हैं तो उनको हम बेरोजगारी भत्ता देते हैं। इसमें बहुत भारी गड़बड़ होती है। जो हमारे बेरोजगार भाई-बहन हैं, जिन्हें जॉब-कार्ड इश्यू किये गये हैं, जिन्होंने यह डिमांड करी थी कि मुझे मजदूरी चाहिए, उनको तो मिलती ही नहीं है। इसीलिए इसके बारे में भी यह हमने अच्छा सा निकाला है कि सबको रोजी मिले और रोजी नहीं तो एलांसेज मिले।

इसके लिए भी बहुत सख्ती से उसका अमलीकरण हो, इस दिशा में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा नहीं तो बेरोजगार के नाम से पैसे खाने वाले लोग पैसे खा जाएंगे और हम यहां बताते रहेंगे कि देखिए, कितना अच्छा हमारा काम हो रहा है।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जैसे डुप्लीकेशन वर्कर्स में होता है, वैसे ही ओवर पेमेंट या डबल पेमेंट का भी बहुत बड़ा किस्सा कैग ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। मैं चाहूंगा कि आप ठीक करके अगर आगे ले जाएंगे तो यह जो राष्ट्रीय रोजगार योजना है, वह सफल होगी अन्यथा वह फेल हो रही है, ऐसी आज तक की रिपोर्ट है। अखबार पढ़िए या रिपोर्ट पढ़िए या अभी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, इसमें प्लानिंग कमीशन ने जो डिटेल्स भेजी हैं, उसमें भी उन्होंने एवरेज डेज के बारे में कहा है और साथ-साथ यह भी कहा है कि इस योजना का इफैक्टिवली इम्पलीमेंटेशन हो। यह मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का भी सवाल है। यह ऑथेंटिक न्यूज है, ऐसा नहीं कि हम यहां सदन में वैसे ही कुछ समाचार पढ़ें और कह दें कि कैग की रिपोर्ट है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए मेरा कहना है कि आज यह राष्ट्रीय रोजगार योजना ठीक तरह से नहीं चलती है। [r11]

अध्यक्ष महोदय : काशीराम जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया है। क्या वहां पंचायत का कोई पार्टिसिपेशन है?

श्री काशीराम राणा : पंचायत का पार्टिसिपेशन तो बहुत है क्योंकि पंचायत ही सैलेक्शन करती है। आखिर यह जो काम है, इसमें काम का सैलेक्शन भी वे करते हैं, पंचायत में जाब कार्ड इश्यू करना है तो उसके लिए किसका सैलेक्शन करना है मजदूरी के लिए, वह भी पंचायत देखती है। इतना ही नहीं, इसका जो सोशल आडिट होता है, वह भी पंचायत के द्वारा होता है। यह होते हुए इसमें इतना घपला होता है और मुझे लगता है कि 16000 करोड़ रुपये की राशि एक ही योजना के पीछे जा रही है। मुझे लगता है कि जो दो साल का अनुभव है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो इस साल भी 16000 करोड़ रुपये बरबाद होने वाले हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): वे यह नहीं बता रहे हैं कि हमारे देश के अंदर गुजरात में लोएस्ट मिनिमम वेज है। That is why people are not getting enough wages. It is the lowest paid wage in the country. ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Do not make it controversial, Mr. Mistry.

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): He is not blaming the Government. Do not politicize it. ...(व्यवधान)

श्री काशीराम राणा : महोदय, मैं उसको पोलिटिसाइज़ नहीं करता। इतना घपला जो हो रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Do not make it controversial. He himself has said that it is an important project. How to do it better is the issue.

â€¦(व्यवधान)

श्री काशीराम राणा : यह कांग्रेस के ही राज में जो तालाब बना था, उसको स्विमिंग पूल में कर दिया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें पार्टी पोलिटिक्स मत लाइए। ठीक ढंग से चर्चा करें।

â€¦(व्यवधान)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): I admire him for making that statement. I am indeed very happy that he made that statement for his own Government.

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइए।

श्री काशीराम राणा : मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जो 100 दिन का रोज़गार देने की योजना है, इसमें 2007-08 में एवरेज डेज़ 38 हैं। मैं कहना चाहूंगा कि 100 दिन के रोज़गार को बढ़ाकर आपको 200 दिन का रोज़गार देना चाहिए। मानसून के दिन आप कम कर लीजिए। अगर 200 दिन का रोज़गार मिलेगा तो जहां 100 दिन के रोज़गार में 38 दिन हैं, वहीं 200 दिन का रोज़गार देना हमारे देश के गरीब और गांवों में बसने वाले बेरोज़गार लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोजैक्ट है, जो वर्क की प्लानिंग होती है, वह ऐसी होनी चाहिए कि जो गांव के डैवलपमैंट का हिस्सा हो। मैंने कई जगह देखा कि ड्रेनेज खोदी जा रही है, मिट्टी वहीं की वहीं पड़ी रहती है। वही मिट्टी मानसून में फिर से अंदर मिल जाएगी और ड्रेनेज खत्म हो जाएगी। मैं कहना चाहूंगा कि इसका स्थायी उपयोग हो ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग एडवांस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे भी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कर दे। उसकी मानीटरिंग भी हो और मानीटरिंग सिर्फ एडवांस प्लानिंग की नहीं, इसके बाद जो काम हुआ, उसकी भी होनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो गांव के एजुकेटेड लोग हैं, पूरे एजुकेटेड नहीं हों, लेकिन उनकी जो समस्या है, उसको भी देखना चाहिए। उनको इन वेजेज़ से संतोष नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि उनके लिए अलग प्रकार से सोचा जाए जिससे उनको भी संतोष हो। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि आज जो सोशल आडिट हो रहा है, वह भी पंचायत ही करती है। कोई न्यूट्रल व्यक्ति या संस्था तालुका स्तर पर होनी चाहिए और एक मानीटरिंग कमेटी बनानी चाहिए जो न्यूट्रल होकर जांच करे। नहीं तो काम भी वह देगा, मीज़रमैंट भी वह लेगा और आडिट भी वही करेगा। आखिर न्याय मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए सोशल आडिट का सिस्टम ऐसा हो जाना चाहिए जिससे उसको लाभ मिले।[b12] इसी प्रकार से जो लैंड रिसोर्सेस का मामला है, इसकी गंभीर समस्या की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। जैसे हमारा गुजरात 16 सौ किलोमीटर का लम्बा बिलकुल एक कोस्टल एरिया है और सारे देश का जो आधा हिस्सा है, वह करीब साढ़े पांच हजार किलोमीटर का पूरा दरियाई एरिया है। आज उनकी जो समस्या है, उसके प्रति सरकार का जितना ध्यान जाना चाहिए, उतना अभी तक नहीं गया। जितना ध्यान उन्होंने दिया है, उसके बारे में जो कुछ उपाय करने चाहिए, वे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाए हैं।

12.56 hrs.

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि अभी एक रिपोर्ट छपी है, हमारे कोस्टल एरिया की जो फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड आज सेलाइन लैंड में कंवर्ट होती जा रही है, इससे कितना भारी नुकसान हो रहा है, इस बारे में आपको भी मालूम होगा। कृषि की उपज कम होती जा रही है। पीने के पानी में भी, सेलिनिटी आने की वजह से पीने लायक पानी नहीं रहा। धीरे-धीरे सेलाइन लैंड आगे बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल इंस्टीटयूशन है - ग्लोबल असेसमेंट ऑफ सॉयल डिग्रेडेशन, इन्होंने रिपोर्ट में यह कहा है कि साऊथ एशिया में 421 लाख हैक्टेयर लाख जमीन सेलाइन लैंड हो चुकी है और भारत में आज 260 लाख हैक्टेयर जमीन सेलाइन लैंड में कंवर्ट हो चुकी है। गुजरात के बारे में भी मैं कहूंगा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड यूज़ प्लानिंग ने जो सर्वे किया है, उसके सर्वे के मुताबिक गुजरात की जो कुल जमीन है, इसका 27.17 परसैंट, यानी 50 लाख 80 हजार जमीन आज सेलाइन लैंड में कंवर्ट हो चुकी है। हर साल दो लाख हैक्टेयर जमीन और भी सेलाइन होती जा रही है। सरकार का ध्यान इसके प्रति नहीं गया है। हम जब कोस्टल एरिया के गांवों में जाते हैं तब वे कहते हैं कि हमारे यहां पीने का पानी नहीं मिलता है। हमे पहले मीठा पानी मिलता था और अब बिलकुल नमक जैसा पानी आ रहा है। वहां पीने का पानी भी नहीं मिलता और एक-दो हैक्टेयर जमीन में कृषि उपज से अपना जो पोषण करता था, वह भी आज बंद हो गया है। उस एरिया में बहुत खराब हालत है, सरकार को जिस प्रकार से उस तरफ ध्यान देकर, इनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उस प्रकार से वह नहीं बढ़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं मंत्री था तो हमने वहां एक पायलट प्रौजेक्ट चलाया था, जो सेलाइन लैंड हो जाती है उसे फिर से फर्टाइल लैंड करना और मीठे पानी की व्यवस्था करना, इसके लिए हमने एक पायलट प्रौजेक्ट सूरत, बल्सार और भड़ौच जिले में बनाया था। मुझे कहते हुए दुख होता है कि हमने जो पायलट प्रौजेक्ट बनाया, वह इतना सफल हुआ। वहां आज कई गांव के लोग कहते हैं कि अगर ये प्रौजेक्ट अन्य जिलों में भी गए तो इसका वहां भी अच्छा परिणाम मिल सकता है। लेकिन न जाने सरकार ने उसे क्यों बंद कर दिया? जो प्रौजेक्ट इम्प्लीमेंट था, वहां पर उसकी जो राशि देनी थी, वह भी आधी दी। इसीलिए एक अच्छा सा पायलट प्रौजेक्ट बनाया था कि जो हजारों किलोमीटर का लम्बा कोस्टल एरिया है, वहां गांवों में जो समस्या है, उसे दूर करने के लिए ऐसे किया था, मगर ऐसा हो नहीं पाया, इसका मुझे बहुत दुख है। आप इस पायलट प्रौजेक्ट को फिर से शुरू करें। इसे शुरू करने से मैं मानता हूं कि हमारी जो लाखों हैक्टेयर फर्टाइल जमीन सेलाइन लैंड में कंवर्ट हुई है। जिसकी वजह से हमारी कृषि की उपज कम होती जा रही है, आज हम एग्रीकल्चर ग्रोथ में चार परसैंट से दो परसैंट पर आ गए हैं। इसके लिए सरकार ने 1825 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।[s13]

–

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यदि इस योजना का बड़े पैमाने पर अमलीकरण हो, तो इससे बहुत बड़ा लाभ आने वाले दिनों में जरूर होगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

श्री काशीराम राणा : महोदय, अब[r14] मैं वाटर मैनेजमेंट, जैसे स्वजलधारा योजना और रूरल वाटर सप्लाई के बारे में थोड़ा कहकर अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। गांवों में पीने के पानी की जो समस्या आज भी मौजूद है। हम इसे दूर नहीं कर सके, इसका हमें दुख है। हरेक को इसका दुख होगा। आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर हम दूर-दराज के गांवों में बसे अपने देशवासियों को पीने का पानी भी नहीं दे सके, तो सरकार का क्या फायदा? हम तो बार-बार कहते हैं कि ऐसी सरकार निकम्मी है। पीने का पानी प्राप्त करने का प्रत्येक ग्रामवासी का अधिकार है। यदि पीने का पानी उस तक नहीं पहुंचाया, तो मुझे लगता है कि आजादी का मतलब थोड़े लोगों के लिए होगा। इनके लिए तो आज भी वही गुलामी है, क्योंकि वे बिना पीने के पानी के जी रहे हैं। गांव में दूर-दूर से, कहीं चार किलोमीटर, कहीं आठ किलोमीटर और कहीं 10 किलोमीटर से, आज भी हमारी बहनें और माताएं पीने का पानी लाती हैं। अगर इस समस्या का निवारण नहीं किया गया और पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया, तो यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। जैसे रोटी के लिए घमासान होता है वैसे ही पानी के लिए भी रायट होगा, ऐसी संभावना आज हम चारों ओर देख रहे हैं।

महोदय, हम ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. चलाते हैं। मैं जानता हूं कि इसमें क्या-क्या हो रहा है, लेकिन चाहे यह योजना हो और चाहे रूरल वाटर सप्लाई की योजना हो, इनमें यदि हम सफलता का प्रतिशत देखें, तो हमें बहुत कम है। रूरल वाटर सप्लाई स्कीम में हमने वर्ष 2007-08 में 1,55,499 हैबीटेशन लिए थे और इनमें से सिर्फ 67,285 हैबीटेशन में हमने अचीवमेंट प्राप्त किया है। हमने सिर्फ 67, 285 हैबीटेशन में पानी पहुंचाया है। इसी प्रकार से ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. में हमने जो एलाटमेंट की, उसे जिस प्रकार से पानी प्राप्त करने के लिए खर्च होना चाहिए था और जिन्हें यह पानी पहुंचाना चाहिए था, वह नहीं पहुंच पाया। हमारे नेता बार-बार रूरल डैवलपमेंट की बात करते हैं और कहते हैं कि सच्ची आजादी तो तभी आएगी जब गांवों में पूरी आबादी होगी। अगर गांवों की आबादी के लिए यह मिनिस्ट्री बनी है और उसके लिए हजारों करोड़ों रुपए के प्रोग्राम बने हैं, तो जब तक इनका सही परिणाम नहीं मिलता है, तब तक इस धन और इन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं है।

महोदय, मैंने मान्यवर मंत्री जी को जब वे यहां बैठते थे, तब बोलते हुए सुना है। वे मुझसे भी ज्यादा तेजाबी भाषा में अपनी बात रखते थे। आज यह जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि वे इसे अच्छी तरह से निभाएं। मैं चाहूंगा कि एक-एक पैसा, फिर चाहे 16000 करोड़ रुपए हों या 42,400 करोड़ रुपए हों, आखिर उसमें इस देश के गरीब लोगों का भी हिस्सा है, वह ठीक प्रकार से खर्च हो और उसे राइट है कि उसे पानी मिले, रोजगार मिले और आवास मिले। मुझे आशा है कि इस योजना के अन्तर्गत जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। यदि ऐसा होगा, तो मैं समझूंगा कि जो पैसा दिया गया है और जिस काम के लिए दिया गया है, वह सार्थक होगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Those hon. Members who wish to lay their written speeches can do so. All such laid speeches will form part of the proceedings.

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रूरल डैवलपमेंट ऑन दि डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2008-09 पर बोलने का मौका दिया। मैं रूरल

डैवलपमेंट डिपार्टमेंट का आभार प्रकट करना चाहती हूं जिसने आज बहुत ज्यादा डैवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में की है। अभी मेरे भाई ने कुछ आपत्तियां जताई। [r15] उन्होंने पीने के पानी की समस्या की बात कही, उन्होंने यह भी कहा कि यहां से जो पैसा जा रहा है, उसकी मॉनीटरिंग होनी चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि सरकार के द्वारा एक मॉनीटरिंग सेल गठित किया गया है। उसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्राम पंचायत लेवल तक सरकार की नजरें हैं। उस पर जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है, उसकी मॉनीटरिंग की जाती है और सही समय पर सरकार को रिपोर्ट दी जाती है। इसलिए इस बात की मुझे खुशी है कि भारत सरकार के द्वारा जो स्कीमें गांव में चल रही हैं, उसकी मॉनीटरिंग ग्राम सभा और ब्लॉक लेवल तक की जाती है।

इसके अलावा आपने पानी की कमी की बात कही, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं पहाड़ी क्षेत्र से आती हूं जहां पानी की बहुत समस्या थी। गांवों में पानी पहुंचाना दुर्लभ कार्य दिखाई देता था, लेकिन मैं यूपीए सरकार का और रघुवंश प्रसाद सिंह जी का आभार प्रकट करना चाहती हूं, जिन्होंने कार्यक्रम चलाकर गांव-गांव में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया है।

माननीय सदस्य ने अपने गुजरात की कुछ समस्याओं का जिक्र यहां किया, लेकिन मैं फिर भी मंत्री जी को दुर्गम क्षेत्र की, गांव की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो स्कीमें चलाई हैं, चाहे वह रोजगार, पीने के पानी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांवों को जोड़ने की बात है, आपने जो कार्य किए हैं, वे बहुत ही सराहनीय हैं। इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप जानते हैं कि गांवों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पर सरकार ने क्रान्तिकारी कदम उठाए हैं। शहरों की तरफ जो लोग दौड़कर चले आते थे और समझते थे कि शहर में जाने से हमारी इस समस्या का हल होगा, आज मैं समझती हूं कि शहर और गांव की दूरी को कम करने के लिए मंत्रालय ने जो कदम उठाए हैं, उससे पलायन पर रोक लगी है। अब गांव के लोग गांव में ही रहकर जीवन बसर करना चाहते हैं और खेती करना चाहते हैं। इन अच्छी योजनाओं को लागू करने के लिए मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय को बधाई देना चाहती हूं। आप जानते हैं कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र की खाई को कम करने के लिए इन्होंने टाइमबाउण्ड प्रोग्राम चलाए हैं। उसी तरह से बजटरी स्पोर्ट भारत सरकार की तरफ से मिला है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में शानदार काम हुए हैं।

महोदय, नेशनल रूरल इम्पलायमेण्ट गारण्टी एक्ट ने फूड सिक्योरिटी को इन्श्योर किया है। गांवों में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले, उनमें बहुत हुनर है, जिसे उभारने के लिए आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहित किया है, उन्हें धन उपलब्ध करवाया है। इसके कारण ग्रामीण लोग अपनी बनाई हुई चीजों को मार्किट तक पहुंचा पाते हैं। मैं आपको उन्हें सहयोग देने के लिए बधाई देना चाहती हूं। आप उनके लिए समय-समय पर शहरों में फेयर लगाकर, जैसे दिल्ली हॉट और प्रगति मैदान में उनके हाथ से बनी चीजों की प्रदर्शनी के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूं।

दूसरी बात, इण्टीग्रेटिड वॉटर शेड प्रोग्राम के तहत गांव में बिना ज़मीन के रहने वाले लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंची है। सरकार ने इस के तहत जो कदम उठाए हैं, मैं उसके लिए मंत्रालय को बधाई देना चाहती हूं। क्योंकि हमारे गरीब लोग यह समझते थे कि उन्हें कभी जमीन मुहैया नहीं हो पाएगी, लेकिन आज सैंकड़ों लोगों को सरकार की मार्फत जमीन मिली है, जिससे वे अपनी रोज़ी-रोटी कमा सकें[r16]।

इसी तरह से भारत निर्माण के तहत चार सालों में सरकार ने एक लाख चौहत्तर हजार करोड़ रूपए की धनराशि देकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़के बनाने का काम किया है, इरीगेशन का काम किया है, रूरल हाउसिंग का काम किया है, रूरल वाटर सप्लाई और बिजली पहुंचाने का काम किया है, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। इससे हर भारतीय नागरिक, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, उसे फायदा पहुंचा है। इसके लिए भी हम भारत सरकार के बहुत आभारी हैं कि आज आपने ये सारी सुख सुविधायें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों को लाभ पहुंचाया है।

आपने रूरल डेवलपमेंट की बात कही और लोगों को रोजगार देने की बात कही। आपने कहा कि साठ साल में भी हम इसे हासिल नहीं कर पाए, परंतु मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उनके ज्यादा पढ़े-लिखे होने की आवश्यकता नहीं है और इसके बावजूद उनको सौ दिन का रोजगार मिल रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि इन्होंने एक बहुत बेहतरीन स्कीम चलायी है। इसमें पहले दो सौ जिले आते थे, आपने इसमें एक सौ तीस और जिलों को जोड़कर उनकी संख्या बढ़ायी है। आपने कहा है कि बाकी दो सौ पचहत्तर जिलों को भी उसमें जोड़ेंगे। आपने पांच साल के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़कर गांव में रोजगार देने की बात कही है। आपने रोजगार को थ्रू एक्ट आफ पार्लियामेंट लीगल राइट दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं। मैं गांव के लोगों की तरफ से आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने हमारे गांव के क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। आज वे अपनी रोजी-रोटी उसके जरिए कमा रहे हैं। उन्हीं के क्षेत्र में, जो उन्हीं के गांव का काम है, उसमें उनकी भागीदारी है, यह एक बहुत ही सराहनीय काम है।

महोदय, आप जानते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चल रही है। मैंने पहले भी कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की आपने मदद की है। सत्ताइस हजार ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिनको आपने बैंक का क्रेडिट दिलाया और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दिलायी। उनकी आपने मदद की। उसमें बीपीएल के लोग आते हैं, एससी एवं एसटी के लोग आते हैं और उसमें बहुत सारी महिलाएं भी लाभान्वित हुयी हैं। इसमें पचहत्तर प्रतिशत भारत सरकार का अनुदान है और पच्चीस प्रतिशत राज्य सरकार को अनुदान देना होता है। यह भी एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसके लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं कि आपने हमारे गांव के लोगों तक इन स्कीम्स को पहुंचाकर उन्हें लाभन्वित किया है।

इसी प्रकार से एक अन्य योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जो कि एक सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम है। इसमें शत-प्रतिशत पैसा भारत सरकार देती है। आज हमें खुशी है कि आपने इसमें तीन लाख इकहत्तर हजार सात सौ पच्चीस किलोमीटर नयी सड़कें बनायी हैं और आपने तीन लाख अड़सठ हजार सड़कों को अपग्रेड किया है। इसी तरह से आज आपने इसके लिए एक लाख बहत्तर हजार करोड़ रूपए व्यय करके गांव-गांव को और हर पंचायत को सड़कों से जोड़ा है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं।

आप जानते हैं कि हमारी सड़कें ही हमारे भाग्य की रेखा हैं। आज गांव तक सड़कें पहुंचाकर हमने गांव में रहने वाले लोगों को जहां रोजगार दिया है, स्वास्थ्य सुविधायें दी हैं, अच्छी शिक्षा दी है, स्वच्छ पीने का पानी दिया है, जमीन को इरीगेट करने के लिए पानी मुहैय्या कराया है। यह सब तभी संभव हो पाया, जब हमारे पास गांव में आने-जाने के लिए अच्छे यातायात के साधन हैं। इसके लिए भी हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं कि आपने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इतनी बड़ी रकम देकर गांव का जो उत्थान किया है, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं।

इसी प्रकार से आपने इंदिरा आवास योजना चलायी है। आप जानते हैं कि बहुत से परिवार हैं जो बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं। उनके पास सिर ढकने के लिए छत भी नहीं है। उनको भी आपने इसके अंतर्गत लाकर धनराशि मुहैय्या करायी है। इसमें पच्चीस हजार रूपए प्रति परिवार को दिया जाता है और जो दुर्गम क्षेत्र में रहता है, ट्राइबल एरिया में रहता है, उसे आपने सत्ताइस हजार पांच सौ रूपए की धनराशि उपलब्ध कराकर एक छोटी सी झोपड़ी अपने लायक बनाने के लिए आपने जो उसकी

मदद की है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं। [p17]

[N18]

उसी तरह नेशनल सोशल असिस्टैंस प्रोग्राम के तहत आपने ओल्ड एज पैंशन स्कीम चलाई है, नेशनल फैमिली बैनीफिट स्कीम चलाई है, नेशनल मेटरनिटी बैनीफिट स्कीम चलाई है, इससे महिलाओं को फायदा पहुंचा है, वृद्ध लोग जिन्हें पैंशन मिलनी थी, उन्हें फायदा पहुंचा है। मैं उनकी तरफ से मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करती हूं। हम प्रधान मंत्री जी के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने जो एनाउंसमैंट की है - Old age pension to all ciitzens above 65 and below poverty line. I think this is highly appreciated. इससे बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए मैं सबकी तरफ से प्रधान मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करती हूं कि आपने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है।

उसी तरह एरिया डैवलपमैंट प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डैवलपमैंट के अंतर्गत आते हैं, उसमें आपने बहुत बेहतरीन योजनाएं चलाई हैं, जैसे ड्राउट प्रोन एरियाज में आपने प्रोग्राम चलाए हैं, डैजर्ट डैवलपमैंट एरिया में प्रोग्राम चलाए हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम चाहते थे कि सरकार की नजरें जाएं। आपने वहां की विकट समस्याओं पर गौर किया है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बहुत ही बढ़िया स्कीम्स वहां चल रही हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूं।

उसी तरह आपने हरियाली इनटिग्रेटेड वेस्टलैंड डैवलपमैंट प्रोग्राम चलाया है जिसके अंतर्गत हरियाली का बहुत सुंदर कार्यक्रम है। उसमें वाटरशेड द्वारा गांव के लोगों को जानकारी दी जाती है कि किस तरह से पानी सिंचित करना है और उसका किस तरह सही उपयोग किया जा सकता है। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। आप जानकारी देते हैं कि जो हमारी बावड़ियां, पॉड्स हैं, उन्हें किस तरह साफ-सुथरा रखना है जिससे लोगों को उसका लाभ होगा। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं कि उसने हरियाली कार्यक्रम चलाकर गांव के लोगों को बहुत राहत पहुंचाई है।

जैसे मैंने शुरू में कहा कि मौनीटरिंग और इवैल्युएशन का कार्यक्रम चला है, भारत सरकार जहां से फंड दे रही है, उसे भी मौनीटर किया जाता है। इसके लिए सरकार ने मौनीटरिंग इवैल्युएशन गठित किया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट लैवल, ब्लॉक लैवल, ग्राम पंचायत के लोगों को इन्वॉल्व किया गया है ताकि वे समय-समय पर सरकार को अवगत करवाते रहें और बताते रहें कि उसमें क्या कमी है, क्या प्रोवीजन होने चाहिए। इसके लिए हम आपके आभारी हैं।

आपने रूरल डैवलपमैंट कार्यक्रम को हाईलाइट करने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, जैसे विभाग द्वारा मीडिया, प्रैस, प्रिंट मीडिया तक बात पहुंचनी चाहिए। उसके लिए आप समय-समय पर प्रैस कौंफ्रैंस करते हैं। ग्रामीण भारत की एक मंथली मैगज़ीन छपती है जिसके द्वारा गांवों के लोगों तक डिटेल में प्रोग्राम पहुंचाए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूं कि ग्राम पंचायत के लोग उस पत्रिका को सुचारू रूप से पढ़ते हैं और विभाग द्वारा उन तक जो जानकारी पहुंचनी चाहिए, वे उस पत्रिका द्वारा उसे हासिल करते हैं। यह भी बहुत सराहनीय कदम है।[N19]

आप सब जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का जो एनुवल बजट है, उसके लिए सरकार द्वारा 3,678 करोड़ रुपये दिए गए हैं। गांवों में रहने वाले बच्चे जिन्हें अच्छी तरह शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, वे आज उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जहां से भी मांग आती है कि स्कूल को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, कमरा बनाने की आवश्यकता है, टॉयलेट बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से जो मदद दी जा रही है, मैं समझती हूं कि यह बहुत ही सराहनीय कदम है। गांव के क्षेत्र में आज इससे बहुत लाभ पहुंचा है। हमारी जो मिड-डे-मील स्कीम है, उसके तहत आज हमारे लाखों बच्चे, जो खाने से वंचित रहते थे, उनको एक समय का भोजन दिया जा रहा है। इसके लिए भी हम भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। इसी तरह नैशनल रूरल हैल्थ मिशन के तहत सरकार ने एनुअल बजट में 12 हजार करोड़ रुपये दिये हैं। मैं समझती हूं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं आज हम गांव के लोगों को दे पा रहे हैं, वे तभी उपलब्ध हो पायी हैं जब सरकार ने इतनी बड़ी धनराशि हमें यहां से दी है। हम जानते हैं कि गांवों में महिलाएं बहुत नैगलेक्टिड रहती हैं। उनके स्वास्थ्य की तरफ हमें ध्यान देना है। आज हमें उसमें पैसे का कोई भी अभाव नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं कि आपने इतनी बड़ी धनराशि देकर इंटीरियर के गांव-गांव में लोगों को खासकर महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की हैं। इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करती हैं।

आपने नैशनल रूरल इम्प्लायमैंट में 16 हजार करोड़ रुपये की धनराशि दी है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि आपने कहा कि 60 सालों में इसका कोई लाभ नहीं हो पाया। परन्तु आप स्वयं जानते हैं कि जब हम अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं और वहां लोगों से बातचीत करते हैं, तो मैं समझती हूं कि सबसे सेक्ससफुल स्कीम इम्प्लायमैंट देने का रही है। गांव के क्षेत्र में इससे बहुत लोगों को लाभ पहुंचा है। जो लोग अपनी दो टाइम की रोटी-रोजी को पूरा नहीं कर पाते थे, आज वे कम से कम अपने इलाके के काम में अपनी भागीदारी देकर उन कामों को कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हैं।

उसी तरह हमारे फार्मर्स के ऊपर जो लोन था, उसे सरकार ने वेव किया है। हमने बार-बार संसद में यह बात उठायी कि हमारे फार्मर्स सूसाइड कमिट कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर आर्थिक बोझ है। इसके लिए भी सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूं कि आपने इस कार्यक्रम के तहत गांव के लोगों को लाभान्वित करने के लिए हजारों-करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इन सब स्कीमों को चलाने के लिए अपने सारे डिपार्टमैंट्स को इन्वाल्व करके आप स्टेट सरकार को बार-बार पत्र लिखते हैं, उनको अवगत कराते हैं। माननीय मंत्री के पत्र भी हम सांसदों को आते हैं कि आप इनको मॉनीटर करें। आप देखें कि ये स्कीमें सही तरीके से चल रही हैं या नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि बहुत ही सेक्ससफुल कार्यक्रम गांव के क्षेत्र में चल रहे हैं।

अंत में, मैं रघुवंश प्रसाद जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं कि जब से आपने यह डिपार्टमैंट संभाला है तब से बहुत बेहतरीन काम इस क्षेत्र में हुआ है। हमारे गांव के लोग इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं चाहे सड़कों की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो या शिक्षा की बात हो। मैं समझती हूं कि भारत सरकार ने अपना रुख गांव की तरफ मोड़ा है, उससे हमारे गांव में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): I rise to support the Demands for Grants (2008-2009) for the Ministry of Rural Development.

After assumption of UPA Government under the leadership of Madam Soniaji, our Hon'ble Prime Minster, Dr. Manmohan Singhji has implemented number of projects for the upliftment of rural and backward areas of this country. Bharat Nirman is one of the initiatives taken by the Union Government. It is having a plan for building rural infrastructure within a period of four years 2005-2009. It has six components *Viz.,* Irrigation, Roads, Water Supply, Housing, Rural Electrification and Rural Telecom Connectivity. Estimated cost for this scheme is Rs. 174,000 crore. Out of above six components, three are implemented by the Rural Development Ministry such as Rural Roads, Rural Water Supply and Rural Housing. The Ministry of Rural Development is also implementing wage employment programmes of national rural Employment Guarantee Scheme (NREGS), Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) and Swaran jayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY). THROUGH BHARAT NIRMAN, it has been envisaged to connect 1.5 lakh km. Village roads habitations over 500 people in hilly areas and over 1,000 people in other areas. It is decided to equip 66,820 villages with telephone and 14,183 remote villages by digital satellite phones. For creating irrigation facilities, 1 cr. hectare of irrigation potential and restore 10 lakh, hectare potential by renovation and modernization schemes. Furthermore, it is decided to provide drinking water facilities for 55,067 uncovered habitations and 2.8 lakh partially covered habitations and provide potable water to 2 lakh villages. It is decided to construct 60 lakh villages for the rural poor and provide electricity to 1.25 villages. Even though Government of India is allocating huge funds for rural development, number of State Governments are still not complying with norms

---

* Speech was laid on the Table.

when it comes to the implementation. Some States have not complied with norms relating to release of funds for District Rural Development Agency (DRDA) administration.

Bihar has emerged as the largest non-complying State with 36 Districts not complying with the norms of SGSY, seven Districts are not complying with Indira Awaas Yojana Scheme norms and 10 districts were proposals for DRDA administration have not received.

Further I want to bring certain facts about the implementation of the NREG Scheme. The Rural Employment Guarantee Scheme is facing with certain challenges in many States. The beneficiaries of jobs cards are not properly identified in many States. Moreover, if identified, there are favoritism in issuing cards to the beneficiaries. The job card holders are not being paid by full wages. In many cases, they are being paid as low as Rs. 25 or Rs.30 per day and the rest of the amount is being swallowed by middlemen. Moreover, the work which has already undertaken are taken up again without any proper time limit. Hence, immediate steps should be taken for continuous supervision of the work undertaken under NREG Scheme.

Before implementing NREG Scheme, Government of India has allocated huge funds for implementation of various schemes through District Panchayats, Intermediate Panchayats and Gram Panchayats under Sampooran Gramin Rojgar Yojana (SGRY). Now, the Government has stopped the total allocation of funds under the SGRY scheme. Through this scheme, out of the total allocation, 22% of the money was earmarked for the individual benefits of the poor downtrodden SC/ST individuals. This Scheme is also now scrapped. District Panchayats and Intermediate panchayats are not having any funds to implement any developmental schemes and they are also not answerable to the public and voters. Hence, I request the Government that the funds should be earmarked for SGRY Scheme or some other schemes to implement through District Panchayat and Intermediate Panchayats.

70% of the population are living in rural are living in rural areas. Villages lack basic amenities of health services, housing, education, safe drinking water, rural connectivity and communication facilities. If Bharat Nirman Scheme is implemented properly, then only these problems will be solved.

In rural areas throughout the country, nearly 28,444 schools are not having drinking water facilities and 9.13 lakh schools are not having sanitation facilities.

Our late leader, Rajivji announced that he allocation of fund by Government of India reaches the masses only 10% and remaining are swallowed. Even now, the same situation continues. All the Government of India schemes to be implemented only through District Panchayats, Intermediate Panchayats and Gram Panchayats, then only the rural problems will be solved.

I want to put forth about the great achievement of our Tamil Nadu Government headed by Dr. Kalaignar Karunanidhi in implementing various rural development schemes. Government of Tamil Nadu and its Local Development, Minister, Shri M.K. Stalin has implemented, "Anaithu Grama Anna Marumalarchi Thittam". It is a novel scheme to identify the village panchayat for implementing various rural development schemes. In contrast, to the conventional practices of choosing one village panchayat annually in very Assembly Constituency for development are spreading resources thinly across all the village panchayats. The Government of Tamil Nadu has developed the scheme during 2007 to identify financially weaker village panchayats and has given priority. The above scheme is covering one-fifth of the village panchayat in each block in each year in the ascending order of its per capita income. Funds from schemes of other departments such as the Highways, Public Works, Social Welfare and Education are allocated to the extent possible for solving the existing problems and it is planned to complete it within 2011. During 2006-2007, Government of Tamil Nadu has allocated Rs. 508 crore for the development of 2,540 village panchayat at the rate of Rs. 20 lakh per village panchayat. Total funds are utilized and schemes were completed within the financial year. During current year, it is proposed to allocate Rs. 507 crore for 2,534 villages. I urge upon the Government to direct all the State Governments to implement this landmark scheme and I am once again appreciating our hon"ble Chief Minister, Dr. Kalaignar and also the Local Administration Minister, Shri M.K. Stalin for implementing this scheme.

With these words, I am supporting the Demands for Grants for Rural

*SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): My thanks to Hon'ble Speaker, for allowing me to speak a few words. In Theni District which is from my constituency The Government is allotting more funds for rural development for which I am extremely Thankful to Hon'ble Minister, Prime Minister Ji and Madam Sonia Ji for giving more importance to rural development projects, particularly drinking water ,road development and basic sanitation under Indira Awas yojana. This year the World Water Day coincides with the International Year of Sanitation. To achieve the targets under Millennium Development Goal the Governments needs to focus efforts for raising awareness and taking concrete action by evolving new interventions and policies to provide this fundamental right of access to safe water and basic sanitation to the millions of people across the country. Happy to say that some territories with 100% grants are implementing Water Supply Schemes in their villages but this should be extended to Tamil Nadu and particularly Theni District also. I welcome the Efforts taken by our UPA government for introducing Centrally Sponsored Scheme namely Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) under Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission (RGNDWM). The Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission was introduced during 1989 and it is nearly two decades old. I feel this is the right time to restructure this mission.

Regarding the funding pattern of all these programmes is different. In ARWSP (Normal) it is 50:50 between Centre & States in Sector Reform Pilot projects and Swajaldhara it is 90:10 between Centre and beneficiaries/Community and Sub-Missions on Water Quality and sustainability it is 75:25 between Centre and States. Under ARWSP (DDP Areas) 100% grant in aid is provided to concerned States. Since Water is essential in not only every body's day to day life but also in all walks of life It would be more appropriate to extend 100% grant in aid to States.

---

* Speech was laid on the Table.

It is noticed that certain Central Government Funds allotted to State Governments for relevant subjects have not been utilized and diverted to some other subjects without any intimation to the Centre which is not a healthy trend. Recently Hon'ble Finance Minister has sanctioned some amount to State Governments for disbursement among Senior Citizens but this was diverted to some other cause with out intimation to the Central Government. Our Chief Minister is whole heartedly supporting the cause of Central Government but the local officers are not co-operating.

In this pious mission of restructuring and rebuilding a vibrant India, I seek their dedication and full co-operation too.

Further, the august House is well aware that the UPA government since its inception in 2004 has been the first

government since Independence to conceive and implement NREGS, to banish rural unemployment in the country to check outflow of rural population to urban areas. Initially this scheme was operational in few districts in the country, but I take this opportunity of congratulating Shri Rahul ji that after assuming the responsibility of General Secretary of AICC, his first concern was to get this scheme implemented in all districts of the country. He made a fervent appeal to government and our Hon'ble Prime Minister gave immediate approval to the same and sizable amount has been earmarked in this budget for the same by our Hon'ble Finance Minister.

Sir, Theni district in my parliament constituency of Periyakulam is covered by mountains and hills from all sides and water during the monsoon goes waste. I request the Ministry to please asses the viability of constructing few reservoirs so that rainwater is harvested to be used in lean and dry season.

Apart from this Sir, Ministry of Rural Development is doing wonderful job under CAP ART. They have different programmes like Village Knowledge Centres, Gramin Vikas Andolan and Nirmal Gram Abhiyan, CAP ART Institute for Poverty Alleviation and Rural Techonology (CIPART), "Demonstration-cum-Awareness Workshop' under Centre for Sustainable Technologies, Special Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojna (SGSY), Arid Horticulture by Rain Water Harvesting etc. The technology advocated by the council is quite simple which is very well adapted by moderately educated and illiterate rural masses. CAP ART renders distant services from a single window point in remote areas through modern Information and Rural Technology. I request the Hon'ble Minister to depute some officials from CAP ART to visit my constituency toasses the situation on the spot, set up their offices to bring awareness among the farming community, for which apart from the Central Government grants and assistance, I am willing to contribute permissible funds from MPLAD and request and persuade Government of Tamil Nadu to provide necessary assistance for infrastructure development in this regard.

Sir, this august house is well aware of agitations in the State of Haryana, Punjab, and West Bengal in the recent past. Agricultural land has been acquired for SEZ's displacing Farmers. We all agree that development of Industry and Agriculture is complementary and supplementary to each other. In this regard my sincere suggestion is that SEZ's be Developed on wastelands and degraded forest lands and if at all the development of SEZ's has to be on agricultural land, the requiring body should be asked to develop equal area of wastelands simultaneously so that the loss of agricultural land could be compensated.

RURAL DEVELOPMENT

At the outset I humbly submit my appreciation on the present excellent trend of centre state relationship. This has become possible because of this liberal financial assistance provided by the Centre to the states for its developmental and welfare activities of the states, major part of the funds allotted by the centre is meant for rural development of some states. Some of the Rural Developmental Schemes are

1 Indira Awas Yojana-(lAY)

.2 Swamajayanti Gram Swarozgar Yojana(SGSY)

.3 [illegible]

.4 Total Sanitation Scheme.

[illegible]

6. Integrated Waste Land Development Program.

[illegible]

.8 SaiyaSikshaAbiyan-(SSA)

.9 National Employment Guarantee Scheme.

All these items relate to Development of the Rurals in India. These schemes are planned, programmed the State Govts. After introduction of the above scheme, We can see the upward change in the living condition of rural populations including the down trodden. However, as elected representatives of the mass I have no role to play, as non-of the schemes is carried out with my knowledge and consultation. Further, the oases relating to the IAY, SSA etc., recommended by me are also hot being considered by the implementing Agency of my constituency, which causes frustration in the minds of the general public. Therefore it is my earnest appeal that the MP's of the constituency should be authoritatively vested with powers to

participate in the implementation of schemes of the constituency funded by the Central Govt. This would facilitate the MP's to have a monitoring system right from the beginning and prevention of any leakages and durations, In fact majority of the people are under the impression that these schemes are done by the states

and the centre, despite pooling enormous funds into the state goes unrecognized or under recognized. Therefore, I once again make it clear that MP's should be made part and parcel of the schemes for which centre provides crores and crores of rupee.

I am having one more reason for active the participation of the MP's in the implementation schemes - ie. of during the recent heavy rains (in March'08) flood situation became worst in my constituency and the authorities were puzzled to control the floods. Several farmers and residents sustained substantial loss. As an elected representative of the people, I could not convince the affected people and remained as a spectator, as I could not promise any future remedial action.

I am also informed that some favoritism is being done by the implementing Agency of the central scheme by allowing more funds to a particular constituency (e.g) Aundipatti is one of the Assembly segments in my constituency and is receiving un-due favoritism just because it happens to be the constituency of the former CM (Ms.Jayalalitha). Therefore, I once again appeal that the active participation of MP's of the constituency is absolutely essential to check favouritism, unauthorized diversion of central funds and to see whether the funds allotted by the center reaches its destination properly to the benefit of the people. Central Govt should ensure that funds given to the Union Govt for CSA, SGSY. PMGSY should be spent on the recommendations of the local MPs so that the MPs can solve the local urgent and needy problems can be addressed. Pure Drinking Water, good roads are the main needs for the local people. I am really thankful to the Govt lead by our Hon'ble PM Dr. Manmohan Singhji under the auspicious guidance of madam sonia ji is doing well for the rural masses. My request is that these programme should reach the people for which we have to monitor through the local MPs. with these words, I conclude Sir.

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। श्री रघुवंश बाबू के दिल में गरीबों के लिए विशेष जगह है। वे उन गरीबों को सुविधाएं देने के लिए बहुत ही ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मगर उनकी समस्या यह है कि जिस माहौल में उनको काम करना पड़ रहा है, जिसे नियो लिबरल इकोनॉमी में काम करना पड़ रहा है, वह उसके खिलाफ है क्योंकि नियो लिबरल इकोनॉमी पूरी दुनिया में गरीबी बढ़ाती है। वे अमीर और गरीब के बीच को खाई को बढ़ाती है। बहुत कोशिश के बावजूद भी इसमें कामयाब होने में हमें मुश्किल हो रही है। यह एक लड़ाई है जिसे हम लड़ रहे हैं। शायद श्री रघुवंश बाबू भी इस लड़ाई में हमारे साथ रहेंगे। आपको बहुत भारी काम करना पड़ता है क्योंकि जो 70 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, उनमें भूमिहीनता हर साल बढ़ती जा रही है।[MSOffice20] यह एक नयी समस्या है। भूमि से ही गांव के लोग अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, अगर वे भूमि खो दें तो उनकी जिन्दगी के लिए समस्या पैदा हो जाती है। बहुत से ग्रामीण जो गरीब हैं, उनके पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है, उनको इसकी सुविधा नहीं मिलती है। खेतिहर मजदूरों की आबादी बढ़ती जा रही है, मगर उसके काम को संरक्षण देने के लिए हम कोई कानून नहीं बना पाए हैं। रोजी-रोटी की तलाश में लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जो पलायन हो रहा है, वह भी एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जो गरीब हैं, उन्हें भी देखना है। देश का असंगठित क्षेत्र, जिसमें देश के कुल मजदूरों का लगभग 93 प्रतिशत हिस्सा आता है, जिनका एक बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है। उनकी समस्याएं भी बोझ के रूप में आपके सिर पर है, जिसको आपको संभालना पड़ता है। इसी तरह ग्रामीण एससी, एसटी और महिलाओं की समस्याएं हैं। इसके साथ ही जैसा कि अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में 63 करोड़ लोग सिर्फ 20 रूपए में किसी तरह जी रहे हैं, ऐसे लोगों की बड़ी संख्या गांवों में रहती है। इन सभी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए जो मंत्रालय है, वह आपका मंत्रालय है। इसलिए इतना बड़ा काम करने के लिए जो आपका मंत्रालय है, आप जो कार्यक्रम लेते हैं, उनके बारे में आज सदन में चर्चा हो रही है, यह बहुत अच्छी बात है। पिछले सालों में इस मंत्रालय के लिए पैसे का प्रावधान बढ़ाया गया है, लेकिन जितने ज्यादा लोगों को इसे कवर करना है, जितनी बड़ी समस्याओं का इस मंत्रालय को सामना करना है, उन्हें देखते हुए यह रकम काफी नहीं है। प्लानिंग कमीशन से आपके मंत्रालय द्वारा जितना पैसा मांगा गया था, शायद उसके 60 प्रतिशत पैसे का ही प्रॉविजन किया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरे सदन को मिलकर कहना चाहिए कि इस मंत्रालय के लिए ज्यादा धनराशि का प्रावधान होना चाहिए।

मंत्रालय में आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना है। यह योजना आपकी सरकार पिछले चार सालों से चला रही है। पहले इसके अंतर्गत 200 जिले थे, जिनको बढ़ाकर 330 किया गया और अब इसका विस्तार पूरे देश पर किया गया है। पिछली बार जब इसमें 330 जिले कवर होते थे, उसके लिए जितने रूपयों का प्रावधान था, उससे अब जिलों की संख्या डबल हो गयी है, लेकिन इसकी तुलना में पैसों में केवल 33 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। जिलों की संख्या बढ़कर डबल हो गयी, लेकिन धनराशि में केवल 33 प्रतिशत की वृद्धि करना सही नहीं है। इसके बारे में प्लानिंग कमीशन की राय से हम सहमत नहीं हैं। इसलिए इस प्रावधान को 100 प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, यह मेरी सरकार और प्लानिंग कमीशन से मांग है। आंकड़े आपके सामने हैं कि रूरल इंप्लायमेंट के लिए हम जीडीपी का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं। यह हिस्सा घट रहा है। रूपए के आंकड़े में तो यह बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी के परसेंटेज के रूप में यह घट रहा है। वर्ष 2007-08 में यह पैसा जीडीपी का 0.36 प्रतिशत था, लेकिन वर्ष 2008-09 में यह घटकर जीडीपी का केवल 0.27 प्रतिशत हो गया। इसलिए इस पैसे को जीडीपी परसेंटेज के रूप में भी बढ़ाना चाहिए। मैं सरकार और प्लानिंग कमीशन से मांग करूंगा कि इस मंत्रालय के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए क्योंकि यह हमारे देश के सबसे ज्यादा गरीबों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। एनआरईजीएस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसे बनाने में हमने बहुत मेहनत और मदद की है। यह प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है, जब हम राज्यों में जाते हैं, गांवों में जाते हैं, वहां से इसमें कुछ सुधार करने के बारे में हमें फीडबैक मिल रहे हैं। इसमें जो कमियां है, मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा।[R21] मैं एक तो यह बात कहना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में अवेयरनैस की कमी है। लोगों

को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मजदूरी के लिए कार्ड तो दे दिए जाते हैं, लेकिन जब दरख्वास्त दी जाती है, वह कहां देनी है, उसकी रसीद लेनी है या नहीं और उसकी कोई शिकायत करनी है तो कहां करनी है, इन सबके बारे में इन तीन वर्षों में काफी लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए सब तरह की जानकारी लोगों को देनी चाहिए, जिससे वे लोग अपने हक को ठीक से समझ सकें और उसके लिए लड़ सकें। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जब दरख्वास्त दी जाती है तो उसकी कोई एकनॉलेजमेंट नहीं दी जाती है, क्योंकि नियम में प्रावधान है कि अगर वह दे दी गई और नाम रजिस्टर्ड हो गया, तो फिर 15 दिन में उस व्यक्ति को काम देना होगा, नहीं दिया जाएगा तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। जब गरीब आदमी दफ्तर में जाकर अपनी दरख्वास्त देता है तो उसे इस चीज का पता नहीं होता। इसलिए इस कमी पर भी ध्यान देना होगा। गरीबों के साथ ठगने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जिस दिन वह दरख्वास्त दे, उसी दिन की उसे रसीद देनी चाहिए।

अब मैं न्यूनतम मजदूरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश के राज्यों में इस सम्बन्ध में अलग-अलग मजदूरी है। सबसे ज्यादा केरल में 125 रुपए मजदूरी दी जाती है और गुजरात में सबसे कम 50 रुपए मजदूरी दी जाती है। मैं पूरे देश में घूमा हूं इसलिए मुझे इस चीज की काफी जानकारी है। यह बात ठीक है कि इस कार्यक्रम की वजह से न्यूनतम मजदूरी में हर राज्य ने वृद्धि की है। इस योजना से लोगों को काम भी मिल रहा है, लेकिन जहां सबसे कम यानि 50 रुपए मजदूरी है, वहां प्रदेश सरकार से बात करके आपको यह बढ़ानी चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक नया सर्कुलर आया है। उसमें कहा गया है कि काम की अवधि नौ घंटे होगी। यह ठीक बात नहीं है। हम सब लोग दिन में आठ घंटे काम करते हैं, आधा घंटा ब्रेक होता है, टिफिन का समय होता है। आईओएल की भी जो कंवेंशन है आठ घंटे काम की, उसके भी खिलाफ है। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। मेटिरियल के रेशों के बारे में भी काम में समस्या आ रही है, उसे भी देखना चाहिए।

आपने इस कार्यक्रम के तहत कामों की सूची जारी की है, उसे बढ़ाना होगा। अभी आपने सूचनी में 11 कामों के नाम दिए हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा काम पानी से सम्बन्धित हैं कि पानी के लिए खुदाई वगैरह करना। कुछ जगह तो यह ठीक है, जैसे राजस्थान है, वहां पानी की समस्या है और जगह भी काफी है इसलिए पानी की खुदाई का वहां काफी औचित्य है। लेकिन जहां पानी ज्यादा है और जगह भी उतनी नहीं है, वहां यह काम ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए आपको लिस्ट में कामों की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि यह प्रेक्टिकल नहीं है। हमारे देश में बाढ़ वाले, सूखे वाले, पहाड़ी, जंगल और रेगिस्तानी क्षेत्र हैं इसलिए इस लिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अभाव में बहुत से राज्यों में काम ढूंढ़ने में काफी परेशानी आ रही है। हर जगह एक ही तरह का काम नहीं हो सकता है इसलिए आप इस ओर जरूर ध्यान दें।

इस कार्यक्रम के लिए जिलों को सीधा पैसा दिया जाता है। हमने देखा है कि कुछ जिलों में ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है और काम भी काफी अच्छा होता है और कुछ में काम सही नहीं हो पाता, क्योंकि पैसे की समस्या आती है। इसलिए आपको राज्य सरकार को यह फ्लैक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि जहां काम नहीं है और जहां काम हो गया है, पैसा भी पड़ा है, वहां का पैसा उस जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए। यह एक प्रेक्टिकल समस्या है इसलिए आप इस पर ध्यान देकर इसे जरूर लागू कराएं, क्योंकि हमने देश के कई भागों में जाकर इस चीज को अनुभव किया है।

बैंकों के जरिए लोगों को पैसा दिया जाता है। कई जगह बैंकों की शाखाएं ही नहीं हैं। देश में कुल 52,000 के करीब बैंकों की शाखाएं हैं, लेकिन गांवों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इसलिए आपने पोस्ट ऑफिस को भी इसमें जोड़ा है, लेकिन हर जगह पोस्ट ऑफिस वाले इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं और सर्विस चार्जेज मांगते हैं। आपको इस ओर ध्यान देकर पोस्ट ऑफिस वालों को निदेश देना चाहिए ताकि गरीब लोगों को ठीक से और समय से पेमेंट हो सके।

मेरा इस कार्यक्रम के तहत एक अनुरोध और है। आपको फूड ग्रेन भी आपको इसके तहत देना चाहिए। आजकल महंगाई काफी बढ़ रही है और खाद्यान्नों के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी पैसा लेकर बाजार जाता है तो ऊंची कीमतों के कारण वह खाद्यान्न खरीद नहीं सकता। जिस तरह पहले फूड फार वर्क होता था, आप पैसा देने के बजाय फूड ग्रेन दें तो काफी उचित होगा। कई जगह पैसा देने में असुविधा हो रही है, अगर आप गेहूं आदि खाद्यान्न देंगे तो गरीब आदमी उसे लेकर अपने घर जा सकता है और उसके लिए खाने का प्रबंध हो सकता है। वैसे इसका इसमें प्रावधान है।[R22] मगर इसमें एफसीआई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और सबसे तालमेल करके, कैसे इसे लागू किया जाए, यह देखना पड़ेगा। यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, इसमें जो कमियां हैं उन्हें देखना पड़ेगा। मेरे पूर्व-वक्ता माननीय काशीराम राणा जी ने कुछ समस्याएं बताई हैं जो कंट्रेक्टर पैदा कर रहे हैं। आपको मालूम है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे गरीब लोग हैं, वहां यह प्रोग्राम सबसे कम लागू हो रहा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग नहीं हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : गरीब लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में काम के लिए पलायन कहां से ज्यादा होता है। वहां काम 18 प्रतिशत होता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सबसे ज्यादा गरीब लोग बंगाल में हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : ठीक है, आप जाकर देखें कि बिहार में काम कम क्यों हो रहा है? वहां क्या अमीर लोग हैं, क्या काम नहीं करना चाहते हैं? यूपी, बिहार में सबसे कम काम हो रहा है और हमारा कहना है कि वहां ज्यादा काम होना चाहिए। बिहार के सब जिलों को इस योजना से जोड़ा गया है, मगर लोग काम नहीं कर रहे हैं। काम में जो कमी है, इस बारे में सरकार को देखना चाहिए और सरकार को इस योजना की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। साथ ही जिनके लिए प्रोग्राम बनाया गया है, उनको भी काम करना चाहिए। जहां ज्यादा जरूरत है वहां काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आवास से वंचित लोगों के लिए भी प्रोग्राम है। आई ए वाई में फिजिकली टार्गेट जो अचीव होता है वह आप 97 परसेंट से ज्यादा दिखा रहे हैं और 84 परसेंट इसमें खर्चा दिखा रहे हैं। यह खर्चा कैसे होता है कि कम खर्च में ज्यादा टार्गेट हासिल होता है? इसमें भी थोड़ी समस्या है, इसे भी ध्यान से देखना चाहिए। इसमें जो जगह दी जाती है, वह भी सही जगह नहीं होती है, वह जगह बहुत दूर दी जाती है। मेन-लोकेलिटी से दूर, एक कोने में जगह पड़ी है, वहां जाकर दो-तीन कमरे बना दिये, वहां जाकर गरीब लोग कैसे रहेगा, जहां कोई सुविधा नहीं है। इसलिए सरकार को मेन-लोकेलिटी के पास ही जगह खरीदकर देनी चाहिए। हाउस-साइट मेन-लोकेलिटी के पास होनी चाहिए, नहीं तो गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। यह एक समस्या है, जिसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

इसके अलावा हमारी प्राइम-मिनिस्टर-ग्रामीण-रोजगार-योजना है, जिसे हजारों करोड़ रुपये खर्च करके हम बना रहे हैं लेकिन राज्य सरकार के पास उसे मेनटेन करने के लिए पैसा नहीं है। वह पांच साल के बाद खराब हो जाएगी, तो इतना पैसा खर्च करने के बाद उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। मेरा आग्रह है कि इसके

मेनटेनेंस की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। इतना अच्छा बनाने के बाद अगर वह बाद में टूट जाए तो इसका फायदा स्थाई रूप से नहीं होगा। इसके मेंटेनेंस के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए।

बीपीएल के सवाल पर प्लानिंग कमीशन ने बोल दिया कि 18 प्रतिशत से ज्यादा गरीब नहीं है, पता नहीं इनका क्या हिसाब है? हम जब गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसे काफी लोग हैं जिनको बीपीएल का कार्ड नहीं मिलता है। इस बारे में जो मानक बनाए हैं, वे मानक ठीक नहीं हैं। इन मानकों में परिवर्तन करके बीपीएल के कार्ड सही ढंग से बनाने का काम होना चाहिए।

इसके अलावा जो रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है, इसमें 50-60 प्रतिशत की अचीवमेंट है। यह भारत निर्माण का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, मगर हम देख रहे हैं कि एआरडब्ल्यूएसपी के 57 प्रतिशत अनकवर्ड विलेजिज में यह प्रोग्राम पूरा हुआ है। बाकी जगह पानी दे रहे हैं लेकिन कुछ दिन बाद पानी का स्रोत सूख जाता है और लोगों को पानी नहीं मिलता है। इसलिए ज्यादा दिनों तक लोगों को पानी मिले, यह भी देखना होगा। इसके साथ-साथ पानी की क्वालिटी को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि फ्लोराइड से 30 हजार और आयरन से 70 हजार गांव प्रभावित हैं। इस बारे में भी हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को ठीक क्वालिटी का पानी दे सकें। गांवों में करीब 80 हजार स्कूल ऐसे हैं जहां पानी की कमी है और वहां पानी के लिए ट्यूबवैल्स दे रहे हैं, लेकिन अभी भी, पूरे हिंदुस्तान के गांवों में 84 हजार, ऐसे स्कूल हैं जहां पानी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी भी ग्रामीण मंत्रालय की है और इस पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी को भी उसे देखना है। [r23]

आपका सेनिटेशन का टोटल अचीवमेंट 49 परसेंट है। यह अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन और ज्यादा अचीवमेंट की जरूरत है। लैंड रिफार्म की बात हम पिछले 60 साल से कहते आए हैं, मगर लैंड रिफार्म नहीं हो रहा है। इसका नतीजा है कि ग्रामीण गरीबी कम नहीं हो रही है। लैंड रिफार्म्स डिपार्टमेंट ने जो काम शुरू किया है, उसे पूरा करे। सरप्लस लैंड, वेस्ट लैंड को ठीक प्रकार से गरीब लोगों में, भूमिहीन लोगों में बांटा जाए। आपका आईडब्ल्युडीपी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन नार्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे कम काम हो रहा है। वहीं इस प्रोग्राम की सबसे अधिक जरूरत है और वहीं यह प्रोग्राम नहीं चल रहा है। इसलिए एन. ई. रीजन में ज्यादा जोर दे कर काम किया जाए।

मेरी यही मांगे हैं। ये सभी कार्य आपके अंतर्गत आते हैं और कमियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री आदरणीय रघुवंश जी को मुबारक और बधाई दूंगा कि उन्होंने जनहित में दबे कुचले गरीब लोगों को राहत देने के लिए कुछ योजनाओं को चलाया है। सांसदों को इन योजनाओं को जिला स्तर पर समिति का निर्माण करके सम्मान देने का भी काम किया है। मैं दो तीन बातें इस मंत्रालय के संबंध में मंत्री जी को, जिनकी इच्छा है कि गरीब लोगों को राहत मिले और योजनाओं को सफलता मिले, बताना चाहता हूं। जहां कहीं बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, उनके बारे में सुझाव दूंगा।

पहली बात भारत सरकार की ओर से आपके मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री सड़क योजना का निर्माण हुआ, यह एक सराहनीय कदम है। आज का जो बजट है, जिसमें इस योजना में और ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि आबादी के आधार पर जहां 500 से 1000 की आबादी है, उन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रावधान था। मुझे लगता है कि शायद आपने यह योजना समाप्त कर दी है। हम आपसे चाहेंगे कि जब आप अपना उत्तर दें, तो इस तरफ भी प्रकाश डालें।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब बैठक हो रही थी, तब हमारे सांसद साथियों ने मिल कर आपसे कहा कि प्रधान मंत्री सड़क योजना का उद्घाटन करने का अधिकार सांसदों को होना चाहिए और उनके सुझाव के अनुसार ही सड़कों का निर्माण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मौखिक रूप से आपने कहा कि उद्घाटन करने का पत्र आपने सांसदों को भेज दिया है, लेकिन शायद या तो आप भूल गए होंगे या आपके दफ्तर में वह पत्र पड़ा हो, लेकिन सांसदों द्वारा उद्घाटन करने का पत्र किसी सांसद के पास नहीं पहुंचा है। हम चाहते हैं कि जब आप उत्तर दें तो कम से कम इस बात को साफ करें कि सांसदों के सुझाव के आधार पर प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण होना है। आपने जब बैठक शुरू हुई थी, तब इस तरह का निर्देश दिया था, उस निर्देश का पालन ही नहीं हुआ है।[R24] अधिकारी मनमाने तरीके से सड़कों का प्रपोजल बनाते हैं और गुणवत्ता के आधार पर सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। सड़कों का जो रूट बनना चाहिए, ठेकेदार और अधिकारी मिल कर मनमानी करते हैं। मैं चाहूंगा कि वह इस पर ध्यान दें। अगर उन्होंने उद्घाटन का परिपत्र जारी किया है तो उसे साफ कर दें और सांसदों के सुझाव के आधार पर जिन सड़कों का निर्माण होना था जिस की उपेक्षा की जा रही है, उनके बारे में हम चाहेंगे कि आप ध्यान देने का काम करे। उत्तर प्रदेश और बिहार जहां दबे, कुचले गरीब लोग झोंपड़ियों में रहते हैं और जहां से आप आते हैं, वहां से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। आपने उनके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण योजना बना कर रोकने का काम किया है। उसे रोकने के साथ-साथ जो प्रारूप बनाया गया उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। इसके संबंध में आपको शिकायतें मिली होंगी। हम चाहेंगे कि आप उसे गम्भीरता से देखें। लिस्ट बन रही है लेकिन वह ठीक से नहीं बन रही है। इसमें भी कोताही बरती जा रही है। लक्ष्य के आधार पर काम हो। बेरोजगार लोग जो गांव से पलायन होकर शहरों की ओर जाते थे, उनको रोजगार मिलना चाहिए। पूरे देश में मजदूरी का निर्धारित लक्ष्य नहीं है। वह कहीं कुछ है और कहीं कुछ है। इसके आधार पर ऐसी परिस्थिति बने कि देश के पैमाने पर जो राज्य सबसे ज्यादा गरीब हैं, जहां लोग भूख से तरस रहे हैं, वहां अच्छी मजदूरी मिले क्योंकि अभी मजदूरी बहुत कम है। आज आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में मेहनत करने वाले श्रमिक की मजदूरी नहीं बढ़ेगी, रोजगार गारंटी योजना असफल हो जाएगी। हम चाहते हैं कि मजदूरी में विसंगतियों को दूर किया जाए। इसके लिए राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों से बात करके सुधार लाने का काम करे।

हमने आपके बजट में इन्दिरा आवास योजना को देखा है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि बेघर लोगों को घर मुहैय्या कराया जाए। जब आप यहां भाषण दे रहे थे तो बड़े जोरदार ढंग से अपनी बातों को रखने का काम कर रहे थे। जो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं जिन का कोई मकान नहीं है जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उनके यहां एक आशा की किरण जगी थी। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इन्दिरा आवास योजना के बारे में आप गम्भीरता से सोचें। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। जो सूची बनायी जाती है, वह दलगत भावना के आधार पर बनायी जाती है। गांवों में गोलबंदी है। अगर कोई गरीब है लेकिन असरदार व्यक्ति के साथ नहीं है तो उसका नाम काट दिया जाता है। जो नौकरी करता है, विदेश में भी रहता है और सम्पन्न है, उसका नाम इन्दिरा आवास की लिस्ट में दर्ज हो जाता है। वह दफ्तरों में जाता है, बंधी हुई रकम है और दफ्तरों में तीन से पांच हजार रुपए दे देता है, बिना सूची बनाए उसे इन्दिरा आवास आवंटित हो जाता है। इस तरह पूरे देश में आपकी भावनाओं

को वोट पहुंचाने का काम हो रहा है। जो तीन हजार या पांच हजार रुपए देकर उनकी पूजा करेगा, उसे इन्दिरा आवास मिल जाएगा और जो नहीं देगा और असरदार आदमी के साथ नहीं है, अधिकारियों के चंगुल में नहीं फंसा है, वह इन्दिरा आवास से वंचित हो जाएगा। आपका एक संदेश गया था कि सूची में कोई भेदभाव न बरता जाए। मेरा अन्दाजा है कि आज की तारीख में वह भेदभावपूर्ण सूची है और इसे लेकर हमारे मन में असंतोष है। पिछली बार हमने कहा था कि महंगाई बढ़ रही है। जब महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के परिवेश में 25000 में से 5000 या 3000 देने के बाद जो धनराशि बचती है उससे निर्माण कैसे करें, इसलिए इसे बढ़ाने का काम कीजिए। आपने शायद 35000 रुपए किया है, जैसा कि आपने बजट में कहा था, जो लोग इस सदन में बैठे हैं सबको मालूम है कि 50000 रुपए से कम में इंदिरा आवास का निर्माण ठीक ढंग से नहीं होगा। इसलिए इस राशि को 35000 से बढ़ाकर 50000 रुपए करें और सूची को भी ठीक तरह से बनाएं जिससे इंदिरा आवास योजना के पैमाने पर गरीब लोग, जो आशा लगा कर बैठे हैं, वह उन्हें मिल जाए। मैंने इसी सदन में पिछली बार आपसे कुछ अर्ज किया था और आपने उसके बाद कहा था जहां दैवी प्रकोप है, आग लग जाती है या बाढ़ आ जाती है, जो परिवार या घर बर्बाद हो जाता है उसे तीन दिन के अंदर इंदिरा आवास में परिवर्तित कर दिया जाए। आपने इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार घोषणा की है कि तीन दिन के अंदर इंदिरा आवास में परिवर्तित कर दिया जाए। मैं आपके ही दफ्तर की चिट्ठी के बारे में बताता हूं, आपके दफ्तर ने 12.04.2006 को जारी की थी, मैं आपकी आज्ञा से चिट्ठी इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सदन में बराबर घोषणा करते हैं कि जले हुए घर के लोगों को इंदिरा आवास का रूप दे दिया जाए। मैं महसूस करता हूं कि ऐसा देश के अनेक राज्यों में हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आपके आदेश का पालन नहीं हुआ, हो सकता है यह आपकी जानकारी में न हो या आपके दफ्तर ने आपको जानकारी न दी हो। पूरे देश में जहां आग लगती है, हर राज्य में राज्य स्तर पर कोई न कोई सहायता मिल जाती है, कहा जाता है कि प्रोफार्मा बना कर भेज दें। 2006-07 और 2007-08 का प्रोफार्मा है कि आगजनित दैवी आपदा से प्रभावित लाभार्थियों को इंदिरा आवासीय सूची के वांछित प्रारूप, प्रारूप में कहा गया है - लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, जाति, डीपीआर नं., दुर्घटना की प्रवृत्ति, दुर्घटना का समय, क्षति सीमा, राज्य अंश धनराशि और अंत में लिखा है कि प्रमाण पत्र साक्ष्य के साथ किसी अन्य माध्यम से सहायता नहीं दी गई है। मेरे कहने का मतलब है कि जहां मकान जलेगा और जब वह प्रमाण पत्र लिख कर देगा कि उसे कोई सहायता नहीं मिलेगी तब आपके वचन के अनुसार इंदिरा आवास मिलेगा। लेकिन कौन अधिकारी देगा? आपके इस आदेश ने आपकी पवित्र भावना को, जिससे लोगों का इंदिरा आवास बन जाता, पूरा नहीं किया है। इस प्रोफार्मा से पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जिले के एक अधिकारी ने भी एक इंदिरा आवास इस योजना के तहत आबंटित नहीं किया। हम चाहते हैं कि आप अपने इस प्रपत्र को देख लें, आपने जनहित में कम से कम जो वादा किया है, जो सदन में कहा है, उसमें रुकावट हो गई है, इसे पुनः पूरा करने का ऐलान करें। अगर ऐलान नहीं करेंगे तो मेरे जैसा आदमी महसूस करेगा आपकी वाणी और भाषा लोगों को सहयोग देने का नहीं बल्कि झुठलाने वाला है। इस पर आपके दफ्तर ने कहीं प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया है तो आप जैसे जमीन से निकलने वाले आदमी, लोगों का दर्द जानने वाले आदमी की भावना पर एक पत्र द्वारा कुठाराघात किया गया इसलिए इसे रोकने का काम करें।[r25] इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज पूरे देश में इतनी लम्बी समयावधि के बाद भी पीने का शुद्ध पानी नहीं दिया जा सका। कहीं भी पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पाया है। हम चाहें कितनी ही डींगें हांकें, लेकिन हम लोगों को स्वच्छ पानी तक नहीं दे पाये हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, मायावती जी अपने दल के विधायकों को 250 हैंडपम्प दे रही हैं और दूसरे दल के विधायकों को सौ हैंडपम्प दे रही हैं। आप कभी हकीकत को भी कबूल किया करो। यह आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है और इस सदन में चाहे किसी भी दल के सदस्य हैं या देश के किसी भी कोने से चुने हुए सदस्य हैं, किसी भी सांसद को अपनी कलम से हैंडपम्प देने का अधिकार नहीं है। अब हमें लोगों ने दिल्ली भेजा है। जब हम कभी अपने इलाके में घूमते हैं और किसी झोंपड़ी में जाते हैं तो वहां से गरीब आदमी निकलकर कहता है, बाबू, आप दिल्ली मे गये हैं, आप हमें पानी के लिए एक हैंडपम्प की व्यवस्था तो करा दीजिए। लेकिन हम यह नहीं कर सकते। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब हम आपसे मिले थे और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें माननीय रेवती रमण सिंह, प्रो.राम गोपाल जी और इलियास आजमी यहां बैठे हैं, हम सभी लोग जाकर प्रधान मंत्री जी से मिले और उन्हें एक ज्ञापन दिया और कहा कि माननीय प्रधान मंत्री जी, कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि प्रत्येक सांसद को अपने लोक सभा क्षेत्र में पांच सौ हैंडपम्प देने का अधिकार मिल जाए। लेकिन यह नहीं हुआ। हम आज भी आपसे इसकी मांग करना चाहते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय इतना बड़ा मंत्रालय है और गांव के लोगों को पीने का शुद्ध पानी देने के काम हेतु जब हम लोगों का ज्ञापन माननीय प्रधान मंत्री जी को गया है, तो हम लोगों को यकीन है कि जब आप सदन में जवाब देंगे तो कम से कम आखिरी सत्र में पांच सौ हैंडपम्प हर सांसदों की संस्तुति पर देने की घोषणा कर दीजिए।

दूसरी बात मैं जल संचय के बारे में कहना चाहता हूं। पोखर खोदकर जल को इकट्ठा करने की आपकी एक योजना है। लेकिन मेरा अंदाजा है कि कहीं भी पोखरा खोदा ही नहीं गया। कागज पर खोदे गये, पैसा ले लिया गया, मजदूरों के द्वारा कहीं खुदाई नहीं हुई, ट्रैक्टर से खुदाई हो गई। हम चाहते हैं कि मंत्री जी इस पर भी थोड़ा ध्यान देकर इस काम को अपने ढंग से पूरा कराने का काम करें।

इसी तरह से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में मैं कहना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भाषण दिया था कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 65 वर्ष के लोगों को पेंशन दी जायेगी। यह प्रक्रिया बहुत अच्छी है। इसके लिए प्रधान मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन यह योजना केवल कागजों में ही रह गई है, यह साकार रूप नहीं ले रही है। हम चाहेंगे कि मंत्री जी इसे भी अपने ढंग से देखें।

इसके अलावा हम आपसे एक निवेदन और करना चाहते हैं कि प्रत्येक गांव सभा में पंचायत भवन की व्यवस्था की जाए। सरकार की इतनी तरह की छोटी-बड़ी योजनाएं आती हैं, गांवों में एक जगह बैठकर इन सारी योजनाओं का लोग निस्तारण करें, इसके लिए एक पंचायत भवन की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक गांव सभा में यदि पंचायत भवन की व्यवस्था हो जाती है तो इससे हमें और गांवों के लोगों को बहुत खुशी होगी। जैसे प्राइमरी स्कूल हैं, वहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है। लेकिन पीने के पानी के लिए हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं है। मैं विशेष तौर से ग्रामीण विकास मंत्री जी से इस बात के पूरा होने की उम्मीद करता हूं।

जैसे राजीव गांधी विद्युत परियोजना है। इस परियोजना के तहत गांवों का विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। हम चाहेंगे कि आप उस पर भी विचार करें और उसे भी पूरा करने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं, वहीं उम्मीद करता हूं कि जो आपके दफ्तर ने पत्र भेजकर काम रोक दिया है, उसमें आप सांसदों की संस्तुति पर पांच सौ हैंडपम्प देने की घोषणा तो कर सकते हैं। कृपया आज आप इसकी घोषणा करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट का समर्थन करता हूं।

s*__श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) :__ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्राम विकास मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी योजना गरीबों, बेरोजगारों के लिए यह योजना बहुत अच्छी योजना है। गांवों का विकास करने वाली योजना है। आशीर्वादरूप योजना है।

किंतु, कहीं कहीं पर यह योजना का लाभ आज भी नहीं मिल पाता है। जैसे कि समुद्र तल में खारापन दूर करने का कोई उपाय नहीं है। एनडीए के समय में योजना थी उनको बंद कर दियाय है और जहां रिजर्व फारेस्ट जैसे वन कानून है। अभ्यारण्य जैसे वन कानून है। वहां ग्रामीण विकास मंत्रालय की बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। वन कानूनों वाले गांवों में आने जाने के लिए रोड़ नहीं है। पीने का पानी नहीं है ऐसे गांवों में प्रधान मंत्री सड़क योजना वाली कोई भी योजना से रोड़ बनाना चाहिये और वैसे गांवों का सम्पूर्ण विकास होना चाहिये।

गुजरात के नर्मदा, भरूच, सूरत जिला के बहुत सारे गांव हैं जो आज भी बहुत सारी यातनायें भुगत रहे हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है तो ऐसे गांवों में ग्रमीण विकास मंत्रालय की बहुत सारी योजना लागू होना चाहिये। रोजगार गारंटी योजना का लाभ मिलना चाहिये।

---

*Speech was laid on the Table.

14.00 hrs.

__उपाध्यक्ष महोदय :__ इसके साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं और वह यह है कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां फस्ट और सैकेंड लैवल पर पानी गंदा है। अगर स्कूलों में बच्चों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो जाए तो बच्चों को स्वच्छ पानी मिल सकेगा।

श्री राम कृपाल यादव।

__श्री प्रभुनाथ सिंह :__ केवल प्रशंसा ही मत करिएगा और बातें भी बिहार के बारे में बोलिएगा।

__श्री राम कृपाल यादव (पटना) :__ बिहार के बारे में जानते हैं तो बिहार पर ही बोल रहा हूं। आप शांति से बैठे रहिए। ...(__व्यवधान__) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक बहुत ही अहम मंत्रालय है और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत जो गांवों का देश है जहां 70 से 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। जब तक गांवों में खुशहाली नहीं होगी, देश खुशहाल नहीं हो सकता। ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से गांवों की खुशहाली की जिम्मेदारी मंत्री जी पर है जिन्होंने बखूबी निभाने का काम किया है। मैं इसके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना भारत निर्माण योजना चलाई है। इंडिया का विकास बहुत हुआ है लेकिन भारत का निर्माण नहीं हो सका है और जब तक भारत का निर्माण नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा, जहां गावों में गरीब तबके के लोग बसते हैं तब तक कितना भी आप कुछ कर लीजिए, मगर भारत विकसित नहीं हो सकता। आज जिस तरह से गांवों और शहरों में खाई बढ़ती जा रही है, किस तरह से गांवों के लोग धीरे-धीरे प्लान करके शहरों में बसते जा रहे हैं, उसका मूल कारण यह है कि गांवों के स्तर पर जो सुविधाएं गरीबों को, मजदूरों को, खेतों में काम करने वाले लोगों को मिलनी चाहिए, वे सुविधाएं उनको गांवों में नहीं मिलती। इसलिए मजबूरी में रोजगार के लिए या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या दूसरी सुविधाएं पाने के लिए पूरी गांव की आबादी शहरों में बसती जा रही है। अगर ये ही सारी सुविधाएं सरकार गांवों में प्रदान कर दे तो जो गरीब लोग मजबूरी में गांवों से शहरों की तरफ बस रहे है और शहर में उनका जो बुरा हाल हो रहा है, वह नहीं होगा। वह रोजी-रोटी कमाने के लिए शहर में बस रहा है। वह गरीब आदमी जो रोजी-रोटी कमाने के लिए गटर में रहने का काम कर रहा है और उनके पास पीने का पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है, वह गरीब आदमी बहुत सारी असुविधाओं को झेलते हुए भी अशुद्ध हवा में भी रहने का काम कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय पर ही ऐसे लेगों की जिम्मेदारी है कि गांवों के उन वर्गों, तबकों

को हम को संतुष्ट करें जो वर्ग, जो तबका असंतुष्ट होकर बड़े पैमाने पर शहरों की तरफ भाग रहा है। आज गांवों के लोग शहरों में बसने का काम कर रहे हैं।

कई माननीय सदस्यों ने भारत निर्माण की कई योजनाओं की चर्चा की है। मैं भी माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, वैसे माननीय मंत्री जी के प्रति जितना हम साधुवाद व्यक्त करें, जितना प्रशंसा करे, वह कम होगी क्योंकि अपने प्रयास से पिछले चार सालों में उन्होंने जो विकास करने का प्रयास किया है, जो धनराशि आबंटित की है और उस राशि को सही जगह पहुंचाने का काम किया है, वह अपने आप में एक रिकार्ड है। पूर्ववर्ती सरकार और इस सरकार ने काफी पैसा विभिन्न योजनाओं में दिया है चाहे वह इंदिरा आवास योजना हो या जल की सुविधा के लिए हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए हो या बंजर जमीन को विकसित करने के लिए हो, रोजगार गारंटी योजना हो, मैं कहूंगा कि जो नया क्रांतिकारी कदम इस सरकार ने उठाया है, जिसके लिए लोग वर्षों से सपना देख रहे थे, उस रोजगार गारंटी योजना को वैधानिक दर्जा देकर जो काम किया है, वह भी अपने आप में सराहनीय है और एक बड़ा कदम है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का और यूपीए सरकार का आभार व्यक्त करना हूं मगर निश्चित तौर पर योजनाएं तो बनती रहती हैं लेकिन योजनाओं का जो सही रूप है, वह आम लोगों तक नहीं जा पाता तो योजनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप राशि आबंटित कर रहे हैं और राशि जा भी रही है, आपका मन भी साफ [r26]है। आपकी नीति भी साफ है और नीयत भी साफ है। हमें लगता है कि जो एजेन्सियां हैं उन पर भी जिम्मेदारी होती है। इसकी एजेन्सी राज्य सरकारें होती हैं। राज्य सरकारें अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगी तो निश्चित तौर पर चूंकि फैडरल स्ट्रक्चर है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सीधे डंडा नहीं चला सकते हैं। आपके पास उतनी शक्ति नहीं है। मैं खासकर बिहार की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य प्रभुनाथ सिंह जी बोल रहे थे। हमारे यहां बिहार में वे सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, उनकी सरकार राज्य में चल रही है। वे क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। यदि राज्य सरकार गड़बड़ करती है तो वे चिल्लाते हैं और यही डैमोक्रेसी का मतलब होता है। इधर चिल्लाने का मतलब नहीं है। सदन में और सदन के बाहर भी यदि कोई सरकार चाहे वह यहां की हो या वहां की हो, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है तो जनता सबको वाच कर रही है क्योंकि सब जनता के बीच में से चुनकर आते हैं। हमें लगता है कि इन दिनों इनको कुछ सत्ता से मोह हो गया है, इनको जरूर सत्ता से प्यार हो गया है, इसलिए ये अपने दायित्वों को भूल गए हैं और जनता की जो आवाज़ उठनी चाहिए, वह ठीक से नहीं उठ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां प्रभुनाथ सिंह जी जबाव देने के लिए बैठे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : वे जवाब देंगे। मैं आपके माध्यम से इनका ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूं क्योंकि ये बहादुर और लड़ाकू साथी हैं। इनका अपना लड़ने का इतिहास रहा है मगर आजकल इन्होंने लड़ना बंद कर दिया है। पता नहीं क्या समझौता हो गया है, इनको शायद मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, इसलिए सही बात नहीं बोल पा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा और बंजर भूमि की बात करना चाहूँगा। बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना भारत निर्माण के अंतर्गत आता है। मैं समझता हूं कि हजारों करोड़ रुपये इन्होंने इसके लिए पूरे देश के पैमाने पर आबंटित किये होंगे। जितनी कृषि योग्य भूमि है, उसको अक्वायर करके वहां उद्योग लगाए जा रहे हैं। उद्योग लगने चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं। जब तक देश में उद्योग नहीं लगेंगे, रोज़गार नहीं होंगे, हम विकसित नहीं होंगे। मगर रोज़गार के अवसर प्राप्त करने के लिए और देश को समृद्ध करने के लिए आम लोगों को खत्म न करें। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के नाम पर न जाने कितने हज़ारों एकड़ ज़मीन देश के विभिन्न राज्यों से ले रहे हैं। आप लीजिए, मगर क्या होगा? हमारी आबादी बढ़ रही है, उत्पादन क्षमता घट रही है। उत्पादन क्षमता इसलिए घट रही है कि कृषि योग्य भूमि को हम सिंचित नहीं कर पा रहे हैं। पानी का अभाव है, कई तरह की बात है। उसमें यह भी है कि इकोनॉमिक ज़ोन के नाम पर हम बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि ले रहे हैं। उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने का दायित्व आपके ऊपर है। हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे और मंत्री जी जब जवाब दें तो उसमें बताएं कि कितने हजार करोड़ रुपये आपने देश के अन्य भागों में बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए आबंटित किये, कितने खर्च कर पाए और कितनी बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बना दिया। नहीं तो यह होगा कि आपकी जो स्कीम है, यह लोकप्रिय स्कीम है, यह कागजों पर रह जाएगी तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं होगी। हम जानना चाहेंगे कि हमारा जो टार्गेट है, हमारा जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति में हमने कितनी सफलता प्राप्त की है। इसकी जानकारी हम चाहेंगे ताकि स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के अंतर्गत की ज़मीन राज्य को भरपाई कर सकें और उत्पादन की क्षमता प्राप्त कर सकें। मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर पर इसका जो कुप्रभाव पड़ रहा है उसको कम करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं और क्या कर पाए हैं यह अवश्य बताएँ।

दूसरी महत्वपूर्ण योजना की चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की है - राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना। यह बहुत ही लोकप्रिय योजना है। इस पर बड़ी चर्चा हुई मगर हमें लगता है कि कहीं न कहीं इसमें कोई कमी है जिसकी वजह से राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत जो हज़ारों करोड़ रुपये आबंटित कर रहे हैं, उसका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जाब कार्ड ठीक से नहीं बन रहे हैं। जाब कार्ड बोगस बनाकर बड़े पैमाने पर ठेकेदारों के हाथ से ट्रैक्टर से काम हो रहा है, जैसा यहां माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। [b27] आप उसकी किस तरह से मोनिटरिंग कर रहे हैं, आप अपने जवाब में बताएंगे। आपने कहा कि हम काम के अवसर उपलब्ध कराएंगे। अगर काम के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तो हम निश्चित तौर पर उतने दिन का पैसा उपलब्ध करा देंगे, नकद राशि उपलब्ध करा देंगे। आपने कितने लोगों को राशि उपलब्ध कराई है? हम खास कर अपने प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, हमारा प्रदेश बिहार जो गरीबों का प्रदेश है, जहां रोजगार की समस्या है। हमारे यहां दो इलाके हैं, जिनमें एक तरफ बाढ़ आती है और एक तरफ सुखाड़ होता है। हमारे यहां बड़े पैमाने पर वर्षों से पलायन हो रहे हैं। वहां के मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम रोजगार के इतने अवसर उपलब्ध प्राप्त करा देंगे कि बाहर के लोग हमारे प्रदेश में आ जाएंगे, जो पहले से बाहर गए हुए हैं, अब तो कोई नहीं जाएगा। हम ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसा रोजगार उपलब्ध कराएंगे कि बाहर के लोग यहां आ जाएंगे। पता नहीं माननीय मंत्री जी को कितनी इसकी जानकारी हुई होगी। आपको इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि वहां कितने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। आज भी बड़े पैमाने पर बिहार के लोग, जैसे पंजाब में आपके यहां है, हरियाणा, मुंबई, असम एवं महाराष्ट्र तथा दिल्ली आदि कई जगहों पर अपना श्रम लगा कर अपनी रोजी-रोटी कमाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वहां इसका असर पड़ा है। जैसे कि मंत्री जी स्वयं यदा-कदा हम लोगों से चर्चा के दरम्यान बोलते रहते हैं कि राम कृपाल जी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत बिहार सरकार को हमने जो राशि आबंटित की है, वह पैसा खर्च नहीं हो रहा है। न सिर्फ रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत, बल्कि विभिन्न योजनाओं में इंदिरा आवास इतनी लोकप्रिय योजना है, उसमें भी खर्च नहीं हो रहा है। पेयजल पर भी खर्च नहीं हो रहा है। पैसा जो बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है, उसमें जो अनियमितता है उस कारण से वह पैसा वहां नहीं पहुंच पा रहा है। यह चिन्ता का विषय है और हमारे लोग बाहर जाकर मार खा रहे हैं। महाराष्ट्र में मार खा रहे हैं, वहां किसी का हाथ काट दिया जाता है। असम में बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे हैं। दिल्ली में भी अब शुरू हो गया है। अगर किसी को अपने यहां रोजगार के अवसर मिल जाएंगे तो वह बाहर क्यों जाएगा। वह मार खाकर और गाली सुन कर क्यों दूसरे राज्य में जाएगा। ऐसी कई समस्याएं हैं। ऐसे कई गरीब एवं पिछड़े प्रदेश हैं जिनके उद्देश्यों की पूर्ति राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत हो सकती है। मगर उसका सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। वहां के मुख्य मंत्री जी किस तरह से मोनिटरिंग कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं, किस तरह से देख-रेख हो रहा है। वहां अधिकारियों को छूट है - लूट सको तो लूट लो, राम-नाम की लूट है और इसी लूट

में प्रभु नाथ बाबू का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब इन्हें बोलने का अवसर मिलेगा तो हम आशा करते हैं कि ये जरूर इस पर बोलेंगें। ये स्पष्ट वक्ता हैं, दूध का दूध और पानी का पानी रखते हैं। हमें विश्वास है कि स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखेंगे। जॉब कार्ड वगैरह ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है। हम अपने क्षेत्र की बात बोल रहे हैं, हमारे क्षेत्र में पटना से सटे हुए फुलवारी विधान सभा क्षेत्र है। हमने इस मामले को सदन में उठाया था, माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया था। वहां बड़े पैमाने पर काम कर लिए गए, लेकिन उन मजदूरों को पेमेंट ही नहीं दे रहे। राज्य सरकारों के माध्यम से पेमेंट होता है, कार्यवाही होती है तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर राज्य सरकार अगर अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रही होती तो यह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती और धरना एवं प्रदर्शन की स्थिति नहीं आती। जब तक इस देश की क्रयशक्ति गरीबों के हाथ में है,...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं, आपकी पार्टी के अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, कृपा कर हमें बोलने का थोड़ा और अवसर दिया जाए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की हमारा यहां बहुत आबादी है। मैं समझता हूं कि उनकी क्रयशक्ति बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम क्रयशक्ति बढ़ाने का उपाय सोचेंगे, या नहीं सोचेंगे।[s28]

उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए और क्या सोचेंगे? ग्रामीणों का विकास कैसे होगा? गरीब अगर विकसित नहीं होगा, गरीब के पास पैसा नहीं आएगा, गरीब की क्रय-शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो ग्रामीण विकास का कोई मतलब नहीं है। देश के 70-80 प्रतिशत गरीब लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ाए बिना देश की हालत ठीक नहीं हो सकती है। जब देश की हालत ठीक करने के लिए आप बैठे हैं, तब गरीबों की क्रय-शक्ति बढ़ाइए। महंगाई की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं।

महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण चीज पानी, जल, ड्रिंकिंग वाटर है। हिन्दुस्तान की आजादी का 61वां वर्ष प्रारम्भ हो गया है और 61 साल की आजादी के बाद भी, हम अगर आम लोगों तक पीने का पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आजादी का कोई मतलब ही नहीं हुआ। आप भी गांव और गरीब परिवार से आते हैं। आप भी अहसास करते होंगे और पूरा सदन भी इस बात का अहसास करता होगा। आज भी देश के ग्रामों में पीने का शुद्ध पानी ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है। किसी गांव के लोग गन्दे कुए का पानी पी रहे हैं, तो किसी गांव के लोग गंदे तालाब का पानी पी रहे हैं। खासकर हमारे प्रदेश बिहार में ऐसी स्थिति है। हमारे प्रदेश में गरीबी भी है; इसमें कोई दो मत नहीं हैं। वहां गरीब भी हैं, पिछड़े भी हैं। उसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है।

महोदय, बिहार के अनेक गांवों के पानी में आर्सेनिक आ रहा है। इस कारण वहां बहुत लोग रोगों से ग्रस्त हैं। इसके लिए हमने क्या कार्रवाई की है? हमारे पास योजना है। बिहार के विभिन्न इलाकों के बारे में आपके पास रिपोर्ट्स हैं, लेकिन वहां अभी तक पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वहां शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? निश्चित तौर पर अगर हम ड्रिंकिंग वाटर नहीं देंगे, तो यह देश के आम नागरिकों के साथ न्याय नहीं होगा।

महोदय, शौचालय की व्यवस्था का मामला भी मंत्री जी के विभाग से सीधा जुड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान की 61 वर्ष की आजादी के बाद भी हमारे देश की मां और बहनें सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले शौच जाने को मजबूर हैं। हमारे नेता, डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि आज जो हिन्दुस्तान है, वह ऐसा हिन्दुस्तान है, जिसकी मां और बहनें दिनभर गंदे शौच को अपने पेट में रखकर जीने को मजबूर हैं। हमने आजादी अवश्य प्राप्त कर ली है, लेकिन आजादी का सही मतलब अभी तक गांवों तक नहीं पहुंच सका है। आपने शौचालय का अभियान चलाया है। बहुत कारगर ढंग से चलाया है और आपके पास योजना है। मगर ये शौचालय कितने हद तक सफल हुए हैं, यह आपको मालूम होगा। आपने पूरे हिन्दुस्तान के स्तर पर और हमारे बिहार के पैमाने पर जो टार्गेट रखा था, क्या वह पूरा हुआ है, यह हम माननीय मंत्री जी से जब वे जबाव देंगे, तब जानना चाहेंगे? आज भी, आपके चाहने के बावजूद गांवों में शौचालयों की उपलब्धता बड़े पैमाने पर नहीं हो रही है। हम यह नहीं कहेंगे कि आप अवेयरनैस जगाने का काम नहीं कर रहे हैं। आप अवेयरनैस जगा रहे हैं। आप लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। आप मीटिंगों के माध्यम से और अपने भाषणों के माध्यम से लोगों में जागृति ला रहे हैं, लेकिन इस काम को करने वाली एजेंसी राज्य सरकार की है और स्टेट गवर्नमेंट अपने काम को ठीक प्रकार से नहीं कर रही है।

महोदय, विज्ञापन छप रहे हैं, वह हम लोगों पर हमला है। माल महाराजा का और मिर्जा खेलें होली, वाली बात हो रही है। भारत सरकार का पैसा है और जो वहां के सांसद हैं, उन्हें ही फंक्शन में नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि हम लोग प्रतिपक्ष के हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमें अपने फोटो नहीं छपवाने हैं, हम तो चाहते हैं कि गांवों का विकास हो। हमारे लिए गांवों का विकास ही सर्वोपरि है। गांवों के विकास का दायित्व राज्य सरकारों का है। वहां ऐसा हो रहा है कि पूरा पैसा भारत सरकार दे रही है और फोटो छप रहा है माननीय मुख्य मंत्री जी का और वहां के मंत्रियों। भारत के प्रधान मंत्री जी गायब, मंत्री जी गायब और वहां के लोकल सांसद गायब। जगह-जगह बोर्ड लगे हुए हैं और उनमें नीचे लिखा हुआ है 'राज्य सरकार के सौजन्य से' मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बारे में आपका क्या विचार है? काम कीजिएगा आप, काम कर रही है यू.पी.ए. सरकार और नाम हो रही है एन.डी.ए. सरकार का। क्या व्यवस्था है, इसमें आप कितने सफल हो रहे हैं, वह हमें बताइए? सारे विकास कार्यों का श्रेय हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ले रहे हैं। उन्हें 'विकास पुरुष' कहा जा रहा है। विकास-विकास का नारा लग रहा है। वाह रे विकास। पैसा हमारा और नाम राज्य सरकार का। वोट हमारा और राज तुम्हारा, यह चलने वाला नहीं है। देश का अवाम जानता है कि अगर वोट हमारा है, तो राज भी हमारा होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए आप कुछ कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : राम कृपाल यादव जी, आपको भाषण करते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं कनक्लूड कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी आप जरा ध्यान दीजिए और कुछ कराइए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गए हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यदि माननीय मंत्री जी चाहें, तो आप रात भर इस बहस को चलाइए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं दो-तीन योजनाओं का जिक्र कर के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सर, अगर हमारी बात कुछ कड़वी लग रही हो, तो हमें माफ कीजिएगा। इंदिरा आवास योजना में आपने 25 हजार रुपए से 35 हजार रुपए कर दिया, अच्छी बात है। [r29]

महोदय, हजारों वर्षों से गरीब का घर का सपना था। उसे पूरा करने के लिए इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई। झोपड़ियों को आवास में बदलने का आपने अच्छा काम किया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कब तक सभी लोगों का सपना पूरा होगा, क्योंकि आप जरूरत के मुताबिक आवास नहीं दे पा रहे हैं। इंदिरा आवास योजना में आवास 25 हजार रुपयों से नहीं बनता है। आपने इस राशि को 35 हजार रुपए किया है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, लोहा, सीमेंट और

मकान बनाने का मैटीरियल का दाम बहुत बढ़ा है, इसके साथ मजदूरी भी महंगी हो गई है, ऐसे में क्या कोई 35 हजार रुपए में मकान बना पाएगा? माननीय सदस्य ने सही कहा है कि इस पैसे को और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। इतने पैसे में भी दलालों को, बिचौलियों को पैसा देना पड़ता है।

14.21 hrs.

(Shri Giridhar Gamang *in the Chair*)

पांच से दस हजार रुपए बिचौलिए या व्यवस्था के अंदर लोगों को पैसा देना पड़ता है। अगर वे यह पैसा नहीं देते हैं तो पैसा लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाएगा। आपने कुछ उपाय किए हैं, लेकिन वे सार्थक नहीं हैं। आज भी बड़े पैमाने पर इस पैसे में लूट हो रही है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो पैसा दिया जा रहा है, पंचायत स्तर पर, बीडीओ से ले कर दूसरे अधिकारी उसमें लूट मचा रहे हैं। उस पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे, कैसे गरीब तक पैसा जाएगा? 35 हजार रुपया आपने इस योजना के लिए लाभार्थी को देने के लिए रखा है, लेकिन उसमें से ज्यादातर पैसा बिचौलियों में ही चला जाता है और गरीब आदमी तक पूरा पैसा नहीं जा रहा है।

वृद्धा अवस्था पेंशन योजना के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह बहुत लोकप्रिय योजना है। आपने पेंशन को बढ़ा कर दो सौ रुपए किया है। उसका दायरा भी प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार बढ़ाया है। यह उत्तम कदम है, लेकिन हम जिस प्रदेश से आते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहां अभी तक राज्य सरकार ने जो योजना थी, दो तरह की योजनाएं थीं, एक भारत सरकार की योजना है और दूसरी राज्य सरकार की योजना है। भारत सरकार की योजना तो चल रही है, लेकिन बिहार सरकार की योजना नहीं चल रही है। वहां की सरकार समझती है कि सौ रुपए को दो सौ रुपया उसने किया है और राज्य सरकार अपने नाम से वह पैसा लाभार्थी को बांट रही है। आप उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? राज्य सरकार वहां सहयोग नहीं दे रही है। राज्य सरकार वहां अपना नाम भांजने का काम कर रही है। इसे रोकने के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? आप जो काम कर रहे हैं, कम से कम उसके लिए विज्ञापन तो छपवाइए। वहां एक पैसा भी राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के लिए नहीं दिया गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो पैसा दिया था, उसे भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं दे रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि इन योजनाओं का प्रचार और प्रसार मंत्रालय अपने माध्यम से करे, जिससे कि राज्य सरकार आपके कामों को अपने खाते में न ले सके। वृद्धावस्था पेंशन योजना एक लोकप्रिय योजना है। आपने 65 वर्षों के वृद्धों के लिए घोषणा की है। आप इस योजना को इम्प्लिमेंट कीजिए। अभी तक राज्य सरकारों द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। लोगों के आवेदन आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है। एक अंतिम बात मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में कहना चाहता हूं। यह योजना एक क्रान्तिकारी कदम है। पूरे देश में इस योजना के अन्तर्गत आपने जो राशि आवंटित की है और योजना रखी है कि वर्ष 2009 तक एक हजार की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। यह अच्छी बात है कि काम हो रहा है और वाहवाही भी हो रही है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, हमारे यहां सेन्ट्रल एजेन्सी काम कर रही है, जिस रफ्तार से आप पैसा देना चाहते हैं, जिस रफ्तार से आप काम करवाना चाहते हैं, उस रफ्तार से देश और बिहार में काम नहीं हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने पिछले तीन-चार वर्षों में जो राशि आवंटित की है, उसका कितनी गुणवत्ता के साथ उपयोग हुआ है? मैंने आपका ध्यान गुणवत्ता की तरफ आकर्षित करवाया है। गुणवत्ता की कमी की वजह से रोड़ पांच साल से पहले ही टूट जाता है। एनबीसीसी इत्यादि चार-पांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन वे धीमी गति से कर रही हैं। इसमें राज्य सरकार का असहयोग भी है। हमारे यहां भारत सरकार जो काम कर रही है, उससे हमारी और यूपीए सरकार की इमेज बढ़ रही है। इससे भारत सरकार और एमपीज़ को फायदा हो रहा है तो राज्य सरकार ने अड़ंगा लगा दिया है, पूर्ववर्ती राज्य सरकार और वर्तमान की केन्द्र सरकार ने एमओयू साइन किया था और सेन्ट्रल एजेन्सी को जिम्मेदारी दे दी गई[r30]। राज्य सरकार ने कहना प्रारंभ कर दिया है कि हम सेंट्रल एजेंसी से काम नहीं करायेंगे, क्योंकि उनका बोर्ड वहां नहीं लगा रहा है। उन्होंने कहा कि इनका डीपीआर बनाकर मत भेजो। डीपीआर बनाने का आपने डायरेक्शन दे दिया, आप अडिग हैं कि आप इसे करायेंगे। आपने यहां तक राज्य सरकार को कहा कि वर्ष 2009 तक सड़कों का निर्माण करना है, जहां भी एक हजार से अधिक की आबादी है। पैसे की कोई कमी नहीं है। आप सेंट्रल एजेंसी को भी काम करने दें, राज्य सरकार भी जितना दे सके, योजना भेजे, हम उसे भी राशि देंगे। मगर राज्य सरकार की वजह से खासकर बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पूरे तौर पर लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि आपको बिहार पर स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि आप बिहार के सपूत हैं और बिहार के लाल हैं। इन तमाम चीजों पर आपको ध्यान देना है। बागवानी योजना के संबंध में कहना चाहूंगा कि पिछले तीन-चार साल के दरम्यान मात्र पैंतीस करोड़ रूपए बिहार की सरकार इसके लिए ले सकी है। ये है, बिहार की सरकार, जहां विकास पुरूष हो रहे हैं। ये वहां के हालत हैं। मैं समझता हूं कि इन तमाम बतों का आप जिक्र करेंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की यदि ठीक ढंग से मानिटरिंग नहीं की जाएगी, ठीक ढंग से राशि आवंटित नहीं की जाएगी, गांव का विकास नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। मैं इस बात को मानता हूं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले वित्तीय वर्ष से इस बार लगभग 18 से 19 प्रतिशत राशि इनहैंस की है। पहले की सरकार से लगभग तीन से चार गुना पैसा बढ़ाने का काम किया है। यूपीए सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी आप गांव की चिंता से चिंतित हैं और आप ही कुछ कर सकते हैं। इनसे कोई आशा नहीं रखी जा सकती है। ये भारत विकास वाले लोग नहीं हैं, ये इंडिया शाइनिंग में विश्वास करते हैं। भारत का निर्माण आपके हाथों में है। जब तक आपका कुशल नेतृत्व नहीं मिलेगा, तब तक देश और गांव का विकास नहीं हो सकता है।

इन्हीं चंद बातों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि जो कमी है, उसे आप दूर कीजिए और देश को आगे ले जाने में सहायक भूमिका अदा कीजिए। गांव का गरीब आपकी तरफ देख रहा है। आप गांव के बेटे हैं। खेत और खलिहान में काम करने वाले किसान हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा।

*SHRIMATI K. RANI (RASIPURAM) : Sir, a great privilege for me to participate in the discussion on the Demands for Grants

of the Ministry of Rural Development for 2008-09, and also to extend my support. While doing so, I would like to place the following few points for the consideration of this august House.

In rural development, we have three very ambitious and flagship programmes, viz. Bharat Nirman, NREG scheme and the PMGSY, among others. As regards Bharat Nirman, our country has made impressive progress in the previous year. Under Bharat Nirman, on each day of the year, 290 habitations are provided with drinking water, 17 habitations are connected through all weather roads. 52 villages are provided with telephones and 42 villages are electrified each day. This is the achievement of our Govt, under Bharat Nirman, which needs recognition from all sections of the House.

Under this programme, action is being taken with regard to irrigation facilities, rural roads, rural housing, rural water supply, rural electrification and rural telecommunication connectivity, etc.

This is a programme envisioned,

â€¢ To connect 66,802 habitations with all weather roads

â€¢ To construct 1,46,185 kilometers of the new rural roads network

â€¢ To upgrade 1,94,132 kilometers of the existing rural roads network

The target to complete them is next year and hopefully, with the guidance of the UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi and under the supervision of our hon. Prime Minister, they would be completed by the targeted date, with sufficient allocation of funds for all the projects.

Coming to the National Rural Employment Guarantee Scheme, it is said that it will be rolled out to all the 596 rural districts in India. Here, Rs. 16,000 crore is provided to start with; and there is also an assurance from the Finance Minister that as and when there is demand, the allocation will be increased.

---

* Speech was laid on the Table.

As far as Tamil Nadu is concerned, there are ten districts which are covered under NREGS now. This Scheme is a grand success all over the country and I request that it may be increased to cover more districts of rural Tamil Nadu so that many poor people are benefited.

In the case of Rajiv Gandhi Drinking Water Mission, the goal is to supply safe drinking water to uncovered habitations and slipped back habitations. Here, the allocation has been increased from Rs.6500 crore to Rs.7300 crore this year.

The other important flagship programme of this Govt, here is the Rural Roads Scheme or PMGSY. Here also, rural roads are being constructed on a grand scale throughout the country, and this Govt, deserves congratulations from all sides of the House.

We know that real India lives in villages. Development has to hit rural India; villages have to be connected by Internet; there should be adequate push to rural economy; 'Roads' should lead to rural prosperity; health facilities should be extended to rural India. There is a need to look into all these major aspects and to make sufficient allocation of funds for these.

I hope the Govt, is focusing its attention on all these and making sufficient allocation of money to make rural India a prosperous India so that urban-rural divide is minimized.

With this, I support the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development and I thank the Chair for having given me time to participate in this discussion.

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का बजट के लिए धन्यवाद करूंगी। मुझे अफसोस है और बड़ा दुख है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे आज विपक्ष की हो या कल हमारी सरकार हो, लेकिन जब भी हम लोग रूरल एरियाज में जाते हैं और यहां आते हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहां आकर हमें बहुत खुशी होती है कि हम भारत सरकार से इतनी सारी योजनाएं रूरल एरियाज के लिए लेकर जा रहे हैं और वह भी उन लोगों के लिए ले जा रहे हैं, जो पिछली पंक्ति में खड़े होते हैं, लेकिन धरातल में उनको कुछ नहीं मिल पा रहा होता है। हम लोग उनके बीच जाते हैं और मीटिंग करते हैं। वहां पर जो जमीनी सच्चाई हमें पता चलती हैं, उसमें उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। आज भी यह सच्चाई है कि आजादी के साठ साल होने जा रहे हैं, फिर भी यदि आप उनके साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, तो उनको यह भी नहीं मालूम होता है कि एक सांसद क्या कर सकता है? न हम वृद्धावस्था पेंशन दे सकते हैं, न ही हम उनको लाल कार्ड दे सकते हैं, न हम उनको किरोसीन तेल दे सकते हैं और न ही उनको इंदिरा आवास दे सकते हैं। उनकी जो जमीनी मांग है, वह इससे ऊपर उठी ही नहीं है। यही सच्चाई है। आज हमारे गांव में खासकर बिहार में, हम जिस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी आधी आबादी बांध के अंदर है उनकी यही मांग रहती है और उनकी आंख में आज भी वही आंसू हैं, जो पचास-साठ साल पहले थे। चाहे जिसकी सरकार रही हो, सिर्फ प्रलोभन देकर उनका वोट ले लिया जाता है। उनको आज यदि सब्सिडी मिल भी रही है, तो भी उनको तीस रूपए से नीचे किरोसीन तेल नहीं मिलता है। यदि उनको आज सब्सिडी मिल रही है, तब भी चाहे अन्योदय योजना हो या अन्नपूर्णा योजना हो लेकिन उनको तीन रूपए प्रति किलो वाला चावल नहीं मिलता है। डीलर सरेआम मार्केट में उसे बेचता है, उसमें ब्लाक भी मिला होता है, एफसीआई के पदाधिकारी भी मिले होते हैं। आप इंदिरा आवास के लिए चाहे पच्चीस हजार से पैंतीस हजार रूपए कर दें, चाहे पचास हजार रूपए कर दें, फायदा अगर किसी को हो रहा है, तो वे बिचौलिए हैं, पदाधिकारी है और पंचायती राज के भी कुछ सदस्य हैं। [p31]

हमने इम्प्लीमैंट किया कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम उनका एकाउंट खुलवाएंगे, लेकिन हम जितनी योजनाएं दे रहे हैं, मैं कहती हूं कि आप उसे एक साइड में रखकर, यदि हमें अभी किसी चीज की जरूरत है तो वह यह है कि इन योजनाओं को इम्प्लीमैंट करने के लिए हम कौन सी योजना बना रहे हैं और इसके लिए हमें ब्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। पदाधिकारी, पंचायती राज, विधायक हों या एमपी हों, जो भी कमीशन ले रहे हैं, यहां कोई नहीं बोलता हो, लेकिन डीएम, डीडीसी, ब्लॉक और मैं कहूंगी कि कुछ एमपीज़ तक का पीसी बंधा हुआ है। चाहे एमपी का फंड हो, चाहे रूरल एरिया का फंड हो, सबमें 22 से 30 प्रतिशत पीसी पदाधिकारियों को जाता है। मैं यह भी कहूंगी कि आपने सांसद को चपरासी की तरह बनाया हुआ है। आपने कहा कि हमने आपको निगरानी कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, लेकिन यदि सरकार विपक्ष की है तो वहां कोई भी डीएम या पदाधिकारी आपकी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी मौनीटरिंग सीएम से होनी है। हमने कई बार मीटिंग की और आज यह सच्चाई है कि मैंने चार महीने से मीटिंग करनी बंद कर दी है। हमने बहुत सी चीजों को उजागर किया, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे बीपीएल की लिस्ट हो, चाहे वृद्धा पैंशन हो, चाहे अन्त्योदय हो, चाहे अन्नपूर्णा है, चाहे प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, धरातल पर लाकर सबूत के साथ रिप्रैजेंट किया गया। आपने प्रधान मंत्री निर्माण सड़क योजना शुरू कर दी। लेकिन प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आज तक कितनी सड़कों का पूर्ण निर्माण हो चुका है। हमने कितने लोगों को ब्लैक लिस्टेड सामने लाकर दिखाया। जो पांच-पांच बार ब्लैक लिस्टेड हुआ, उसे ही बार-बार टेंडर दिया जाता है, सरेआम टेंडर दिया जाता है। उसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। सच्चाई यह है कि जब तक हम धरातल में जाकर इस चीज को इम्प्लीमैंट नहीं करेंगे कि हमें अपनी राशि को इम्प्लीमैंट कैसे करवाना है, तब तक कुछ नहीं होगा। यह सच्चाई है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि एक रुपये में से 15 पैसे ही गरीब को मिलते हैं। आज मुझे लगता है कि उससे भी कम मिलता है। आज बिहार में जो प्रशासन की मनमानी चल रही है, पदाधिकारियों की मनमानी चल रही है, सरेआम पीसी और घूस ली जा रही है। मैं कहूंगी कि अपने संविधान में संशोधन करके यदि हम इस पीसी को अनिवार्य कर दें, तो 80 परसेंट राशि जमीन पर उतरनी शुरू हो जायेगी, क्योंकि हम अंदर-अंदर कमीशन और पीसी ले रहे हैं, दे रहे हैं लेकिन ऊपर से बोलने वाला कोई नहीं है। आज हम इंदिरा आवास के लिए गांव-कूचों में जाते हैं, जो जैनविन आदमी है, उसे कुछ मिल नहीं रहा है। हमने बीपीएल की लिस्ट बनाई। एक बार बनायी, तो एपीएल के लोग बीपीएल में आये और बीपीएल के लोग एपीएल में आये। 20 साल से जो लोग बीपीएल के तहत लाभार्थी थे, आज उनका नाम बीपीएल में नहीं है। उसकी जांच बैठायी गयी और दोबारा बीपीएल लिस्ट बनी। आज तक जो जनरल बीपीएल धारक हैं, उनको अभी तक कार्ड भी मुहैया नहीं कराया गया। अभी जो नयी बीपीएल लिस्ट आयी है, उसमें भी जैनविन लोगों का नाम नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी आपको मालूम है कि पंचायती राज में पदाधिकारी और ब्लॉक वोट देखकर कि किस जाति ने, किस पार्टी ने हमें वोट दिया और कौन ग्रुप, कौन गांव, कौन कस्बा हमें वोट देता है, उसके आधार पर बीपीएल लिस्ट बनायी जाती है। उसके आधार पर अन्त्योदय औंर अन्नपूर्णा दिया जाता है। उसके आधार पर किरोसिन तेल दिया जाता है। हम लोग जब गांव में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम आपको वोट देकर मर गये क्योंकि सरकार किसी और की है। वे एक ग्रुप को तेल देकर चला जाता है, हम लोगों को कहता है कि 30-40 रुपये में लेना है, तो ले लो। उसके बावजूद जो बचा हुआ तेल है, जो 30-40 रुपये में लेने लायक है, वह यदि मरकर लेते भी हैं लेकि उसमें भी 70 प्रतिशत तेल मार्केट में बेच दिया जाता है या थोड़े अच्छे किसानों को दे दिया जाता है। वे खेतों में ट्रैक्टर चलवाते हैं।

अभी हमारे माननीय सदस्य रोजगार गारंटी योजना के बारे में कह रहे थे। आप स्पष्ट करें कि रोजगार गारंटी योजना के तहत क्या बिहार में मिट्टी का कार्य भारत सरकार ने तय किया है या बिहार सरकार ने तय किया है क्योंकि सबको मालूम है कि 17 जुलाई को बिहार में बाढ़ आती है। वहां पर सिवाय मिट्टी के कार्य के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं दिया गया है। कार्य करने वाले लोग जिला परिषद के हों या रोजगार गारंटी के तहत मजदूर लोग हों, वे कहते हैं कि हमें पदाधिकारी ने बोला है कि हमें किसी भी हालत में पैसा खर्च करना है। आप जहां मर्जी गड्ढ़ा खोदो लेकिन पैसा खर्च कर दो। आज किसी के खेत में गड्ढ़ा खोद दिया गया है, सड़क के किनारे गड्ढ़ा खोद दिया गया है। उसके कारण सड़क भी खराब हो रही है और गड्ढ़े भी खराब हो रहे हैं। उसके कारण कीचड़ भी हो रहा है और सड़क भी खराब हुई। इसके अलावा खेतों में गड्ढ़े किये हुए हैं। क्या इसके बारे में किसी ने सर्वे या निगरानी कराई है कि रोजगार गारंटी के तहत मिट्टी का कार्य हो रहा है, मात्र दो तीन महीने के लिए मिट्टी का कार्य होता है। वे लोग पूजा कर रहे होते हैं कि कब बरसात आये और हम अपना फाइल में पैमेंट उठायें और फिर मिट्टी का मिट्टी हो। हम दोबारा से फिर वहीं गड्ढ़ा खोदेंगे।[N32]

उसी तरह मंत्री जी, क्या आपको मालूम है कि जॉब कार्ड बनाने के लिए 25 रुपये से लेकर सौ-दो रुपये रुपये तक लिये जाते हैं। यहां वह गरीब व्यक्ति मरता है जो इंदिरा आवास में भी मर रहा है क्योंकि जहां तक कमीशन का सवाल है, तो जो व्यक्ति पांच हजार रुपये देने की हैसियत रखता है, वह गरीब नहीं है । हम लोगों ने गांव मे जाकर देखा कि जो गरीब है, जिसे जैनुइन तरीके से इंदिरा आवास की जरूरत है, वह पांच हजार रुपये की हैसियत नहीं रखता है। ऐसे लोग गांव के बिचौलिये को दो हजार रुपये देकर आज भी इंदिरा आवास का सपना देख रहे हैं। जब हम मीटिंग करते हैं, तो पता लगता है कि 90 प्रतिशत इंदिरा आवास बन गये हैं। उसके लिए इतनी राशि खर्च हो गयी लेकिन यदि आप गांव में जायें, तो जो गरीब तबका है जिनको शायद भूले से एक राशि मिली भी होगी, उनके पास छत नहीं है। सिर्फ चार या दस फीट की दीवार खड़ी की गयी है। अब आप 35 हजार रुपये करें या 50 हजार रुपये करें, यदि 50 हजार रुपये होंगे, तो मुझे यह जरूर मालूम है कि उनका कमीशन बढ़ जायेगा। आज दिनों-दिन कमीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैनुअन तरीके से जो गरीब व्यक्ति है उसे न केरोसिन तेल मिलता है और न

ही इंदिरा आवास मिलता है। यहां तक कि बीपीएल लिस्ट से भी उसका नाम छांट दिया गया है। यही हालत भारत सरकार की वृद्धा पेंशन की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को यह जानकारी नही है कि भारत सरकार की वृद्धा पेंशन कौन सी है और बिहार सरकार की कौन सी है और किस तरह का हमें लाभ मिल रहा है? हम जहां जाते हैं वहां हम प्रयास करते है कि लोगों को इस बात की जानकारी हो, लेकिन उसके बावजूद पदाधिकारियों का रवैया बहुत उदासीन है। हमें इन योजनाओं को सही तरह से इम्प्लीमैंट करना चाहिए। पहले हम लोगों को जागृत करें कि आपके लिए ऐसी कितनी योजनाएं हैं, जो भारत सरकार आपके हक के लिए दे रही हैं। लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती। आज भी उन्हें यही भ्रम है कि जिनका बीपीएल में नाम है, उन्हीं के लिए वह है जबकि आपने कहा है कि जो भी 65 वर्ष से ऊपर है, उसे पैंशन मिलेगी। इसी तरह से आपने विकलांग लोगों के लिए पर पंचायत 15 लोगों का किया है। लेकिन आज तक ब्लाक द्वारा, पंचायत द्वारा बिहार के प्रशासन द्वारा किसी को जानकारी देने की अहमियत नहीं की गयी है ताकि लोगों को जानकारी मिले। जब लोग जागृत होंगे, लोगों को पता चल जायेगा कि हमारा हक है, तो वहां पर कमीशन थोड़ा कम हो जायेगा, लेकिन बंद नहीं होगा।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहूंगी कि सबसे पहले यदि योजना को कार्यान्वित कराना है, तो हम उसे इम्प्लीमैंट कैसे करें, यह बहुत ही चिंतन का विषय है। यह सिर्फ आज का नहीं है चाहे उसकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, यह 60 साल से चला आ रहा है। जब तक यह कमीशन बंद नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जिन लोगों को खाना मिल रहा है या जिनके पास घर है, वे थोड़ा बहुत कमीशन देकर अपना काम करा लेंगे, लेकिन जो एक दीवार अमीरी और गरीबी को दिनोंदिन पटती जा रही है, हम अपने टाउन का जितना माडर्नाइजेशन कर लें, जितना आगे बढ़ जायें, लेकिन गरीब आज भी गरीब होता जा रहा है, उसकी स्थिति ऊपर नहीं आ रही है। आज भी गांवों में लोगों के पेट में खाना नहीं है। उनको न मिड डे मील मिल रहा है और न ही स्कूलों में सही शिक्षा हो रही है। हम यहां शिक्षा को और अच्छा करने की बात करते हैं, लेकिन गांवों में आपकी बेसिक शिक्षा से ही लोग बेहाल हैं। मैं मिड-डे मील की बात करना चाहूंगी। मैं आपसे यह जरूर कहना चाहूंगी कि मिड डे मील की जिम्मेदारी आप शिक्षकों को न दें। मिड डे मील की जिम्मेदारी होने से वे शिक्षक दो-तीन दिन छुट्टी ले लेते हैं कि हमें चावल लेकर आना है, दाल लेकर आनी है। आप उसका अलग से कोई पदाधिकारी नियुक्त करें और उसके बाद उसकी क्वालिटी को मेनटेन किया जाये। आज भी बहुत सारे पेपरों में आपने देखा होगा, हम लोगों ने आंखों से देखा है कि मिड डे मील में जो खाना बच्चों को परोसा जाता है, उससे कई बच्चे बीमार हुए हैं क्योंकि वे फूफंदी लगा हुआ चवल खा रहे होते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगी कि पहले हम उन गरीबों की उपेक्षा न करें, उन गरीबों का भी हक समझें कि उनका भी हिन्दुस्तान में उतना ही हक है। उनको भी सही फूड, अच्छा भोजन और स्वास्थ्य लाभ का उतना ही हक है जितना एक अमीर आदमी को है। उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं।

मैं एक प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने क्वेश्चन ऑवर में स्वजलधारा योजना के बारे में क्वेश्चन उठाया था। आपको भी जानकारी होगी कि वहां जो कोशी एरिया है, मैं सच बता रही हूं कि मैं भी वहां का पानी नहीं पीती क्योंकि यदि मैं चार दिन भी वह पानी पी लूं, तो बीमार पड़ जाऊंगी। वहां पर बहुत ज्यादा आयरन है, आर्सेनिक है जिसके कारण लाखों करोड़ों की संख्या में व्यक्ति बीमार पड़ रहे हैं। वे कैंसर, गेंगरिन, ट्यूमर की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही। आज भी वे दूषित पानी ही पीते हैं चाहे चापाकल से पीयें, चाहे कुएं से पीयें या नदी से पीयें। [MSOffice33]

आज तक इस पर रिसर्च नहीं हुई कि जब हम पानी को नॉर्मल फिल्टर करने के बाद भी उस पानी से आर्सेनिक नहीं जाता है। एक जगह आप दस किलोमीटर चलकर एक घड़ा पानी लेकर आते हैं और दूसरी तरफ हमारे यहां दूषित पानी, जिसे मैं कह सकती हूँ कि जहरीला पानी है, आज तक लोग पी रहे हैं और इसकी ओर किसी की नजर नहीं गयी, न आज तक कोई रिसर्च टीम वहां इसके अध्ययन के लिए गयी। इसी तरह स्वच्छता अभियान के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि पंचायत का कोई भी पदाधिकारी इसमें रूचि नहीं लेता है कि वह लोगों को यह बताए कि 1500 रूपए में उनके घर में शौचालय बन सकता है। आज लोगों की ऐसी मंशा बन चुकी है कि वे हम लोगों से डायरेक्ट मांगते हैं कि आपको शौचालय बनाने के लिए पैसा देना है तो दीजिए, 35,000 रूपए या 40,000 रूपए देने हैं तो दीजिए क्योंकि वे जानते हैं कि इसमें से कम से कम 10,000 रूपए वे बचा लेंगे। हम उन गरीबों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जिनको सिर्फ शौचालय चाहिए, न कि पैसे चाहिए। आज भी गांवों में, घरों में जिनको इसकी जरूरत है, वहां पर उनके लिए शौचालय नहीं बन रहे हैं। मैं बजट का समर्थन करते हुए यह कहूंगी कि आपका काम योजना बनाना है। आपने योजना बनाई है, लेकिन हम सभी का काम है उसे इंप्लीमेंट करना, जिसके लिए हम सभी दोषी हैं और हमें ही इन्हें सही ढंग से इंप्लीमेंट करना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि कोई ऐसी योजना बने जिसमें सभी को यह भाव मिले कि इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसमें जमीन पर किस तरह उतारेंगे और गरीब को उसका हक किस तरह से देंगे।

*SHRI K.C. PALLANI SHAMY (KARUR) : Hon. Sir, Vanakkam ! I extend my support to the Demands for Grants pertaining to the Union Ministry of Rural Development. Let me thank the chair for giving me this opportunity. I would like to place on record my deep gratitude and heartfelt thanks to our leader the Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar Karunanidhi and Thalapathi Mu. Ka. Stalin, the lieutenant of our Dravidian Movement who is also the Rural Development Minister of Tamil Nadu, who have enabled me to represent the people of my constituency in this august House.

I also would like to congratulate and thank our Hon. Ministers for Rural Development both Shri Raghuvansh Prasad Singh and Shri Chandra Shekhar Sahu for implementing various programmes for social, economical and infrastructural development of rural areas in the country.

As a Member of the Departmentally Related Standing Committee on Rural Development, I have witnessed a lot of improvement in the monitoring mechanism and I am sure that with the efforts put in by the Ministry, the status of our rural people in our country would considerably improve.

After becoming a member of this august House in 2004, atleast till 2006, whenever we met our Union Minister of Rural Development Dr. Raghuvansh Prasad with some demands he would always be insisting on forwarding of recommendation from the State Government. The then Government in Tamil Nadu used to ignore all our recommendations. It is our good

fortune that we now have good governance in Tamil Nadu with Dr. Kalaignar Karunanidhi at the helm of affairs. After his coming to power, we were spared from running from pillar to post. Instead of our going in search of officials the officials themselves are coming to people's representatives like me as directed by our Chief Minister. So the schemes suggested by us are being recommended by the State Government.

---

*English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Hence I urge upon the Union Rural Development Minister to take note of the welcome change and concede to our rightful demands duly recommended by the Government of Tamil Nadu.

I would like to point out that Government of Tamil Nadu is in the forefront in implementing all the centrally sponsored Rural Development Schemes. Our leader Thalapathi Mu. Ka Stalin, as Minister of Rural Development has done a very commendable job in making all round development particularly in providing good rural roads and clean drinking water to all the villages in rural Tamil Nadu under Anna Marumalarchi Scheme. Government of Tamil Nadu has made a great strides in computerization of records pertaining to land and rural water supply. As he has been taking very keen interest in all aspects of Rural Development, I personally appeal to the Hon. Union Minister Shri Prasad to allocate additional funds for Rural Development Schemes in Tamil Nadu, especially to upgrade the rural roads from being mud road to metalled roads.

I am glad that National Rural Employment Guarantee Act that came in to force in February, 2006, has been extended to all the 604 districts throughout the country. Government of Tamil Nadu has provided marketing infrastructure facility to women's self help groups under the Poomalai Scheme. This is a pioneering scheme to promote the sales of products manufactured by rural women in villages. I urge upon the Union Rural Development Ministry to encourage the State Governments towards construction of State level marketing complexes to provide linkage to the products of Self Help Groups (SHG's). I also urge upon the Union Government to render financial assistance to the Government of Tamil Nadu for setting up pioneering marketing complex units.

Our UPA Government has increased the amount of National Old Age Pension from Rs.200/- to Rs.400/-. In Indira Awaz Yojana that provide Rs.22000 to construct houses in rural areas there has been an increase to Rs.42000. I thank the Hon. Minister and Hon. Prime Minister and also the chairperson of UPA Madame Sonia Gandhi for this remarkable achievement. I thank them on my own behalf and on behalf of our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi.

I would like to make a few demands on behalf of the people of our state and my constituency Karur. Sanitation facilities including Aanganwadi buildings & toilets are not adequate and the number of toilets units should be increased. Fund allocation is made once in five years for their maintenance. It must be made annual. Allocation of additional funds under Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana for my Karur constituency is not there anymore after the implementation of NREGA. I wish the scheme is continued with. Tamil Nadu must get more funds for rural roads.

I would like to request the Union Rural Development Ministry to enhance from Rs. 15000 to Rs.25000 the grant to convert Kutcha houses to Pukkah houses under Indian Awaz Yojana.

Tamil Nadu Government has set up rural libraries extensively in villages. I urge upon the Union Government to provide them with computers so that rural youth will be connected to outer world and job market through internet in the information highway.

While contemplating rural development taking industries and infrastructure facilities there, unfortunately we find nationalized Banks moving out of villages. This trend must be arrested. I urge upon the Union Rural Development Ministry to make a co-ordinated effort to expand and increase the services of Banks and Post offices in rural areas and villages. Information Technology, Postal Services and the Banking Services must be available in a co-ordinated manner in a knowledge society.

I have already requested Hon. Minister to look into these areas. I hope, he would consider these issues favourably for the welfare of rural people of my Karur constituency.

I sincerely express my thanks to the chair for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants 2008-09 pertaining to the Ministry of Rural Development.

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर) : सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी पार्टी बीएसपी की ओर से वर्ष 2008-2009 की ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे प्रदेश में आवासहीन परिवारों को इंदिरा आवास उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार की वचनबद्धता है। प्रदेश में 2002 के बीपीएल सर्वे के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना तक लगभग 45 लाख आवासों की आवश्यकता है, जिसमें नौ लाख आवास प्रति वर्ष की दर से निर्मित कराए जाने थे। केन्द्र सरकार द्वारा 2007-2008 में विभिन्न राज्यों को इस मद में 4032.70 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे।[R34]

उत्तर प्रदेश के साथ, धनराशि के आवंटन में, सौतेला व्यवहार किया गया। इसमें 2 लाख 55 हजार आवासों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 467 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी। बिहार जो हमारे माननीय मंत्री जी का स्टेट है, उसे आपने 5 लाख 67 हजार आवास निर्मित करने के लिए करीब दुगुनी राशि उपलब्ध कराई थी। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत गरीब है और हमारी बगल में माननीय हरिकेवल प्रसाद जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने बताया कि अग्नि-कांड में जिन लोगों को आवास मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिलता है। जब चोरी होती है तो घर का कुछ सामान बच जाता है लेकिन अग्नि-कांड में घर का कुछ भी सामान नहीं बचता है। जिन लोगों का पूरा घर जल जाता है उनको आवास देने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। सर, आप गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं इसलिए गरीबों का दर्द आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोगों की आपसे गुजारिश है कि गरीब लोगों की समस्याओं का आप विशेष ख्याल रखें। आपने आवास के लिए अब 35 हजार रुपये कर दिये हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन आप भी जानते हैं कि आज 35 हजार रुपये में कुछ नहीं बनता है। बिचौलिये चार-पांच हजार रुपये बीच में खा जाते हैं, इसलिए इस राशि को बढ़ाकर आप 50 हजार रुपये करने का कष्ट करें। आज महंगाई बहुत बढ़ गयी है, हर सामान के रेट बहुत बढ़ गये हैं, इसलिए गरीबों के साथ न्याय करके उन्हें आवास दिलाने का कष्ट करें। गरीब के साथ न्याय हो और वह देश की मुख्य धारा में शामिल हो, ऐसा कार्य आपको करना चाहिए।

पिछले बजट में, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, हमारे क्षेत्र सुल्तानपुर को आपने प्राथमिकता दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपने वर्ष 2007-2008 में, उत्तर प्रदेश को 1213 करोड़ रुपये की धनराशि दी थी और वह सारी की सारी राशि इस काम में लग गयी। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1087 करोड़ रुपये की मांग की गयी है लेकिन अभी तक एक पैसा भी वहां नहीं पहुंचा है। आपसे प्रार्थना है कि इस राशि को भिजवाने की कृपा करें।

पिछली बार, केन्द्र सरकार द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 1657 करोड़ 60 लाख रुपये दिये गये, जिनका उपयोग किया जा चुका है। करीब 1057 करोड़ रुपये की मांग और की गयी है। मैं आपसे मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार न करते हुए इस राशि को भी देने का कष्ट करें।

सर, आप गरीबों पर दया दिखाने वाले बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि वर्ष 2002 में बीपीएल की जो सूची बनी थी, उसमें बड़े पैमाने पर गरीबों को हक नहीं मिला, गरीबों के साथ चिटिंग हुई। जो लोग ताकतवर थे, उन्होंने उस सूची में अपना नाम चढ़वा लिया, इसलिए आप उस सूची का दुबारा सर्वे कराकर, गरीबों का जो हक ताकतवर लोगों द्वारा मारा जा रहा है, उसे दिलाने का कष्ट करें, उनके साथ इंसाफ करें।

नल के विषय में मेरा कहना है कि हमारे दोस्त ने 500 नलों की मांग की। हम लोगों को हमारे क्षेत्र में बेइज्जत किया जाता है। जो 542 एमपीज चुनकर आते हैं उनमें से हाई-लेवल एमपीज को छोड़कर, जो हम जैसे गरीब एमपीज हैं उनको टार्चर किया जाता है। इसलिए हर गरीब एमपीज को 1000 नल देने का काम करें, जिससे वे 100-100, 200-200 नल हर विधान सभा क्षेत्र में लगवा सकें और गरीबों के साथ न्याय कर सके। गरीबों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों या सर्वजन समाज में, जो गरीब ब्राह्मण या ठाकुर लोग हैं, जिनके साथ गरीबी के कारण न्याय नहीं हो पाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमेशा उन्हीं को न्याय मिला है जो यहां ताकतवर और मालदार लोग थे। [r35]

महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आप एक हजार नल देने का काम करें। आप बहुत बड़े खजाने के मालिक हैं। आप ही सभी सांसदों के साथ इंसाफ कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) :** महोदय, जब भी कोई राजनेता भाषण देता है तो अपनी बात देश के बारे में इस ढंग से शुरू करता है कि अगर किसी ने भारत देखना है तो भारत के गांव में देखा जा सकता है। अगर कोई धार्मिक नेता बात करता है तो वह कहेगा कि अगर भगवान देखना है तो भारत के गांव में देखा जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी भारत के गांव के उत्थान का सपना देखा था और कहा था कि अगर भारत का गांव विकसित होगा तो देश विकसित होगा। शायद हम आजादी के बाद देश के गांव को भूल गये हैं और गांव के विकास को भूल गये हैं। देश के गांववासियों को भी भूल गये हैं। जितना योगदान देश के विकास में एक गांव का होता है उतना योगदान सरकारों का उस गांव के विकास के लिए नहीं होता। भारत निर्माण के तहत गांव में सड़कें पीने का पानी, खेतों का पानी, घर, बिजली और टेलीफोन जैसी सुविधा देना का छः सूत्री कार्यक्रम लागू करने की योजना भी शायद नाकाफी सिद्ध हो रही है और पिछले चार सालों में भारत निर्माण के तहत 174000 करोड़ रूपये खर्च करने का अनुमान है। रोजगार योजना, सम्पूर्ण रोजगार योजना, सवर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण सेहत मिशन इत्यादि भी देश के गांव के विकास की गति को बड़ा नहीं पा रही।

आज गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई पीने का पानी खेत को लगाने के लिए पानी सड़कें इत्यादि की बहुत भारी कमी देखी जा रही है। अगर कहीं सभी समस्याओं को एक साथ देखना हो तो गांव में देखा जा सकता है। देश में ऐसे भी गांव हैं जहां से शिक्षा लेने के लिए स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए मीलों दूर जाना पडता है। सरकारी अधिकारी वहां जाने को तैयार नहीं है ताकि गांव के लोगों का हाल जाना जा सके। जितनी भी हम योजना बनायेंगे उन योजनाओं का लाभ गांव तक इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी रहती है और केन्द्र भी बहुत सी बातों को राज्यों के ऊपर अपनी जिम्मेवारी से भागता है।

आज गांव से शहरों की तरफ पलायन बहुत बढ़ रहा है। शहरों की भी व्यवस्था इस पलायन के कारण खराब हो रही है। अगर गांव को ही शहरों जैसी सुविधा दी जाये तो इस पलायन को भी रोका जा सकता है। गांव का कुटीर उद्योग लगभग बंद हो चुका है। गांव का किसान भी अब खेती में उतना फायदा नहीं ले पा रहा जितना वो मेहनत करता है। इसलिए खेती भी एक लाभप्रद व्यवसाय नहीं रहा। पहले खेती के कारण कई लोगों को रोजगार मिलता था। और कई परिवारों की रोजी रोटी खेतों के ऊपर ही निर्भर थी। आज जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम हो रही है और फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती की आमदनी की अनिश्चितता बनी रहती है।

---

* Speech was laid on the Table.

इन सभी बातों के ध्यान में रखते हुए प्रश्न पैदा होता है कि गांव का विकास कैसे हो इतना पैसा देने के बावजूद भी जो गांव का विकास होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। फिर कमी कहां है, अगर इस बात का विषलेशण नहीं करेंगे तो एक के बाद एक योजना फेल होती जायेगी और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। मेरा एक सुझाव है मैं लम्बी चौड़ी बहस में पड़ना नहीं चाहता। अगर इस सुझाव पर विचार कर लिया जाये तो हम गांव को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं और गांव का विकास भी कर सकते हैं। सुझाव निम्नलिखित हैं कि जो भी राजस्व एक गांव से मिलता है उस राजस्व की निश्चित मात्रा वो वहीं गांव को दे दी जाये तो एक पंचायत के पास एक साल में कतना पैसा आने वाला है वो हिसाब उनके पास रहेगा। उदाहरण के तौर पर किसी गांव में कोई से बिजली, टेलिफोन बिल मार्किट फीस इतयादि इकटठे होते और वह पैसा राज्य या केन्द्र के पास चला जाता है। अगर पहले सारा पैसा सरकार को जाये फिर वह पैसा वापिस गांव को जाये इस आने जाने में लिकेज बहुत होती है। अगर उस पैसे का प्रतिशत यहीं हर गांव को दे दिया जाये तो गांव की एक निश्चित आमदनी हो जायेगी। तो हर समय उस गांव को विकास के लिए सरकार की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। इसी तरह गांव में ईट के भटटे लगते हैं, पैट्रोल पम्प होते हैं, शराब के ठेके खुलते हैं या कोई उद्योग लगता है। उससे जो भी कर एकत्रित हो उसका एक निश्चित प्रतिशत वहीं गांव को दे देना चाहिए। इससे गांव आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। इससे विकास होगा। रोजगार के साधन पैदा होंगे और पंचायती राज प्रणाली मजबूत होगी। आशा है कि मंत्री जी इस विषय को ध्यान में रखते हुए सरकार की योजना मेरे इस बिन्दु को ध्यान में रखकर बनायेंगे।

*SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGAT SINGH PUR) : Hon. Chairman Sir, I thank you sincerely for allowing me to participate in the Demand for Grants for the Ministry of Rural Development. As you are aware, the soul of India lives in her villages. Ours is a rural-based civilization. The Government which is not concerned about the villages or the upliftment of the rural population can never build a prosperous India. In this context we have to find out why some states in India are regarded as backward. Many of the backward states have majority of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Minority population. In the language of the UPA Government, they are the "Aam Aadmi" Gandhiji believed that if we fail to bring a smile on the faces of the common man, we can never prosper as a nation.

In our villages, the rural people face a multitude of problems like poverty, illiteracy, unemployment etc. They have no access to potable drinking water, no sanitation facilities or good quality roads. They remain cut-off from the urban cities and from development.

Sir, I represent a state called Orissa which is regarded as a backward state although she is richly endowed with bounties of Mother Nature like minerals, forests and a long coastline. Due to the negligence of the centre, the people of Orissa remain deprived and they have not benefited as compared to some other states.

Sir, you yourself represent a tribal-dominant area of our state. It is our good fortune that a revolutionary man like the Hon. Minister is occupying the highest chair in the Ministry of Rural Development. The Minister of State Mr. Chandra Sekhar Suhu, who is from my state is an equally capable man and a pro-active leader. Both of them are great visionaries. They dream of a prosperous India by hastening the pace of work in rural areas. Whenever Hon. Minister delivers his speech, we all listen with rapt attention and get deeply moved.

---

* English translation of the speech originally delivered in Oriya.

We feel, if his vision of the future is translated into reality, very soon the face of rural India will be transformed. There will be no poverty, unemployment or deprivation and all our rural brethren will comfortably march forward to a better life.

In order to reach this goal, the "Pradhanmantri Gram Sadak Yojna" is the 1st step. The Department of Rural Development has taken up the onerous task of connecting all the villages to sub-divisional headquaters and capital cities. But there are certain bottlenecks. In this context I would like to draw your attention to the bordering districts of Orissa as well as other states. There are certain districts which are located in the far flung border areas, in hilly, inhospitable terrain. These areas remain cut off from the national main stream, which has now become the brewing ground of Naxalism, Maoism and Terrorism etc. Sir, I believe the primary reason of this development is the absence of navigable roads. Even after 60 years of independence the tribal people have no access to good quality roads and they remain isolated. Hence I would request the Hon. Minister to give priority to tribal districts and far-flung border areas regarding construction of roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. These areas which are infested with Naxalism, Maoism and Terrorism, the people are rather vulnerable. They are away from civilization and all its progress as they do not have even the most basic infrastructure like road. Thus if these areas are given priority under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojan, it will reduce their bitterness and may dilute their extremist mindset.

Sir, huge amount of funds have been allocated for the purpose of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojan. However, it is now observed that there is a lack of interest in the part of road-contractors. They are reluctant to apply for tender as the profit margin is stated to be very discouraging. Recently while I was chairing a Vigilance Committee, I interacted with district officials. They told me that, there has been an escalation in the price of cement, steel and other raw material. Again there are also problem of transportation. The bridges constructed on the roads are very narrow, their width being only 15 meters. If the width of the bridges are expanded upto 20/30 meters it will greatly benefit the commuters.

Sir, 47.13% of the backward class people reside in Orissa. I am sure there may be some other states who will have similar population dynamics. Orissa is the holy land of Lord Jagannath, who is a symbol of secularism. Two of his most famous devotees are 'Salabeg', a Muslim and 'Dasia' a Scheduled Caste. The real theme of Socialism, Communism and Secularism originates from the land of Jaganath.

Hon. Minister for Rural Development belongs to my neighbouring state. Orissa and Bihar have a rich, cultural, social and spiritual tie. We are thus in a position to demand from the Hon. Minister that he should be extra-generous to us. I am confident that he will respect our hopes with positive action. I would also request that Hon. Minister for State Mr. Chandra Sekhar Sahu be given some additional independent responsibility. As Rural Development is a huge department and Mr. Sahu is a competent, pro-active man, we can hope for better things.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINSTRY OF DEFENCE (SHRI M.M. PALLAM RAJU): You make him Chief Minister. â€¦(Interruptions)

SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGAT SINGH PUR) : Hon. Chairman Sir, drinking water is a basic necessity. It is very unfortunate that after 60 years of independence people do not get clear drinking water. I represent a constituency called JagatSinghPur which is touched by the Bay of Bengal in four places – Balikuda, Ersama, Tirtol and Kakatpur. The people of some villages which are adjacent to the sea do not get potable drinking water. Villagers in many villages of Orissa have to drink with infected water. No wonder they suffer from Dysentery, Diarrhoea and Malaria etc. If after six decades of independence the 'Aam Aadmi' does not get a basic requirement like 'drinking water', it is a sad commentary on the state of affairs. It is sheer injustice. In Orissa the districts of Ganjam faces acute shortage of drinking water. Other sea-bordering districts like Bhadrak, Balasore, Kendrapara etc. too face this hardship. If 'Desalination' is done properly, this problem can be solved.

Again, the problem of sanitation is also very acute. Huge amount of funds are being allocated. But no monitoring is being done. I would request the Hon. Minister to constitute an Expert Committee under his stewardship to do periodical monitoring and establish inter-state coordination. So that progress can truly be evaluated.

Recently Dr. A.P.J. Abdul Kalam has expressed his concern about widening gap between rural and urban India and the mass migration of rural poor to the urban slums. Today bonded labours, workers etc are leaving their native land to get exploited in an alien land. Are we really the largest democratic country of the world? Is this the future we had dreamt of? We are the representatives of the people in this august House. We are here to voice their grievances.

Sir, the National Rural Employment Guarantee Progarmme is a very good step. But it is going through a lot of uncertainties and we are doubtful about its future. It is a scheme which is like giving homeopathy to an ailing elephant. Merely ensuring 100 days work for a jobless person is very inadequate. It should be increased further. As one of my predecessor was mentioning, a member of the Legislative Assembly can sanction 200 hand-pumps. But we the Member of Parliament can not sanction even two hand-pumps. It is very unfortunate. Hence I would request the Hon. Minister to sanction at least 500 hand-pumps per constituency and also speed up Indira Awaas Yojna for the rural poor. In many areas we see the poor

homeless does not make it to the BPL list, but the well-to-do manages to do. I do not want to go into details.

As per the record of 1997, Orissa had 44 lakh beneficiaries for the Indira Awaas Yojna. But as per the BPL list of 2002 the number has been restricted to 34 lakh families only. We are very unhappy with this development. Our Hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik has met Hon. Minister for Rural Development regarding this issue and hence we demand that the list of 2002 be made null and void and the list of 1997 be prevailed.

Sir, Orissa is a backward state where 70% of the people live in villages. I would like to recite a poem of revolutionary poet Dr. Sachi Routray –

"My village is a small one

it may not be found in a geography book

but if such small villages are happy

they will make India smile".

Sir, lastly I demand that 'Orissa' be given a 'Special package', so that it can prosper like the other states. Jai Jagannatha

Glory to our Mother land Utkal.

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : मंत्री जी, उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की है कि आपने बहुत जोरदार ढंग से अपनी बात रखी है। वह सिर्फ यह मांग रहे हैं कि जैसे एम.एल.एज. को कुछ ट्यूबवैल वगैरह दिये जाते हैं, ऐसे ही सब एम.पीज. को भी अपने-अपने क्षेत्र में लगाने के लिए आप कुछ न कुछ दीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सभापति महोदय, आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शिवसेना पार्टी की ओर से मैं यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्ष 2008-2009 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में मैं शिवसेना पार्टी की ओर से भाग ले रहा हूं। मैं मंत्री जी और उनके मंत्रालय को सपोर्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सारी अनुदान मांगे जल्दी मंजूर हो जायेंगी।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, मैं कहूंगा कि हमारे मंत्री जी बहुत डायनामिक, कार्यकुशल और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। जमीन पर रहकर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कार्य किया है और ग्रास रूट के व्यक्ति होने के कारण ही ग्रामीण विकास की योजनाओं को सब जगहों पर कार्यान्वित करने और उन्हें पूरा करने के लिए वह दिल से आगे आ रहे हैं। उनके साथ साहू जी, श्रीमती सूर्यकान्ता ताई पाटील भी हैं, लेकिन फिर भी उनके मंत्रालय की प्रसिद्धि और प्रचार-प्रसार कम हो रहा है। चाहे जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो, इन सभी जगहों से इतना प्रचार-प्रसार नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो अधिकारीगण हैं, हो सकता है कि वे लोग आपको इतना सहयोग नहीं दे पा रहे होंगे। आप यूपीए सरकार में इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और उसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए, लेकिन वे लोग शायद आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यह बात मैं प्रचार-प्रसार कम होने के कारण कह रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। ग्रामीण विकास संबंधी प्रमुख योजना में वर्ष 2007-2008 में 5262.14 करोड़ की राशि खर्च नहीं की गई। ग्रामीण आवास का मुद्दा अभी बहुत से सांसदों ने यहां उठाया। उसमें 1186.12 करोड़ रुपये ग्रामीण आवास की मद में खर्च नहीं हुए। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की 1491.02 करोड़ रुपये की राशि ऐसे ही पड़ी है। इस मुद्दे पर मैं आगे बोलूंगा। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में 835.74 करोड़ रुपये की राशि ऐसे ही पड़ी है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में भी 434.26 करोड़ रुपये ऐसे ही पड़े हैं, यानी उसका काम आगे नहीं बढ़ पाया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है[b36]?

ग्रामीण विकास के लिए आबंटित राशि जो गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि राज्यों का सहयोग नहीं मिलता, पंचायत राज के हिसाब से फिर जिला परिषद पंचायत समिति का सहयोग नहीं मिलता। मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे सांसदों की एक निगरानी समिति स्थापित की। मैं तो हर साढ़े तीन महीने में एक मीटिंग हमेशा लेता हूं और उसमें कई मुद्दे हल हो जाते हैं और हमें राज्य शासन और केन्द्र शासन की ओर से कभी जो भी धनराशि नहीं मिलती है तो वह मैं आदरणीय मंत्री जी से कहकर वह राशि भी दिलवाता हूं। इसलिए कमेटी के कारण से हमारे कई मुद्दे सॉल्व होते हैं लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सरकार में बैठे कुछ अधिकारीगण इसके बारे में बहुत उत्सुक नहीं हैं। मैं कहूंगा कि कुछ अधिकारी मनमानी क्यों कर रहे हैं? यह गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली योजना निकाली गई है, उसका फायदा गरीब लोगों तक कुछ अधिकारी नहीं होने दे रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत चिंतित हूं। मैं यह भी कहना

चाहूंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था- गांव चलो अभियान। वह इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र के सारे लोग किसान हों या किसान के बच्चे हों, वे सारे शहर में काम करने के लिए जाते हैं क्योंकि उनको गांवों में काम नहीं मिलता है। ये ग्रामीण क्षेत्र से कनैक्टिविटी इसीलिए जोड़ी गई है कि वहां यातायात होगा और उसके बाद किसान ने जो खेती की होगी, उसका जो उत्पादन निकला होगा, वह शहर के क्षेत्र में लाने के लिए एक अच्छी सुविधा होगी और इससे गांवों का भी विकास होगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह योजना शुरु की थी और मैं आदरणीय मनमोहन सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस योजना को कंटीन्यू किया और इसमें बढ़ोतरी भी की। लेकिन बढ़ोतरी करने के बाद हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़े हैं तो वहां के लोग हमेशा कहते हैं कि यहां का रास्ता बनवा दीजिए। अब मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार मैंने मेरे जिले के 110 करोड़ रु. के प्रस्ताव भेजे थे। उसमें से सिर्फ 40 करोड़ के प्रस्ताव पास हो गये। बीच में हम लोगों ने ऑफिसर्स से इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के लोग भी यहां आए थे। आपके जिले का 60 करोड़ रु. का ही प्रस्ताव पास होने वाला है। हमने 110 करोड़ रु. का प्रस्ताव देने के समय सारे गांव वालों को बोल दिया कि आपका यह रास्ता आने वाला है। लेकिन 60 करोड़ रु. का प्रस्ताव पास होने के बाद कौन सा गांव नहीं आया तो लोग हमें कहेंगे कि क्या बात है, आप कैसे कह रहे थे? बाद में जब मैंने फिगर देखी तो उससे भी और कम हो गया। अनुदानों का समर्थन करते समय मैं भारत सरकार से कहूंगा कि हमारी ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दे। जैसे आपने गृह मंत्रालय को ज्यादा पैसे दिए, रक्षा मंत्रालय को ज्यादा पैसे दिए लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण विकास योजना को सबमें ज्यादा पैसा देना चाहिए, यह मेरा सरकार से अनुरोध है।

मैं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कहूंगा कि उसमें कई रास्ते आते हैं, लेकिन आज जो छठां प्लान था, उसमें से कई लोगों ने टेंडर भी नहीं भेजे हैं। उनका कहना है कि सीमेंट, डांबर, तारकोल और रोड़ी का भाव बढ़ गया है, हम कहां से करेंगे? जिन्होंने यह टेंडर लिया था, उन्होंने काम भी शुरु नहीं किया है। उनको पेनल्टी भी लगाई तो भी उन्होंने काम शुरु नहीं किया। उनको ब्लैकलिस्ट भी किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें ब्लैकलिस्ट में डालो लेकिन हम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए काम करने वाले नहीं हैं। सर, मेरा कहना यह है कि यह बहुत अच्छी योजना है। आपने कई रास्ते देखे होंगे, ठीक है कि 5 साल तक उसे मेनटेन करना पड़ेगा। कई सांसदों ने यह कहा कि 5 साल के बाद राज्य शासन को करना चाहिए। राज्य सरकार के लिए अच्छी बात है कि इतनी बड़ी योजना से मदद हो रही है। मैं यह भी कहूंगा कि आपके मंत्रालय से जो लोग भी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, उनके कारण इसमें पारदर्शिता है। मैं यह कहूंगा कि यह जो आज वर्ष 2007-08 में लम्बाई 55020 कि.मी. थी, वह दिसम्बर 2007 तक 22237 ही हो गई। यानी इसमें काम आगे नहीं आ रहा है। इसके लिए कुछ न कुछ मोनीटरिंग हम लोग तो करते ही हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र में हैं लेकिन आपके मंत्रालय से चीफ सैक्रेटरियों को ऐसा पत्र जाना चाहिए कि इसमें कलैक्टर ने या बाकी अधिकारियों ने या पीडब्ल्यूडी हो या जो भी काम करने वाली एजेंसी होगी, उनके जो हैड हो जिन्होंने काम नहीं किया तो उनके ऊपर फाइन होना चाहिए। [r37]

मेरे जिले के 110 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए थे, उनको आप छठे और सातवें प्लान में लीजिए, मैं ऐसी विनती आपसे करूंगा। उसमें एक महत्वपूर्ण काम आप करिए। चूंकि सीमेंट, डामर और खड़ी आदि के भाव बढ़ गए हैं, इसलिए आप उसमें एक्सपैंशन और सुधार करें।

आज भारत निर्माण कार्यक्रम बहुत ज़ोर से चल रहा है। इसमें महाराष्ट्र की अनुदान का बहुत सा रुपया अभी तक नहीं आया है। निर्माण के लिए कहते हैं कि दस प्रतिशत पब्लिक कंट्रीब्यूशन से जमा करके करते हैं, लेकिन मैं प्रामाणिकता से कहूंगा कि उसको भी कांट्रैक्टर ही भरता है। जब मैं ग्रामीण और शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का चेयरमैन था तो हमने जाकर इंस्पैक्शन किया था। हमने वहां सरपंच और ग्रामसेवकों को कहा कि अपनी ग्राम पंचायत की लैजर बुक बताइए। आप कहीं भी बोलेंगे कि इन्होंने उन्होंने पैसा दिया है, डेटवाइज़ बताइए। फिर वे पकड़े गए। उसमें भी कुछ लोग होशियारी करने लगे हैं। उसमें काम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। जैसे आप प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में किसी को देखने के लिए भेजते हैं, उसी प्रकार इस योजना के लिए भी किसी को भेजा जाए, ऐसी मेरी विनती है। मेरे गांव में तो 783 का हमने प्लान करके भेजा है। उसमें से कुछ काम शुरू हो गया है। 1267 गांवों के लिए पीने के पानी की योजना के अंतर्गत हमने भारत निर्माण योजना में लिया है लेकिन उसमें अभी कुछ मंजूरी नहीं मिली है। मैं आदरणीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहूंगा कि ...(व्यवधान) महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है। मुझे 15 मिनट का समय और दीजिए।

सभापति महोदय : एक दो पॉइंट बोलकर आप अपनी बात खत्म करें।

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदय, भारत निर्माण में जो पेयजल की योजना है, उसमें इनको मंजूर करा दीजिए, ऐसी मेरी विनती है। भारत निर्माण में आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे बाढ़ को रोकने के लिए पुरनियंत्रण साठवण तालाब होता है गांव गांव में, उसकी एक शृंखला का निर्माण करिये। आपके विभाग से अभी लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट नहीं आया है। वह आना चाहिए। जो प्रकल्प गृहस्थ होते हैं, उनके लिए जो लैन्ड एक्वीजीशन और उनका पुनर्वसन करते हैं, उसकी योजना भी भारत निर्माण में आनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि भारत निर्माण में जो पुराने तालाब हैं, उनमें जो कचरा और गार नीचे बैठा है, उसे भी निकालने का काम होना चाहिए। उसके कारण बहुत सी पानी की योजनाओं को बल मिल सकता है। सीमेंट बंधारा जो हम करते हैं, उसकी भी गार निकालते जाइए। यह भी भारत निर्माण में एक बड़ी सहायता करेगा। कई जगह बाडी मिलती है, उसमें पानी लगता है, नहीं लगता है। जो पहले के तालाब बने हुए हैं, वे भी कई वर्षों से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ही बने हुए हैं।

सर्व शिक्षा अभियान की बात भी मैं कहूंगा। उसमें स्कूल के कमरों की दुरुस्ती करने के लिए भी आपको प्रावधान करना पड़ेगा। मेरी मंत्री जी से एक मांग है कि आपने जो कहा कि गांव का सरपंच और हैडमास्टर जो होगा, वे दोनों मिलकर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कई कंस्ट्रक्शन इतने बोगस बन रहे हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। आप स्कूल के शिक्षकों को या हैडमास्टर्स को यह काम मत दीजिए। उनका पढ़ाई में ख्याल कम होता है और इधर ख्याल ज्यादा होता है। जैसे मेरे जिले में 28 करोड़ रुपये के कंप्यूटर्स की योजना आई थी। वहां की समिति के माध्यम से वह बाजार में जाते हैं। कंप्यूटर वाला कहता है कि कंप्यूटर हमें ही दे दो। पांच पांच हजार रुपये कंप्यूटर्स के लिए ले लेते हैं और कंप्यूटर बेच देते हैं। आज कई कंप्यूटर्स बंद पड़े हैं। उनका उपयोग क्या है? हम इतने करोड़ों रुपये वहां ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव में भेजते हैं। उसका सैन्ट्रलाइज़ ऑफिस होना चाहिए और सीईओ के माध्यम से सारे गांवों को हैडक्वार्टर्स से कम्प्यूटर्स लेकर जाना चाहिए। यह शिक्षक और बाकी का काम नहीं है। जिला परिषद् का जो पीडब्लूडी विभाग होता है, उसको स्कूल निर्माण का पूरा काम करना चाहिए। उनके माध्यम से स्कूल के जो कमरे होते हैं उनके लिए हम 1 लाख 5 2हजार रुपये तक देते हैं। यह सारा काम इधर के डिपार्टमेंट को करना चाहिए, इसे सरपंच आदि को देना मैं उचित नहीं समझता। मैं एक दिन गांव के रास्ते का उद्घाटन करने गया था तो मैंने देखा कि वहां सीमेंट मिट्टी जैसा निकल रहा है तो मैंने कहा कि मैं इसकी ओपनिंग नहीं करता। वहां देखा गया तो पता चला कि दसवें, 11वें और 12वें वित्त आयोग में जो पैसा आता है, उस पैसे को सब लोग आपस में बांट लेते हैं, इसलिए कोई काम नहीं होता है। इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

महोदय, सिंचाई योजना के लिए भी उसमें एक अच्छा लक्ष्य होना चाहिए। आप जो 12वें वित्त आयोग के पैसे यहां से भेजते हैं, जैसे हमारा एमपी लैड और एमएलए लैड होता है, हमारे जिला परिषद के मेम्बर्स समझते हैं कि जो 12वां वित्त आयोग का पैसा है, अगर हमारे 60 मेम्बर होंगे तो वे सब आपस में बांट लेते हैं। वे कहते हैं कि यह हमारी निधि है। इसे जो वे अपनी निधि मान कर काम करते हैं, यह गलत है।

महोदय, मेरा कहना है कि ऐसे स्थानों पर ज्यादा धन का प्रावधान होना चाहिए, जो साधारण इलाके होंगे, वहां के लिए 12वें वित्त आयोग का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और वहां जनसंख्या के हिसाब से पैसा दिया जाना चाहिए। ऐसा एक नार्म भारत सरकार के वित्त आयोग का आपके डिपार्टमेंट से गया तो ठीक हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लेटर आ गया तभी ये सारे लोग चुप बैठते हैं। सेंट्रल ग्रुप का आपने हमारे यहां भी ओपनिंग किया था, लेकिन उसमें यह हो रहा है कि जो सन् 2000 के पहले के सेल्फ हैल्प ग्रुप्स हैं, उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही, 2000 के बाद वालों को मदद मिल रही है। इसमें भेदभाव मत करिए, यह मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि सेल्फ हैल्प ग्रुप के माध्यम से हमारे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाएं बहुत सशक्त हो रही हैं। उनकी मदद करना, उन्हें पूरी मार्केटिंग दिलवाना बहुत अच्छा काम है।

महोदय, मेरा इसमें कहना है कि जो शौचालय है, आप मेरे यहां खंडाला में आए थे तो आपने देखा था और कहा था कि यहां कितनी गंदगी है। तब मैंने आपसे कहा था कि आप इसके लिए पैसा दीजिए। उस समय आपने कहा कि मैं इसके लिए अपने भाषण में बोलूंगा। मैंने भाषण में बोला और लोक सभा में भी मैंने प्रश्न पूछा। फिर आपने 15 सौ रुपए बीपीएल के नीचे वाले लोगों के लिए दिए।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से यूपीए गवर्नमेंट और मंत्रालय से विनती है कि आप ऐसा मत करिए। ग्रामीण क्षेत्र में कितने घर होते हैं, कहीं पांच सौ, आठ सौ और नौ सौ भी होते हैं, उसमें से बीपीएल के दो सौ होंगे, बाकी के चार सौ लोग रास्ते में बैठे रहते हैं। हमारी माताएं भी रात को बैठी रहती हैं, यह गलत है। आपको मालूम है कि हमारे मराठी में आपने उद्घाटन किया, हगनदारी मुक्त, आपने इसके लिए बहुत प्राइस रखे हैं। गांव-गांव में जाकर हम उनका पूचार भी करते हैं। इसके लिए मैं कहूंगा कि आपने 15 सौ रुपए बीपीएल को दिए तो आप जितने भी वहां गांव में रहने वाले लोग हैं, उन सब को आप दीजिए, ऐसी मेरी आपसे बहुत आग्रहपूर्ण विनती है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से उनका यह सपना पूरा हो सकता है। इंदिरा आवास के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। इस समय सीमेंट और स्टील आदि चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। मैं इंदिरा आवास के बारे में कहूंगा कि 35 हजार रुपए बहुत कम हैं, ये कुछ ज्यादा होने चाहिए। इसमें एक लाख रुपए होने चाहिए, यह मेरी आपसे विनती है। मैं आपको इसके आंकड़े बताऊं तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही कम हैं। पिछले साल 97.71 परसैंट का लक्ष्य पूरा किया, लेकिन अभी तक 58 परसैंट ही पूरा हुआ। इसलिए इसमें जो बेसिक आवश्यकता है, उसे ठीक करना चाहिए। यूपीए गवर्नमेंट ने एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है, हमने उसका स्वागत किया है। रात को देर तक बैठ कर हमने वह बिल भी पास किया।[s38]

सभापति महोदय, मंत्री जी बहुत उत्सुक थे, बाकी यू.पी.ए. गवर्नमेंट के सारे पदाधिकारी उत्सुक [r39]थे और इस संबंध में बिल भी यहां पारित हुआ, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। हो सकता है कि यह बहुत ही कॉम्प्रीहैंसिव योजना है, लेकिन इसमें नीचे के अधिकारी काम ही नहीं कर रहे हैं, कभी बॉयकाट करते हैं और कभी कुछ और करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में यहां से एक लैटर कलैक्टर और सी.ई.ओ. को रेस्पांसीबल बनाने के संबंध में जाए और उसमें स्पष्ट रूप से लिखिए कि यदि आपके यहां रोजगार गारंटी स्कीम का काम ठीक प्रकार से नहीं चला, तो आप रेस्पांसीबल होंगे। हमारे महाराष्ट्र में 365 दिन का काम देने की गारंटी वाला विधेयक बनाया गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 दिन की गारंटी का विधेयक पास किया है, परन्तु 100 दिन का काम भी लोगों को नहीं मिल रहा है। इसका प्रतिशत बहुत कम है। इस बारे में आपको बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए। सिर्फ 9,55,025 परिवारों को ही अभी तक इस योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया गया है, यह अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से कुछ मुद्दे सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक अखबार, दैनिक जागरण में यह आया था कि 'सांसद जी अब सरकार आपसे पूछेगी गांव के विकास का हिसाब-किताब' यह अच्छा विचार है। आप बोलते अच्छा हैं, यह बात भी सही है और इस हेतु आपकी प्रशंसा सारे लोग करते हैं। कुछ योजनाएं केन्द्र सरकार की ऐसी हैं, जिनका उद्घाटन हमें बिना बुलाए कर दिया जाता है, हमें उनके बारे में कैसे पता लगेगा और हम उनके बारे में क्या बताएंगे? अभी हमारे एक मित्र सांसद ने यहां कहा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्घाटन वहां के सांसद, वहां के विधायक की उपस्थिति में ही करना चाहिए और जिला परिषद का अध्यक्ष भी उपस्थित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस योजना के अन्तर्गत कोई भी वहां जाकर उद्घाटन कर लेता है। राज्य सरकार का मंत्री आ जाता है या कोई और आ जाता है और उद्घाटन कर लेता है। हमें कुछ पता नहीं चलता। इसलिए मैं कहूंगा कि सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीमों का उद्घाटन वहां के सांसदों के माध्यम से ही कराया जाना चाहिए। इस बारे में भी आप स्ट्रिक्ट आदेश निकालिए।

महोदय, दूसरी बात मैं भारत निर्माण योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि सारी योजनाओं का उद्घाटन स्थानीय सरकार के लोगों द्वारा किया जा रहा है। मैं बार-बार कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का उद्घाटन सांसदों द्वारा ही किया जाना चाहिए और वहां का विधायक तथा जिला परिषद् का अध्यक्ष उपस्थित रहना चाहिए। डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन भी सांसद को बनाया जाना चाहिए। इस बारे में अनेक बार सदन में अनेक माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है, लेकिन अभी तक इस बारे में नहीं सोचा गया है। वित्त आयोग द्वारा दिए गए धन का डिस्ट्रीब्यूशन भी जिला परिषद् के अध्यक्ष करते हैं, यह गलत है। उसका वितरण वहां के सांसद के माध्यम से ही होना चाहिए। जो नॉर्म्स मैंने बताए हैं, उनके अनुसार उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। शौचालय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत बी.पी.एल. के अलावा भी जो अपर क्लास के लोग हों, उन्हें भी इसकी सुविधा दी जानी चाहिए। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. के लोगों को शौचालय बनाने हेतु 1500 रुपए की सहायता दी है। मैं चाहता हूं कि जो वहां के अपर क्लास के लोग हैं, उन्हें भी यह सहायता दी जानी चाहिए। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आपको एक लाख रुपए की सहायता देनी चाहिए। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलने वाले स्कूलों में इस हेतु बनाई गई कमेटियों को बर्खास्त कर, सेंट्रल कमेटी बनानी चाहिए। सभी बचत घटकों को समान न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय मंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से निश्चित रूप से ग्रामीण विकास हो रहा है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण यह योजना पिछड़ जाएगी। आपका नाम खराब न हो, इसलिए हम हमेशा आपका नाम लेकर काम करते हैं। इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप और सख्त हो जाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन पहले ही करना चाहता हूं कि ज्यादा घंटी बजाएंगे, तो मैं अपना भाषण अभी समाप्त कर देता हूं।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है। आप प्रारम्भ कीजिए और पांच मिनट में खत्म कीजिए। उनके 5 मिनट की बजाय 15 मिनट हो गए। ऐसा अच्छा नहीं लगता। फिर दूसरे लोगों को बोलने के लिए समय नहीं बचेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हम अपना भाषण अपनी ओर से बहुत ही कम समय में समाप्त करेंगे।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, इसी चर्चा में हम भाग भी ले रहे हैं और ये मांगें पास भी होंगी, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। हमें लगता है कि पैसा कम रखा गया है। यदि आप और ज्यादा पैसा रखते, तो सदन को उतना पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सभी लोग इसमें आपका सहयोग करते। जितने भी वक्ता सदन में अभी तक बोले हैं, उन सभी ने व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत किया है। लोगों ने कहा है कि आप जमीनी आदमी हैं और जमीनी हकीकत को जानते हैं। आपके कार्यक्रमों की भी किसी ने शिकायत नहीं की है, लेकिन कार्यक्रमों के रिजल्ट पर किसी ने संतोष भी जाहिर नहीं किया है। हम भी वही करेंगे। कारण यह है कि ग्रामीण विकास, केवल बिहार या उड़ीसा की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश की बात है और मैं पूरे देश की ही बात कहूंगा। [r40]

सभापति जी, ग्रामीण इलाकों और गांवों के विकास की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग का कार्य है। गांव और शहर में समानता, लोन की व्यवस्था और गांव में रोजगार सृजन और गांव की आम सुविधा की चीजें, जैसे बिजली, पानी, सड़क और सिंचाई आदि महत्वपूर्ण विषय हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास तीन महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनमें आवास, पेयजल और सड़क आती है। सभी योजनाओं के लिए राज्यों को पैसा जाता है। यह बात सच है कि काम आप सीधे तौर पर नहीं करवाते हैं, काम कराने की एजेंसी आपने राज्य सरकार को दी है। राज्य सरकार का अगर पूर्ण सहयोग न मिले या राज्य सरकार की एजेंसी सही तरीके से काम न करे, तो आपकी नीति और नीयत पूरी नहीं हो पाएगी, यह बात सत्य है।

दो-चार बिंदुओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे स्वर्ण जयंती रोजगार योजना आप चलाते हैं, यह बहुत ही अच्छी योजना है। एक समूह के आधार पर आप गांव के कमजोर गरीब लोगों की मदद करते हैं, ताकि स्वरोजगार उत्पन्न हो। जैसे-जैसे वह समूह कार्य रूप में बढ़ता है, उसके अनुसार बैंकों से 10, 20, 30 या 40 प्रतिशत पर ऋण की भी सुविधा प्राप्त है। आप सच्चाई को जानते हैं, जो मैं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, लेकिन सदन में चूंकि चर्चा चल रही है, इसलिए आपका ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है। इसमें बैंकों का सहयोग नहीं है। बैंकों का सहयोग मिलता भी है, तो पता नहीं चलता है कि बैंकों पर सरकार का कोई नियंत्रण है भी या नहीं हैं। जो आप कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, निर्देश देते हैं, उनका अनुपालन करने में भारी गड़बड़ी है। हम सदन में नहीं कहते कि पैसा लेने के लिए कुछ प्रतिशत पैसा देना पड़ता है, यह उचित नहीं है। जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि आप जमीनी हकीकत को जानते हैं और मैं भी मानता हूं कि आप हकीकत को जानते होंगे। जब बैंकों का सहयोग नहीं मिलेगा, तो आपकी जो नियत है कि बैंकों के माध्यम से रोजगार दे कर गांवों के लोगों को मजबूत करेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर वे कुछ खास वस्तुओं का उत्पादन कर भी लेते हैं, तो उनके लिए बाजार उपलब्ध नहीं है।

आपने वार्षिक प्रतिवेदन दिया है, उसमें दिल्ली में आपने तीन-चार स्थानों पर बाजारों का जिक्र किया है। आप चिंतन कीजिए कि देहाती इलाके की गरीब महिलाएं क्या दिल्ली के बाजार में सामान ले कर आ सकती हैं? उस प्रदर्शनी से ग्रामीण लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। अगर प्रदर्शनी लगानी है तो प्रचार और प्रसार के माध्यम से कम से कम जिला स्तर पर होनी चाहिए। यह प्रदर्शनी प्रखंड स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रखंड स्तर पर आप नहीं भी आयोजित कर सकते हैं तो कम से कम देश में जिला स्तर पर यह प्रदर्शनी करवा कर बाजार की व्यवस्था कराइए। इससे आपको इस कार्य को करने में सफलता मिल सकेगी। सम्मानजनक स्थिति में जीवन बिताने के लिए आप लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस तरह प्रोत्साहन का क्या लाभ मिलेगा? अभी एक साथी कह रहे थे कि जब आप इनके यहां गए, आपने कहा कि कुछ मांग कीजिए। इन्होंने मांग की और आपने घोषणा भी कर दी तथा बीपीएल के लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था करने के लिए पैसा भी चला गया। इस काम के लिए 1500 रुपया दिया गया, आप ही बताइए कि 1500 रुपए से कौन सा शौचालय बन सकता है। क्या आपको यह व्यावहारिक लगता है? आप यह पैसा शायद इसलिए दे रहे हैं कि दो-चार लोग इस पैसे को आपस में बांट लें। सुलभ शौचालय यदि गांव में एक है, तो आप उसे एक गांव में दो कर दीजिए। एक जगह, दो-चार, महिलाओं और पुरूषों के लिए आप एक ही कैंपस में उसे बना दीजिए। उसमें एपीएल और बीपीएल का क्यों भेदभाव करते हैं? पखाना जाने में भी बीपीएल और एपीएल का आप भेदभाव कर रहे हैं। मंत्री जी, यह कैसा देश है? जिस देश में पखाना जाने के लिए, शरीर की सफाई के लिए आप भेदभाव करते हैं। हमें नहीं लगता है कि यह कोई अच्छा काम हो रहा है। इस तरह से पैसे की सीधी लूट हो रही है। आप व्यावहारिक आदमी भी हैं। बराबर यह मांग होती रहती है, इस पर चर्चा भी होती है, कई माध्यमों से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से आप उत्तर भी देते रहते हैं। हम आज आपसे व्यावहारिक उत्तर की उम्मीद करेंगे, क्योंकि चार साल बीत चुके हैं। हो सकता है कि यह आपका इस दौर का अंतिम उत्तर हो। हम यह नहीं कहते हैं कि इसके बाद आप मंत्री नहीं होंगे, लेकिन इस टर्म का लगता है कि यह अंतिम उत्तर हो। इस अंतिम उत्तर में कम से कम, चार साल तो आप कागज देखकर बोले, जो पदाधिकारियों ने आपको लिखकर दिया, जिसे आप पढ़ते रहे, कम से कम अंतिम समय में व्यावहारिक बिंदु बता दीजिए, ताकि देश की जनता और गांव के लोग व्यावहारिक बात की तरफ देख सकें। हमें लगता है कि आप पन्द्रह सौ रूपए जरूर समाप्त करिए। इसे बढ़ाइए, जिससे लोग इसका उपयोग कर सकें। चूंकि आप चाहते हैं कि उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। वे भी एक स्वच्छ जिंदगी जी सकें, इसके लिए जरूर आप कदम उठायेंगे, ऐसा हमें भरोसा है।

मंत्री जी, पिछले दिनों एक योजना चली थी - श्रम विकास योजना। हर जिले में आप प्रति वर्ष 15 करोड़ रूपए के हिसाब से इसमें देते थे। जिन जिलों में आपने नहीं दिए, खासकर बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने उन जिलों को उतनी ही राशि, जितनी आप केंद्र से दे रहे थे ...(व्यवधान) वह दी गयी थी। जो राज्य से मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसे मुख्यमंत्री विकास योजना नाम से जिलों में भेजा गया। सचमुच योजना बहुत अच्छी थी। नाम बदलने में आप बहुत माहिर आदमी हैं। आप नाम बदलिए, किसी के नाम पर भी रखिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी पिछड़ा जिला के नाम से वही पैसा भेजा। कल जो उस पैसे का उपयोग हो रहा था और आज जो उपयोग हो रहा है, मंत्री जी आप उसे देख लीजिए। दोनों में बड़ा अंतर है। कल भी उसमें कोई एमएलए या एमपी मेंबर नहीं होते थे। उसके उपयोग से आज भी जिन इलाकों में काम हुआ है, वह दिखता है। पिछड़ा जिला के नाम पर आप राशि भेजते हैं। हमें देश भर का तो मालूम नहीं है, देश का आंकड़ा आपको मालूम होगा, लेकिन बिहार में यह तय हो चुका है कि हर पंचायत में जिस तरह से सत्यनारायण का प्रसाद बंटता है, वैसे ही पांच-पांच लाख रूपए बंट रहा है। कौन उसमें विकास का काम कर रहा है? पंचायतों को आप रूपये देते ही हैं। पंचायतों को बहुत सा पैसा जाता है, लेकिन जिस जिले के विकास के लिए आप पैसे दे रहे हैं, पंचायत के हिसाब से पांच-पांच लाख रूपए दे रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि सारे रूपए का दुरूपयोग हो रहा है। जिला स्तर पर जिस प्रकार से श्रम विकास का रूपया जाता था, आपको जिला स्तर पर उसी तरह से रूपया भेजना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उसमें आप एमएलए या एमपी को मेंबर बनाइए। आप जैसे भी करिए, लेकिन जिला प्रशासन के माध्यम से ही दीजिए। जिले में जो इफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो, उसके अनुरूप जिला प्रशासन को आप निर्देश दीजिए कि वह रूपया खर्च करे। सत्यनारायण का प्रसाद मत बंटवाइए। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं।

दूसरी बात हम आपसे इंदिरा आवास के संबंध में कहना चाहते हैं। बिहार में क्या हो रहा है, हमसे कम आप नहीं जानते हैं। आपने गाइडलाइन दिया और गाइडलाइन के आधार पर बैंकों के माध्यम से, सूची प्रखंड से जा रही है, बैंक में खाते खुल रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। जो प्वाइंट आपने बीपीएल का निर्धारित है, वह बहुत बेमुनासिब है। मैं बेमुनासिब इसलिए बोल रहा हूं कि आप बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के लोगों का एक शौक है और जीने का अपना उनका एक तरीका है। जिसके पास दस कठा जमीन है, वह दस कठा जमीन बेचकर दो कमरे का मकान लेता है। उसके दरवाजे पर चापाकल है। शौच के लिए उसने टूटी-फूटी ही सही, एक

लैट्रिन की व्यवस्था कर ली। अब उसके पास कुछ भी जमीन नहीं बची। जो दस कठा जमीन थी, उसे बेचकर उसने यह सब कर लिया। वह किसी के दरवाजे पर परिश्रम करके, मजदूरी करके भोजन करता है। साल में हो सकता है कि महीना या कुछ दिन उसे और उसके परिवार को उपवास रखना पड़ता हो। [p41]

आपने जो गाइडलाइन्स दी हैं, बीपीएल में उसका नाम नहीं आ सकता। घर का नम्बर इतना, चापाकल का नम्बर इतना, लैट्रिन का नम्बर इतना, आप देश में एकरूपता की बात कैसे सोचते हैं जब आप ही इतना भेदभाव बरतेंगे, आपकी गाइडलाइन्स इतना भेदभाव बरतेगी, आप गांवों के लोगों को अपनी गाइडलाइन्स के आधार पर टुकड़े-टुकड़े में बांट रहे हैं तो लोगों के साथ कैसे इंसाफ होगा, कैसे न्याय होगा। हम नहीं कहते कि जो लोग सम्पन्न हों, जिनके पास साधन हों, आप उन्हें उसमें शामिल कीजिए, लेकिन प्वाइंट का जो तरीका है, उसमें जैन्यूइन लोग भी मारे गए हैं। उसमें दूसरी गड़बड़ी भी हुई है। सब प्राइवेट कम्प्यूटर वाले लोगों को ठेका दिया गया था और जो बाजार में घूमने वाली पब्लिक कहलाती है, कम्प्यूटर वालों से मिलकर जैन्यूइन लोगों का नाम निकलवा दिया, जबकि दूसरे लोगों का नाम शामिल कर दिया। क्योंकि उनका सूची में नाम आ गया तो वे उसका लाभ ले रहे हैं। जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

इसलिए इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। आपने कह दिया कि बैंक में खाता खुलेगा। यह कह दिया कि प्वाइंट पर वितरण होगा, लेकिन जब प्रखंड स्तर पर आप इसका आवंटन भेजते हैं तो प्रखंड पंचायत स्तर पर कर देता है। मान लें कि एक पंचायत में यदि एक प्वाइंट पर पचास लोगों का नाम हो और उसमें दस आवास ही देने हों तो दस आवास में से, किसी को तय करना पड़ेगा, उसमें प्वाइंट की कमी-बेशी नहीं होगी, उसी में हेरा-फेरी शुरू हो जाती है। उसमें बिचौलिए इस्तेमाल करते हैं। बैंकों में जब खाता खुलता है,

15.47 hrs.

(Shri Varkala Radhakrishnan *in the Chair*)

वह जिस दिन रुपये निकालता है, उस दिन बिचौलिया वहीं खड़ा रहता है और उनके हाथ से नकद दान वहीं पर ले लेता है। इसे दुरुस्त करने का कानूनी तरीका कोई नहीं है, मैं यह भी कहता हूं। जो देता है, उससे पूछेंगे तो वह स्वीकार भी नहीं करेगा कि हमने पैसा दिया है और लेने वाले को कहने का सवाल ही नहीं है। इस बारे में हमारा एक निवेदन है कि आप इस काम को डिपार्टमैंटली करवाइए। पैसों का दूसरा दुरुपयोग भी होता है। आप जिन्हें पैसा दे रहे हैं, वे महाजन से पैसा कर्ज पर लेते हैं। जब महाजन को मालूम हो जाता है कि उन्हें घर वाला पैसा मिला है तो उनके दरवाजे पर पहुंचने से पहले वह रास्ते में खड़ा रहता है कि माल मिल गया, अब पहले हमें दे दो। जो बचता है, उसे वह ले लेता है। मजदूर क्लास का आदमी है, उसे पहले से आदत है कि वह दिनभर परिश्रम करता है तो शरीर को नियंत्रित करने के लिए जब तक एल्कोहल नहीं लेगा, तब तक दुरुस्त नहीं होगा। जो पैसा बचता है, उसे वह एल्कोहल की दुकान में जाकर दे देता है। आप घर बनाने का तरीका अपना रहे हैं - इस तरह नहीं बनेगा, किसी कीमत पर नहीं बनेगा। यदि आपकी बनाने की नीयत है तो उसका एक रास्ता है कि आप डिपार्टमैंटली बनवाएं। उसमें जिस एजैंसी को लगाएं, उसे हिदायत दीजिए, टाइम बाउंड कर दीजिए कि यदि पैसे लेने के बाद दो महीने, पांच महीने के अंदर घर पूरा नहीं हुआ तो सीधे कार्यवाही कर दीजिए। लेकिन यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो बैंक में देते रह जाएंगे, पैसों का भुगतान कागजों में आ जाएगा, कागज में आ जाएगा कि इतने मकान बन चुके, लेकिन मंत्री जी, व्यावहारिक रूप में आपको भी वहीं चलना है, हमें भी चलना है, लोग बहुत कोसेंगे, आपकी भी दुर्गति होगी, हमारी भी दुर्गति होगी। इसलिए बचाइए। घर बनाने का इंतजाम करवाइए, बिचौलियों को रास्ते से हटाने का इंतजाम करवाइए, इंदिरा आवास में प्वाइंट में सुधार करवाइए, यही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं।

भारत निर्माण और प्रधान मंत्री सड़क योजना की चर्चा चल रही थी। कोई नहीं कह सकता कि यह गलत कदम है। गांवों के उत्थान में सड़क निर्माण सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हम देश के बारे में नहीं जानते लेकिन बिहार में प्रधान मंत्री सड़क की एजेंसी राज्य सरकार को नहीं दी गई बल्कि केन्द्र सरकार अपनी एजेंसी से काम करवाती है। हमें लगता है कि जिस तरह से काम चल रहा है, उससे बिहार के विकास में बाधा हो रही है। हम उदाहरण के तौर पर कहना चाहते हैं। एक पथ - मांझी से बड़ौली है जो तीन जिलों को जोड़ता है - छपरा, सीवान और गोपालगंज।[N42]

एक बार मैंने अपना आधा हिस्सा प्रधान मंत्री सड़क में ले लिया जो कि छपरा जिले का हिस्सा था। जब दूसरा हिस्सा आपने नहीं दिया तो राज्य सरकार ने उसके निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपये आवंटित किये। तभी केन्द्र सरकार की एजेंसी इरकॉन ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी कि हम इसका डीपीआर बना रहे हैं, इसलिए आप इस पर काम मत कराइये। राज्य सरकार ने अपना पैसा वापस ले लिया। मंत्री जी, डेढ़ साल हो गये, अभी तक उस डीपीआर का काम पूरा नहीं हुआ। उस रोड की स्थिति बिल्कुल गड्ढ़े जैसी है। आप सोचिए कि जिस पथ के लिए पैसे का आवंटन हो गया हो और वहां के आम लोग जान गये हों, कि हमारे पथ के निर्माण के लिए पैसा केन्द्रीय एजेंसी की वजह से वापस हो चुका है, तो आप बताइये कि वहां के लोगों के मन में क्या होगा? इसलिए हम कहते हैं कि बिहार के विकास में बहुत बाधा पहुंच रही है। इतना ही नहीं, वहां डीपीआर बनाने में होड़ लगी हुई है। केन्द्र की एजेंसी गांव की सड़कों को नापकर नाम नोट करके आयी है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की एजेंसी भी अलग से नाम नोट करके ले आयी है। हमको लगता है कि एक ही रोड की दोनों डीपीआर बना रहे हैं। सिर्फ उसका डीपीआर ही बन रहा है, काम शुरू नहीं हो रहा है। बिहार के इस पथ निर्माण के काम में भारी बाधा पहुंच रही है। वहां जो भी काम हो रहा है, वह महा घटिया स्तर का है। इसे हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। आपके विभाग की एक रिपोर्ट है। पेटीशन कमेटी में एक पेटीशन आयी थी जिसके तहत पेटीशन कमेटी ने आपके विभाग से कुछ प्रतिवेदन मांगा था। बनियापुर प्रखंड के प्रमोद कुमार सिंह ने वह पेटीशन दी थी। हम रिपोर्ट का मुख्य अंश हम आपको बता देना चाहते हैं। बिहार के सारंग जिले के पीएमजीएसवाई चरण-III तथा बाद की परियोजनाएं कार्यान्वित करने वाली एजेंसी मैसर्स इरकॉन इंटरनैशनल लिमिटेड ने सूचित किया है कि सड़क कार्य जून 2007 में पूरा कर लिया गया है। यह उसकी सूचना है । जब जांच हुई, तो स्वतंत्र गुणवत्ता सहायक के जरिये करवाई गई प्रारंभिक जांच से पता चला कि पूरी सड़क पर असफलता के चिह्न दिखाई दे रहे हैं। पूरी सड़क पर दरारों तथा पैचमेंट के खराब होने इत्यादि के रूप में असफलता लक्षित हो रही है। जब उन्होंने जांच की, तो प्रतिशत में क्या लिखा? बिहार के सारंग जिले में 1.4. 2002 से 31,8.2007 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी कर्ताओं द्वारा कराये गये निरीक्षण का ब्यौरा तथा गुणवत्ता ग्रेडिंग निम्नानुसार है। इसमें उन्होंने लिखा है कि कुल निरीक्षण 53 बार किया गया। इन 53 बार में से 20 सड़कों के निर्माण में उन्होंने तीन सड़कों का काम संतोषजनक बताया और 17 सड़कों का काम असंतोषजनक बताया। उन्होंने 85 प्रतिशत असंतोषजनक काम कहा है। जिस पथ पर 85 प्रतिशत असंतोषजनक काम है और 15 परसेंट संतोषजनक काम है, तो मंत्री जी आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि केन्द्रीय एजेंसी का काम कितना अच्छा और कितना घटिया हो रहा है। उसके बाद के चरण का उन्होंने बताया है कि 62 प्रतिशत घटिया किस्म का काम हो रहा है। ...(व्यवधान) आप एक-दो मिनट रुकिये।

...(व्यवधान) *

MR. CHAIRMAN : The time allotted to you is over long ago.

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। हम यह बता रहे थे कि माननीय मंत्री जी केन्द्रीय एजेंसी का जो काम हो रहा है खासकर इरकान का काम हो रहा है, तो वह एजेंसी पर एजेंसी हो रहा है।

* Not recorded.

इरकान एक एजेंसी है, जब वह निविदा निकालती है, तो किसी ठेकेदार को काम देती है। वह ठेकेदार खुद काम नहीं करता है, वह पैटी कांट्रेक्ट में किसी को देता है यानी कांट्रेक्ट पर कांट्रेक्ट होता है। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए । एक रोड मेरी कांस्टीट्सीं का है। इस रोड के बारे में हम आपको पढकर सुना देते हैं। एकमा से मसरक जिसकी लम्बाई लगभग 31.55 किलोमीटर है। इसमें इन्होंने लिखा है कि समय, बारिश, मजदूरों तथा सामग्री की कमी, एग्रीमैंट, पंचायत चुनाव, भीषण बाढ़, अब उस इलाके में बाढ़ ही नहीं आई थी, लेकिन लिखते हैं कि बाढ़ की वजह से काम नहीं हो रहा। सन् 2005 से काम हो रहा है। लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। मंत्री जी बिहार आपका भी है। राज्य में सरकार आती जाती रहती है। कल आपकी सरकार थी, तो आज दूसरी पार्टी की सरकार है। फिर परिस्थिति के अनुसार होना है। [MSOffice43]

अगर आप इन चीजों को गंभीरता से नहीं देखेंगे तो बिहार के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। माननीय सदस्य श्री राम कृपाल यादव जी यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा है। यहां तक मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन उन्होंने इसका दूसरा हिस्सा नहीं बताया। उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि बिहार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने बहुत मजबूती से कदम उठाए हैं, जिनमें 175 लोग रंगे हाथों पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है और उनको जेल में बंद किया गया है। डीजीपी स्तर के और आईएएस स्तर तक के लोगों को पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और गिरफ्तार किया गया है। यह बात ठीक है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन उस पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही भी हो रही है। उन्होंने कहा कि वह साफ बोलते हैं, अगर साफ बोलते हैं तो उनको इसे सुनना भी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राम कृपाल यादव जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि राज्य सरकार के काम में जहां दिक्कत होती है, बराबर उन चीजों पर हम जनता के हित में विरोध करते रहते हैं और जिस दिन आवश्यकता आएगी जुबान खोलने के लिए, तो राम कृपाल यादव जी, हम किसी की मजदूरी नहीं करते हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं और बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से हम जनता की भावनाओं को, चाहे वह आपकी सरकार हो या बिहार सरकार हो, अगर खामियां महसूस करेंगे तो उसे जरूर उजागर करेंगे।

एक और बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। रोजगार गारंटी योजना एक खत्म हो चुकी योजना है। मंत्री जी, जिस दिन आप इस बिल को लाए थे, उस दिन भी मैंने इसका विरोध किया था और आज भी कह रहा हूं कि आप इस बोगस योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार कैसे देंगे। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में देख रहा हूं कि कभी जिन मार्गों पर एमपी ने एमपी फण्ड से पैसा देकर मिट्टी का काम लिखा था, उसी के लिए एमएलए ने छः महीने बाद पैसे दिए हैं, जिला परिषद वाला भी जल्दी-जल्दी उसी पर मिट्टी भरवा रहा है, पंचायत समिति वाला उसी पर मिट्टी भरवा रहा है और मुखिया भी उसी पर मिट्टी डलवा रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या इस तरह से लोगों को रोजगार मिल सकेगा? आप कह रहे हैं कि जिसका जॉब कार्ड हो अगर वह पंचायत में दरख्वास्त देगा तो उसे 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे पैसा दिया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या इस बात का कोई रिकॉर्ड है कि कितनी ऐसी दरख्वास्त आपके आई हैं? क्या मजदूर मुखिया से मजबूत पड़ेगा? मजदूर मुखिया के पास जाकर कुछ इधर-उधर करेगा तो मुखिया उसको ठीक भी कर देगा। क्या पंचायत में आपने उसकी दरख्वास्त को रिसीव करने के लिए कोई व्यवस्था की है? जहां लोग देखते हैं कि योजना में कुछ इधर-उधर करने की गुंजाइश है, वे लोग मिलकर पास कराते हैं। आपने पैसे के भुगतान के लिए यहां से बहुत ताकीद किया है और राज्य सरकार ने भी खाते खुलवा दिए हैं, उसका भुगतान बिना काम कराए, 50-50 प्रतिशत पर हो जाता है। वे लोग आपस में तय कर लेते हैं कि बिना काम किए 50 प्रतिशत पैसा आप ले लीजिए और बाकी 50 प्रतिशत हमारे लिए छोड़ दो। यह पैसे की लूट हो रही है, इससे रोजगार नहीं मिलेगा। इसका कोई और तरीका निकालिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. You have taken nearly half an hour. I cannot allow it.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : So far, you have taken 40 minutes. Even the Minister is not permitted to continue his speech beyond that.

श्री प्रभुनाथ सिंह : मंत्री जी, बिहार में खांड़-बांध की सफाई का काम चल रहा है। बिहार की बहुत जमीन जल जमाव से बर्बाद होती है। जल जमाव वाले इलाकों में पानी की निकासी के लिए जितना मिट्टी का काम होना है, उतने मिट्टी के काम के लिए और बाकी पैसे से पक्के नाले के निर्माण की अनुमति होनी चाहिए। अभी यह प्रॉविजन है कि मिट्टी का काम 60 प्रतिशत और पक्का काम 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए उनको इसके बारे में छूट मिलनी चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो मिट्टी का काम हो जाए और बाकी पैसे से पक्का निर्माण पानी की निकासी के लिए हो जाए। अगर जल जमाव की समस्या का समाधान हो जाए तो वहां की हजारों एकड़ भूमि कृषि योग्य बन जाएगी जिससे वहां प्रतिवर्ष पैदावार बढ़ जाएगी।

मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE) : I must, in the very beginning, thank you very much for calling me to participate on the disucssion on the Demands for Grants for the Ministry of Rural Development. I must thank the Minister and, in fact, I am an admirer of the Minister. He is very active, very sincere and very dynamic. In fact, this Department has been playing a great role all over the country. Besides, the Ministry of Rural Development, there are other Ministries also for the

development work in rural sector, particularly, the Department of Social Justice and Empowerment, the Human Resource Department, the Health and Family Welfare Department and so on and so forth. But, this Department has a greater role to play in the development of the social sector as compared to the other Departments. The schemes being implemented by this Department have their tremendous impact on the social sector by providing drinking water, housing, employment, poverty alleviation, and increase in capacity building and improving rural infrastructure, sanitation, encouraging group activities – all these things are there. My first point is that the development should be proportionate with tax revenue collection. I am talking about the proportion to the tax revenue collection. The tax revenue collection, the growth of tax revenue collection is there. But, the development in the rural sector should be proportionate to that so that maximum benefit should go to the poor people, to the poorest of the poor and the farmers, to the agriculturists, labourers and so on. I am talking first about the BPL families. Many things have been said here by hon. Members, my predecessors. It is not quite understandable how the Government or the Planning Commission can set a limit on the number of the BPL households in the rural areas. It is not understood if BPL is staying in the village or BPL is staying in the Planning Commission. How is the Planning Commission limiting this BPL figure? The Minister should answer it and we should take concrete steps so that all the resources from below should come. Sometimes, it is said they add all the information, but source of information is not coming properly. So the exact number of BPL cannot be assessed. So, if there is something wrong in the information collection, if something is wrong in the collection from the sources, then of course, the BPL houses will be left out. These should be collected properly. Not only that, the criteria of fixing the BPL category should also be reviewed. In USA, it is said that at least one dollar per day should be the minimum number and so that is the line of the BPL category. I am referring to the Commission headed by Shri Arjun Sengupta. He remarks in his Report that about 63 crores of population of our country is living at Rs.8 to Rs.20 per day. It is assumed that more than 70 per cent of our population is living below the poverty line. [MSOffice44]

So, this should be reviewed and the assessment procedure should be changed.

I, now, come to the National Rural Employment Guarantee Programme. It has been already mentioned by my predecessors that the hon. Finance Minister has made the announcement that the number of districts which are covered under this programme has been more than doubled now, but the increase in budget allocation is only 33 per cent. Why has it not been increased by 100 per cent? So, I demand that it should be enhanced by 100 per cent.

My next point about the NREGP is regarding the productivity norm in respect of work to be done by a labourer in a day. I had a talk with the hon. Minister and I also wrote a letter to him about this stipulation. I am particularly referring to the stipulation about the earth work. It is so harsh that no village worker can meet that norm in a day. The earth work of 100 cubic metres in a day cannot be met by any labourer. So, this norm should be changed. When fixing the stipulation, panchayats, their representatives and local people should be consulted. Not only that, the norm could vary from one district to another district and from one State to another State. So, there should not be a uniform stipulation for the entire country.

I, now, come to the minimum wage. There is no uniform national minimum wage in our country. The Minimum Wages Act of 1948 is still existing. A new Act should be enacted for the minimum wage because the minimum wage differs from State to State. So far as my State West Bengal is concerned, more than 70 per cent villages are irrigated and in the irrigated areas, there is no mono crop, there are multi crops and there are high yielding varieties. The farm worker in our State earns Rs. 100 per day. If an agricultural worker earns Rs. 100 per day in agricultural work or horticultural work, how will he be interested to work in the NREGP? So, I think the time has come for bringing a new legislation in respect of minimum wage.

Now I turn my attention to some other points regarding the NREGP. It has been correctly mentioned by some hon. Members here that the workers participating in this programme should be paid in kind. Earlier, the Food-for-Work Programme was there. Under that programme, some vegetables used to be given to the workers. Now, there is huge production of potato in our country and potato prices are gradually falling. The potato growers are not even getting the cost of production. So, why should potato not be given to the workers participating in the NREGP so that they can get potato and other vegetables directly?

I would like to say a few words about the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Many hon. Members have talked about the poor maintenance of PMGSY roads. There is a guarantee of five years for roads constructed under PMGSY, but the roads are damaged before five years.[R45]

[r46]What would happen to the flood prone areas? Who would guarantee that after five years, there would be no floods and the roads would be all right? Who will take the responsibility of maintenance of PMGSY? Most of the States are not in such a position financially to take the responsibility. So, the Union Government, this Ministry, should take the responsibility and a ratio should be developed. The hon. Minister should think over the maintenance aspect also.

I would like to submit that no compensation is being given to the poor farmers whose land has been acquired for widening the roads. We take their land for widening the roads, but no compensation is being provided to the poor farmers. Land acquisition problem is there all over the country. The peasants are agitating; the public at large is agitating as far as land acquisition is concerned. But so far as the PMGSY is concerned, land acquisition is taking place, but no compensation is provided to the people. I would request the hon. Minister to think over it.

Coming to the SGRY, the banks are coming in the way of its implementation. In most of the Gram Panchayat areas, there are no commercial banks. There should be a mandatory provision to open the commercial banks at the headquarters of the Gram Panchayat and the process of giving the credit should be very easy so that it helps the poor farmers.

As far as Indira Awas Yojana is concerned, it is a good programme, but cost escalation, that is the rate of inflation, should be taken into account. Day by day, inflation is going on and on. If you do not provide more money for the construction of houses under Indira Awas Yojana, how will this small or meagre amount be sufficient for construction of houses?

I would also like to know what has happened to the land reforms. It has already been mentioned in the Common Minimum Programme. But this UPA Government's time is running out fast, the time is going to be over. When will they respond to that? So, my request to the hon. Minister is to call a meeting, of all the Ministers of the State of the concerned Department, at the national level. Land is a scarce subject. So, this matter should be taken centrally as it is mentioned in the Common Minimum Programme.

What has happened to the land acquisition and rehabilitation matters? Some Bill has been introduced in the Parliament, but there has been no discussion on that. Even in this Budget Session, this point is not coming up for discussion. Lakhs and lakhs of farmers are agitating across the country. We should not be indifferent to that. So, we should bring forward a comprehensive legislation repealing the old one, which belongs to the colonial rule. It was enacted in the colonial time in 1894. So, they should repeal it and should bring forward a new comprehensive legislation as far as rehabilitation policy is concerned. Sir, much has been said in the Press and in the media, but nothing is being discussed on these matters in this Parliament.

Sir, the IWDP is a good programme. The Waste Land Development Programme is taking up good things, particularly, in the North-Eastern areas.

In conclusion, I would reiterate the historic remarks made by Bapu Ji. He said, "India lives in vill[r47]ages".

But in villages, disparity is happening and it is widening. If you do not address properly to the problems of the rural areas and to the problems of the rural habitants, then the problems will not be solved.

With these few words, I would once again thank the hon. Minister and support the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development.

MR. CHAIRMAN : Now, I have a list of 40 hon. Members. I can give five minutes' time each, and even then it will take three hours. I am prepared to five minutes' time to all. Being the matter concerning rural development and rural issues, it is quite welcome to cover as many as Members as possible. So, following that principle, in three hours' time, 40 Members can be allowed. So, I would request you all to co-operate with the Chair. Please do not think that I am unkind but this is the position.

Shri Subash Maharia.

श्री सुभाष महरिया (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। 60 साल की आजादी के बाद 70 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रामीण अंचलों में रहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भारतवर्ष है क्योंकि 70 करोड़ लोग 34 लाख नुमाइंदों को चुनते हैं, जो 487 जिला परिषदों, करीब 6000 पंचायत समितियों, दो लाख 32 हजार ग्राम पंचायतों के जरिए गांवों के विकास का काम करते हैं। ग्रामीण विकास के अंतर्गत बिजली, पानी सड़क आदि जितने भी कार्य शुरू हुए, उसे लेकर आजादी के बाद सब के मन में एक बात थी, एक सपना था कि वे समान रूप से विकास में दौड़ पाएंगे लेकिन हमने 60 साल के बाद भी देखा कि 70 करोड़ लोगों में 22 फीसदी लोग आज भी ऐसे हैं जिन के हिस्से 12 रुपए प्रतिदिन आते हैं। ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने की शुरुआत 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत की। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि उस योजना की शुरुआत से लेकर आज तक देश के करीब साढ़े छः लाख राजस्व ग्रामों मे से बहुत बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव जोड़े जा चुके हैं। आपके मंत्रालय संभालने के बाद उसमें और गति आई है। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि आपने ग्रास रूट पर इस यूपीए को भी चलाया है। आपका जिस तरह काम करने का निराला तरीका है जिस की शुरुआत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की उसमें आपने और धनराशि देने में कभी हिचकिचाहट नहीं की क्योंकि वह एक ऐतिहासिक शुरुआत थी लेकिन मुझे आपके ध्यान में 2-3 बातें

लानी हैं।

2001 के राजस्व ग्रामों के बाद जितने राजस्व ग्राम बने हैं, जिन की संख्या हजारों में है, वे 28 प्रदेशों में हैं, उनकी आबादी चाहे हजार हो या 1500 हो, दो हजार हो या पांच सौ हो, आप उनको सड़कों से जोड़ने की जो अनुशंसाएं राज्य सरकारों से मंगवाते हैं, उसके लिए बनी गाइडलाइन में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है जबकि हमने इसके बारे में आपसे आग्रह भी किया था कि सन् 2001 के बाद जिन गावों को राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका है, राज्य सरकारों से उनके प्रस्ताव भी जिला परिषद के जरिए, पंचायत समितियों के जरिए, राज्य सरकारों के जरिए मंगाएं और उनको सड़कों की लिस्ट में शामिल करने के लिए आदेश दें। उन गांवों तथा दूसरे गांवों के बीच आज बहुत बड़ी खाई बन चुकी है।

एक तरफ शहर और गांव की खाई की बात करते हैं। लेकिन यह एक ज्वलंत समस्या है, मैं मानकर चलता हूं कि 2001 के बाद जो राजस्व ग्राम घोषित हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया जाए। यह बहुत अहम बात है और इस बार में पूरे सदन की तरफ से हमेशा कहा जाता रहा है कि 2001 के बाद के गांवों को शामिल कीजिए।

मैं सड़कों के संबंध में माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में प्रति किलोमीटरवार जो सड़कें बनी हैं, उसमें कुछ राज्यों ने बहुत अव्वल काम किया है। इस काम में राजस्थान पहले नंबर पर रहा है। आपने स्वयं राजस्थान जाकर इस बात की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर का है और जनसंख्या साढ़े छः करोड़ है लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें जो मिलना चाहिए उसका 40 परसेंट ही मिल पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बड़े क्षेत्रफल के लिहाज से राज्यों को आबंटन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात के बीच में निश्चित रूप से सामंजस्य होना चाहिए। इसके साथ ही इस समय गांवों में भारत निर्माण के तहत बिजली की जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे एफआरईपी की योजना के तहत धाणी के लोगों को, छोटी हैबीटेशन के लोगों को पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है। टाणी में बहुत गरीब लोग रहते हैं, दूर-दराज इलाकों में रहते हैं लेकिन डिमांड नोटिस ऐसे हैं कि वे पूरा नहीं कर सकते हैं अगर पूरा नहीं करते हैं तो बिजली नहीं दे पाते हैं। एक ओर सरकार का दावा है कि चौदह लाख हैबिटेशन्स में सबको बिजली मुहैया कराकर छोड़ेंगे लेकिन इनमें से आज भी छः लाख हैबीटेशन्स ऐसी हैं जिन्होंने जिंदगी में बिजली नहीं देखी है। मैं आपसे पानी के बारे में आग्रह करना चाहता हूं। आज की स्थिति यह है कि हमारे देश में सात लाख गांवों में से करीब पांच या साढ़े पांच लाख बसावटें ऐसी हैं जो अशुद्ध पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वे दूर दराज से पानी लेकर आएं भी तो कहां से लेकर आएं? इसलिए मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं, रीजनल स्कीम्स पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जब तक इन पर जोर नहीं दिया जाएगा तक तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। जहां हैंडपंप की जरूरत है वहां हैंडपंप लगने चाहिए और जहां ट्यूबवैल की जरूरत है वहां ट्यूबवैल लगने चाहिए क्योंकि जमीनी सतह का पानी दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है इसलिए रीजनल स्कीम पर जोर देना चाहिए। वहां मीठा पानी दूर-दराज जाकर मिलता है इसलिए रीजनल स्कीम्स के माध्यम से मीठे पानी को वितरित करना चाहिए और इसका खर्च भी कम पड़ेगा।

महोदय, मॉनिटरिंग के अभाव में आप राज्य सरकार को कई बार छूट दे देते हैं और बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां मॉनिटरिंग हो पाती है। मॉनिटरिंग का जबर्दस्त अभाव है, सैंट्रल लैवल पर मंत्रालय की ओर से मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की विशेष आवश्यकता है, टीम को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि सही तस्वीर सामने आ सके। यहां से जो पैसा जाता है उस पैसे का सदुपयोग तभी हो सकता है जब मॉनिटरिंग बराबर हो। रोजगार गारंटी योजना के बारे में बात चल रही थी, मेरे से पूर्व प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा और मैं उसी बात को बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी योजना के तहत पक्के कामों की बहुत आवश्यकता है। पक्के कामों के लिए अलग से आबंटन होना चाहिए, चाहे इसके लिए अलग से राज्य सरकारों से बात करनी पड़े तो वह भी करें। जब तक पक्के कामों को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक रोजगार गारंटी योजना सफल नहीं हो सकती है। इस प्रकार के कामों में मिट्टी इधर से उधर डालकर पैसे के दुरुपयोग को रोकना चाहिए। हमें पुराने कामों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद् पर निश्चित रूप से मॉनिटरिंग करनी चाहिए।[r48] अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो रोजगार गांरटी योजना देश की सबसे बड़ी फेल्योर योजना साबित होगी। बी.पी.एल. परिवार और उनकी पहचान के लिए जो बातें सामने आई हैं, उन मामलों में हमें आगे बढ़कर...(व्यवधान) महोदय, मैंने अभी बोलना ही शुरू किया है। मैं गांव से आता हूं, इसलिए गांव की बात मैं बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : This is the list submitted by your Party.

श्री सुभाष महरिया : मेरे साथी अपना भाषण लिखित में दे रहे हैं। यह अपना टाइम दे रहे हैं।

MR. CHAIRMAN : If the other Members agree that you alone will be speaking, it is all right. Please conclude.

श्री सुभाष महरिया : इसलिए आज गांव के जो लोग आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हैं, उन्हें काम मिलना चाहिए जब तक उन्हें काम नहीं मिलेगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: There are so many Members from your Party. If they agree that you alone will be speaking, then it is all right. Please conclude.

श्री सुभाष महरिया : तब तो जो जीवन की आर्थिक दौड़ है, उसमें भी हम नहीं दौड़ सकते। इसलिए आवास और विद्युत के लिए जिस प्रकार की योजनाओं का जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Jai Prakash. You arrange your speech in five minutes. On no condition, further time will be given.

श्री सुभाष महरिया : उन योजनाओं को भी हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, इस डिपार्टमैन्ट के साथ 70 करोड़ लोग जुड़े हैं, लेकिन हमारा आवंटन बहुत कम है। इसलिए मैं सभापति महोदय के जरिये निवेदन करूंगा कि जो आवंटन किया गया है, उसके मुकाबले चार गुना आवंटन होना चाहिए। जब तक गांवों का व्यक्ति मजबूत नहीं होगा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक यह देश सुदृढ़ नहीं हो सकता और आप जैसे माननीय मंत्री जी से हम यह उम्मीद करते हैं कि गांव के व्यक्ति के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमें अधिक धनराशि मुहैया कराई जाए, ताकि इस देश के आर्थिक विकास में गांव के लोगों की पूर्ण भागीदारी हो। मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत से बड़ा कोई एनजीओ नहीं है। दो लाख बत्तीस हजार जो हमारी

ग्राम पंचायतें हैं, उनसे बड़ा कोई एनजीओ नहीं है। वे जवाबदार हैं, उनकी जवाबदेही बनती है। राज्य सरकार की डोर उनके ऊपर रहती है, भारत सरकार की डोर उनके ऊपर रहती है। जो एनजीओज कुकुरमुत्तों की तरह घूम रहे हैं, जिन्हें एनजीओ कहते हैं, इन एनजीओज का काम बंद कर दीजिए। जब तक मंत्रालय में एनजीओज. घूमते रहेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर सबसे बड़ा कोई एनजीओ है तो वह इस देश में हमारे देश की जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Shri Jai Prakash – please conclude within five minutes. I am telling this in your interest.

SHRI JAI PRAKASH (HISSAR): I am the second speaker from my Party. महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, you arrange your speech by taking the important points.

श्री जय प्रकाश : इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष गांवों में बसता है और भारतवर्ष की 70 फीसदी जनसंख्या गांवों में निवास करती है, चाहे वे किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, दस्तकार हैं या कर्मचारी हैं। लेकिन आज बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ता है कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा कुछ ऐसी अनियमितताएं बरती गई, जिनके राज में गांवों का विकास नहीं हुआ और गांवों का विकास न होने की वजह से गांवों के गरीब लोग, जिन्हें प्रतिदिन की मजदूरी नहीं मिलती थी, उनके राज में खेती घाटे का सौदा थी, इसलिए वे खेतिहर मजदूर गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर गये। उससे यह नुकसान हुआ कि शहरों की जनसंख्या बढ़ गई और शहरों में सीवरेज, वाटर सप्लाई, इलैक्ट्रिसिटी आदि की समस्या हो गई और उसके साथ ही शहरी जमीनों के भाव भी ज्यादा बढ़ गये और गांवों की जनसंख्या घट गई। इसका आभास इस बात से होता है कि हर दो-तीन वर्ष के बाद जब वोटर लिस्ट बनती हैं तो गांवों के मतदाता सूची में घट रहे हैं और शहरों में जनसंख्या या शहरों के मतदाता बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने और यूपीए की चेयरपर्सन, श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गनिर्देशन पर प्रधान मंत्री जी और हमारे मंत्री जी ने जो फैसले लिये हैं, वे बहुत ही सराहनीय हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था 'ग्रामीण स्वराज तब आयेगा - जब तक भारतवर्ष में गांवों का विकास नहीं होगा, किसानी का विकास नहीं होगा, तब तक भारतवर्ष तरक्की नहीं कर सकता' यह बात आपको भी माननी पड़ेगी। इसलिए मेरे पांच-सात सुझाव हैं। जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हमारे गरीब व्यक्तियों को, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं थे, प्लाट नहीं थे, उन्हें सौ-सौ गज के प्लाट दिये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह योजना पूरे भारतवर्ष में लागू की जाए, ताकि जिन गरीब लोगों के पास अपने घर की जमीन नहीं है, खेती की जमीन है, पंचायतों से लेकर उन्हें प्लाट दिये जाएं और जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने गरीब व्यक्तियों को प्लाट देने की प्रक्रिया शुरू की है, उसमें पैसा बहुत खर्च होगा[b49]।

[r50]

मैं ग्रामीण रोजगार मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें केन्द्र सरकार से हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से आपने दो वर्ष पहले 250 करोड़ रुपये दिये थे, उसी तरीके से कुछ पैसा हरियाणा प्रदेश की सरकार को पुन: दिया जाए।

बीपीएल की चर्चा बहुत चलती है। हरियाणा प्रदेश में भी बीपीएल की गाइडलाइन को पूरा माना जाए तो मैं समझता हूं कि एक भी गरीब आदमी बीपीएल में नहीं आ सकता क्योंकि हमारा कोई गरीब हरिजन भाई ऐसा नहीं है जिसके पास पक्का मकान नहीं है, घर में बिजली नहीं है, टी.वी. नहीं है। या तो ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि गरीब गरीब होता जाए वर्ना यह कोई सिस्टम नहीं है कि पूरे देश की बीपीएल गाइडलाइन एक बना दी गई है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि बीपीएल की गाइडलाइन पूरे हरियाणा प्रदेश और पंजाब जैसे प्रदेशों में जहां पर मजदूर वर्ग खुशहाल है, वहां की अलग बना दी जाए वर्ना एनडीए सरकार ने तो इस देश के साथ बड़ा जुल्म किया था वर्ना बीपीएल की जरुरत क्या थी? मैं कहता हूं कि सरकारी राशन की दुकान से हर व्यक्ति जिसके पास भी राशन कार्ड है, सबको गल्ला खरीदने की इजाजत 1998 से पहले थी तो उसी व्यवस्था को लागू कर दिया जाए।

अब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लीजिए, जिसकी शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहस में हिस्सा लेते हुए सबसे पहले की थी। आज हमारे कुछ भाई कहते हैं कि उसका देश को लाभ नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यूपीए सरकार ने लागू करके उन प्रदेशों की सरकारों को जो पूर्ववर्ती देश की सरकारें रही हैं, उनको कम से कम इस बात का आभास कराने की चेष्टा की है कि गरीब व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष में, 365 दिनों में से 100 दिन रोजगार तो मिले। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य में यदि आप सौ दिन रोजगार मुहैया कराएंगे और उसके बाद धान या गेहूं के सीजन में उस मजबूर व्यक्ति को किसान के क्षेत्र में मजदूरी मिलेगी और आप इसे इंदिरा आवास योजना से एक सस्ता मकान देंगे तो शहरों की तरफ पड़ने वाला दबाव कम हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इंदिरा आवास योजना में मंत्री जी 35000 की बजाए कम से कम 50000 रुपया दिया जाए।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पैसा खूब दिया गया है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन प्रदेशों की सरकारों ने पैसा ठीक से खर्च नहीं किया और जो प्रदेश सरकार पैसा ज्यादा खर्च करती है, यदि वह उसका दुरुपयोग करती है तो वे पैसे हरियाणा सरकार को दिलाए जाएं।

जलापूर्ति योजना के अंदर मेरा निवेदन है,...(व्यवधान) सर, यह आपके काम की बात है। जब आप अपने क्षेत्र में इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे तो जो हैंड पंप लगा देंगे तो आपको भी वोट ज्यादा मिल जाएंगे। इसमें मेरा निवेदन है कि जैसे हर घर में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 100 लीटर की पानी की टंकी गरीब हरिजनों के लिए खरीदी है, उसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि हर सांसद को एक विधान सभा के अंदर 1000 हैंड-पंप की इजाजत दी जाए क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हम पाइप लाइन नहीं बिछा सकते और यदि एक-एक सांसद को यदि इसकी इजाजत दे दी जाए तो हमारा उससे काम चल जाएगा।

इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह योजना अच्छी है क्योंकि गांवों में जो जच्चा और बच्चा है, उनके लिए कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। हमसे पहले हमारे एक साथ राजवीर जो 6 वर्ष तक रहे हैं, क्या उन्होंने कभी गांवों की सुध ली कि गांवों में जो औरत बच्चा पैदा करती है, वह औरत दवाई के अभाव में या सैप्टिक या किसी और वजह से मर जाती थी, लेकिन आज हमारी सरकार ने इस योजना को लागू किया है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

श्री जय प्रकाश: महोदय, मेरा कहना है कि हर गांव में मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया जाए। सर्व शिक्षा अभियान में मिड-डे-मील को सरकारी स्कूलों में ऐसा बना दिया कि कमरे तीन हैं। एक में लक्कड़ डाल दिया, बच्चे सारे दिन वहां भोजन बनाते हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि इस भोजन पकाने की व्यवस्था के अंदर एक ऐसा दूसरा सिस्टम बनाया जाए ताकि बच्चों को समय पर भोजन मिले।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing more will go on record except the speech of Shri Ponnuswamy.

*(Interruptions) â€¦ **

* Not recorded.

***श्री संजय धोत्रे (अकोला) :** महोदय, डिमांड्स फार ग्रांटस - ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो चालू सत्र में चर्चा हो रही है उसमें मैं भाग लेना चाहता हूं। मुझे इजाजत देने के लिए आपका धन्यवाद ।

वाटर शेड डेवलपमेंट का अनन्य साधारण महत्व है। पर्यावरण पेयजल सिंचाई और अनाज की समस्या इसका यह महत्वपूर्ण विकल्प है। इसके लिये सरकार के विविध विभाग के एनजीओ काम कर रहे हैं1 बहुत सारी राशि भी खर्च हुई, लेकिन सही ढंग से काम न होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इसके लिये प्रॉपर इंटीग्रेटिड प्लानिंग इम्पलीमेंटेशन और मॉनिटरिंग होना चाहिए। देश के बहुत सारे हिस्सों में खेत में जाने के लिए रास्ते नहीं हैं और जिला स्तर पर इस काम को मंजूर करने में दिक्कते आती हैं। मंजूरी के बाद काम पूरा नहीं होता और यदि काम हो जाये तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। कई रस्ते साल भर में खराब हो जाते हैं, पानी से बह जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत अच्छे क्वालिटी के रस्ते तय समय सीमा के अंतर्गत खेत सड़क को प्रधाव्य क्रम दिया जाये।

स्वजलधारा के अंतर्गत जो काम मंजूर होता है उसमें मंजूरी के बाद योजना राशि के 45औ धन की पहली किस्त ग्राम समिति को मिल जाती है इसमें कई जगह काम की शुरूआत नहीं होती और दूसरी किस्त भी नहीं मांगी जाती। ग्राम पंचायत के पास तकनीकि यंत्रणा नहीं होती इसलिये इस व्यवस्था में सुधार करना और 45औ जगह 10औ पहली किस्त देना और सुचारू तरीके से विजीलेंस और मॉनिटरिंग करना आवश्यक है। काम की क्वालिटी के बारे में कई जगह शिकायतें हैं। करोड़ों रूपये खर्च हो रहे हैं। इस काम के देखभाल एवं नियंत्रण पर ध्यान देना जरूरी है। कई गांवों में प्रधान मंत्री योजनाकी सड़के बनी पांच साल तक रख रखाव की जिम्मेदारी कॉंट्रेक्टर की है लेकिन जहां पांच साल पूरे हो चुके हैं उन सड़कों की हालत बदतर है। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिये केन्द्र सरकार इस काम के लिये पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध कराये।

---

* Speech was laid on the Table.

MR. CHAIRMAN: Shri E. Ponnuswamy, you can start your speech. Nothing else will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

MR. CHAIRMAN: I am sorry. Nothing will be recorded. Shri E. Ponnuswamy, you can start your speech. He is just creating trouble.

(Interruptions) â€¦

MR. CHAIRMAN: It will not go on record. Shri E. Ponnuswamy, you can start your speech.

(Interruptions) â€¦

MR. CHAIRMAN: He is only making noise.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The time is getting wasted. Shri E. Ponnuswamy, you can start your speech. Let him continue as it is only noise. I have politely requested all the hon. Members that everybody should be given time, but you would not cooperate with the Chair.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No, nothing will be recorded.

*(Interruptions) â€¦ **

MR. CHAIRMAN: It is not being recorded.

(Interruptions) â€¦

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, Shri Jai Prakash, you must realize â€¦

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will be recorded. Not a word will be recorded now.

*(Interruptions) â€¦ **

MR. CHAIRMAN: Please do not write anything.

...(*Interruptions*)

---

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Now, I have to tell you one thing. All those portions have not come on record. He is a Member of the Ruling Party, and I am here to help him, but he is not cooperating as he has kept on speaking.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No, I am doing this job for this House. If you do not agree â€¦

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I have already politely told you that there are about 40 Members who wish to speak on this issue. This being a topic on rural development, everybody must be given a chance and it would mean giving five minutes for each Member. This would itself take more than three hours. How can I conduct this job if hon. Member, Shri Jai Prakash, is doing like this?

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Kindly allow me to conclude. I am on my legs. I am referring to the Ruling Party for the simple reason that they are duty-bound to see that the House runs more than these people sitting there. I am a person who is experienced

with all these matters for over 50 years.[r51] That is why, I am speaking. They are not bound to conduct this House. They can criticize and cooperate, but it is the bounden duty of the ruling benches to see that the House functions. I am here doing the job for all.

KUNWAR MANVENDRA SINGH (MATHURA): How can we complete in five minutes? It is not possible and, therefore, the time has to be extended.

MR. CHAIRMAN: Now, the Opposition is cooperating in these matters, but the ruling alliance is not cooperative enough. It is in your interest only that I am mentioning all these things. If you do not understand the basic principles of parliamentary democracy, what can I do?

KUNWAR MANVENDRA SINGH : Sir, you increase the time of the House.

MR. CHAIRMAN: Kindly listen to me.

SHRI E. PONNUSWAMY (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to participate in this debate. I thank our hon. Minister also on behalf of my Party, PMK. The Rural Development Ministry is the most important one, only next to the Defence. It is an important Ministry like the Agriculture, Education and Health. Rural development is the lifeline of the village people. As our Mahatma said, "Our nation lives in the villages", and we have to do justice to the village people. Our hon. Minister really knows the pulse of the people because he comes from a village. He permitted me to opt for this Committee because I have not been nominated by the hon. Speaker to this Committee. I opted myself because I am interested in joining and participating in this Committee. Rural development, as I already said, is the lifeline of India. This is most important Ministry because it covers most of the basic needs of the people.

There are more than ten schemes. Kindly bear with me and I will not take more than five to six minutes. On each point, I will speak only one or two sentences. The National Rural Employment Guarantee Scheme is a very important scheme by which the poorest of the poor gained considerably. But in our system, in India, any project, plan or scheme has got its own loopholes. Under the NREGA, the work is not being selected properly. Under NMR, if 100 people are supposed to work, the Panchayat President tends to add more people in the list. When you have to take the job card, you have to pay something. It is a very shameful thing which is happening in every village. The wages have to be paid according to the work done, but the work taken up is also not being completed fully. It is being left half way. I told the Collector in my constituency that any work selected under this scheme has to be completed. I told him to select such works so that people in the village can have the full benefit of it.

Second, the self-employment scheme has to benefit the unemployed youth, but it is not going down well with this scheme. As far as my constituency is concerned, I used to call the District Administration, namely, the Collector, but he is not able to do justice to the expected level. I used to tell him that for the unemployed youth, though our Tamil Nadu Government under the dynamic leadership of our Kalaignar is doling out some help to the unemployed youth, this scheme is an important one. Actually, this is a genuine scheme and its benefits have to go down to the people so that their expectations can be fulfilled. We have to take some steps in that regard. I used to tell this in the Committee and also requested the hon. Minister to take necessary steps.[r52]

The third important scheme is Indira Awas Yojana. People in the villages erect some huts at places like the tank bund, the side of the road, on the *Porambok* land, and start living there. But they need houses. We have to increase the number of the houses. I made a request to the hon. Minister more than once in the Committee also. The assistance given for the construction of houses is inadequate. I have requested the hon. Minister to give houses to the beneficiaries instead of giving them the money. When the money is given, there is no guarantee that it would be properly utilised. I suggested that even big contractors like L&T can be taken into the fold and entrusted with the task of constructing pucca houses at a minimum cost. I would request the Government to consider this proposal of giving houses instead of giving money to the beneficiaries. Amounts of Rs.25,000 to Rs.30,000 are not at all adequate to construct even one room. The hon. Minister is quite aware of this issue. So, I would request him to consider this suggestion of giving houses in lieu of money.

The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is no longer with the State Governments, it is being implemented by the Central Government. I would request the Government of India to give this scheme back to the State Governments because they know better as to what is necessary to be done and where.

Another important scheme is the Wastelands Development Scheme. There are a lot of wastelands in the country which remain unutilised, undistributed to the needy. The poor people need land and they do not get it. If the Government wants to do justice in this regard, it can take over all the wastelands, develop them and distribute them to the landless, more importantly to the poorest of the poor like SCs, STs and OBCs and other deserving communities.

16.47 hrs (Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

I come to the Rural Drinking Water Supply Scheme now. This is the most important scheme. Drinking water is available where some infrastructure like overhead tank or a pipe is created. But the water is not supplied adequately. Maintenance of the infrastructure is of great importance. The motors fixed are not in working order. In most of the villages we have to appoint a person on payment to maintain the water body to supply drinking water without interruption and according to the need of the people

There is another scheme called Total Sanitation. This is a very important one, especially for the womenfolk in the villages. They are finding it very difficult to use this facility due to a lack of water. Sanitary halls and other things are constructed but they are not being maintained. That is why they are not being utilised properly. I would request the Government to do something through the State Governments and the District Administration to maintain these things.

Computerisation of land records and other documents is a very important point which is being done remarkably well. I would request the Government to instruct the State Governments and the District Administrations to complete this task quickly so that valuable records will be protected.

My next point relates to the Vigilance and Monitoring Committee. This is an important point. The local MPs are appointed as Chairmen. But, the importance and the role of a Member of Parliament are being totally ignored and minimised. No importance is being given to the MPs' requests or MPs' instructions. I have requested the hon. Minister more than once and he has also been periodically writing lengthy letters.

In spite of that, nothing moves on. Governments in several States have not been paying attention to this. Our Tamil Nadu Government is paying more attention. The present Minister is doing a very good work. We all in fact appreciate him. But the Vigilance and Monitoring Committee has to be activated effectively. Wherever the Minister is appointed, he is not convening the meetings and not being cooperative with others. So, I requested the hon. Minister to appoint Members of Parliament wherever they have got six constituencies in a District. This has to be considered.[KMR53]

Finally, I would say that the Ministry of Rural Development is an important Ministry. I have already stated that it is the lifeline of the society. Our hon. Minister is really doing very good work because he knows the needs of the people. We all cooperate in the Committee to help him find solution but the Government as a whole must provide more funds so that he would in turn provide more funds to the States and the districts so that these schemes can be bettered and the situation can be improved.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call the next hon. Member, I would like to inform you that I have a list of 40 Members. Therefore, I would request those hon. Members who would like to lay their written speeches on the Table of House, they may do so.

Now, I call Shri Lakshman Seth.

...(*Interruptions*)

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि चर्चा को कल तक समय बढ़ा दिया जाए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल 40 सदस्य बोलने वाले हैं, आप ही बताइए उसके लिए कब तक बढ़ा सकते हैं?

प्रो. महादेवराव शिवनकर : महोदय, पार्टी ने जिन मैम्बर्स के नाम बोलने के लिए दिए हैं, कम से कम उन्हें तो बोलने का मौका मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

डॉ. राम लखन सिंह (भिण्ड) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सभी बोलना चाहते हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर बोलने के लिए समय का निर्धारण बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने निर्धारित किया है।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. राम लखन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी चर्चा पर चार घंटे आलरेडी हो चुके हैं।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. राम लखन सिंह : इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इसे कल तक बढ़ाया जाए। हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not possible.

...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : बीएसी ने इस पर बोलने के लिए चार घण्टे का समय दिया था।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल यह विनती कर रहा था कि जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच लैं करना चाहते हैं, वे कर सकते हैं।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. राम लखन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें स्पीच लै नहीं करनी है, हमें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: That we would see later on. पहले छः तो बजने दीजिए, उस समय देखेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस वर्ष बजट का जो आवंटन बढ़ाया है, वह स्वागत योग्य है। मैं अपने संक्षिप्त सम्बोधन में उस विभाग में जो त्रुटियां हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1946 में महात्मा गांधी ने नौखाली में एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो भूख से रहित हो, कोई भूखा न हो, ग्राम स्वराज्य हो और हर गांव का विकास हो। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्ष 2008 तक देश के लोग भूखे हैं और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपीए शासन ने यह तय किया और भारत निर्माण की एक महत्वकांक्षी योजना बनाई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई। इससे पहले कि मैं इन योजनाओं का आकलन करूं, मैं आपका ध्यान उन योजनाओं की तरफ दिलाना चाहूंगा जो कि आजादी के बाद से आज तक हम बनाते रहे और उनके फेल होने के क्या कारण रहे? एक सर्वेक्षण के अनुसार Accelerated Rural Water Supply Programme, 1972 के बारे में दिया गया है, which failed due to inadequate funding and lack of technical capacity of Zila Parishads to operate and maintain water supply and sanitation facilities. IRDP – Integrated Rural Development Programme, 1980 –provided rural poor subsidy and bank credit for productive employment, one-time provision of credit without follow up; sub-critical investments, over-crowding and lack of market linkages weakened the scheme. [r54]

इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985 से आज तक चल रही है। यह क्यों उस तरह से सफल नहीं हो पा रही है, जिस तरह से होना चाहिए? Aimed to give free housing in rural areas, especially to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and bonded labourers. It failed due to limited coverage, resource constraints and leakages to un-deserving candidates. इंप्लायमेंट इंश्योरेंस स्कीम वर्ष 1993 में शुरू हुयी। वह क्यों फेल हुयी? Provided rural employment during lean agricultural season. It was unsuccessful due to corruption and uneven distribution. मैं आशा करता हूं कि जो भूल पूर्व में हुयी हैं, उनसे शासन ने कुछ सीख ली होगी। अब जिन योजनाओं का क्रियान्वयन ये करने जा रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से सुधार लाएंगे। हमारा ग्रामीण भारत बहुत महत्वपूर्ण है। आज ग्रामीण भारत का योगदान हमारे देश की जीडीपी में पचास प्रतिशत है। हमारा जो योगदान पर-कैपिटा इंकम रूरल इंडिया का है, वह अर्बन एवरेज से 56 प्रतिशत कम है, जबकि हम पचास प्रतिशत योगदान जीडीपी में देते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार बीस साल बाद हमारा ग्रामीण बाजार पच्चीस लाख करोड़ रूपए का होगा और जो हमारा अर्बन मार्केट, शेयर मार्केट है, वह उससे चार गुना ज्यादा होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ग्रामीण विकास की योजनाएं सफल हों और इनका क्रियान्वयन सही हो।

भारत निर्माण के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, अब हम उस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का पैसा और भारत निर्माण का पैसा आपने बाजार से लिया है। मार्केट बारोइंग से यह पैसा आया है, यह राज्य सरकारों का पैसा है, विदेशों से इसके लिए मदद आयी है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी आडिटिंग सही हो और इसका दुरूपयोग न हो, यह देखना हमारे लिए आवश्यक है। हम देखते हैं कि केवल बीस प्रतिशत टारगेट हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एचीव कर पाए हैं। एक नजर हम राज्यों की तरफ डालें। आंध्र प्रदेश की तरफ देखें, यह एक विकसित प्रदेश है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आज वह कहां पहुंचा है? आपकी फोर्टीन्थ परफार्मेंस रिव्यू कमेटी मीटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर हुयी थी। उसमें केवल उन्नीस प्रतिशत काम अपग्रेडेशन आफ रूरल रोड्स का आंध्र प्रदेश में किया गया। वर्ष 2007-08 में चार सौ इकत्तीस किलोमीटर काम हुआ, जबकि दो हजार दो सौ अट्ठावन किलोमीटर काम होना था, यह आंध्र प्रदेश की बात है। इसके बाद हम कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक में दो हजार पांच सौ तिहत्तर किलोमीटर अपग्रेडेशन का काम होना था, लेकिन आठ सौ उनहत्तर किलोमीटर अपग्रेडेशन हुआ। केरल में अपग्रेडेशन का टारगेट था - दो हजार दो सौ एक किलोमीटर, वहां से no progress has been reported so far. यह आपकी रिव्यू कमेटी की मीटिंग के मिनट्स हैं। अगर आप इन राज्यों के भरोसे और अपने एलाइज के भरोसे भारत निर्माण करेंगे, तो क्या नतीजा होगा, आपको मालूम है। आप स्वयं आगे बढ़कर अपने विवेक से निर्णय लीजिए और इस पर आगे जो करना हो, उसे करिए। तमिलनाड़ में भी केरल जैसा हाल है। इसके लिए

आवश्यक है कि प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट्स को मजबूत किया जाए। टेंडर डाक्यूमेंट में काफी समय लगता है। एक स्टैंडर्डाइज्ड डाक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे समय न लगे और समय पर सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। आपने 68.90 करोड़ रूपए दिए हैं, for management support to rural development programmes and strengthening of district planning process. यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह राशि जिलों में नहीं पहुंची है। जब हम सतर्कता समिति की बैठक में भाग लेते हैं और उनसे सवाल करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि यह राशि उन्हें नहीं मिली है। एक तो आप इसकी राशि को बढ़ाइए, इस योजना को सफल करने के लिए वहां राशि पहुंचे और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का कार्य अनुभवी लोगों के हाथों में हो, यह बहुत आवश्यक है। पड़त भूमि विकास (वेस्ट लैंड डेवलपमेंट) आपने उसमें काफी आवंटन दिया है, लेकिन आवंटन देना ही पर्याप्त नहीं है। वर्ष 1992 से वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बना हुआ है। [p55]

17.00 hrs.

आज क्यों हमारे वेस्टलैंड डैवलप नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि इधर हम वृक्षारोपण करते हैं, इधर चारा का कार्यक्रम लेते हैं और पीछे से मवेशी आकर सब चर जाते हैं। यह एक समस्या और इसीलिए आपका वेस्टलैंड का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि भारत की विश्व में ढाई प्रतिशत आबादी है और विश्व का 20 प्रतिशत पशुधन भारत में है। इसलिए पशुधन के लिए चारागाह बने। इसके लिए गौशालाओं को मजबूत करना पड़ेगा, गौशालाओं के लिए पैसा देना पड़ेगा और गौशालाओं को विकास से जोड़ना पड़ेगा जिससे हम अपने पशुधन को खड़ा करके चरा सके। स्टॉल फीडिंग के कार्यक्रम लेने पड़ेंगे। आप वेस्टलैंड में एसईजैड बना रहे हैं। ...(व्यवधान) आप वेस्टलैंड पर एसईजैड बनाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं एक-दो प्वाइंट बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह : ठीक है, मैं लिखकर दे दूंगा।

डॉ0 तुषार अमर सिंह चौधरी (मांडवी) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्री जो मांगें लेकर आए हैं, मैं उसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। मैं सबसे पहले मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इंदिरा आवास के अंतर्गत उन्होंने राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दी है। इस हिसाब से गुजरात में आज एक आम आदमी 50 हजार रुपये की कीमत का अपना घर बना सकेगा। साथ ही वित्त मंत्री जी ने 20 हजार रुपये चार प्रतिशत ब्याज से इंदिरा आवास लाभार्थी को ऋण देने की बात भी की है। इस हिसाब से देखें तो एक आदमी 70 हजार रुपये तक का आवास गुजरात में बना सकेगा। आम आदमी का अपना घर हो, इस सपने को साकार करने का काम यूपीए सरकार ने किया है। इसलिए मैं यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और डा. मनमोहन सिंह जी को भी बधाई देना चाहता हूं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं सन् 2002 में गुजरात में विधायक था। उस वक्त मेरी असैम्बली कौन्सटीटूंसी में मुझे साल में मुश्किल से 140-150 इंदिरा आवास मिलते थे। मैं किसको दूं, किसे न दूं, उस समय मैं बहुत विडंबना महसूस करता था। लेकिन जब से यूपीए सरकार आई है तो पहले ही साल में 900 इंदिरा आवास मेरे एक विधान सभा क्षेत्र में मिले, जिसके कारण मैं कई लोगों को संतुष्ट कर सका। लेकिन मैं इसमें आने वाली दिक्कतों के बारे में कहना चाहता हूं। 2002 सैन्सस के सर्वे के हिसाब से देखा गया कि मेरे मत क्षेत्र में बीपीएल का दायरा छोटा हो गया और इंदिरा आवास बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे यहां इंदिरा आवास का कोई लाभार्थी नहीं बचेगा। मैं मानता हूं कि सर्वे का जो मापदंड बनाया गया है, उसके जो पैरामीटर तय किए थे, उसने न कभी गांव देखा न कभी गरीबी देखी।

आज हमारे देश में दो करोड़ रुपये की बैन्टले रॉल्स रॉय गाड़ी मिलती है और उसे हिन्दुस्तानी आदमी खरीदकर घूमता है, लेकिन यदि किसी गरीब आदमी के पास साइकिल हो तो आप कहते हैं कि यह पैसे वाला हो गया, इसे बीपीएल की लिस्ट से निकाल दें। आज कम्प्यूटर का जमाना आ गया है। आज मिडिल क्लास फैमिली के घर में कम्प्यूटर होता है। धनी वर्ग के घर में हर फैमिली मैम्बर का अलग कम्प्यूटर होता है, लेकिन यदि गरीब आदमी के पास रेडियो या ट्रंजिस्टर हो तो आप कहते हैं कि यह पैसे वाला हो गया है, इसका नाम बीपीएल सूची से निकाल दें। यह कैसा सर्वे है। गुजरात में जो सर्वे हुआ है, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गुजरात सरकार ने बेरोजगार नौजवान को टारगेट दिया कि आप यदि दिन में सौ आदमियों का सर्वे करेंगे तो आपको सौ रुपये मिलेंगे। वह नौजवान गांव में गया, वह गांव में किसी को जानता नहीं था। उसे जहां चाय मिली, अच्छा पानी पीने को मिला, उसने वहां बैठकर सर्वे किया। जिन लोगों का नाम बीपीएल सूची में आना चाहिए, वे नहीं आ सके और वह जिसके घर बैठा था, उसके पास मोटर साइकिल थी, ट्रैक्टर था, फिर भी उसका नाम बीपीएल की लिस्ट में आ गया। मेरी मंत्री जी से मांग है कि सर्वे को दुबारा से करवाना चाहिए। इस सर्वे को रद्द करके नए तौर से बीपीएल लिस्ट बनानी चाहिए और उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का समावेश करना चाहिए।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में एनडीए के कार्यकाल के दौरान 50-60 लाख रुपये से ज्यादा एक मत क्षेत्र में सड़कें नहीं आती थी। जब से यूपीए सरकार आई है, पहले ही साल में एक विधान सभा क्षेत्र में 6 करोड़ रुपये, दूसरे साल में 8 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये की प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत काम हो रहा है।[N56] लेकिन उसमें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की जो गाइडलाइन सरकार ने बनायी है, उसका पालन गुजरात में नहीं हो रहा है। गाइडलाइन यह कहती है कि एमपी का हर प्रपोजल में मशविरा लेना चाहिए। एमपी से मशविरा लेकर ही हर प्रपोजल भेजा जाना चाहिए, लेकिन मुझे एमपी बने हुए आज चार साल हो गये हैं। मेरे साथ एक बार भी कोई मशविरा नहीं किया गया। एक परिपत्र है कि छः महीने में एक बार सुपरीटेंडिंग इंजीनियर के साथ ऑनरेबल एमपी को लेकर ग्राम सड़क योजना का इंसपेक्शन होना चाहिए लेकिन चार साल में मैंने एक भी इंसपेक्शन नहीं किया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी और उद्घाटन है, उसे एमपी को साथ रखकर करना चाहिए। लेकिन आज चार साल हो गये, मैंने एक भी उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी नहीं की है। मैं स्टेट लैवल विजिलेंस कमेटी का भी मैम्बर हूं। आज चार साल हो गये हैं, स्टेट लैवल विजिलेंस कमेटी की एक भी मीटिंग गुजरात में नहीं हुई है। मंत्री जी इसे आप ध्यान में रखिये। जब कभी आगे राशि देने की बात हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाये। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

SHRI ABU AYES MONDAL (KATWA): Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development for the year 2008-09. While supporting the Demands I would like to point out that the mandate of the Ministry of Rural Development is to alleviate poverty in the rural areas. With the objective of providing avenues of employment to the disadvantaged sections of the society, many programmes and schemes are being implemented throughout the country for improving the quality of life in the rural sector. The *Swarnajayanti Gram Swarojgar Yojana* is a major self-employment programme that is being implemented all over the country. The guidelines of the programme stipulate that at least 50 per cent of the *Swarojgaris* would have to be from people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes; 40 per cent would have to be women and three per cent would have to be disabled. The subsidy given is 30 per cent. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that this subsidy has to be enhanced to 50 per cent.

Sir, owing to paucity of time, I would like to briefly refer to the issue of supply of safe drinking water. Drinking Water Supply is one of the six components of Bharat Nirman which has been conceived as a Plan to be implemented in four years from 2005-06 to 2008-09. This is the last year of that plan for building rural infrastructure. The objective of the said component is to provide 55, 067 inhabitants with safe drinking water so as to address the problem of affected habitations by 2008-09. Here I would like to mention that this figure, as given, should be re-considered because I think, this is not the right figure, it will be much higher than this. In the rural drinking water sector the biggest problem is seepage. I would like to mention that the State of West Bengal is facing a formidable challenge in this regard as many parts of the State is arsenic affected. The other States where this problem is there are States of Assam, Jharkhand and Bihar. In the State of West Bengal eight districts out of 19 districts are seriously affected by arsenic. About 166 crore people are living in these arsenic affected areas of the State. These people are entitled for safe drinking water. The Government of West Bengal has tried its level best to supply safe drinking water to these areas. [R57]

Various projects are also being implemented successfully. It needs to be mentioned that upto 1977, only 0.07 per cent of the rural people were under pipe water supply scheme. Now, 33.55 per cent people have come under this scheme. Under arsenic sub-mission programme, on the basis of 75:25 share by Centre and State Governments respectively, projects were in progress. It is a matter of great sadness that the Central Government discontinued the scheme from 1st April, 1999. As a protest, an all-Party delegation from West Bengal Assembly came to Delhi to meet the then concerned Minister. In reply, the then Minister wrote a letter dated 26.9.2001 to the West Bengal Government informing that the matter was under consideration. But nothing has been done. In the meantime, the hon. Minister has done a lot by providing money for continuing the programme.

Furthermore, in January, 2000, the Central Government agreed to set up an Arsenic Free Drinking Water Research Centre of national dimension in Kolkata. Land has also been allotted for this Centre by the State Government. But no progress has been made as yet.

I urge upon the hon. Minister to take initiatives as regards the schemes which are pending for a long time.

As regards ARWS programme, the Central Government is to supply more money to the States and Union Territories for creating and augmenting drinking water supply infrastructure especially the arsenic and fluoride-affected States and areas.

Lastly, I want to add a few words about the Total Sanitation Campaign. More attention has been given with the object of improving the quality of life of the rural people and to provide privacy and dignity to women. The goals of Total Sanitation Campaign are, full-household coverage by 2012, and coverage of all schools by 2007-08. Emphasis is on attaining 100 per cent coverage in villages so that the practice of open defecation is completely eliminated. To have more success, more Central assistance should be given to TSC.

I conclude here by thanking you, Sir.

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहूं। इतनी बड़ी रकम ग्राम विकास में इतने लंबे समय से जा रही है, 37,000-38,000 करोड़ रूपए जा रहे हैं, लेकिन गांव जहां पहले खड़े थे, वहीं आज भी खड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इनकी तारीफ करनी चाहिए।

श्री इलियास आज़मी : मंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूं, पहले सांसद के लिए सिर्फ यह भूमिका यह थी कि वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्ताव करेगा कि वहां सड़क दी जाए, उसका शिलान्यास और उद्घाटन वह करेगा और उसमें 10,000 रूपए प्रति सड़क जाते थे। लेकिन माननीय मंत्री जी ने बाकायदा आदेश जारी करके उसे समाप्त कर दिया कि 10,000 रूपए नहीं दिए जाएंगे। एक-एक सड़क पर 50-50 लाख रूपए कमीशन खाए जा रहे हैं लेकिन 10,000 रूपए समाप्त कर

दिए ताकि किसी एमपी का नाम उसमें न आए। एक साल से आश्वासन दे रहे हैं। कम से कम दस बार मुझे यह आश्वासन दे चुके हौं कि बस हो गया है, अगली बार से होगा। इसी तरह डेढ़ साल से हो रहा है। मेरे क्षेत्र में जिला लखीमपुर खीरी के चार ब्लॉकों 32 सड़कें वर्ष 2003 की बनी हैं, जिन पर आज तक पांच रूपए खर्च नहीं हुए, कोई काम नहीं हुआ। कई बार मैंने इसके लिए पत्र लिखे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चार साल में मंत्री जी ने 445 लोकसभा सदस्यों में से शायद किसी एक सदस्य के लिखे पर भी कोई काम नहीं किया होगा।[R58]

यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप यह बताएं कि कितनी बार आपने यह आश्वासन दिया कि 10,000 रुपए बहाल करके सड़कों का उद्घाटन का काम हो जाएगा। सन् 2003 की सड़कें अब तक नहीं बन सकी हैं। आपने सतर्कता निगरानी समितियां बनाने की बात सीना तान कर गला फाड़-फाड़ कर कही थी कि सारे अधिकार आपको दे दिए हैं। मैं भी अपने क्षेत्र की एक सतर्कता निगरानी समिति का सदस्य हूं। हम हमेशा उसकी मीटिंग बुलाते हैं। कई कामों की मैंने ताबड़-तोड़ जांच कराई, लेकिन जो जिला अधिकारी हैं, चाहे डीआरडीए के हों या अन्य तकनीकी अधिकारी हों, उन्होंने सहयोग नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि एक भी जांच पूरी नहीं हो सकी। इसके अलावा सतर्कता निगरानी समिति के चेयरमैन को सुई की नोक के बराबर भी अधिकार प्राप्त नहीं है, सिवाय मीटिंग बुलाकर समय बर्बाद करने के। मीटिंग बुलाने से यह होता है कि एक-दो दिन तक हलचल रहती है, उसके बाद फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। ये भ्रष्ट अधिकारी पच्चीसों हजार करोड़ रुपया, गरीबों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जाता है, उसे हड़प कर जाते हैं। समयाभाव के कारण मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता कि इन पर कोई निगरानी न होने से ये कैसे पैसे का दुरुपयोग करते हैं।

आप छोटी योजनाओं को ले लें। उनके लिए आप गाइडलाइंस बनाते हैं और वह पूरे देश के लिए बनाते हैं, जबकि हर इलाके के और हर सूबे के अपने-अपने हालात हैं। सूबों में भी कई हिस्से होते हैं, जिनके अलग-अलग हालात होते हैं। आपने गरीबी की परिभाषा के लिए जो गाइडलाइंस बनाई हैं, पंजाब और उड़ीसा के लिए एक समान हैं, जबकि दोनों के हालात अलग-अलग हैं। इसलिए आप एक ही गाइडलाइन से सबको हांकना चाहेंगे तो वे नहीं हांके जाएंगे और सारा पैसा खा लिया जाएगा। आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, उनका सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। जो योजनाएं पंचायतों के जरिए लागू की जाती हैं, उनके बारे में राहुल गांधी जी ने जो कहा है, मैं उनसे सहमत हूं। उनके पिता राजीव गांधी जी कहा करते थे कि केन्द्र से जो पैसा जाता है, उसका 15 फीसदी ही खर्च होता है और बाकी बीच में हडप लिया जाता है। लेकिन जैसा राहुल जी ने कहा कि आज कल 95 प्रतिशत पैसा हड़प लिया जाता है और पांच प्रतिशत पैसा ही विकास के काम में लगता है। पंचायतों के माध्यम से आप जो काम करा रहे हैं, उसमें 95 प्रतिशत पैसा खाया जा रहा है और केवल पांच प्रतिशत ही लग रहा है। इस बारे में कितना भी हम लोगों द्वारा कहा जाए, लेकिन आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर एक जिले में मान लिया जाए कि 10-15 योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए खर्च होने हैं तो आप लम्प सम वह पैसा जिले के हालात के मुताबिक दे दें। जिले के सांसद, विधायक, कलेक्टर या जो भी अधिकारी आप मुकर्रर करें, विकास के कौन से काम होने चाहिए, यह उन्हें पहले बता दें। लेकिन आप कहेंगे कि संडास बनाने के लिए इतना पैसा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो योजनाओं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और इंदिरा आवास योजना को छोड़ कर बाकी योजनाओं के लिए लम्प सम पैसा दे दें। अगर आप एक जिले में विकास के लिए यह नहीं देंगे, कच्चे काम पर प्रतिबंध नहीं लगाएं और पक्का काम जब तक नहीं कराएंगे, तब तक यह भ्रष्टाचार चलता ही रहेगा। आपकी इस योजना का नाम ही अब भ्रष्टाचार गारंटी योजना हो गया है। हालांकि मैं मानता हूं कि इस योजना के साथ ज्यादती हुई है। जनता ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और इंदिरा आवास योजना को छोड़ कर बाकी योजनाओं का नाम भ्रष्टाचार योजना रख दिया है और सभी में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका इलाज मैं आपको बता दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं लिखित में दे सकता हूं। अगर फिर भी विकास न हो तो उसकी जो चाहे सजा हो, वह मुझे दीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि गरीबी दूर करने की जो परिभाषा तय की गई है, अगर पूरे देश में एक जैसी लागू करेंगी तो उसका फायदा नहीं होगा।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): यू.पी. में तो सारा पैसा अम्बेडकर योजना पर खर्च हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहिएगा। इस तरह बीच में टोकेंगे तो फिर आपके समय में इन्हें भी मैं नहीं रोक पाऊंगा।

श्री इलियास आज़मी : कच्चे कामों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं। इसके अलावा पंचायतों के माध्यम से पांच रुपए भी विकास के नाम पर खर्च न करें। आप रहम करें, इस देश का अरबों रुपया, गरीब जनता का पैसा ऐसे व्यर्थ न जाने दें। पूरे जिले की योजना बनाकर उसके विकास के लिए पैसा दें तो ग्रामीण विकास सार्थक होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA (BOBBILI): Sir, I am privileged to participate in the discussion on Demands for Grants for the Ministry of Rural Development for the financial year 2008-09. For the first time, the allocation of funds to the Rural Development Ministry is the highest, second after the Ministry of Defence. After the UP A Government came into power, I am proud to say that the allocation for the Ministry of Rural Development has been stepped up year-after-year. Now it is Rs.49,450 crores. This shows the concern of the UPA Government for the *aam admi;* and its focus on the economic development of the rural areas. Thanks to the UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhiji, Honorable Prime Minister Shri. Manmohan Singhji and Union Rural development Minister Sri. Raghu Vamsaprasadji.

Sir, even as the Indian economy surged ahead at an unprecedented 8 per cent plus growth rate for yet another year, the realization that this growth has to be of an inclusive nature meant renewed importance for development of the rural areas of the country. The four years of the UPA Government so far has seen the introduction of new programmes and restructuring of the existing ones to deal with the task of ensuring reduction of poverty, and creation of employment. The Ministry of Rural Development continued to play a key role in this strategy. A paradigm shift in the policy of rural development has also taken place, with the rural poor treated as resources who form an integral part of the development strategy, and not as burden. The Ministry co-ordinates, implements and funds scheme which aim at ensuring that the fruits of economic development reach the villages and the common man.

Now, I want to highlight some important programmes under the Ministry.

The NREGP program is one of its kinds in the world. As a member of NREGP council, I visited many villages in different parts of India. People are delighted to

---

* Speech was laid on the Table.

have this program, which is guaranteeing wage employment and ensuring food security. More important is the Act brings equality between men and women as far as wages are concerned, equal wages are paid to both for equal work. For the first time in India's history, employment has been made a legal right through an Act of Parliament.. The Act is structured towards harnessing the rural work-force, not as recipients of doles, but as productive partners in our economic development. The assets created result in sustained employment in the area for future growth, employment and self-sufficiency. From 1st April 2008 NREGP has been implemented in all the districts in the country. Thanks to the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi, Dr. Manmohan Singh, the Prime Minister. I welcome the allocation of Rs. 16000 crores for this program. As more and more is required to be done, I would humbly request the hon. Finance Minister to increase the allocation further.

Here I want to stress that, if all the State Governments increase their transparency and accountability and follows the systems established under the NRGPA, the misuse of funds in certain places can be greatly curtailed.

Under Bharat Nirman, development works are undertaken in the areas of irrigation, road, rural housing, rural water supply, rural electrification and rural telecommunication and rural connectivity. The mandate given to Rural Development Ministry under Bharat Nirman is viewed as an effort to unlock rural India's growth potential and to be a key for ushering in a new era. It is also expected that Bharat Nirman will lead to creation of considerable assets along with the National Rural Employment Guarantee Act. Bharat Nirman, however, is a collective agenda in which every Indian has a role to play either as a user or as a partner. This program is really creating ripples in rural areas and bridging the gap between the rural and urban divide.

As you know, Sir, in my Bobbili parliamentary constituency, there are about 150 panchayats with a population of less than 5000 in each panchayat jurisdiction and an annual revenue of less than Rs.50,000. How is it possible for the panchayat to undertake developmental works with this meager revenue? Therefore, I humbly request the hon. Minister to provide special corpus fund to develop these panchayats.

Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY): The promotion of self employment amongst the rural poor for their socio economic uplift has been long an integral part of the strategy for poverty eradication. SGSY is the largest self employment program for the rural poor. Since its inception (Up to Dec. 2007) more than 27 lakh of Self Help Groups (SHGs) have been formed. Total number of swarozgaris assisted is 93.27 lakhs. Subsidy has been distributed to the tune of Rs. 540.98 crores. Per capita investment (Ave./per year) amounted to Rs. 27,069/-. Here I would like to add that Self Help Groups should be provided loans at Re.0.25 interest. This would empower the women financially. The Government of Andhra Pradesh is already implementing it. This would make them economically independent. Agriculture and animal husbandry go hand-in-hand. Here I urge upon the hon. Minister to sanction milk dairy centres exclusively to be handled by women belonging to Self Help Groups under SJYS Scheme. In this connection, I have already forwarded to the Ministry a proposal for sanctioning the same. I request the Minister to approve the proposal at the earliest in my Constituency.

Thanks to the UPA Government that they have identified 42 lakh persons for the Aam Admi Bima Yojana. As per the information available about 42 lakh people were covered under this scheme in the country. Out of this, 38 lakh policies

were covered in Andhra Pradesh alone. This was made possible because of the efforts of the Government of Andhra Pradesh in providing matching grants in the ratio of 50:50. This shows the success of the scheme if any State Government comes forward to implement schemes for the poor people. 'Aam Admi Bima Yojna's goal is to reach every poor men in the country,'

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY); aims at providing connectivity to un connected habitations. It is expected under the scheme that an expanded and renovated rural network will lead to increase in rural employment opportunities, better access to regulated and fair market, better access to health, education and other public services and thus bridge the rural-urban divide and pave the path of economic growth. In the current financial year 2007-08, up to December 2007, nearly 50,000 kms of new all-weather roads have been completed. New connectivity has been provided to nearly 17,000 habitations and 65,000 kms of existing rural roads upgraded. Thanks to the UPA Government. I congratulate the hon. Rural Development Minister for this spectacular achievement.

Indira Awas Yojana (IAY): Rural housing is one of the components of Bharat Nirman package. In the current financial year i.e 2007-08, 10.6 lakhs homes have been built so far, while 8.40 lakh homes are under construction. The target is 21.27 lakhs for the current financial year. In a major initiative to impart transparency in the selection process a "Permanent Wait list" is being prepared under IAY. I welcome this step.

Here I want to bring to the notice of the Ministry that in the State of Andhra Pradesh under the dynamic leadership of hon. Chief Minister Dr Y. S. Rajasekhar Reddy the State has set an ambitious target to construct 60 lakh houses for the poor, in three years, ending with current financial year 2008-09. On behalf of the State Government, I thank the Central Government for extending overwhelming support.

Here I would like to add that instead of 5 per cent of the total allocated funds under IAY to meet the exigencies arising out of natural calamities and other emergent situations like riot, arson, fire, rehabilitation, etc., it should be enhanced to 20 per cent because my Andhra Pradesh State is situated in coastal area which is always on the radar of the cyclone. Very often my State has become a victim of cyclones resulting in unprecedented loss of life and property. There are many huts in villages. Very often fire accidents take place which also result in huge loss of life and property.

Land reforms: Aims at greater access to land by landless rural poor through various initiatives. In Andhra Pradesh, the State Government has distributed more than 6.17 lakh acres of land to the landless poor. Thanks to the State Government and the Central Government for excellent coordination.

Accelerated Rural Water Supply Program (ARWSP): By 2009, 55,067 uncovered, 3.31 lakh slipped back and 2.17 lakh quality affected habitations are to be addressed. Sir, The Ministry's efforts are praiseworthy for covering, by November, 2007, more than 30,000 uncovered habitations, around 2 lakhs "slipped back" habitations and 54,000 villages where water quality was a problem had been covered under Bharat Nirman.

Sir I am representing the Coastal , Tribals and plain areas which are suffering a lot due to brackish, salt and flouride problems. In this connection, I request for a special drinking water project in Echerla Assembly Constituency which is also a Coastal Area.

I will end my speech with Mahatma Gandhi's quotation. I quote: "We must be the change we wish to see. India lives in rural areas." For overall development of the country, the rural areas must develop. For this purpose, resources must be allotted on a priority basis. Therefore, I support the Demands for Grants for 2008-09, in respect of the Ministry of Rural Development comprising the Department of Rural Development, Department of Land Resources and Department of Drinking Water Supply.

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर) : उपाध्यक्ष जी, आपने अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत एक कृषि

प्रधान देश है और यहां के 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। आज हम भारत-निर्माण की बात कर रहे हैं जबकि आम आदमी के पास खाने के लिए अन्न नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए घर नहीं तो भारत का निर्माण कैसे होगा, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव से आता हूं और मैं राजस्थान प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां आपने कुछ योजनाएं पूरे देश के साथ लागू की हैं। राजस्थान में कुछ मरुस्थलीय जिले हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुछ सिंचाई क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्रों में सिंचाई तालाब से होती है तो कुछ क्षेत्रों में सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। योजनाएं जब वहां तक पहुंचती हैं तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रदेश मरुस्थलीय हो, तटीय हो, रेतीला हो या फिर नहरी क्षेत्र हो, एक जैसी योजनाएं पूरे प्रदेश में लागू नहीं हो सकतीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस समय देश के किसानों की हालात अत्यन्त खराब है। सन् 1991 की आर्थिक उदारीकरण की नीति ने भी इस देश के किसान के लिए आग में घी डालने वाला काम किया है। किसान को उसकी उपज का सही मूल्य न मिले तो यह उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह बात है। इस उदारीकरण की नीति के बाद किसान अपनी मातृभूमि छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हुआ है। वह रोजगार के लिए दूसरी जगह जाना उचित समझता है। किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। अभी राजस्थान में पाले से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं लेकिन पाला प्राकृतिक आपदा में गिना नहीं जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पाले को भी इस प्राकृतिक आपदा में शामिल करें।

उपाध्यक्ष जी, जब एनडीए की सरकार थी तो उसने कुछ ऐसी योजनाएं इस देश में लागू की थीं जिनको यूपीए की सरकार ने समाप्त कर दिया है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, कृषि और ग्रामीण मंत्रालय गठन करने की योजना इस सरकार ने पूर्णतः बंद कर दी है जिससे गांवों के गरीब लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा के तहत जो योजनाएं शुरू की गयी हैं उससे कच्चे काम की शुरूआत हुई है तथा गांवों के गरीब आदमी को उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं कुछ आंकड़े इस संबंध में आपके सामने रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यूपीए की सरकार बनने के बाद, आपने पिछले साल सड़क निर्माण के काम में 50 हजार 674 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा था लेकिन केवल 49 हजार 476 किलोमीटर का ही काम पूरा किया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो लक्ष्य निर्धारित करे, उसे अगर पूरा करे तो यह देश का सौभाग्य होगा। भारत का निर्माण तभी संभव होगा जब आप अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पिछले साल अपने टार्गेट में रखा था कि हम 60 लाख लोगों को मकान बनाकर देंगे लेकिन उन्होंने केवल 28 लाख मकान बनाने का लक्ष्य ही पूरा किया है। आज भी गांवों के 19 प्रतिशत परिवार कच्चे घरों में रहते हैं, 50 प्रतिशत परिवार ही पक्के घरों में रहते हैं और 31 प्रतिशत लोग अर्ध-कच्चे-पक्के घरों में रहते हैं।

उपाध्यक्ष जी, सरकार ने पेय-जल का जो टार्गेट रखा था, वह भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। [r59] महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 55 हजार से ज्यादा बस्तियां पेयजल से वंचित हैं। तीस प्रतिशत शहर नगर निगम या नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। शहरों की बस्तियों में आज भी नगर निगम या नगर पालिका द्वारा पीने के पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। 26 प्रतिशत लोगों के पास इस देश में शौचालय की सुविधा नहीं है।

सरकार ने वर्ष 2007 में लक्ष्य रखा था कि एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे, लेकिन इन्होंने मात्र बीस लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम किया है। सरकार को लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मेरे से पहले कई सदस्यों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जिक्र किया है कि एक हजार से कम की आबादी वाले गांव को इस योजना से जोड़ा जाए और क्षेत्रफल की दृष्टि से पैसा दिया जाए। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं कि पचास किलोमीटर या सौ किलोमीटर सांसदों की अनुशंसा से ग्रामीण सड़क योजना की शुरूआत की जाए। इसमें क्षेत्रफल रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है और माननीय मंत्री जी स्वयं जयपुर गए थे तथा इन्होंने तारीफ की थी कि अगर सड़क कहीं भी सबसे अच्छी बनी है, तो वह राजस्थान में बनी है। क्षेत्रफल का आंकड़ा सरकार को जरूर रखना चाहिए।

महोदय, केंद्र सरकार ने 125 लाख गांवों में बिजली देने के लिए 230 करोड़ लोगों को, जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 56 प्रतिशत लोगों के घरों में बिजली है और 44 प्रतिशत आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने घरों में केरोसीन तेल से रोशनी करते हैं।

सरकार ने पिछले बजट सत्र में कहा था कि 22700 प्राथमिक केंद्रों को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन 22700 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 8 प्रतिशत स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टर नहीं हैं। जहां डाक्टर हैं, वहां कम्पाउंडर नहीं हैं, जहां कम्पाउंडर हैं, वहां नर्सें नहीं हैं। कहीं पर बिल्डिंग नहीं है, कहीं औजार नहीं हैं, कहीं दवाइयां नहीं हैं, ये हालात इस देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के हैं। सरकार जो घोषणा करती है, उसे सरकार पूरा करने का काम करे। देश में आज भी सिर्फ 9 प्रतिशत लोग रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 74 प्रतिशत लोग लकड़ी से चूल्हे जलाते हैं।

मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत हुई है, उसके तहत एनडीए की सरकार ने जो योजनाएं शुरू की थीं, उन्हें बंद करके नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं पर अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा है।

महोदय, मैं एक बात का और निवेदन करना चाहूंगा कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं या सिंचित क्षेत्र हैं, वहां पक्के थाले बनाए जाएं। अगर इस योजना की शुरूआत हो, तो यह योजना बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।

*महोदय, भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। भारत की 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं1 भारत पूर्णतया जब विकास के पथ पर पहुंचेगा जब गांव का ग्रामीण के लिए खाने के लिए अन्न होगा और पीने के पानी होगा और रहने के लिए मकान होगा। जब तीनों मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक इंसान के लिए होगी तब देश पूर्णतया विकास के पथ पर पहुंचेगा। भारत की समृद्धि का रास्ता गांवों और खेतों से होकर गुजरता है। गांवों की हालत बहुत नाजुक है। जिसको हम लोग बडे नजदीकी तौर पर देखते हैं1 ग्रामीण क्षेत्र में मानव निर्मित संसाधनों की पूर्वूस्ता उनके विकास के लिए प्राकृतिक वरदानों का उपयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्र की जो योजना केन्द्र सरकार ने लागू की है। वे पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच नहीं पा रही है। राजस्थान प्रदेश का उदाहरण लें तो यहां पर मरूस्थलीय जिले हैं, पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, सिंचित क्षेत्र भी हैं, कुओं और नदियों से भी सिंचाई होती है। केन्द्र सरकार की योजनाओं को पूर्णतया हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लागू किया जाये तब जाकर विकास संभव होगा।

महोदय, हम भारत निर्माण की बात करते हैं1 इस देश में कुल 582 जिले हैं। 457 जिला परिषद हैं, 5913 पंचायत समिति हैं, 227617 ग्राम पंचायतें हैं। छोटे से

लेकर बडे तब जन प्रतिनिधियों की

---

* â€¦â€¦.* This part of the speech was laid on the Table.

संख्या इस देश में 34 लाख हैं। भारत की ग्रामीण इलाके में अगर नजर दौड़ाये तो गांव का इलाका आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछले साल केन्द्र सरकार ने 1.25 लाख गांव में बिजली देने व 230 करोड परिवार जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं इनको बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। जो 30 प्रतिशत लोगों के बीच में बिजली पहुंचाने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में 56 प्रतिशत लोगों के घर में बिजली पहुंची है। इस देश को आजाद हुए 61 साल हो गये हैं। आज भी 42 प्रतिशत लोगों की घरों में केरोसिन से रोशनी करते हैं। आज भी 55067 बस्ती पेयजल से वंचित है। 30 प्रतिशत शहर के लोगों को नगर निगम से पेयजल नहीं मिलता। 26 प्रतिशत लोगों के पास आज भी शौचालय की सुविधा नहीं है।

महोदय, सरकार ने 2007 में 1 करोड हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा था जिसका मात्र 20 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित नहीं हो पाई। एनडीए सरकार ने जिन योजनाओं की शुरूआत की थी वे योजनाएं इस सरकार ने बंद कर दी। नदियों से नदियां जोडने का काम एनडीए सरकार ने शुरूआत की थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजना, कृषि और ग्रामीण मंत्रालय का गठन ये योजनाएं वर्तमान की सरकार ने पूर्णतया बंद कर दी हैं। जिससे वर्तमान में गांवों को नुकसान हुआ है। केन्द्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की नरेगा स्कीम जो केन्द्र सरकार ने चालू की है जिससे गांव का बहुत बडा उत्थान होने वाला नहीं है। नरेगा स्कीम से गांवों के बेरोजगार को व श्रमिकों को पूर्णतया रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यह स्कीम हमारे लिये नासूर बनकर खड़ी हो गई है। ग्रामीण विभाग ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना के तहत इस साल का लक्ष्य 50674 किमी0 सडक बनाने का लक्ष्य रखा था, परंतु वर्तमान में 39476 किमी. सड़क का काम पूरा हुआ जो आम लोगों के साथ में विश्वासघात हुआ। इस सरकार ने 60 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा था, परंतु 28 लाख मकान का निर्माण कर सकी।

महोदय, इस देश में 19 प्रतिशत परिवार आज भी कच्चे घरों में रहते हैं और 50 प्रतिशत लोग पक्के घरों में रहते हैं और 31 प्रतिशत लोग अर्द्ध कच्चे घरों में रहते हैं। इस देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 22700 हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सिर्फ प्रतिशत डाक्टर ही उपलब्ध हैं। कहीं पर नर्स नहीं हैं कहीं कम्पाउडर नहीं है और कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं पर मेडिसिन नहीं है। इस देश में शहर में 40 से लेकर 70 प्रतिशत लोग रसोई गैस का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 74 प्रतिशत लकड़ी के चूल्हे का प्रयोग करते हैं। सर्वे के मुताबिक मात्र 9 प्रतिशत लोग ही गैस का प्रयोग करते हैं।

महोदय, 1991 की आर्थिक उदारीकरण की नीति भी इस देश में आग में घी डालने का काम किया। प्रत्येक किसान को इस उदारीकरण की नीति से घाटा हुआ। लोगों ने पलायन किया। अपनी मातृभूमि को छोडकर दूसरी जगहों पर बसे जिससे ग्रामीण इकाई को घाटा हुआ। इस देश का किसान बर्बाद हुआ पड़ा है जब तक किसान की फसल का उचित मूल्य किसान को नहीं मिलता है तब तक किसान का उत्थान नहीं हो सकता। अतः किसान की फसल का उचित मूल्य किसान को मिले ऐसी व्यवस्था बजट में होनी चाहिए। किसान की फसलें पाले से बर्बाद हो जाती हैं। उनका मुआवजा उनको नहीं मिलता है क्योंकि पाला प्राकृतिक आपदा में नहीं गिना जाता है। पाले को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाये। किसान की फसल खराब होने का मुआवजा केन्द्र सरकार व बैंकों ने तहसील सतू का मान रखा है उसको ग्राम इकाई मानकर उसका मुआवजा दिया जाये।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी आज्ञा से यहां से बोलने की परमिशन दी जाए। मैं सर्वप्रथम सारे किसानों और ग्रामीण अंचल के लोगों की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री, यूपीए सरकार की चेयरपर्सन सोनिया जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साहू जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आजादी के बाद गांधी जी का आन्दोलन गांव से झोंपड़ी तक पहुंचा और गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका इस बजट के माध्यम से यूपीए सरकार ने निभायी है जिस का ग्रामीण अंचलों में बहुत लाभ हुआ है। सर्वशिक्षा अभियान में 13 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गांवों में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की कमी है, प्राइमरी लैवल में इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर्स की कमी है, बच्चों के लिए साफ पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है। आज भी प्राइमरी स्कूल के छात्र भूखे रहते हैं और पेड़ के नीचे शिक्षा प्राप्त करते हैं। केन्द्र सरकार का पैसा प्रान्तीय सरकारों में जाता है। हमारे बीएसपी के साथी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सारा रुपया अम्बेडकर योजना के तहत खर्च किया जा रहा है। जिन योजनाओं के लिए पैसा जाना चाहिए, वहां नहीं लगाया जा रहा है। मिड-डे मील के लिए आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधन बजट में किया गया है। हमें इस पर निगाह रखनी चाहिए। मिड-डे मील का पैसा बच्चों तक पहुंच नहीं रहा है। बहुत से प्रॉविएन्सिज में जहां सरकारें सक्षम हैं, उसे कर रही हैं। हमारे यहां मथुरा में मुझे कहते खुशी हो रही है कि आक्षेपातू एक संस्था है जो अन्य जिलों में भी कार्य कर रही है। वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में करीब 80 हजार बच्चों को स्कूलों में भोजन देती हैं। उनके गर्म कंटेनर्स हैं, वैन्स हैं, उनमें चावल, सब्जी, गर्म रोटी पहुंचती हैं जिन से बच्चों की संख्या बढ़ी है। मैंने स्वयं वहां जाकर खाना खाया है। केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह आगे इस तरह की

योजनाएं बनाए और एनजीओज आगे आकर सहयोग दें जिससे यह पैसा ठीक तरह से लग सके। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन के अन्तर्गत Social health activities have been taken up. Sanitation committees are functioning in a number of villages. In 323 districts, hospitals have been taken up for upgradation. इसके लिए पैसा बढ़ा कर 12 हजार 500 करोड़ रुपया किया गया है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हैल्थ सैंटर्स की कमी है। अगर हम हर गांवों में न जा सकें तो प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स को मजबूत करें। मैं आग्रह करूंगा कि ब्लॉक स्तर पर कम से कम 30 से 50 बैड वाले अस्पताल बनाएं जहां मैटरनिटी अस्पताल हों, पेशेंट फैसिलिटीज हों, ब्लड टैस्ट हों, एमआरआई हो, एक्सरे की फैसिलिटी हो जिससे मरीज वहां जा सकें। आज सुबह भी क्वैश्चन आवर में ग्रामीण अंचलों में डॉक्टरों के न जाने की समस्या पर एक प्रश्न था। रूरल हैल्थ सर्विस का गठन करना चाहिए। हम डॉक्टरों को रूरल हैल्थ सर्विस में नियुक्त करें जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं देख सकें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, This Health Insurance Scheme provides health cover of Rs. 30,000 for every worker in the unorganised sector falling under the BPL category. मेरा आग्रह है कि बीपीएल कैटेगिरी के अलावा गरीब गांव के लोगों को इसमें जोड़ा जाए जिससे उनको बीमारी में दवाओं का लाभ मिल सके, इसे कम से कम 50,000 रुपए तक किया जाए। अभी केवल 10,000 रुपए रखा गया है जबकि दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं, डॉक्टरों की फीस बढ़ी है, वहां आने-जाने के साधन नहीं है, खाने की कीमतें बढ़ी हैं इसलिए बीमा हैल्थ का पैसा बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाए। इसमें हर फैमिली मैम्बर को लिया जाए जिससे वे अच्छी तरह अपना इलाज करा सकें।

मैं नेशनल एम्पलाएमेंट गारंटी स्कीम के संबंध में माननीय राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि पहले 200 डिस्ट्रिक्ट्स लिए गए थे, और उनके आग्रह पर सारे देश के जिलों के इसमें शामिल किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कार्ड बनते हैं उनको ठीक से बनाया जाए ताकि प्रत्येक गरीब परिवार के एक सदस्य या एक महिला को रोजगार मिले। अभी कुछ दिन पहले माननीय उपाध्यक्ष जी और माननीय सदस्यों ने टीवी पर देखा होगा, एक इंटरव्यू आया था जिसमें तमाम धांधली को दिखाया गया था। गांव के लोग गांव से पलायन कर रहे थे, उनसे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने पूछा - आप कहां जा रहे हैं आपके यहां तो यह योजना है? उन्होंने कहा - हम काम करने गांव से बाहर जा रहे हैं तब पूछा गया - आपको गांव में काम नहीं मिला तब जवाब मिला - हमें धमकाया गया है कि आप गांव से बाहर जाओ, फर्जी कार्ड बनाए जा रहे हैं, फर्जी काम दिखाकर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा वहां पर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, वहां केंद्र सरकार की टीम होनी चाहिए जो इसका गहन अध्ययन करे। इसमें माननीय सांसदों, एमएलए और जनप्रतिनिधियों को रखा जाना चाहिए जिससे मॉनिटरिंग ठीक तरह से हो सके। मैं राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी आपके यहां भी यह समस्या होगी, यह समस्या हमारे यहां भी है और सदन के सम्मानित सदस्य भी इससे जूझ रहे हैं। गांव में पीने का पानी आज भी नहीं है। आजादी को 60 वर्ष हो गए हैं, मैं अपनी कांस्टीटुंसी में अभी घूमकर आया हूं, मैं बराबर जाता रहता हूं वहां आज भी महिलाएं दो किलोमीटर दूर से सिर पर पानी लेकर आती हैं। हमारी बेटियां, बहुं और गांव की औरतें दूर से पानी लेकर आती हैं, इससे बड़ी शर्म की बात हमारी सरकार, हमारे और इस सदन के लिए क्या हो सकती है। मैं पिछले सप्ताह शनिवार और रविवार को गांव को दौरे पर था, बहुत से लोगों ने बताया कि एक बाल्टी पानी पांच किलोमीटर दूर से लाते हैं, जिसका पैसा दस रुपए दिया जाता है। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद ऐसा हो रहा है। इस बजट में करीब 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान पीने के पानी के लिए रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी को अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, हमारे यहां बारह ब्लॉक हैं, उनकी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार में भेजी गई हैं लेकिन चार साल में एक भी योजना की स्वीकृति नहीं मिली है, एक पैसा नहीं मिला है। जो योजनाएं स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में बनी थीं जिसे जल निगम का स्वरूप दिया गया था, तीन गांवों को एक योजना से जोड़ा गया था, इसके लिए वहां से जवाब मिला है, उत्तर प्रदेश सरकार के पेयजल विभाग, जो राजीव गांधी की योजनाओं को बैठकर देख रहे हैं, हमारे यहां से जो अफसर गए उनको कहा गया कि पांच हजार से ऊपर की जनसंख्या के गांवों को पानी दिया जाएगा इससे नीचे की जनसंख्या के गांवों को पानी नहीं दिया जाएगा।[r60]

उसमें उन्हें 25 परसैन्ट की भागीदारी करनी होगी, उधर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसमें भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के लोग, वहां के अधिकारियों द्वारा बनी हुई योजनाओं को वापस करते हैं। इसके कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। चार साल में एक भी योजना को एक पैसा तक नहीं मिला। इसके अलावा प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं में करीब 7530 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार का हृदय से आभारी हूं कि मेरे जिले में करीब 400 किलोमीटर सड़कें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी हैं। मगर मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां की सड़कों की क्वालिटी बहुत खराब है। 22 लाख रुपये प्रति किलोमीटर एक सड़क के लिए दिया जाता है। यदि आप वहां जाकर देखें तो उत्तर प्रदेश के वे ठेके हमारे यहां आर.ई.एस. विभाग देखता है। ये काम उसके द्वारा किये जाते हैं। उनके अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं। इस बारे में जिला प्रशासन को कई बार कहा गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि माननीय मंत्री जी से मैंने इस बारे में शिकायत की तो केन्द्र सरकार की तरफ से आपके विभाग की एक टीम वहां गई। मेरे पास वहां से एक ठेकेदार का फोन आया और उस ठेकेदार ने कहा कि मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मगर हम लोग पचास लाख रुपये का चंदा करके इस टीम को दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि जो टीम वहां पर निरीक्षण करने के लिए गई थी, वह पचास लाख रुपये लेकर वापस आ गई, आखिर कौन इसकी देखभाल करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम हमारे यहां विधान सभा के पांच क्षेत्र हैं। वहां पर एक हजार हैंडपंप दिये जाए। क्योंकि अब चुनाव में एक साल रह गया है, चुनाव में हम लोगों को क्या जवाब देंगे, जिन्हें हम पानी मुहैया नहीं करा सके। भारत सरकार ने पैसा रखा है, परंतु प्रान्तीय सरकारें उसमें सहयोग नहीं कर रही हैं। इसलिए मंत्री जी से आग्रह है कि आप वहां केन्द्र की टीम भेजकर वहां अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करायें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती परमजीत कौर गुलशन जी, आप बोलिये।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में केन्द्र सरकार के पैसे की नेमप्लेट माननीय संसद सदस्यों के नाम से लगे, ताकि लोगों को पता लगे। हमारे प्रदेश में माननीय मायावती जी, जो वहां की मुख्य मंत्री है, उनके द्वारा इस सारे पैसे को अम्बेडकर गांव में दिया जा रहा है। इंदिरा आवास के नाम पर कहा जा रहा है कि यह प्रान्तीय सरकार की योजना है, इसमें हरिजनों को आवास दिये जा रहे हैं। वहां जो पेंशन दी जा रही है, वह भी प्रान्तीय सरकार अपने नाम से दे रही है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह प्रचार-प्रसार के द्वारा केन्द्र सरकार की योजनाओं और उसके कार्यों को पूरे जोरशोर से लोगों में फैलाने का कार्य करें। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing more will be recorded

*.(Interruptions) â€¦ **

- Not recorded.
- *SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (BHATINDA): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Demands for Grants for the year 2008-2009 pertaining to the Ministry of Rural Development.

Sir, there are many shortcomings in various programmes launched by the Central Government for rural development. I would like to draw the attention of the Hon. Minister towards these shortcomings. I also appeal to him to rectify the errors in these programmes.

Sir, more then 70% people living in the villages of our country are leading a life of hunger, poverty and deprivation. In the villages, there is no health-care, no electricity, no facilities for good education, no drinking-water facilities, no sanitation facilities and no road-connectivity. Sir, I would specially like to point towards the lack of pure and non-contaminated drinking water facility. On what basis can the Government claim that India is moving forward on the path of development? Without the development of our villages, we cannot claim to make real progress.

Of course, the Government has chalked out various schemes for the welfare of the rural poor. But, is the benefit of these programmes reaching the needy? Sir, if you provide water to a field, and instead of reaching the roots of the plants, if that water is squandered elsewhere, it does not serve the purpose. The implementation of these programmes is flawed.

For instance, let us take the case of BPL families. Time and again, we have exhaustively discussed this issue in this august House. Lacuna in its implementation has been repeatedly pointed out. However, the Government has failed to rectify its errors. Genuine people have been kept out of the purview of this programme meant for BPL families.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

Sir, all states cannot be equated as far as implementation of programmes is concerned. Different states have different problems. Culturally and economically, Punjab is different from Bihar. Only 10% people of Punjab have been included in the BPL list. It is due to the faulty yardsticks adopted by the Government. There are 52 points to identify a BPL family. These include : a family should not own a fan or a fridge. Sir, when the heat wave sweeps the country, even the poor people try to get hold of a fan. How else will the poor people survive in the searing heat of 45 degrees and beyond?

So, the norms and standards used to identify BPL families are faulty and far removed from reality. Fans and cold water have become the basic facilities needed by everyone.

Also, Sir, Panchayat members have been granted the power to identify BPL families. As a result, names of genuine people have not been included in the BPL list. Lot of politics is involved in this exercise. The village headman belongs to a particular party. He tries to include the names of his supporters and sycophants in the BPL list. Bogus people are included in this list. There should be a review of this entire scheme. The process of identification of BPL families should be simplified. The different conditions prevailing in different states should be kept in mind while fixing the norms pertaining to this scheme. Much water has flown down the Ganges since the UPA Government tried to implement the National Rural Guarantee Scheme. 4 years have passed but the UPA Government has failed to implement this scheme throughout the country. Wherever it has been implemented, it has been an utter failure.

It was announced that the scheme will be fully implemented soon. However, due to Panchayat and Zila Parishad elections, it was put in cold storage. Now, the Parliament elections are also round the corner. As a result, this scheme is bound to flop.

The Government provides only Rs.102/- as daily wage to one member of a poor family for 100 days. However, the poor person can easily get Rs.150/- to Rs.200/- as daily wage in Punjab. As such, he cannot benefit from Rs.102/- doled out by the Government. The Government should increase the amount given to the poor people as daily wage under this scheme. Village headmen should not be given the power to identify BPL person. Instead, a committee comprising of all political parties should discharge this function.

Many a time, thumb-impression of the poor people are taken on the paper that claims to pay Rs.102/- to them. However, actually, they are paid only Rs.50/-. All these malpractises must stop. 60% money under this scheme is provided for payment of wages and 40% is provided as material cost for the equipment purchased. This ratio should be 50:50 and not 60:40.

Also, many works are excluded from this scheme. For instance, in Punjab, cleaning of water-works is needed. Why is this work not included under the Employment Guarantee Scheme? Sir, the need of the hour is to review this entire scheme and make it more people-friendly.

There is no monitoring of this scheme. How many people the family get to work for how many hours a day under this scheme? The Government has no data or statistics regarding these points.

Sir, under the Indira Awas Yojana, Rs.25,000/- is paid by the Government for construction of houses in the rural areas. This is a cruel joke played by the Government on the poor people, Rs.25,000/- is a drop in the ocean. You cannot construct a house in this meagre amount. I appeal to the Government to increase this amount to at least rupees 2 lakhs.

Sir, the Government pays Rs.600/- to the poor people in the rural areas for construction of latrines. But, the bricks used for this purpose cost Rs.1000/-. So, this is another cruel joke played by the Government on the poor people of rural areas. Punjab Government is paying Rs. 7800/- to BPL families and Rs.6800/- to non-BPL families. Under these circumstances, Rs.600/- is a pittance. It needs to be increased.

Sir, there is a dearth of clean drinking water in the villages of Punjab. The water that is available is contaminated with carcinogenic compounds. It leads to cancer. If a survey is conducted in Mansa and Bhatinda, it will come to light that every third family has a cancer patient. It is due to contaminated drinking water. So, I appeal to the Government to install submersible water-pumps in the villages and houses of poor people and Dalits, and in all educational institutes of the area.

Sir, the self-help groups in Punjab have failed as they do not get direct marketing facilities. So, I appeal to the Government to generate more employment for the rural poor. Only then can the villages taste the fruits of real progress. Also, the rural people should be made aware of the various schemes launched by the Government. A publicity campaign should be launched through the print and electronic media. Time should be fixed for the telecast of such publicity campaigns on T.V. Also, all programmes for the rural poor should be effectively implemented.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chandra Bhushan Singh - your Party's time has already been exhausted. So, you are requested to speak only for four to five minutes.

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फ़र्रुख़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं मंत्री से कहना चाहूंगा कि आप देश के ऐसे इलाके से आते हैं, जहं की गरीबी की जानकारी आपको अच्छी तरीके से है। आपके विभाग से कई मंत्रालय जुड़े हुए हैं, जब तक ये सारे मंत्रालय आपसे में विचार-विमर्श करके कोई योजना नहीं बनाएंगे तब तक कोई सही नतीजे सामने नहीं आ सकते। अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रेड्डी साहब ने अर्जेनटाइना में भाषण दिया, उन्होंने एक बात कही कि हमारे हिन्दुस्तान की नौ प्रतिशत सालाना विकास दर है। यदि यही विकास दर बनी रही तो खेतिहर और गैर-खेतिहर लोगों में विषमता बढ़ेगी, उनमें दूरियां और बढ़ेंगी। उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक एग्रीकल्चर की ग्रोथ चार प्रतिशत नहीं होगी तब तक हम सही तरीके से इसका क्रियान्वयन नहीं कर सकते।

आप यह भी जानते हैं कि ग्रामीण विकास से तात्पर्य सीधा कृषि से जुड़ता है। यदि कृषि का विकास होता है तभी हम ग्रामीण विकास करने में संभव होंगे। योजना आयोग ने सन् 2005 में जो शुरुआत की थी, उसके तहत उन्होंने ग्रामीण सड़क योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, गृह निर्माण, पेयजल और टेलीफोन, मुख्यत: ये बातें उन्होंने ली थीं। बहुत सारे वक्ताओं ने यह बात कही और मैं भी आपको इस बारे में बताना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी भी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में मौजूद थे, जहां एम.एस. आलूवालिया जी भी थे। उन्होंने एक बात कही ग्रामीण सड़क योजना के तहत गुणवत्ता यदि नहीं आ रही है तो उसके मानक को तय करने के लिए ऐसी कोई योजना क्यों नहीं बनाई जाती कि उसके मानक सही हों। उस पर यह ऑब्जेक्शन आया कि आपको फिर हिन्दुस्तान में ठेकेदार नहीं मिलेंगे। आप दुर्भाग्य की बात देखिए कि प्रधानमंत्री जी यह रिकोमेंड कर रहे हैं कि इसकी गुणवत्ता सुधरे, इसके लिए कोई मानक तय कर दिए जाएं, लेकिन उसके लिए आपको ठेकेदार नहीं मिलेगा।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बीआरओ आपके पास है, जो सारी सड़कें कठिनतम जगहों में भीषण परिस्थितियों में बनाते हैं, आप क्यों नहीं ऐसी योजना लाते कि जहां ठेकेदारी की प्रथा खत्म हो और आप ही उस सड़क को बनवाएं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप गुणवत्ता नहीं पा सकते। आपको गुणवत्ता तभी मिलेगी जब आपका अपना विभाग हो और काम करने वाले लोग आपके हों। आपकी शुरु के दो साल में सड़क निर्माण की जो स्थितियां थीं, आपका 50647 किलोमीटर का टारगेट था और उसके तहत आपने मात्र 39 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई थीं। इसी तरीके से इंदिरा आवास, जो गृह निर्माण की बात है, उसमें भी यही बात रही। आपको 60 लाख मकान बनाने थे, लेकिन 28 लाख मकान आपके बने। आपकी जो इंदिरा आवास योजना है, इसमें मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: छ: बज गए हैं, मेरा ख्याल है कि बार-बार समय बढ़ाने की बजाए जितनी देर तक बिजनैस खत्म नहीं होता तब तक टाइम बढ़ा लिया जाए तो अच्छा रहेगा।[s61]

18.00 hrs.

श्री चन्द्रभूषण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंदिरा आवास योजना के बारे में बता रहा था। हमारे बहुत से साथियों ने कहा है कि इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत सहायता राशि को 25 हजार से 35 हजार और 35 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया जाए। इस तरीके से काम बनने वाला नहीं है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि देश में दूर-दराज के ऐसे बहुत से इलाके हैं, जहां कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडीचर ज्यादा पड़ता है। जब वह ज्यादा बढ़ेगा, तो नैचुरली आप 50 हजार रुपए में भी मकान नहीं बनवा सकेंगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और जितने दूर-दराज के इलाके हैं, उनमें आपको इंदिरा आवास का पैसा उसके अनुकूल तय करना चाहिए, तभी आपकी यह योजना सफल हो सकती है।

महोदय, अब बात खाद्य समस्या की आती है। देखिए, एक ऐसा समय था, जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे देश की खाद्य समस्या को हल करता था। आज आखिरकार कौन सी ऐसी वजह हुई कि पैडी के प्रोडक्शन के मामले में जो पंजाब फर्स्ट नंबर पर रहता था, वह पांचवें नंबर पर पहुंच गया और जो छत्तीसगढ़ 20वें नंबर पर था, आज पहले नंबर पर है, क्या कभी इस पर विचार किया गया? क्या कभी इस पर विचार हुआ, नहीं हुआ। मैं चूंकि कृषि का आदमी हूं, कृषि पढ़ा हूं और कृषि ही करता हूं, इसलिए सुझाव देता हूं कि फर्टीलाइजर का अधिक इस्तेमाल होने से, हमारी जमीन ऊसर हुई। इसी प्रकार का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके समक्ष देना चाहता हूं। जब कोई आदमी मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ हो, तो फिर उसे चाहे जितने कोरामिन के इंजैक्शन लगाइए, उसे कोई लाभ नहीं होता। आज हमारी जमीन मर चुकी है। इसलिए उसे आप कितना ही कोरामिन दीजिए, उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। क्या वजह है, वजह यह है कि आर्गेनिक कंटेंट्स की जमीन में कमी हुई और लगातार फर्टीलाइजर का इस्तेमाल हुआ। उससे दो नुकसान हुए, हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति कम हुई और उसके नीचे का जो पानी है, वह भी कंटैमिनेटेड हुआ।

महोदय, अभी हमारी पंजाब की एम.पी. साहिबा बता रही थीं कि वहां जमीन के नीचे कैंसर या डिफरेंट डिजीज के कंटेंट पाए जाते हैं। क्या वजह है, इस पर भी आपको गौर करने की आवश्यकता है। इस पर गौर होना चाहिए, अगर गौर नहीं होगा, तो आप निश्चित मानिए कि हम इस पर जितना रुपया खर्च करेंगे, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है कि आपके पास इतना रुपया है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश की सरकारों को आप लगातार हिदायत भी देते हैं, उन पर गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि आपको गरीबी की जानकारी है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा। मुझे दो मिनट की मोहलत दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूं। आज इत्तेफाक से नंबर आ गया, तो बोलने लगा। मैं आपसे एक बात के लिए निवेदन करता हूं कि हैंडपम्प्स के लिए हमारे लोगों नें डिमांड्स की कि एक-एक हजार हैंडपम्प मिलने चाहिए। क्या कभी इस पर भी गौर हुआ कि हमारा वाटर-स्ट्रैटा कहां जा रहा है, क्या वाटर हारवेस्टिंग के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका सही क्रियान्वयन हो रहा है? मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां भूमिगत जल का लैवल चार मीटर डाउन हुआ है। अब से दो साल पहले जितने हैंडपम्प लगे हुए थे, वे सब बेकार हो गए, फेल हो गए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे हैंडपम्प लगवाकर, क्योंकि आप रीबोरिंग के लिए तो पैसा नहीं देते? जिनका इस साल बोर हुआ है, वही लोग तीन साल बाद आ जाएंगे कि साहब हमारा तो हैंडपम्प फेल हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने वाटर हारवेस्टिंग के लिए क्या व्यवस्था की है, क्या आपसे यह रिलेटेड नहीं है, क्या यह ग्रामीण विकास से रिलेटेड नहीं है? जब तक आप इस पर गौर नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे।

महोदय, अब मैं राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के बारे में कहना चाहता हूं। हर गांव को बिजली मिल जाए, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बिजली के खम्बे लगवा देने से बिजली पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया कि हमारे देश की कितनी जरूरत है और कितना प्रोडक्शन है? आज विभिन्न प्रदेशों में बिजली उत्पादन पर अगर आप गौर करें, तो आप पाएंगे कि बिजली उत्पादन बहुत कम हो रहा है। मैं अन्य प्रदेशों के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं कि आज भी वहां 14 घंटे बिजली नहीं आती है। वहां आप क्या करेंगे? खम्बों और तारों पर पैसा खर्च करेंगे?

महोदय, एक बात पर अभी तक कतई गौर नहीं हुआ और यह देश का दुर्भाग्य है कि जब बिजली चोरी का मामला आता है, तो हमारे अधिकारी यह दिखाते हैं कि लाइन लॉसेस हुए हैं। अरे लाइन लॉसेस की भी एक लिमिट होती है। लाइन लॉसेस के बाद भी आखिर क्या हो रहा है? मेरा इस बारे में एक निवेदन है कि नए-नए पॉवर हाउस बनाने के लिए आप इन्वैस्ट करें बजाय इसके कि ग्रामीणों को बिजली देने के लिए खम्बे लगवाएं, क्योंकि खम्बे लगाने से बिजली ग्रामीणों को नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ एक मिनट और लूंगा। मैं खत्म कर रहा हूं। नंबर तो मेरा पहले था, लेकिन दुर्भाग्य से बाद में आया, क्योंकि हमारे एक साथी को पहले मौका दे दिया गया। [r62]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं लिस्ट के हिसाब से ही नाम बुला रहा हूं।

श्री चन्द्रभूÂाण सिंह : मेरी दरख्वास्त है कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जो भी हेण्डपम्प लगाए जाते हैं, उनके पानी की जांच अवश्य करवायी जाए, तभी हेण्डपम्प लगाए जाएं। यह बहुत आवश्यक है। इसके लिए मेरा आपसे विशेष अनुरोध है।

दूसरा, जब तक जनभागीदारी नहीं होगी, तब तक विकास नहीं हो सकता है। माननीय राजीव गांधी जी ने पंचायत राज योजना लागू की थी। लेकिन क्या वजह है कि केरल और मध्य प्रदेश के बारे में वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी कि केवल ये ही दो राज्य हैं, पूरे हिन्दुस्तान में, जिन्होंने सही काम किया है? आखिरकार अन्य प्रदेशों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने वहां जनभागीदारी से कार्य किया। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने बीच की अफसरशाही को खत्म कर दिया। केरल में लोगों को एम्ज़ीक्यूट करने के लिए, सिखाने के लिए सरकार आगे आई। उन्होंने गांव के लिए योजनाएं बनाई, गांव को अपने व्यय बताया। मैं निवेदन करता हूं कि उन्हीं को एक रूप मानकर कार्य किया जाए तो निश्चित ही मैं अच्छे भारत की कल्पना कर सकता हूं।

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : महोदय, मैं मांगों का समर्थन करते हुए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छी नीति और सोच के तहत गांव के लिए काम शुरू किया है। सभी सदस्यों ने प्रशंसा भी की है और मंत्री जी की प्रशंसा करना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी सोच भारत निर्माण योजना के तहत गांव के विकास के लिए है। नरेगा के अंतर्गत जब देश के सभी जिलों को ले लिया गया, तो मैं समझता हूं कि जिस रूप में नरेगा के लिए बजट में जितना प्रावधान होना चाहिए था, ग्रामीण विकास के लिए जितना पैसा मिलना चाहिए था, वह आंकड़ों के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से और ज्यादा बजट एलोकेशन बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, इसमें बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जिन पर सुझाव देना मुनासिब लगता है। नरेगा बहुत ही अच्छी योजना है। एक तरफ बेरोजगारी दूर होगी और दूसरी तरफ देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां इसका प्रतिशत बहुत कम है। आंकड़ों के हिसाब से बिहार में इसकी प्रगति बहुत कम है। जिस राज्य से हमारे माननीय मंत्री आते हैं, उस राज्य में इसकी प्रगति नगण्य है और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी कम है। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने योजना तय की और राज्य सरकार के जिम्मे इस काम को दिया है। फरवरी, 2005 को प्रधानमंत्री जी ने इसे शुरू किया था। इस योजना का यह तीसरा वर्ष चल रहा है। इसका प्रतिशत इतना कम है कि राज्य सरकार के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठ कर प्रधानमंत्री और विभागीय मंत्री इस बारे में कोई राय नहीं

बना सकते कि इतना कम प्रतिशत क्यों है। राज्य सरकार इसमें सहयोग क्यों नहीं कर रही है?

दूसरी बात यह है कि इसके लिए नियम के तहत जो जॉब कार्ड बनाने हैं, उनमें गड़बड़ियां हो रही हैं और जॉब कार्ड कम दिए जा रहे हैं। जॉबकार्ड में जो गलतियां हो रही हैं, उनको सही करने में काफी वक्त लगेगा।[r63]

तीसरी बात, जो मजदूरों को पेमेंट करने की है, उसमें भी काफी अनियमिततायें हैं। मनमाने ढंग से मजदूरों को पेमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए आपने कानून बनाया, उसे 15-15 दिन बाद भुगतान होता है। जिस उद्देश्य से इस कानून को भारत सरकार ने बनाया, मेज थपथपाकर हम सभी लोगों ने उसका समर्थन किया, उसका मैसेज भी बहुत अच्छा गया, लेकिन जिनके लिए आपने कानून बनाया, सीधा उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उनमें से बहुत कम प्रतिशत को ही इसका लाभ मिल रहा है।

इस कानून का आज भी गांव में बेहतर तरीके से प्रचार नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिया और राज्य सरकार की जो एजेंसी है, बीडीओ से लेकर कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी तक, वह इसे बेहतर प्रचार नहीं दे रही है। इस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। यह बहुत चिंता का विषय है। इतनी रकम, इतना बड़ा कानून, इतना बड़ा फायदा, इतने बहुसंख्यकों को लाभ पहुंचाना, परंतु उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। एमपी और एमएलए लोगों को देने की जहां तक बात है, हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकारी एजेंसी को जनता को अवेयर करने के लिए इस पर ज्यादा बल देना होगा।

महोदय, मैं एक दो और बातें कहना चाहूंगा। कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं कहना चाहता हूं कि साठ वर्ष की आजादी वाला यह देश हो गया है और सदन में पानी-पानी गूंज रहा है। पहली बात - पानी नहीं है, दूसरी बात - शुद्ध पानी नहीं है। सारे पैसे यूपीए सरकार गांव के लिए दे रही है, यूपीए की गवर्नमेंट के समय बहुत से काम इतने अच्छे हुए हैं, जो पिछली सरकारों ने नहीं किए। जो लोग खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, फिर भी आज देश के गांवों में पानी नहीं है, यह बहुत चिंता का विषय है। मैं ज्यादा प्रवचन न देते हुए कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की गांव को पानी देने की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए।

भारत सरकार ने जो पैसा शौचालय निर्माण के लिए दिया, सैनिटेशन की बात आप करते हैं कि इतना पैसा जिलों के अंदर जा रहा है, लेकिन शौचालयों का निर्माण नहीं हो रहा है। एक-दो स्टेट जरूर इसके लिए ईनाम लेकर यहां से चले गए, लेकिन देश के पैमाने पर शौचालयों का निर्माण, गरीबों के लिए जिसकी आप बात करते हैं, नहीं हो रहा है। एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और जो बिल्कुल ठीक बात है कि हम शौचालय के मामले में सार्वजनिक भी बनें। गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए आपने कानून बना दिया, लेकिन यह हमारे बिहार में लागू नहीं है, बहुत नगण्य है, लगभग 0.5 भी नहीं है। इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इस पर आपको ज्यादा विचार करना होगा।

महोदय, जहां तक इंदिरा आवास की बात है, इसके लिए भारत सरकार ने कानून बना दिया और कह दिया कि गरीबी रेखा तय हो जाएगी और इसकी सूची टंग जाएगी। उसी सूची के अनुसार इंदिरा आवास का पैसा मिलेगा, लेकिन बिहार में गरीबी रेखा तय नहीं हुयी। वहां गरीब आदमी दौड़ रहा है। उसे पांच हजार रूपए घूस देनी पड़ती है। मैं सदन में बहुत ऊंचा बोल रहा हूं, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। जिस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इतना बड़ा कानून बना कि गरीबी रेखा तय करो और उसी के अनुसार इंदिरा आवास बांटो, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। आज भी गरीबों को परेशानी हो रही है। गरीबी रेखा तय नहीं हुयी है। माननीय सांसद कह रहे थे कि गरीबी रेखा का मानक बहुत गलत है। जो मानक अभी तक बना, मैं मानता हूं कि उसमें और सुधार होना जरूरी हो, तो हो जाए, लेकिन जो मानक बना है, उसे राज्य सरकारें लागू नहीं कर रही हैं। यह बिहार में तो बिल्कुल लागू नहीं हुआ है। बिहार में गरीबी रेखा तय नहीं हुयी। ...(व्यवधान) अमीरी रेखा तय हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी रेखा तय करने के लिए जो आवंटन आपने राज्यों को दिया, माननीय मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए और बात को ऐसे-वैसे नहीं जाने देना चाहिए। इस बारे में सख्ती के साथ बात होनी चाहिए कि गरीबी रेखा तय करके समय-सीमा में हमें रिपोर्ट दो। जो धन भारत सरकार की ओर से हम दे रहे हैं, आप उसे बांटने का काम कर रहे हैं। हम धन दे रहे हैं, आप तो केवल परोसने वाला काम करने वाले हैं। हमारा धन गरीबों तक पहुंचा दीजिए। वह हमारे राज्य बिहार में लागू नहीं हो रहा है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि आप बिल्कुल पथरीली जमीन को सुधारेंगे, खेती योग्य बनाएंगे, गरीबों के बीच बांटेंगे और बेहतर परफार्मेंस करेंगे। देश में अभी कितनी जमीन बंजर पड़ी है, क्या सरकार के पास इस बारे में रिकार्ड है। आपने एक साल में इसे कितने प्रतिशत लागू किया, कितनी भूमि को खेती योग्य बनाया और आगे कितनी जमीन को गरीबों के बीच खेती करने के लिए बांटेंगे। मेरा सुझाव है कि कम्प्यूटर के युग में, इंटरनेट के युग में पहले लैंड रिकार्ड बनाइए, सिर्फ इस प्रोग्राम मात्र को देने से काम नहीं होगा, इसे आपको सर-जमीन पर ले जाने के लिए सिस्टम में लाना पड़ेगा, तब आप इसे आगे बढ़ाएं तो बेहतर काम कर सकेंगे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पौने पांच मिनट की बात करते थे।

श्री सीताराम सिंह : प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क के काम में जो एजेंसियां लगी हुई हैं, उन्हें थोड़ा और मजबूती और तीव्रता से काम करने के लिए दबाव बनाने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Sir, I rise to support the demands for Grants in the Ministry of Rural Development for the year 2008-2009.

Rural Development occupies place of pride in the process of economic development of India. Despite faster urbanization in the country over the past 60 years, India still lives in villages. A projection report of UN has opined that though most countries would see rapid urbanization. India would continue to leave the longest rural population in the world until 2050.

Therefore, the hurdles of the Government lie in rural development. Development is not merely a proven of raising the perception or national income but of developing people or enhancing the welfare of the people, especially, the poor, weaker section, SC, STs, OBCs and women. Poverty alleviation through income generation is the surest way of promoting rural lives. Provisions of basic opportunities such as water, road, electricity, education, health, sanitation can also strengthen the lives of the people.

Realizing the above rationale, the UPA Government under the leadership of Dr. Manmohan Singhji and guidance of Madam Sonia Gandhiji has launched a number of flagship programmes in the area of income generation and augmentation of basic facilities to the people. True to its commitment made in the common minimum programme, the Government implemented the National Rural Employment Guarantee Programme in 200 rural districts in 2006; extended it to another 130 districts in 2007 and to all remaining districts further april 2008.

NREGP is really or revolutionary programme and no country in the world a programme of such a scale as NREGP is implemented. This programme translates the rights of employment as a legal right and any rural household member who is prepared to do unskilled work is assured of it for 100 days in a year earning about Rs 8000 per year. This Programme over a period of time, improving the rural people, would help to eradicate poverty in rural areas.

---

* Speech was laid on the Table.

The Swarajayanti Gram Swarozgar Yojana, through self help groups helps to generate self employment and income to rural people. This will also help to eradicate poverty. The Indira Awas Yojana by providing houses to the people would help to solve the problems of shelterlessness in rurual areas. The scheme of Provision to urhau Amenitites in rural areas (PURA) would strengthen the growth potential in rural cluster and thereby steen rural urban migration. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana(PMGSY) would provide road connectivity in rural areas. Integrated water lands Development Programme and land reforms Programme would also contribute to rural development.

The above mentioned programmes of rural development would require sufficient funds for their implementation. The Hon'ble Minister of Rural Development has come before the house for the approval of Rs 31,524.05 crores as budgeted outlay. Investment in public enterprises would be about Rs 7000 crores and the Central Plan outlay would be Rs 38,500 crores. In all, the expenditure of the rural development for this year would be Rs 77,024.06 crores and I am happy to approve this demand for grants.

While approving these grants, I wish to draw the attention of the Minister to some of the important aspects of implementation.

The implementation of NREGP in some districts has attracted audit objections and revealed deficiencies. These should be carefully analyzed and remedial measures later improve the programme. The involvement of reported NGOs and external agencies in the implementation of the scheme and strict action against the corrupt and guilty can stem the mismanagement of the programme.

In the case of self employment through SHGs, adequate attention should be paid to link credit with SHGs and marketing and technological support to SHGs. SHGs should be encouraged to produce more goods and services and they should be marketed promptly.

There should be proper coordination between all schemes of rural development like NREGP Barath Nirman, Sarvashiksha Ahyan, National Rural Health Mission etc. A logistic approach to rural development should be our endeavour rather than taking isolated action. There should also be coordination between elected representatives and social representatives represented by NGOs in the implementation of schemes.

All schemes should be properly monitored and evolutionally competent external agencies so that we are able to get maximum advantage.

We should set up an effective mechanism dedicated to rural development programmes from state to panchayat levels. Rural development should focus on creating move employment opportunities in the non form sector.

There are huge unspent colonies under various schemes of rural development in the past. This has to be avoided. The monthly expenditure plan (2007-08) has not been followed. There is one urgent need for strengthening the expenditure monitoring machinery with the latest technology.

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): महोदय, ग्राम विकास के कुछ मुद्दों पर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं पेज नम्बर 7 ऑफ दी रिपोर्ट ऑफ दी स्टैंडिंग कमेटी आन रूरल डैवलपमैंट से कोट करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमें जो कॉपी मिली, उसमें ग्राम विकास के लिए जो आउटले दिया गया है, मैं चंद वाक्य आपके सामने उपस्थित करूंगा:-

> "In 2007-08 and 2008-09, the allocation provided is not proportionate to the outlays approved for the Eleventh Plan. During the first two years of the Eleventh Plan Rs.59,000 crore, just 30.2 per cent of the total outlay of Rs.1,94,933.28 crore, has been allocated; whereas the proportionate allocation during the first two years should have been 40 per cent of the total outlay, Rs.77,973 crore which means that Rs.18.973 crore less have been allotted during the first two years of the Eleventh Plan."

ग्राम विकास मंत्री गांव, गरीब और किसान के संबंध में हमेशा बात करते हैं, मगर आउटले कम क्यों हुआ, इस संबंध में उन्हें खुलासा करना पड़ेगा। कमेटी ने रिकमैंड किया:-

> "The Committee strongly recommends to the Department to provide the allocation commensurate with the requirements under different schemes as proposed by the Department with a view to ensure inclusive growth so that the benefits of the growing economy are shared by the poorest of the poor in the country."

इस सरकार का सम्पूर्ण ध्यान ग्राम विकास की तरफ नहीं रहा है, यह इससे साबित होता है।

मैं दूसरे मुद्दे के बारे में कहना चाहता हूं और वह अनस्पैंट बैलैंस का है। हमें यह देखना होगा कि 31.12.2007 तक अनस्पैंट बैलैंस के संबंध में कमेटी ने क्या कहा। 11,430.78 करोड़ रुपये अनस्पैंट बैलैंस छोटी-मोटी रकम नहीं है। यह विभाग कैसे चल रहा है, यह इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है।[N64] इसमें राज्य भी अवलम्बित हैं और केन्द्र सरकार भी है। इनका मॉनीटरिंग सिस्टम ठीक नहीं है इसलिए कमेटी इस पर कहती है--Committee have repeatedly - the word used is `repeatedly' - been expressing concern over huge unspent balances under various schemes of the Department. As per the information provided by the Department, Rs.11,430.78 crore is lying unspent under different schemes as on 31.12.2007. मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। माननीय मंत्री जी को इसका खुलासा करना चाहिए। आगे कमेटी कहती है--

"The Committee while expressing a serious concerned over the huge unspent balances, would like to strongly recommend that the Government should analyse the position, State-wise, and take the corrective action accordingly. Besides, focused attention need to be given to the backward States like Uttar Pradesh, Bihar and others. There was mention about recurring features, etc." मैं चाहूंगा कि इसके क्या कारण हैं, इस संबंध में माननीय मंत्री जी खुलासा करेंगे।

The Committee feel that there is an urgent need to strengthen the expenditure monitoring machinery with latest technology so that the expenditure progress reports and the proposals are achieved from the implementing agencies in time.

माननीय मंत्री जी, स्टैंडिंग कमेटी के वेरीयस अलग-अलग पैराग्राफ्स हैं। मैं बाकी पैराग्राफ की डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि समय कम हैं। आप डिटेल्स में जाइये। इतनी बड़ी कमेटी, 35 लोगों की स्टैंडिंग कमेटी, जिसे इस सभागार ने बनाया है, उस की सिफारिशों पर आप विचार नहीं करते। उसमें आपका डिपार्टमैंट कोई बदलाव नहीं करना चाहता। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि यह बात अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। मासिक आधार पर नापी गयी अपर्याप्त भोजन की समस्या के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैं जहां से आता हूं--गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया आदि जिलों में 80 हजार से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं जिसमें फर्स्ट स्टेज के भी बालक हैं और फोर्थ स्टेज, जो बिल्कुल मरने की स्टेज पर हैं, वे पांच हजार से ज्यादा बालक हैं। क्या यह राज चलाने का तरीका है? क्या यही देश चलाने का तरीका है? आप अनाज देते हैं लेकिन वह जाता नहीं है। मैं कई गांवों में गया हूं। इस बारे में टेलीविजन पर सारा दिखाया गया है। हम आंगनवाड़ी में जो अनाज देते हैं, जो पकाया हुआ भोजन देते हैं, उस गांव में चूल्हा भी जला हुआ नहीं दिखा। मेरे पास इसके फोटोग्राफ्स हैं। अगर आप बाद में समय दें, तो मैं वे फोटोग्राफ्स आपको दिखा सकता हूं। इसलिए मेरा कहना है कि भोजन का इंतजाम कुछ राज्यों में अच्छा है। हमने गुजरात में देखा है। वहां भोजन की व्यवस्था अच्छी है मगर मैं महाराष्ट्र से आता हूं वहां मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए भोजन का पैसा ग्राम विकास या महिला बाल कल्याण द्वारा पूरा जाता है।

भारत निर्माण के अंतर्गत पेयजल के संबंध में व्यवस्था की जाती है। शुरू से ही इस देश में कहा गया कि रोजी-रोटी, मकान ,पीने का पानी आदि पांच बातें गांव की दृष्टि से प्रमुख हैं। अब पेयजल के संबंध में पैसा बहुत खर्च किया गया। पेयजल की व्यवस्था के लिए पैसा खर्च नहीं किया, ऐसा मैं नहीं कहता, मगर मैं कहना चाहता हूं कि क्या गांव को पेयजल मिला? जो पेयजल से वंचित बस्तियां हैं, वहां क्या शुद्ध पानी मिला? हमारे यहां हस्तीपाई रोग बड़े पैमाने पर है। अंडकोष वृद्धि का रोग है, जो इसके कारण पनपता है। कुछ रोग पानी के कारण आते हैं। इसलिए क्या आप लोगों को मौत की कगार पर ढकेलना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। पीने का शुद्ध पानी अगर हम 60 वर्षों के बाद भी नहीं दे सकें, तो मुझे लगता है कि सदन के सारे सदस्यों का सिर शर्म से नीचे झुक जायेगा। इस संबंध में हम केवल पैसा खर्च करते हैं, हमारी केवल इतनी ही जवाबदारी नहीं है। हमारी जवाबदारी लोगों को पानी देने की है। इस देश में 72 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं। इस संबंध में जनवरी, 2006 में एक पृथक मंत्रालय भी बना। मगर जो बचतघर बनाये गये, मेरे पास गोंदिया जिले के बचतघर की एक रिपोर्ट है। वहां आपका भेजा हुआ अधिकारी है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक-एक एजेंसी ने, एनजीओ ने एक-एक हजार बचतघर बनाये हैं। हमने वहां पर एज-ए-चेयरमैन, आपने जो कहा, उस आधार पर आठ बचतघर बनाने वाले एनजीओज को सस्पेंड करने के लिए कहा।[MSOffice65] अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग साल में तीन-चार बार वहां मीटिंग करते हैं, मगर प्रत्यक्ष में, जो व्यवहार में आना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इनके पास कोई मॉनीटरिंग सिस्टम नहीं है। इस कारण राज्य सरकारें मनमानी करती हैं। बचतघर में बैंक्स फाइनेंस करती रही हैं...(व्यवधान) यह वस्तुस्थिति है।

महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण विषय स्वरोजगार देने का है। यह कार्यक्रम फेल हो गया है। भंडारा में जहां मैं एक मीटिंग में गया था, वहां वर्ष भर में केवल 70 लोगों को स्वरोजगार मिला। खुद मेरे गोंडिया जिले में, जहां से मैं आता हूं, केवल 1700 लोगों को रोजगार मिला। लोगों के कार्ड बन गए, मगर प्रत्यक्ष में रोजगार देने की बात होती ही नहीं है। इस संबंध में जो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है, आप उसे देखिए। कमेटी ने कहा कि रोजगार देने कौन देता है। इसके लिए वहां रोजगार के लिए जो सेवक नियुक्त किया है, वह कार्यवाही करेगा, लेकिन वे करते ही नहीं। गांव का सरपंच, तहसीलदार और बीडीओ तब रोजगार देते हैं, जब एक हजार काम मंजूर हो जाते हैं। आपने इसको 600 जिलों में बढ़ा दिया, बताने के लिए बड़ा माहौल खड़ा करेंगे, बताएंगे कि हिमालय जैसी योजनाएं आपने शुरू की हैं, मगर प्रत्यक्ष में क्या है? इसलिए जो वस्तुस्थिति है, वह हमें आप बताएं। अगर अभी नहीं बताते हैं तो बाद में पोस्ट से भेजिए कि इस देश के 600 जिलों में से कितने जिलों में आपने स्वरोजगार कितने लोगों को प्रदान किया है।

महोदय, गरीब लोगों को आवास देने के लिए इंदिरा आवास योजना के बारे में बातें कही गयी हैं। सीमेंट के रेट बढ़ गए, लोहे के रेट बढ़ गए, लेकिन अभी भी 28,000 रूपए ही आप देते हैं। उसमे यह हो ही नहीं सकता है, इतने में यह बनना असंभव हो गया है। इसलिए इस रकम को डबल करना होगा क्योंकि रेट दोगुने हो गए, महंगाई दोगुनी हो गयी। आप इसी हाउस में इसको मंजूरी देने के पहले इसे बढ़ाने की घोषणा करेंगे, अन्यथा हम इसका विरोध करेंगे। इसे कम से कम 50,000 रूपए करना चाहिए, जिसकी मांग आपकी पार्टी के सदस्यों ने भी की है। गढचिरौली चन्द्रपुर जिले में कुपोषण से जो लोग मरते हैं, उनके बारे में मेरा कहना है कि एक स्पेशल आईएएस ऑफिसर वहां नियुक्त किया जाए या फिर प्लानिंग कमीशन उसे अपने हाथ में ले। मैं केवल टीका करने या आरोप लगाने के लिए ही यह बात नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, मगर यह हो सकता है कि आपके आस-पास ऐसे लोग हों जो आपको काम करने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए केवल विचारों से काम नहीं चलेगा, उसका इंप्लीमेंटेशन करना होगा। आप बहुत अच्छे हैं, आप गरीबों के संबंध में चिंतित हैं। अगर आपने यह नहीं किया तो देश की जनता दोष तो मिनिस्टर साहब को देगी, रिस्पांसिबिलिटी आपकी भी होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें आप आमूल परिवर्तन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : गांवों में शौचालय बनाने के लिए आप 600 रूपए या 900 रूपए देते हैं, जो कि बहुत कम है। इस पर भी विचार कर लीजिए।

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पहले यह 600 रूपए था जिसे बढ़ाकर अब 1500 रूपए कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : 1500 रूपए भी बहुत कम है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हां, यह कम तो है। मैं जानता हूं लेकिन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैंने यह बात कही है।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : इसे बढ़ाकर 3,000 रूपए किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समझ से यह अभी भी 900 रूपए ही है। आप इसे देख लीजिए।

*SHRI A.V. BELLARMIN (NAGERCOIL): Sir I wish to congratulate the Hon'ble Minister of Rural Development for his untiring and strenuous efforts taken in the matter of development of Rural India.

India lives in villages, this maxims is kept in sprit word and Act while formulating rural schemes and projects. The priorities are also being accurately addressed while exercising the financial allotments. Rural India is beginning to experience the results of 4 years of renewed efforts in the matter of infrastructural developments such as Rural Housing, Rural Roads, Sanitation, Electricity , Watersheds and Irrigation etc. of late various projects are being implemented and many more are in offing to make even the remotest village of India taste the fruits of Modern High Technological Developments.

Despite all these achievements to the credit of the Govt. there are still certain areas to which the pointed attention of the Ministry is to be focused. The first and foremost one is the Tardy allotment of the amount for the schemes. Constricting Houses under IAY. Say Rs. 37500/- including state share is a poultry some it should be considerably increased to Rs. 1.50 lac at least to construct a House with a plight area of 400 Sq. ft. It is to be noted such an amount is been allotted in Kerala State. Also the allotments of all Rural Development Schemes should be increased, secondly, the newly introduced scheme which is the pet child of the UPA Govt. the Care should be exercised prudently in identifying and selecting the works under the scheme. Formulations, maintenance and renovation of water bodies should be given preference.

Lastly, the objective of the scheme to provide employment to rural House Hold to be kept in mind while executing the selected work. That is to say direct manual labour should be put into use avoiding contracting system and heavy

---

* Speech was laid on the Table.

mechanisms. Before I conclude I would like to invite the attention of the Govt. towards a fact of serious concern. It is authoritatively reported that in most part of the country. Paise 17 only reaching out to the target end out of the allotted.

1 Rupee under the various development schemes. The grounds involved in the filferage of 83 paise should be probed into. A suitable mechanism with prosecuting powers should be constituted to moniter and keep in vigil upon the spending over the schemes. So that the peoples money reaches out to the people in full.

*SHRI.RAVICHANDRAN SIPPIPARAI (SIVAKASI) : Father of the Nation Mahatma Gandhi said, "India lives in its villages". In order to realize that dream to bring about a change in the lives of those who live in our rural areas and to enhance the standard of living of about 70% of our population living in our villages and also to improve the living condition of those who live below the poverty line, Union Ministry of Rural Development has been apportioned fund allocation. I would like to point out that it is not adequate and not at all enough.

The tax revenue of the Union Government has increased in the past year to the tune of 25.12%. But the Union Ministry of Rural Development that has got to improve the lot of 70% of our population has got its allocation increased by a mere 10.52%.

National Rural Employment Guarantee Act was implemented in 330 districts of the country while the remaining districts had SGRY implementation. Now both the schemes have been merged and introduced in all the 604 districts in the country from the first of April this year. But a mere Rs.200 crores have been allocated to meet the additional requirement and that

may not be sufficient. It is a sorry state affairs. Hence I urge upon the Government to allocate more funds for this scheme.

Similarly the fund allocation for Rural Development during the Eleventh Five year Plan period is less by Rs.18,973 crores. A scheme that has given rise to great hopes has been allotted with inadequate funds. I have a doubt whether we would be able to achieve what we aim at.

Seven hours of hard physical labour in the open on the dry lands in the scorching heat would prove tedious. Round the year the toil and moil for all the seven hours rendering labour is a heavy burden. Such rural agricultural labourers

---

* English transalation of the speech originally delivered in Tamil.

who get paid on a task oriented basis must get enhanced wages and duration of work hours must be reduced to 6 hours. There is also no uniformity through out India and the conditions vary from state to state. In Kerala, such labourers get Rs.125/-. But in Tamil Nadu where there is much of publicity to this scheme the rural labour get only Rs.80/- as minimum wages. Hence I urge upon the Government to increase it to Rs.125/- as uniform wages through out a country. I would like to point out that this anomaly must go.

About four crores of people have got identity card under this scheme. These job card holders must be extended with social security cover including insurance cover. Long term permanent activities like laying of roads and construction of buildings have been given a go by and jobs temporary in nature are taken up under this scheme. Additional jobs on long term basis must be identified under this National Rural Employment Guarantee Scheme which needs to be streamlined.

Indira Awas Yojana is a useful scheme for which an allocation of only Rs.5400 crores have been made whereas Rs.8000 crores of rupees was expected to be allotted for this scheme. The grants under this scheme has been increased from Rs.25000 to Rs.30000 and in hilly areas this has been enhanced to Rs.27500 from Rs.38500. In some states further increased grants are paid to the beneficiaries of the scheme. Prices of cement and steel has increased today. In Tamil Nadu cost of construction materials like sand have increased three fold. It is just not possible to construct a house measuring 210 sq. feet even at a cost of rupees one lakh. The hope for a house construction should not end up as a dream for the poor. Hence I urge upon the Government to increase this allocation for the Indira Awaz Yojana. It is also necessary to ensure that such earmarked funds reach the needy fully with out being pilfered.

At least half of the women population of this country are benefited from the women self help groups. This good scheme must be utilized properly to improve the conditions of women. Such women who join such SHG's are extended with loans on rotational basis in the be ginning and some get financial assistance. But efforts at co-ordinating both the training and infrastructure facilities are not there. Well Co-ordinated measures are necessary to ensure proper utilization of allocation funds.

We have known of tropical line and equatorial line but no one knows fully about the poverty line. The BPL figures identified in 2002 ought to have been updated in 2007. But it has not been done yet. Hence there is a confusion all over the country in identifying people living below the poverty line. Hence I urge upon the Government to prepare exact data of people living below poverty line.

There is a good Minister for this Ministry which aims high. But he has not got adequate budgetary support. Recording this anguish of mine, let me conclude my speech,

18.35 hrs (Mr. Speaker *in the Chair*)

SHRI K.V. THANGKABALU (SALEM): Mr. Speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants for the Ministry of Rural Development for the year 2008-09. While we debate and discuss about the various programmes under the Ministry of Rural Development and the Demands of this Ministry, I would like to take this opportunity to bring to the notice of this august House the great contributions made by the late Indira Gandhi in this regard. Her *Garibi Hatao* slogan and the programmes associated with it were one of the most important milestones in the history of the development of rural India. It was the programmes enunciated by her under *Garibi Hatao* that led to the foundation for all the developments that have taken place

in this respect over the years. Again, after her, the late Rajiv Gandhi carried on with those programmes and now due to the initiative and effort of the UPA Chairperson and our reverend leader Shrimati Sonia Gandhi, the programmes have found a new boost, particularly under the Bharat Nirman programme. Also, the NREG programme came into being because of her directions to the UPA and the nation.

From this year the scope of NREG has been enlarged and from 200 districts the number has been increased to 596 districts. Under this scheme, a member from each and every household in the rural area, those who are poor and marginalized, would have guaranteed work for 100 days in a year. In no country of the world such a scheme has neither been contemplated ever, nor is in vogue. Owing to the rural poor and marginalized households getting guaranteed work for 100 days in a year, the poorest of the poor in the country are being benefited. The scope of the scheme has been enlarged to cover all districts in the country because of the effort made by the young General Secretary of the Congress Party, Shri Rahul Gandhi met the hon. Prime Minister along with his other young colleagues and made a demand that the entire country should be covered by this scheme. Today the scheme is being implemented all over the country with great vigour.

Sir, I would like to inform this august House that around 3.23 crore of households were covered under this scheme in the year 2007-08 as against 2.20 crore households in the previous year. These many people have benefited out of this programme. Now with the scope of the scheme being enlarged, a sum of Rs. 16,000 crore has been earmarked for this scheme. There were a few problems here and there at the start of the scheme. This is quite natural as any new programmes will have some initial problems. But this programme is working very well, though some of our friends and also people in the rural areas are asking for raising the amount from Rs. 80 per day as they consider this amount to be insufficient to meet the needs. So, I would like to appeal to the hon. Chairperson of the UPA and also to the hon. Minister of Rural Development to consider raising this amount from Rs. 80 per day to Rs. 125/- per day. That will be good. [R66]

I do not want to go into too many details of other areas. Another important area is drinking water. Again, I want to inform the House on this point. Our friends on the other side said that we have not done enough for the people. We have done maximum for the people compared to the NDA Government. In the last four years of their rule, Rs. 8505 crore were earmarked for this sector. But under the UPA Government, under the guidance of our beloved leader, Rs. 18,030 crore have been earmarked. This is our achievement. This is the programme under the Eleventh Plan and Rs. 39,490 crore has been earmarked for it. Our Finance Minister has announced that the Rajiv Gandhi Drinking Water Mission will have enough funds as and when there will be a requirement and there need not be any worry about it. But at the same time, there is another issue which is important, namely, housing for the poor. The Indira Awas Yojana has been one of the noble schemes which have been implemented. Last year, about 51.77 lakh houses were built as against 41 lakh houses.

Coming to subsidy, we have increased the subsidy from Rs. 12,500 to Rs. 15,000 to every beneficiary. Then, the increase from Rs. 25,000 to Rs. 35,000 is not enough. In today's condition, under the Indira Awas Yojana programme, at least it should be made as Rs. 75,000 per house and only then, the poorest of the poor will be getting the benefit. This is due to the price rise today.

Another point is, in the Budget speech, our hon. Finance Minister had announced that an additional amount upto Rs. 20,000 will be given to people with four per interest for the purpose of loan. Instead of giving Rs. 20,000, it should be added in the component itself.

Regarding the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, this is another important programme where all the roads are connected and the rural areas are linked to the main cities. We would like to see that this programme should be implemented with more vigour. In fact, we, MPs, used to go to the rural areas and discuss with the district officers regarding this programme. Every year, there is damage of roads which should be contained immediately. The national programme should be remodified and we should see to it that, under the road development programme, when a road is laid, it should work for at least 40 years as per norms. But nowadays, it is not even working for two or three years. And during rain, the road gets damaged. This should not happen. There should be strict vigil on the part of the Central Government and directions should go to all the State Governments in this regard. The State Government should implement it in a rational way. Only then, the roads which are built with a noble cause will be in a good condition for the welfare of the people of this great land.

The other issue is about SJSY. We have integrated all the programmes under IRDP and this programme is now giving weightage to the vulnerable sections of the society, that is, 50 per cent of it goes to the SCs/STs, 40 per cent goes to women and 3 per cent goes to the disabled. Under this programme, maximum component, that is, the subsidy component, comes to Rs. 7500 and it should be increased to Rs. 10,000 because this is meant for the poorest of the poor, vulnerable sections of the society, that is, the SCs and STs. They should get the benefit of this programme.

Likewise, regarding SHGs, today, we are going to integrate 30 lakh SHGs with the insurance policy. It is one of the[MSOffice67] good ideas. Fifty per cent of the people are women in this country. They need more and more benefit. In Tamil Nadu, the hon. Chief Minister has increased their salary, their perquisites. Likewise, I urge upon the Government of India and the hon. Minister to increase the salary of SGH people to at least that of the minimum living standard of Rs. 3,000 to Rs. 5,000 so that they will be able to work among the rural women and that they are empowered. This is another important area. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Thangkabalu, please conclude. There are some new and young Members who want to speak on this.

...(*Interruptions*)

SHRI K. V. THANGKABALU : The SHGs play a very vital role and these SHGs have to be given more weightage by giving them additional support. If the Ministry gives them additional support, the rural poverty will be eliminated because they are the tools. They can go to the people; they can meet the people; and they can popularise the Government programmes. They have good linkages in our country and they should be supported by this Ministry.

MR. SPEAKER: I am sorry I had to interrupt you. All the parties except the Congress have exhausted their allotted time. Even then I have a long list of Members who want to speak. I am sorry I cannot accommodate them. Already we have spent more than six hours on this discussion.

...(*Interruptions*)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Sir, we have been sitting so long. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: So kind of you. It is your job. It is everybody's job to sit here. No charity is done to anybody. Thank you for your patience.

Those hon. Members who wish to lay their written speeches on the Table, they are welcome to do so.

श्रीमती करुणा शुक्ला (जॉजगीर) : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी और अपना वक्तव्य आपके आदेशानुसार ले करूंगी। आज सदन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। राÂट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी के समय कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यह गहन भी है और गम्भीर भी है जिस की प्रासंगिकता हम 60 साल बाद भी महसूस करते हैं। आजादी के तत्काल बाद राÂट्रपिता महात्मा गांधी की भावनाओं का सम्मान किया जाता तो आज देश में यह हालत नहीं होती। आज हमें पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है, ग्रामीण महिलाओं को शौचालय उपलब्ध नहीं हैं, जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं वे आज भी टाट-पट्टी पर बैठने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए फर्नीचर नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। भारत की जो तस्वीर हमारे सामने आई है, उस तस्वीर को बदलने का प्रयास माननीय रघुवंश प्रसाद जी कर रहे हैं। उन्होंने भारत निर्माण का एक नया बीड़ा उठाया है। भारत निर्माण का बीड़ा केवल कागजों पर नहीं हो सकता, खाली नेक इरादे और नीयत से नहीं हो सकता। यदि आपको भारत निर्माण करना था तो एनडीए सरकार के समय पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो योजनाएं प्रारम्भ करायी थी, उन पर और धन मुहैय्या कराते, उन योजनाओं पर और मुस्तैदी से काम करके निगरानी करते जिससे वे योजनाएं अंजाम तक पहुंचती और आपके भारत निर्माण का सपना साकार होता।

मैं दो-तीने बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी। देश में 2 लाख 27 हजार 697 ग्राम पंचायतें हैं। क्या आपने इसका कोई मॉडल तैयार किया है? आपकी यहां से योजना गई। किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या एक हजार है, किसी की दो हजार है और कोई ग्राम पंचायत 12 हजार की जनसंख्या से जूझ रहा है। उन ग्राम पंचायतों को आपके यहां से एक जैसा आदेश चला जाता है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान मिल रहे हैं लेकिन वे भी ग्राम सभा में पारित होते हैं और गरीबों को कुछ नहीं मिलता। बिचौलिए इन्दिरा आवास ले जाते हैं जिस की आपने कीमत 25 हजार और 27 हजार रुपए रखी है। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है जिससे लोग निजात नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ इन्दिरा आवास का पैसा कम है। आप उसे कम से कम 50 हजार रुपए करिए ताकि लोग अपना मकान बना सकें और गरीबों को लाभ मिल सके।

एक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है। सम्माननीय सदस्यों ने यहां अपना दुख व्यक्त किया। सांसद के नाते एक नारियल फोड़ने का भी सम्मान अगर सांसदों को प्राप्त न हो तो इससे बड़ा अपमान सांसदों का हो नहीं सकता। सांसदों से सिफारिश नहीं ली जाती है। सांसद क्षेत्रों में घूमते हैं, दौरा करते हैं, वे जानते हैं कि कौन सी सड़क बननी चाहिए लेकिन उनसे आपका विभाग सिफारिश नहीं लेता है। इसमें गुणवत्ता की तो इतनी कमी है कि अगर सड़क दस किलोमीटर बननी है तो केवल पांच किलोमीटर बनेगी और जब बाद की पांच किलोमीटर बनना शुरू होती है तो पहले बनी पांच किलोमीटर उखड़ जाती है, कृपया आप इस पर ध्यान दीजिए। स्वयं सहायता समूह की बहनों को गांवों में काम मिलता है लेकिन उनके लिए बाजार उपलब्ध नहीं है। वे दिल्ली के प्रगति मैदान में नहीं आएंगी। आप उनके लिए विकास खंडों में बाजार उपलब्ध कराएं।

अंत में मैं यही कहूंगी कि आपको विभाग बहुत अच्छा मिला है और आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहना चाहूंगी। आप स्वयं छत्तीसगढ़ गए थे और आपने वहां के काम की प्रशंसा की है। हमारे यहां ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अच्छी तरह से चल रही है इसके अलावा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी

अच्छी तरह से चल रहे हैं अगर कहीं कोई खराबी है तो वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता में है। आप ग्रामीण सफाई योजना के तहत 1500 रुपए दे रहे हैं और 1500 रुपए राज्य सरकार दे रही है, लेकिन 3000 में शौचालय नहीं बन सकता है। वहां जो शौचालय बने हैं, आप जाकर देखेंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी क्योंकि वहां टाट का पर्दा लगा दिया गया है और ऊपर छत भी नहीं है। ऐसे शौचालयों का प्रयोग माताएं और बहनें कैसे करेंगी? आप जो राशि दें, वह इतनी दें ताकि उससे काम अच्छा हो सके, आप राशि को व्यर्थ न गवाएं। आपकी नीयत अच्छी है, आप दृढ़ इच्छाशक्ति के धनी हैं, आप जो काम करना चाहते हैं वह विश्वास और ईमानदारी के साथ करते हैं। आपका भारत निर्माण का सपना तभी सफल होगा जब गांव समृद्ध होगा, गांव खुशहाल होगा, गांवों में सब भाईचारे और प्यार से रहेंगे। जब आप उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तभी ग्राम संपन्न होगा।

* महोदय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा ग्रामों में बसती है इस बात में गहन एवं गम्भीर मर्म छुपा हे तथा आज भी उतना ही प्रसांगिक है। ग्रामों को समृद्ध, समपन्न करके

â€¦â€¦ This part of the speech was laid on the Table.

ही शहरों का समग्र विकास किया जा सकता हैं क्योंकि ग्राम व शहर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इनके समपान समृद्ध होने से ही भारत सशक्त एवं मजबूत होगा तभी भारत निर्माण हो सकेगा।

महोदय हमारे लोकतांत्रिक देशमें इस समय 2,27,697 ग्राम पंचायते 5,913 जनपद समितियाँ तथा 457 जिला परिषदें कार्यरत हैं जिनमें चुने हुये 34 लाख जनप्रतिनिधि हैं। इन सभी से यिद पूछा जाये तो जो सभी सदस्यों ने सुझाव दिए हैं ये भी उनसे सहमत होंगे।

महोदय मैं कुछ योजनाओं की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करा रही हूँ कृपया ध्यान देने की कृपा करेंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - इस योजना का शुभारम्भ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल विहारी वाजपेजी जी ने इस भावना के साथ किया कि ग्रामों से शहर तक आने का आवागमन जितना सरल सुविधाजनक होगा, ग्रामों का एवं ग्रामीणजनों का किसानों का विकास उतना ही जल्दी होगा। किन्तु आपकी सड़कों का हाथ यह है कि प्रथम दो वर्षों में 674 कि मी लम्बी ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था किन्तु 39,476 कि मी का ही निर्माण संभव हो पाया।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया है। छत्तीगढ़ के कुछ इलाकों में सड़क पूरी बन नहीं पायी और उखड़ना प्रारम्भ हो गयी कृपया इसकी जाँच करवाने का कष्ट करें।

इंदिरा आवास - माननीय मंत्री महोदय इंदिरा आवास उन आवास हीन लोगों के लिए है जो गरीब है। किन्तु ग्राम पंचायतों में एक तो आवासों की संख्या कम आती है दूसरे बिचौलिये पैसे ले लेते हैं। भोले-भाले ग्रामीण ठगी का शिकार हो जाते हैं। इंदिरा आवास प्रत्येक पंचायत में एक साथ एक स्थान को चयन कर उस स्थान पर पीने का पानी बिजली सड़क आदि की व्यवस्था कर के सरकार की कोइ एजेन्सी बनाये तो ज्यादा उत्तम रहेगा। 1985 से चलने वाली योजना आज भी असफल है। तथा इसका बजट तय किया जाये। यदि बीती बातों को छोड़ दें तो अभी भी समय है। इस योजना में सुधार करने का आपने 60 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा केवल 28 लाख 69 हजार मकानों का निर्माण हुआ गरीब आज भी भी किसी अमीर की देहरी अमीर के बरामदे अमीर की गाय कोठों पर अपनी नींद पूरी करने को मजबूर हैं।

भारत निर्माण - आपने ग्रामीण शौचालय के निर्माग का बीड़ा उठाया हे आपने ग्राम की परिकपना भी की है और जिस ग्राम पंचायत में सभी दरों में शौचालयों का निर्माण हो जाता है तो उसे निर्मल ग्राम घोषित कर राष्ट्रपति से पुरस्कार दिलाया जाता है। पर आपने राशि रखी है सिर्फ 1,500 रू और छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है 1,500 रू तब भी 3,000 रू में ग्रामीण ने शौचालय तो दिखाने के लिए बना लिए और आज भी पुरुष एवं महिलाएं खुले में शौच के लिए जा रहे हैं।

बी. पी. एफ का ग्रामों का सर्वे फिर से आपको करना चाहिए क्योंकि समजन लोगों का नाम तो सूचि में है पर सच में गरीबों का नाम उस में नहीं है। सर्वे का मानक बदलिए जो घर खेत के मापंदड से नहीं सूरत से रहन सहन से गरीब दिखे उसे शामिक करना चाहिए छत्तीसगढ़ में 34 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गये हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- महोदय राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना माननीय मंत्री जी आपके द्वारा लायी गयी एक बहुत अच्छी योजना है छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस योजना में प्रत्येक जिलों में अच्छा काम हो रहा है पर इसमें 60 प्रतिशत रोजगार और 40 प्रतिशत सामान या मशीन पर जो खर्च होता है स्थान और काम को देखकर असमें संशोधन करने की छूट आपकों देना चाहिए। तथा स्कूलों एवं शासकीय भवनों की बाउन्ड्री बॉल बनाने की जो सुरक्षित होंगे शासकीय भवन सुरक्षित होंगे तथा ग्रामों में जमीनों पर जो कब्जा हो रहा है उससे भी मुक्ति मिलेगी।

स्व सहायता समूहों को बाजार से सम्पर्क कराने उन्हें बाजार उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रत्येक विकास खंडों पर एवं बाजार बनाकर दिए जाने चाहिए ताकि स्वंय के द्वारा निर्माण किए गए सामानों को बाजार उपलब्ध हो सके।

भूमि सुधार योजना - महोदय यह योजना तो बहुत अच्छी है इससे भू अभिलेखों का संधारण अच्छी तरह से होगा कई राज्यों में यह काम धीमी गति से हो रहा है इस काम में तेजी लानी चाहिए।

महोदय 11 वी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के मुताबिक भारत निर्माण कार्यक्रम की प्रगति कुल मिलाकर संतोष जनक नहीं है बहुत से क्षेत्रों के काम लक्ष्य से पीछे है और कुछ तो लक्ष्य को पूरा करने की नियत में ही दिखयी नहीं देते हैं। जिन क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार लाना था वह प्रगाति केवल पाँच फीसदी ही दर्ज हो पायी है।

ग्रामीण विद्यालय - महोदय ग्रामीण विद्यालयों में पानी और शौचालयों की व्यवस्था अवश्य करिए क्योंकि ग्रामीण बच्चे घरों से पानी की बोतल तो लाते नहीं है यदि स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है तो दौड-दौड कर घर जाते हैं। और पढ़ाई मे व्यवधान पैदा होता है शौचालय बने तथा पीने के पानी की व्यवस्था हो। आजादी के 60 वर्ष बाद भी गांव के बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ते हैं। उन्हें फर्नीचर उपलब्ध कराया जाय और स्कूलों में बिजली की व्यवस्था हो ताकि कक्षा में पखें लग सकें।

रोजगार गांटी योजना - का 15 हजारा करोड़ का उपयोग 29 जनवरी तक नहीं हूआ यह आपकी असफलता का घोतक है।

10. स्वास्थ्य सेवाओं - का तो देश के ग्रामों में सबसे ज्यादा खराब है प्राथमिक स्वास्थ्य के भवन है तो चिकित्सिक नहीं चिकित्सक है तो भवन नहीं ग्रामीणों को समय पर सही चिकित्सा नहीं मिलती ।

महोदय मैं यही कहूंगी कि ग्रामों में अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है ग्राम की धरती तो अमीर है और उस पर गरीब निवास करते है यह इस देश का दूर्भाग्य माना जायेगा।

अन्त में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि गांवों को यदि समपन्न करना है तो गौ संवर्धन व्यवस्था की जाये ग्रामों में पहले अमराई हो थी मउहा के बड़े-बडे पेड़ होते थे। उनकी छा में धूल में खेलकर जो बचपन बड़ा होता था वो वही खो गया है आप ग्रामों में ऐसी हरियाली की व्यवस्थ भी अवश्य करें ।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी हूं।

MR. SPEAKER: Shrimati Karuna Shukla, thank you very much for your cooperation.

Now, I call Shri Vijay Bahuguna. Since you are a new Member, please conclude your speech within five minutes.

SHRI VIJAY BAHUGUNA (TEHRI GARHWAL): Sir, I rise to support the budgetary demands of the Ministry of Rural Development.

The UPA Government has done commendable work in redressing the burning problems of the rural population of our country.

Sir in a ratio of 75: 25 per cent and in a ratio of 92: 8 per cent, the Central Government is flowing funds to the States under the DAVP and DDP schemes and under the National Rural Guarantee Scheme. Sir, what concerns is that the amount which is going from the Centre is not being properly utilized. In fact, it is being mismanaged. Now the only option that we have is that we take very stringent actions against the delinquent officers like the Election Commission has the power, during the course of elections, to take action against the officers. Unless and until there is an amendment in the Act and the power is vested that we recommend action against officers who are guilty of negligence and corruption in enforcing the Central schemes including the National Rural Guarantee Scheme, perhaps the purpose for which these schemes have been enunciated will not be fruitful.

Sir, on this occasion I would like to draw the attention of the hon. Minister to the serious drinking water problem which is being faced by the people living in the remote Himalayas. Both Ganga and Yamuna flow from my constituency, but nearly 68 per cent of the villagers are suffering from drinking water problem. The only option we have is that the Central Government prepares drinking water schemes through lift irrigation and we pump waters from the rivers so that there is sufficient water in the villages. The State Governments are not spending any money on these schemes and they are being spoon-fed by the Central Government. So we have to see that the State Governments also contribute in these social welfare schemes which the Central Government has enunciated.

Sir, the other problem is that during monsoons there is tremendous soil erosion, as a result of which, the cultivable agricultural land is being reduced in the entire Himalayan belt. For this we have to have major programmes for watershed management. So, for all the Himalayan States, the Government of India should come out with a policy and programme that we can conserve this water during monsoons so that there is less of soil erosion and the life becomes easier for the people living in the Himalayas. If we have to prosper then we have to look at the rural India.

I congratulate the hon. Minister and the entire UPA Government for the commendable work that they have done in bringing about a total facelift to the agriculturists and the people living in the rural India[a68]. We can see millions of smiles now especially on the face of women who have been benefited by these schemes.

With these words, I express my gratitude.

MR. SPEAKER: Thank you. I wish to compliment you and your speech. You have done well.

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं वर्ष 2008-2009 की ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाकई में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन मुझसे पूर्व कई माननीय सांसदों ने सदन में यह बात रखी है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार का पैसा है, लेकिन जिन विभागों के द्वारा जो कार्य कराये जाते हैं, वे स्टेट गवर्नमैन्ट के विभाग हैं और वे उन्हीं के माध्यम से उनका प्रचार करते हैं कि उनके क्षेत्रीय विधायकों द्वारा या स्टेट गवर्नमैन्ट के द्वारा ये कार्य कराये जा रहे हैं। इसलिए इसमें बहुत से माननीय सदस्यों की जो पूर्व से मांग है कि जितने भी प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कार्य कराये जाएं, उनमें क्षेत्रीय सांसदों का नाम बोर्ड पर आना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसकी निहायत आवश्यकता है और इसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी को मैंने स्वयं पत्र लिखकर भी मांग की थी कि मंत्री जी ने जो मानक बनायें हैं कि गांव की एक हजार की आबादी होनी चाहिए, पांच सौ मीटर से अधिक की दूरी होनी चाहिए, उस तरह के कार्य हमारे क्षेत्र में लगभग पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे गांव हैं, उनकी दो-दो सौ, तीन-तीन सौ की आबादी है, उनकी दूरी कहीं कम है और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली योजना को भी इस योजना में नहीं रखा गया है। मैंने अपनी पूरी की पूरी सांसद निधि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण में ही लगाई है, उसके पश्चात भी वहां इनकी बहुत आवश्यकता है। मैंने माननीय मंत्री जी से भी इस बात की मांग की थी कि इस योजना के अंतर्गत हमारे क्षेत्र में आप कुछ सहायता करने का कष्ट करें, जिससे सीधे-सीधे एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क और जो आपका एक हजार की आबादी और दूरी पांच सौ मीटर से कम न हो, उन मानकों से हटकर इन सड़कों का निर्माण हो सके। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं।

दूसरा सम्पूर्ण स्वच्छता शौचालय अभियान में 1900 रुपये लाभार्थी को दिये जाते हैं, जिसमें चार सौ रुपये वह स्वयं अपने पास से लगायेगा, छः सौ रुपये राज्य सरकार का हिस्सा है और नौ सौ रुपये भारत सरकार का हिस्सा है। मैं समझता हूं कि 1900 रुपये में आज के समय में एक हजार ईट भी नहीं आती हैं तो वह शौचालय कैसे बनना संभव है। लिहाजा दो-दो, तीन-तीन नामों से वह फर्जी आवंटन कराते हैं, तब कहीं एक शौचालय बनता है। इसलिए स्वच्छता शौचालय योजना के लिए मेरी मांग है कि इसमें कम से कम पांच हजार रुपये का पूर्ण खर्चा होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सीमेंट, ईट और सरिया बहुत महंगा है। इसलिए जो व्यावहारिक है, जो संभव है, जिससे शौचालय बन सकता है, वैसा ही किया जाए। इसके अलावा आप जितना भी पैसा देंगे, वह उसमें किसी भी तरह से नहीं बनेगा या फिर वह कागजों में बनेगा और उसका जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, वह लाभ जनता को नहीं मिल सकेगा।

इसी तरह से जो छोटे-छोटे नगर हैं, हालांकि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर नहीं है, लेकिन उन नगर क्षेत्रों में भी अगर सीवरेज जिला मुख्यालयों में बनाई जाए तो वह भी बहुत बेहतर होगा। इसके साथ ही प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जितने आपके द्वारा कार्य किये गये हैं, जिनकी हम शिकायतें करते हैं, जो अधिकारी आप यहां से भेजते हैं, वे अपने आप उसकी रिपोर्ट बनाकर आपको दे देते हैं और आप उत्तर भेज देते हैं कि वे ठीक-ठाक पाई गई, जबकि ऐसा नहीं है। आपका कोई भी अधिकारी बुलाना या मिलना उचित नहीं समझता, सिर्फ वे लीपापोती करके आते हैं। माननीय सदस्यों ने इस पर बहुत ज्यादा जोर देकर शिकायत की है कि जितनी भी सड़कों के निर्माण कराये जा रहे हैं, वे मानक के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार नहीं कराये जा रहे हैं। आपने हमें समिति का अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन समिति के अध्यक्ष की हैसियत से, जिला निगरानी अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष की हैसियत से, जितने भी प्वाइंट हम वहां रखते हैं, आज की तारीख में ब्यूरोक्रेट्स इतने मनमाने हो गये हैं कि वे किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जो अधिकारी भारत सरकार की तरफ से भेजते हैं, वे भी उन्हीं जिले के अधिकारियों से मिलकर उन कागजों की लीपापोती करके आपके पास रिपोर्ट जमा कर देते हैं। लिहाजा जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, यदि वे आपके पास कोई शिकायत कर रहे हैं तो उसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए[b69]।

19.00 hrs.

इसकी जांच भी इतनी ही गंभीरता से की जानी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना- जैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा है, यह बात सही है कि फर्जी कार्ड नहीं बनने चाहिए। इन कार्डों का सही उपयोग किये जाने के लिए कुछ न कुछ सही मार्गदर्शन होना चाहिए। धन्यवाद।

MR. SPEAKER: Thank you very much. You spoke well, Mr. Munshi Ram.

***श्री बापू हरी चौरे (धुले) :** ग्रामीण विकास अनुदान की मांगों पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आभारी हूं। मैं समर्थन करता हूं समय की कमी होने के कारण कुछ विषय सामने रखता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में महाराष्ट्र में या मेरे चुनाव क्षेत्र धुले में ग्राम पंचायत के माध्यम से काम करने के लिए पंचायत उदासीन है। निश्चित रूप में कुछ खामिया हैं उसका संशोधन करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दूर दराज पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र में प्राधान्य देना जरूरी है। जैसा कि मेरे चुनाव क्षेत्र धुले से आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र होते हुए 100 करोड़ रू0 का प्रस्ताव दिया था उसमें मे 19 करोड़ की मंजूरी दी है। इन्दिरा आवास योजना में बीपीएल धारकां को और गुणक के आधार पर लाभ देना है मगर बीपीएल का जो सर्वेक्षण हुआ है वह गलत है। इसलिए बहुत सारे गरीब उससे वंचित है। तो दुबारा सर्वेक्षण हुआ है वह गलत है। इसलिए बहुत सारे गरीब उससे वंचित है। तो दुबारा सर्वेक्षण करना जरूरी है। इन्दिरा आवास योजना में 28,500 से बढ़ाकर लगभग 35,000 बढाया है वह भी कम है। आज के सीमेंट, ईट और लोहा के भाव देखते हुए यह रुपये बहुत कम है। एक लाख तक बढ़ोतरी करना जरूरी है।

ग्रामीण जलपूर्ति योजना में 10 टका निधि की भागीदारी गांव वालों की है। मगर वह पैसे ठेकेदार भरते हैं और वही काम करते हैं। पेयजल समिति कागज पर चलती है। पेयजी योजना कागज पर पेयजल समिति के नाम से दिखाते हैं। और सही मायने में ठेकेदार काम करते हैं। स्वजल धारा योजना में जो 10 टका भागीदारी निश्चित की है और वही नियम आदिवासी उपयोजना को लागू किया है। जो कि आदिवासी क्षेत्र के गांव की क्षमता के बाहर है। इसलिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में जो उपयोजना निधि में से जो पेयजल योजना बनाएंगे उसमें भागीदारी मुक्त करना चाहिए। क्योंकि ऐसे करने से ठेकेदार बीच में नहीं आयेंगे।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से जो पक्का माल तैयार होता है उसको बाजार में मार्केट दिलाने के लिए शासकीय योजनाओं में उत्पादित माल को शामिल करना चाहिए। जैसाकि आदिवासी विकास या समाज कल्याण के जो निवासी आश्रम या होस्टल हैं उनको स्वरोजगार के अंतर्गत जो खाद्य मसाले जैसे - मिर्ची, हल्दी, मसाला आदि तैयार होते हैं वह सरकार के माध्यम से खरीदना चाहिए तभी उनको मार्केअ मिलेगा।

आदिवासी विकास विभाग में अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना में जो व्यक्तिगत रूप में विकास करने के लिए लाभ दिया जाता है उसमें महाराष्ट्र में बहुत धांधली है। 2005-06 से 2007-08 में जो गाय,

---

* Speech was laid on the Table.

भैंसे और बकरे दिये हैं वह पुरवठा करने के लिए ठेकेदार नियुक्त किए है जबकि इसमें ठेकेदार नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। ठेकेदार को दो भैंसे पुरवठा करने के 45,000रू0 और दो गाय के 30,000 रू0 दिये हैं मगर ठेकेदार की तरफ से आदिवासियों को जो जानवर महाराष्ट्र में दिये गये वह सब बिना दूध देने वाले थें उसमें में कुछ मर गये या लाभार्थियों ने चारा के खर्च करने के बगैर बेच डाले।

केन्द्र की तरफ से इसकी जानकारी लेना जरूरी है जोकि आदिवासियों को सही मायने में उनको लाभ मिले। जोकि महाराष्ट्र में कितने जानवर दिये गये और उसमें लाभार्थियों के पास कितने बचे? आदिवासियों का सही दिशा में विकास होने के लिए आदिवासी उपयोजना निधि पर अमल करने के लिए एक संसद सदस्य की अध्यक्षता में दक्षता कमेटी नियुक्त करना जरूरी है।

MR. SPEAKER : Now, Shri Francisco Cosme Sardinha. You are new to this House, but not so new. You are welcome to speak, please. You have four minutes.

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (MORMUGAO): I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development for the year 2008-2009. I must congratulate and appreciate the efforts of the UPA Government to alleviate the sufferings of 70 per cent of India living in rural areas. If the influx of people from rural to urban areas in search of employment is to be stopped or arrested, it is only by improving the lot of the poor living in rural areas.

It is heartening to note that an amount of Rs. 49.450 crore has been earmarked for this Ministry bringing the Budget allocation only second to Defence. For the first time, the Government has brought National Rural Employment Guarantee Scheme whereby employment of a minimum of 100 days is assured to every unemployed citizen of this country. Also, the other existing schemes like Indira Awas Yojana, Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana are very effective.

However, when you see the implementation of these schemes in the country, only 51 per cent of rural housing is achieved, 25 per cent of rural roads have been built and only 52 per cent of drinking water supply has been achieved. This only shows that there might be some inherent deficiencies in their implementation which must be corrected. Considering Indira Awas Yojana which is to provide shelter to the poor who are living below the poverty line, the amount earmarked for a new house and for upgradation of the existing houses has to be enhanced, as the amount is not enough due to existing prices of cement and steel. It also depends on the location of the site of the house from the existing roads because carrying the material on the head load will automatically increase the cost.

I would like this august House to realise some factual ground realities in implementation of the existing schemes. Every State is under different stages of development depending upon local economy, literacy ratio, urbanisation, industrialisation and historical and geographical background. Therefore, the schemes need flexibility in their application depending upon local scenario and the needs of the people.

Referring to Goa, which is a tourist State, where the literacy rate is very high, the road connectivity is good and the villages are semi-urban, we are not able to implement these schemes in toto, as the wages are high and our requirements are different. Therefore, first of all, minimum wages have to be increased. Goa needs wider roads and garbage free clean environment. Since the parameters of Central schemes, as mentioned earlier, are stringent, the benefit of the schemes mostly goes to the migrant population from the neighbouring States and not to the local unemployed educated youth who shun accepting the menial unskilled jobs.

In view of these practical constraints, I will urge the Ministry to modify the rural development schemes or to give flexibility to the States to address the local needs and psyche to suit the prevailing social conditions of the people. In short, the schemes should be State-specific and not generalistic. Therefore, while making modifications, State Governments need

to be consulted to make the schemes more successful.

MR. SPEAKER: Now, I wish to call two hon. Members if they commit to complete their speeches within three minutes each. If you do not commit to do so, please do not stand up. Now, Shrimati Sujatha.

SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): Can I lay my speech on the Table of the House?

MR. SPEAKER: Of course. I have already given you the permission. [MSOffice70]

SHRIMATI C.S. SUJATHA (MAVELIKARA): Mr. Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion.

Sir, there are many schemes under the Ministry of Rural Development. But over the years, the allocation of funds for rural development has been found to be shrinking. This has been affecting the rural poor adversely.

The present Central unit cost of the Indira Awas Yojana is Rs. 35,000. But the steep increase of the basic materials makes it impossible to complete the work within this budget. Therefore, it is necessary to increase the amount adequately, at least to Rs. 50,000 to general category and Rs. 1 lakh to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Secondly, under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the width of the road is fixed at 8 metres. But Kerala being a densely populated State with per capita land availability being low, there is a difficulty in fulfilling the 8 metre norm. So, I request that it should be changed to 6metres in view of the particular situation in the State of Kerala. Then, in the case of habitat connectivity roads, there is no provision to include the expenses on the bridges. Kerala has a long stretch of sea shore and a number of bridges are to be built between roads connecting habitats. Therefore, there should be a provision included to cover the construction of bridges also.

Thirdly, the construction of BPL houses and the preparation of paddy field for sowing should also be included in the National Rural Employment Guarantee Programme.

Fourthly, solid waste management should be included in the Total Sanitation Campaign Scheme and 20 per cent of the funds should be kept separately for this purpose.

There are many NGOs involved in the implementation of rural development schemes. Though most of them are working as per the guidelines, some NGOs are facing charges of rampant corruption. So, the Ministry of Rural Development should have a transparent regulatory and controlling mechanism over the functioning of NGOs.

Sir, my last and the most important point is, there is a move by the Centre to release funds directly to the local self-government bodies. It is an ill-conceived idea and is an effort to undermine the federal system of the country. So, I request the Government to desist from any such move.

*SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): Hon'ble Speaker, Sir, First of all I thank Shri Rajghu Bangshi for his active role played in the Ministry of Rural Development. We are discussing demands & grants (General) for the year 2008-09.

It is needless to mention that the allocation of fund is meagre specially 100 days National Rural Employment Guarantee Scheme. Though you have increased total number of districts but the allocation is 30% what Minister is thinking to do the best of the development but the Planning Commission is not in a position to do that. This is the cause of neo-liberalization policy adopted in our country.

Sir, you are aware that more 75% are of our country fallen under rural area.

So Government should come out with a comprehensive planning by which Bharat Nirman will be completed.

National Rural Employment Guarantee Scheme is a welcome step. But Government should come out for awareness of for job card holders and how they will get the job? What will be time limit? And if the Panchayat failed to give the job within 15 days job card holder will be paid unemployed allowance.

The payment should be made regularly. Sir, I am regret to say that while we were visiting Arunchal Pradesh as Standing Committee of Chemicals and Fertilizers. We visited three villages namely Mani, Juli Basti and Model Villages nearest to Itanagar of A.P. All the members of that villages complained that NREGS has not been implemented even `Sikha Anjan' also in the same way.

I would like to know from the Hon'ble Minister the reason behind the non-implementation of NREGS.

Sir, regarding Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana is not properly maintained.

Regarding Accelerated Rural Sanitation which is implemented from 1999. This year is called International Year of Sanitation.

---

* Speech was laid on the Table.

The West Bengal Government has been doing its best for Nirmal Gram Panchayat. First of all Midnapur distt. has shown total sanitation of which 1st Nirmal Panchayat Samity is `Nandigram' of Midnapur distt.

Sir, Burdwan distt. already applied for the year 2008 as Nirmal Distt.

I would like to remind you that `Karisunda' gram panchayat which falls under Indus Panchayat of Bankura distt. in West Bengal was the icon of other gram panchayat of Indus Panchayat Samity to became Nirmal Gram Panchayat but still the `icon' is not declared as Nirmal Gram Panchayat of Indus Panchayat Samiti of Bankura distt. in West Bengal .

Sir, sanitation is essential to reduce child mortality rate and morbidity.

So, it should be given top priority. Allocation of Indira Abhas Yojna should be increased and also sanctioned fund should be increased because the building material increase very fast.

I would like to submit regarding drinking water to be looked and irrigation facilities should be increased so that India as a whole will be developed.

SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR): Mr. Speaker, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. I will touch upon two or three points only.

The first is regarding the budget allocation. The Ministry of Rural Development is one of the most important Ministries of the Government of India, along with the Ministry of Panchayati Raj, which deals with most of the poverty alleviation programmes. In 2007-08, the budget allocation including Plan and Non-Plan was hardly Rs. 28,500 crore and this year it is only Rs. 31,524 crore which is not commensurate with the 11th Plan. So, if the Minister gets the opportunity of presenting the Demands for Grants next year, he should get the budget allocation enhanced. But I do not think he will get the opportunity.

MR. SPEAKER: You keep it for the next Government!

SHRI PRASANNA ACHARYA : So, this should be enhanced.

Sir, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is considered to be a landmark programme in the history of rural development in this country in the last 60 years. The credit for this goes to the erstwhile Government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee and thanks to this Government they have decided to continue with this programme. But I want to point out one or two loopholes that are there in this programme.

Sir, in some places when the rural road construction work is taken up, some private lands are being acquired, but there is no provision in the PMGSY for giving compensation to the private land owners. Therefore, there is a lot of resentment and a lot of constraints are coming in the way of implementation of this programme. So, there should be a provision that wherever private lands are acquired or taken up for the construction of rural roads, these private land owners should be given compensation so that the work can be accelerated and completed smoothly. This is my suggestion to the Government.

Another point is the impediment caused by the Railways and I had raised this point during the discussion on the Railway Budget also. In many places, when the PMGSY road construction work is taken up, the Railway is coming in the way because when it needs to cross a railway line, the Railway authorities are coming and stopping the work saying that they cannot provide any unmanned level crossing. I have drawn the attention of the hon. Railway Minister and also the Minister of State to this important problem and thanks to them they have assured me to look into this problem. This problem has occurred in my own constituency and that is one of the bottlenecks in the implementation of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

Sir, my last point is that the Ministry of Rural Development is the nodal Ministry to operationalise the National Mission on Biodiesel. But the point is, when the non-edible oilseed plantation like jatropa is done, it causes depletion of ground water.

MR. SPEAKER: It does not come under this Ministry.

SHRI PRASANNA ACHARYA : Sir, it is coming under this Ministry. [R71][r72] That has to be reassessed because there are two opinions. One of the opinions is, where large scale jetropha cultivation was taken up, the water level has depleted and that is damaging the neighbouring land. So, that should be reassessedâ€¦..(Interruptions).

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, so many hon. Members of our Party are there to speak. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Sorry, time is long-long elapsed.

...(*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, they have been waiting since morning...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: All right. Leave it to me.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, please give them some time. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please take your seat. We have already crossed six-and-a-half hours. Your time has elapsed. I have called the hon. Member from your Party, please do not disturb.

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ग्रामीण विकास की सन् 2008-09 की मांगों पर चर्चा करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। कई सम्माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और अधिक्तर सदस्यों ने यहां पर मंत्री जी की तारीफ की। मंत्री जी ग्राम से आते हैं और ज़मीनी हकीकत जानते हैं, यह बात भी सही है। मंत्री जी ने इस विभाग का आबंटन बढ़ाया है, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। जो कुछ खामियां रही हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

महोदय, इस क्षेत्र का सीधा संपर्क ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है। कई सदस्यों ने बताया कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। लेकिन रोजी-रोजी-कपड़ा-मकान और पानी मिलना मूलभूत अधिकार है। हमें खेद है कि आजादी के 60 साल बाद भी ये सुविधाएं मुहैया नहीं करा सके। इस डिपार्टमेंट का संबंध कई खातों से आता है, लेकिन जब तक सभी डिपार्टमेंट एक जगह बैठ कर कोई नीति तय नहीं करेंगे, तब तक इसमें किसी योजना का ठीक से कार्यान्वयन नहीं होगा।

महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन कार्यान्वयन करने वाले अधिकारी या राज्य सरकारें अगर अच्छे ठीक ढंग से काम नहीं करतीं तो सवालिया निशान मंत्री जी या केन्द्र सरकार पर आता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने सांसदों की जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में इस डिपार्टमेंट की चर्चा आपने की थी और बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई थीं। उस समय मैंने एसजीआरवाई के बारे में कहा था कि इस योजना के तहत जो काम हो रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे क्षेत्र में एक अप्रैल से यह योजना शुरू हुई और एसजीआरवाई बंद हो गई है। एसजीआरवाई का जितना बजट था, उससे कई गुना ज्यादा, वहां पर जो काम करने वाले आफिसर्स हैं, उन्होंने वहां बजट से दोगुना काम सैंक्शन करके रखा है। आज काम हुआ है, योजना बंद हुई है, लेकिन पैसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति वहां पैदा हो रही है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इन्होंने वहां भ्रष्टाचार करके ज्यादा काम सैंक्शन किए हैं। मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी थी कि यहां से वहां टीम भेज कर प्रौजेक्ट आफिसर की वहां चौकसी की जाए ताकि पता लगे कि उन्होंने ज्यादा काम क्यों सैंक्शन किए। यह जो योजना बंद हो गई है, इसके बारे में आप अगर कुछ करें तो मुझे लगता है कि उन लोगों को न्याय मिलेगा।

महोदय, वहां आज जो लोग काम करते हैं, आपने वहां जो योजनाएं शुरु की हैं, लोगों को रोजगार देने के लिए वह योजना शुरु की थी, लेकिन वहां मशीनरी से काम किया गया। वहां पर जिन लोगों के नाम दर्ज किए गए, उन्हें भी पता नहीं कि हमारे नाम इसमें हैं और हमारे नाम पर पेमेंट लिया गया। इस बारे में मैंने आपको कई बार बोला। आपने मीटिंग में बताया था कि आपको आफिसर आकर मिलेंगे, आप उन्हें डिटेल में बताओ, लेकिन न तो कोई आफिसर आया और न ही उन लोगों की कोई चर्चा हुई। यह वहां की हकीकत है। इंदिरा आवास के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा की कि 28 हजार का इंदिरा आवास आप घर दे रहे हैं, लेकिन अगर आज के डीएसआर रेट देखे जाएं तो पता चलेगा कि ये कई गुना बढ़ गए हैं। आप जो 28 हजार रुपया देते हैं, वह लाभधारक को देते हैं। मेरा कहना यह है कि 28 हजार का जो इंदिरा आवास है, उसे 50 हजार किया जाए, क्योंकि आप जो 28 हजार रुपए देते हो उससे घर नहीं बनता। घर की जो जरूरी चीजें हैं, उन्हें बेच कर वह घर बनाता है और उसकी हालत ज्यादा बिगड़ जाती है, इसलिए उसे इससे कोई फायदा नहीं होता है।[s73]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसमें खुद ध्यान देंगे, तो कुछ काम हो पाएगा। मैंने अपने क्षेत्र की आपको जो बात बताई, उसकी जांच करने के लिए आप कमेटी भेजें और वह चौकसी करे, तो न्याय मिलेगा। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य भाषण देना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने-अपने भाषण लिखित रूप में भेज दें।

â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Now, the hon. Minister.

...(*Interruptions)*

DR. VALLABHBHAI KATHIRIA (RAJKOT): Sir, please give us two minutes time to speak. ...(*Interruptions*)

डॉ. राम लखन सिंह (भिण्ड) : अध्यक्ष महोदय, जब उपाध्यक्ष महोदय आसन पर थे, तब यह सहमति बनी थी कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, वे बोलें तब तक सभा का समय बढ़ा दिया था।

MR. SPEAKER: Will you kindly take your seats? There are some procedures and some rules. We have fixed four hours but we have already taken six hours and forty minutes. I am very happy that the hon. Members are taking so much of interest.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please allow me to complete.

â€¦(व्यवधान)

डॉ. राम लखन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब सब लोग बैठने के लिए तैयार हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: If you want to dictate to me, you will never get a chance in your life. Be polite to the Chair. सुनिए।

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You please listen now. There are still six names from your Party. क्या होगा?

...(*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN : Some Members are absent now. â€¦ (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : सम आर एबसैंट होने से क्या होगा, आपने तो नाम लिख कर भेज दिए हैं। I am[H74] assuring that they are present.

...(*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, the hon. Deputy Speaker has said that it would continue and all the Members who have given their names would get a chance to speak. You kindly go through the records. The hon. Deputy Speaker has assured us. So, please allow some of our Members to speak. ...(व्यवधान) सर, थोड़ा समय दे दीजिए। सर, अपोजीशन के पास बोलने के सिवाय और क्या है?

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

श्री खारबेल स्वाई : नहीं सर, मुझे नहीं बोलना है। हमारी पार्टी के अन्य सदस्य बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सुनिए, बात यह है कि यह बोलने में तो अच्छा लगता है कि हम बैठे हैं। हमारा बैठने का तो काम ही है। लोगों ने हमें यहां बैठने के लिए ही भेजा है। क्या यहां कोई चैरिटी हो रही है?

***श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) :** अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग पर सदन में चर्चा हो रही है, इसमें मैं अपने आप को सम्मिलित करते हुए कहना चाहूंगा कि -

भारत गांवों का देश है, इसे दूसरे शब्दों में ग्रामीण भारत भी पुकारने लगे हैं।

हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित है। 23औ वन क्षेत्र व 7औ शहरी क्षेत्र को अलग कर दिया जाये, जिसके विकास का जिम्मा ग्रामीण विकास मंत्रालय का है।

भारत देश की कुल आबादी का करीब 70औ भाग गांवों में बसता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि आपके क्षेत्राधिकार आबादी व क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु तदनुसार बजट का प्रावधान करायेंगे। बजट मांग के देखने से पता चलता है कि इस मंत्रालय ने 42,429.86 करोड़ रूपयों का प्रावधान है जो अनुपातिक रूप से अपर्याप्त है। आम आदमी की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा व मकान है। साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, बिजली, परिवहन आदि भी विकास के आधार स्तम्भ हैं।

मैं यहां राजस्थान राज्य का जिक्र करूंगा जिसमें आज भी करीब 34183 आबादी शुद्ध पेयजल से वंचित है। करीब 12,000 गांव विद्युत सुविधा से वंचित हैं। कई ढाणियां, बस्तियों के लोगों ने बिजली कैसी है, उसके दर्शन तक नहीं किये हैं।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आपने स्व0 प्रधान मंत्री राजीव गांधी के नाम से राजीव गांधी पेयजल मिशन एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रस्तुत की थी परन्तु बजट के अभाव में अभी योजनाएं कागजों तक ही सीमित हैं।

इसी तरह वॉटर शेड योजना में दो से तीन वर्षों से बजट आबंटन के अभाव में मजदूरों को भुगतान नहीं हो रहा है। मेरा आग्रह है कि पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाये।

मैं रोजगार गारंटी योजना में आदिवासी, रेगीस्तानी क्षेत्र में जहां रोजगार का हमेशा अभाव रहा है कम से कम 200 दिन काम दिया जाये ताकि गरीब परिवार अपने परिवार का वर्ष भर भरण पोषण कर सके।

* Speech was laid on the Table.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जो को सुझाव है कि उन्होंने लैंड एक्वीजीशन एक्ट को अमेंड करने के लिए पेश किया है और नई आर एंड आर पॉलिसी लाए हैं, इसमें बहुत देरी हुई है। देश में लगभग दो-तीन लाख हैक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ है। इससे देश में बहुत सामाजिक उत्तेजना फैल रही है और लोग इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। इसलिए आप इस बारे में जल्दी से जल्दी नया कानून लाइए, अमेंडमेंट लाइए और उसमें लोगों की भागीदारी कराइए।

महोदय, मेरा दूसरा सजैश्चन है कि बी.आर.जी.एफ. की एक अलग दुकान भारत सरकार ने खोली है, पंचायतीराज डिपार्टमेंट और उसका भाषण अभी बाहर चल रहा है, या तो आप अपनी दुकान बन्द करो या उनकी दुकान बन्द करो। इसके कारण जमीन पर बहुत डुप्लीकेशन हो रहा है। पंचायतीराज डिपार्टमेंट और ग्रामीण विकास विभाग, दोनों को मिलाकर एक करो। जिसको आप चाहो, चलाओ, लेकिन दोनों को मिलाकर एक करो। मेरे यही दो सुझाव हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्रालय है। देश के ग्रामीण इलाकों के 65 से 70 परसेंट लोग इनके अन्तर्गत कवर होते हैं। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी के पास जो डिपार्टमेंट हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और वे स्वयं बहुत मजबूत मंत्री भी हैं। इसलिए उन्हें ग्रामीण विकास के कार्यों को करने के लिए धन ज्यादा दिए जाने की आवश्यकता है। मेरा कहना है कि देश में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की संख्या 26 परसेंट है और वर्ल्ड बैंक के सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक देश में 43 परसेंट बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की संख्या है। मेरा माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की संख्या है, उसे कम करने के लिए गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने की आवश्यकता है। अभी तक जो बी.पी.एल. का सर्वे हुआ है, उसमें काफी गड़बड़ियां पाई गई हैं, इसलिए उसे दुबारा करने की आवश्यकता है।

MR. SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, you have properly utilized it.

Now, Shri Ganesh Singh.[H75]

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश की पहचान गांव के देश के रूप में है। हमारी आबादी का 70 फीसदी हिस्सा गांवों में बसता है। आजादी के इन 60 वर्षों में अभी तक जो कुछ भी हमने गांव के लिए किया है, वह अपर्याप्त है। हम सभी यह महसूस करते हैं कि समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलाए गए होते, तो आज देश की तस्वीर कुछ और ही होती। आज भी अपनी जरूरतों के लिए लोग मोहताज़ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार स्कूलों की व्यवस्था करना सबसे पहली जरूरत है। जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो कार्यक्रम शुरू किए थे, उसी समय ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए समयबद्ध योजना बनाई जाती तो आज तक काफी कुछ हो चुका होता। एनडीए के शासनकाल में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो समयबद्ध योजनाएं बनाई थीं, आज उन्हीं को भारत निर्माण के रूप में यूपीए सरकार ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन काम कितने समय तक पूरे होंगे, इसका कहीं उल्लेख नहीं हो रहा है। भारत निर्माण का जो लक्ष्य वर्ष 2009 तक निर्धारित किया गया है, आंकड़े उसे 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अलग है, लेकिन आंकड़े 50 प्रतिशत से नीचे बता रहे हैं, जबकि सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर क्या आप यह बता सकते हैं कि फलां गांव में हमने इस समस्या का निदान किया है? आज तक किसी समस्या का निदान नहीं ढूंढा गया है। मध्य प्रदेश के बारे में मैं दो मिनट में कहूंगा। मध्य प्रदेश के 38 जिले और 163 तहसीलें...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Sorry. There is no more time. You all agreed to stick to two minutes time. Please follow it.

श्री गणेश सिंह : गांवों की हालत खराब है, भयंकर सूखा है, पेयजल की समस्या है, मैं लगातार इस हाउस में इस बात को उठाता रहा हूं कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार की तरफ से एक रूपया नहीं मिला है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Now, Dr. Ram Lakhan Singh.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Mr. Ganesh Singh, please do not interrupt your own party Member. आपके पास लिखी हुई स्पीच है, उसे ले कर दीजिए।

श्री गणेश सिंह : महोदय, लिखी हुई स्पीच नहीं है।

MR. SPEAKER: I cannot help you. Your name should have come earlier by your party.

श्री गणेश सिंह : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मैं लिखकर दे देता हूं।

*अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों के संबंध में अपने विचार रख रहा हूं1

भारत देश गांव का देश है यहां की कुल आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा गांवों में बसता है। आजादी के 60 वर्ष बी गये लेकिन आज भी देश के गांव बुनियादी जरूरतों के लिए मुहताज है। आजादी के बाद से यदि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने ग्रामीण विकास की समयबद्ध योजना बनाई होती तो शायद देश की तस्वीर आज कुछ और होती, सरकारों का कार्यकाल पूरा होता चला गया पैसा भी खर्च होता चला गया लेकिन देश के सामने किसी भी समस्या का अंत कर दिया गया, ऐसा उदाहरण नहीं मिल पाया। यदि सच कहा जाये तो समयबद्ध कार्य एनडीए सरकार में मा0 अटल विहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। यूपीए सरकार ने भारत निर्माण के नाम पर आगे बढ़ाने का प्रयास तो किया लेकिन उसकी गति अत्यंत धीमी है। भारत निर्माण में जो कार्यक्रम शुरू किये गये जिनमें ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन, ग्रामीण सड़क, पेयजल आवास और सिंचाई को लिया गया था। 2009 तक के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था जो कि अभी तक 50 प्रतिशत से भी कम है।

यदि 11वीं योजना के दस्तावेजों को सही माना जाये तो भारत निर्माण कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक रही है। दो वर्ष के समयावधि में विद्युतीकरण 36 एवं 6 फीसदी का लक्ष्य पूरा कर पाये हैं। 1-25 लाख गांव और बीपीएल के 2.30 करोड परिवारों को बिजली देने का लक्ष्य था उसका पता नहीं क्या किया। 55067 बस्तियों को शुद्ध पेयजल देने का लक्ष्य था वह भी अधूरा है।

50674 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य था उसके बदल 39476 किलोमीटर मात्र सड़क बन पायी है। 60 लाख मकान बनाने का लक्ष्य था, जिसमें 28.69 लाख ही मकान बन पाये हैं। अभी भी 42 प्रतिशत लोग बिजली के अभाव में है। 74 प्रतिशत लोग रसोई गैस से वंचित हैं। दो लाख गांव से शुद्ध

â€¦ This part of the speech was laid on the Table.

पेयजल नहीं है। देश में कुल प्रा0 केंद्रों की संख्या 22669 ही मात्र है जबकि देश में 6.5 लाख गांव अस्पतालों में 50 प्रतिशत चिकित्सकों की कमी है। लोग अभी भी इलाज के लिए 30 कि0मी0 की दूरी तय करते हैं।

देश के प्रत्येक पंचायतों में प्रा0 स्वत केन्द्र खोले जाना चाहिए। देश का बजट ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त न देने के कारण ही देश विकास में पिछड़ गया। दुनिया में हमारी पहचान पिछडे देश के रूप में है और दूसरा कारण ग्रामीण विकास की कमी है।

देश गांवों को सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, आवास, संचार की जरूरत बुनियादी रूप से है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी जी तक एक ही नारा लगाया जाता रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान का एवं गरीबी हटाने का। अब तक कितने लोगों को दोनों वक्त की रोटी मिल रही है? कितने लोग हैं, जिनको कपड़ा उपलबध कराया गया? कितने लोगों को मकान अब तक मिल पाया है? इंदिरा आवास योजना 1985-86 से प्रारंभ की गई।

आज भी देश की हर पंचायत को एक भी इंदिरा आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब तक देश कोई भी ऐसा गांव उदाहरण नहीं बन पाया जहां सभी गरीबों को मकान मिल पाया हो। आज भी लाखों लोग आसमान के छत के नीचे सोने को मजबूर हैं।

स्वंय राहुल जी ने आदिवासी परिवारों में जाकर देखा है। स्वीकार किया है कि लोग आज भी टूटी खाट में पेड़ के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं।

यदि सरकार चाहती तो अब तक देश के सभी आवासहीन परिवारों को मकान दे सकते थे लेकिन नहीं कर पाये। राहुल जी ने आदिवासियों के जीवन स्तर पर गहरी चिंता प्रकट किया है। सूखी रोटी, नमक और चटनी से आदिवासी घरों में खाया जाता है। क्या राहुल जी ने उन गरीबों का मजाक नहीं उड़ाया है। उनके परिवार के नेतृत्व में ही यह देश 50 वर्षों तक का सफर पूरा किया है।

यदि इसके बावजूद भी आदिवासी सूखी रोटी खाने के लिए मजबूर है अथवा पेड़ के नीचे सोने के लिए मजबूर हो रहा है। यदि इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी ही है। यदि आदिवासी परिवार के लोगों के पास इतनी मंहगाई में तेल सब्जी खरीदने की स्थिति होती तो शायद राहुल जी को सूखी रोटी नमक चटनी नहीं खिलाते।

इस देश के गांवों को विकास तभी पूरा होगा जब सरकार समयबद्ध कार्यक्रम चलायेगी। एनडीए के समय पर मा0 अटल जी ने समयबद्ध कार्यक्रम चलाया था उसी का परिणाम है कि आज देश के गांवों में पक्की सड़क पहुंच रही है। अब लगता है कि 2012 तक देश के सभी गांव पक्की सड़क से जुड़ जायेंगे। आज देश के अंदर सभी स्कूल भवनयुक्त हो रहे हैं, यह उन्हीं की सोच थी। शुद्ध पेयजल लोगों को मिल सके, इसके लिए भी समयबद्ध कार्यक्रम चलाया था लेकिन अब उसकी गति धीमी हो गयी। सड़क निर्माण की भी गति धीमी हो गयी है। यदि नेहरू जी के समय से समयबद्ध कार्यक्रम चलाये गये होते तो देश की आज तस्वीर बदली हुई मिलती।

देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, क्या इसकी समीक्षा हुई है, इसका क्या कारण है। 100 में 37 गरीब हैं। जबकि गरीबों की संख्या 100 में 50 से अधिक है। प्रमाण के रूप में म0प्र0 सरकार ने वास्तविक गरीबों का नाम जोडने के तहत अब तक 60 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के रूप में पहचान की गई है। देशा के गरीबों को भरपेट अनाज तक नहीं मिल पा रहा। लाल गेहूं, विदेशों से आयात किया है जो मानव उपयोग हेतु नहीं है। उसे खाने के लिए मजबूर है। इसमें भी कटौती कर ली गई लेकिन वही म0प्र0 सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 3 रूपया किलो गेहूं, 4.50 रूपये प्रति किलो चावल दे रही है।

रोजगार गारंटी योजना जब से चलाई गई तब से सभी जो ग्रामीण विकास की योजना चल रही थी, बंद कर दी गई। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। केन्द्र से बजट का आबंटन नहीं होने से महीनों मजदूरों को मजदूरी के लिए इंतजार करना पडता है। मध्य प्रदेश को आबंटन न मिलने से लाखों कृमिकों को मजदूरी नहीं मिल पाई।

रोजगार गारंटी योजना में जो प्रावधान है उनसे सम्पूर्ण विकास की कल्पना नहीं पूरी हो सकती। कुछ भवन निर्माण कभी कार्य जोडने की जरूरत है। इस योजना में खेतों में कुएं बना रहे हैं। तो क्या इस योजना से गरीबों का मकान नहीं बनाया जा सकता है।

चेकों के भुगतान से भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता । इससे मजदूरों की परेशानी और बढ़ गई है। म0प्र0 में सतना जिले के साथ साथ बाढ़ से जिन लोगों के मकान गिर गये थे उनको इंदिरा आवास दिया गया था लेकिन एक किस्त के बाद दूसरी किस्त नहीं दिया गया उसे दे दिया जाये।

म0प्र0 के 38 जिलों की 63 तहसील भयंकर सूखे की चपेट में हैं। जलस्रोतों में, नदी तालाब, कुएं सभी सूख गये हैं। नल जल योजनाओं के मरम्मत की जरूरत है। नये हैण्डपम्पों के खनन की जरूरत है।

अतः अतिरिक्त आबंटन हेतु प्रदेश सरकार को कम से कम 25 हजार करोड़ का आबंटन दिया जाये। वैसे भी म0प्र0 सरकार ग्रामीण विकास के सभी कार्यों का ठीक ढंग से क्रियान्वयन कर रही है। इसलिए भी भारत सरकार को राज्य सरकार को पुरस्कृत करना चाहिए। *

डॉ. राम लखन सिंह (भिण्ड) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांगों पर चल रही है और मैं इसे लगातार सुन रहा हूं। सभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है कि स्वच्छ निर्मल ग्राम योजना, जो कि सरकार की एक योजना है। मैं मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि शौचालय बनाने के लिए जो 1500 रूपये दिए जाते हैं, वे अपर्याप्त हैं। यह तो बाद की बात है, लेकिन आपका देश किधर जा रहा है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और आप शौचालय बनाकर उनको साफ कैसे रख सकेंगे? पीने का पानी जब तीन किलोमीटर दूर से आ रहा है, इस पर शौचालय बनाकर आप यह कल्पना करते है कि उसकी सफाई हो सकेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि रोजगार गारण्टी योजना के तहत आप जो काम दे रहे हैं, उसको विकास से जोड़िए। कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां मजदूर नहीं हैं और जॉबकार्ड खाली पड़े हुए हैं। वहां कोई काम नहीं हो सकता है। वहां विकास का कार्य इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि वहां पानी का संरक्षण ज्यादा से ज्यादा हो सके। मेरा तो यहां तक मानना है कि आने वाले 15-20 वर्ष में पीने के पानी को लेकर राशन कार्ड बन जाएंगे। लेकिन आप उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी पहली प्राथमिकता पीने के पानी का संरक्षण होना चाहिए ताकि गांव में पीने के पानी की व्यवस्था हो सके, तभी आप आगे बढ़ें और गांवों को स्वच्छ बनाने की कल्पना करें। इसके रहते आप कैसे कल्पना कर सकते हैं?

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आईईसी के तहत आप जो बजट आवंटित करते हैं, उसका कोई फिज़ीकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। उसमें विभाग के लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार इसमें अपनी एक एजेन्सी नियुक्त करे, जो यह तय करे कि इस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, कार्य के अंत में और किस गांव को कितना पैसा मिल रहा है[r76]? गांव के लोगों को मालूम नहीं रहता कि सरपंचों को कि किस विभाग से कितना मद जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : आपने जो लिखा हुआ है, उसे भेज दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. राम लखन सिंह : किस गांव को किस मद से कितना पैसा मिल रहा है? यह तय होना बहुत जरूरी है।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Speaker, Sir, we are talking about eight per cent growth in the country. I would like to mention in the House regarding the per capita consumption expenditure. In the rural areas, it is less than Rs.12 a day. In the urban areas, it is Rs.19 per person per day. Out of every rupee spent in 2005-06 by average rural Indian on consumption, 53 paise was spent on food; 17 paise on cereals and cereal substitute; eight paise on milk and milk products; six paise on vegetable; and five paise on sugar, salt and spices. Sir, 40 to 75 per cent of the people in the urban areas use gas. But in the rural areas, more than 74 per cent of the people use firewood, which is degrading the forests, and it is initiating deforestation of the area and thereby it is spoiling the environment. Therefore, the biggest challenge to save the environment is to eradicate poverty. If you can eradicate poverty, then we can have a healthy environment.

Then, I would like to say here that about nine per cent of the people use dung cakes for electricity; and nine per cent of the people use LPGs. Sir, 50 per cent of the people in the urban area use electricity and 42 per cent of the people use kerosene. We have to depend on the Gulf countries for kerosene. The price has become 117 dollars. So, the Rural Development Ministry has taken up a Mission known as Bio-fuel Mission. It is a good Mission. I encourage it. I say that this should be encouraged.â€¦ (*Interruptions*)

Sir, I need just one-and-half-a-minutes.

MR. SPEAKER: You have already taken three minutes. Your watch is going slow. I am not very happy to interrupt. I am doing a very unpleasant job.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Thank you, Sir.

Lastly, I would like to say that the main executive agency of the NREG Programme is the Panchayat Raj. I had gone to Jharkhand. I had gone to Daltonganj also. In that area, I travelled about 400 kilometres and I was searching and trying to find a logo of the *Pradhan Mantri Sadak Yojana*. But there is no *Pradhan Mantri Sadak Yojana* in these 400 kilometres in Jharkhand.

अध्यक्ष महोदय : होता है, हमारा नाम भी कोई नहीं लिखता है।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : There is no Panchayat Raj in Jharkhand!....(*Interruptions*) So, they must have elections. Thank you, Sir.

अध्यक्ष महोदय : आपके जो सुझाव हों, दे दीजिएगा।

*SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Even as the Indian economy surged ahead at an unprecedented 8% plus growth should be inclusive in nature. Bridging the rural-urban divides, a lot of schemes have come to the fore to eradicate poverty in the backward areas. NREGA Act, PMGSY, Restoring loss or depleted productivity of the land for better livelihood., Bharat Nirman, Samyojna Grameen Rozgar Yojana (SGRY), Swarnajyanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY), IAX , NOAPS, NFBS, NMBS, Drought Prone Areas Programme (DPAP), IWDP (Integrated waste land development Project), ARWSP, 9th Plan – Rs 42000 crores, 10th Plan – Rs 1,14000 crores. During 2007-08 an increase of 18.3% over 2006-2008. NREGA- completes 2 years, Dec 2007 2.67 crores households have demanded employment; while 2.57 crores given work. Dec 2007 – 12 lakh work, which 801 lakh in water conservation, irrigation & flood control. ARWSP, Six components or Bharat Nirman By 2009, 55,067 uncovered, 3.31 lakh slipped back and 2.17 lakhs quality affected habitation are to be addressed. National Mission on Bio-Fuel Central Rural Sanitation Programme Bio-Fuel Mission, Identification or non-forest land notable in consultation with State Government., PURA 2008-2009 pura has been allocated 27 crores rupees 18 crore more than Rs 9 crores it got in 2007-2008. At present PURA is restricted to seven clusters. Gohpur-Assam,

---

â€¦â€¦ This part of the speech was laid on the Table.

Rayadurg in A.P, Madipur in Bihar, Basmath in Maharashtra, Knjanja in orissa, Sohpure in Rajasthan and Bharthana in U.P. It should be extended to Kalahandi and KBK region of Orissa . Also budgetary allocation should be enhanced to 500 crores. *

MR. SPEAKER: Dr. Vallabhbhai Kathiria, I have made you Convenor of the Water Forum. आपकी उन्होंने कोई हेल्प की? आप उसके बारे में बोलिए।

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि सतत् संवाद करते हुए हम सांसदों के साथ आपने अपनी जो मानीटरिंग कमेटी बनायी, उसको भी मानीटर करने का काम आपने किया है। आपने लास्ट लेटर लिखा कि साल में कितनी मीटिंग्स आपने कीं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आप भी गांव से आते हैं, इसलिए गांव का ध्यान रखने के लिए और आप मंत्रालय का जो ध्यान रखते हैं, उसके लिए भी मैं आपको अभिनंदन करता हूं।

महोदय, मेरे दो-तीन सुझाव हैं। पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूट के बारे में ही है। जैसा कि कहा गया कि बहुत सी स्कीम्स मिक्स हो गयी हैं, इसलिए दोनों में से एक को स्थान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात हमारे ध्यान में यह आयी है कि गांव में सरपंच पंचायती राज संस्था होने के कारण सरपंच को हर दो-तीन दिन में तहसील पर या तो कलेक्ट्रेट में या डीडीओ के पास डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जाना पड़ता है। उन सबका यह कहना है कि हम कितना अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं? इसलिए वह करप्शन का माध्यम बन जाता है। वहां गांव में जो स्कीम आती है, उसमें करप्शन इसीलिए करते हैं कि उनको आने-जाने में, जो अधिकारी आते हैं, उनका खर्च, एमपीज-एमएलएज आते हैं, उनका खर्च, मुझे लगता है कि इस बारे में कोई सजेशन की आवश्यकता है, ताकि सरपंच और बाकी लोगों के काम करने की और अपने गांव का विकास करने की इच्छा भी रहे और करप्शन भी न हो।

वाटर शेड डेवलपमेंट के संबंध में कहना चाहूंगा। गुजरात का एक एग्जांपल सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वाटर शेड डेवलपमेंट का जो काम गुजरात में हुआ, वहां हमने चेक-डैम बनाकर इतने पानी का संरक्षण किया, उसे पूरे देश में एक साथ लागू करने की आवश्यकता है। वहां जो पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ, राज्य सरकार की भी पालिटिकल विल, प्रजा और एनजीओ का सहयोग और केंद्र सरकार सहित सभी के सहयोग के कारण काफी काम हुआ है।

पीएमजीएसवाई के बारे में यहां कहा गया। प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना में, हमारे यहां ऐसा है कि हर गांव पांच सौ की बस्ती वाले गांव सड़क से आन पेपर जुड़े हुए हैं। [p77] वह सड़क पन्द्रह या बीस साल पहले बनी थी और अभी वह सड़क रही नहीं है। ऐसे गांवों के बारे में क्या आपकी गाइडलाइन में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है।

मैं इंदिरा आवास योजना के बारे में कहना चाहता हूं। सैनीटेशन की बात अच्छी है। सब 900 से 1500 करने की बात कह रहे हैं, पांच हजार करने की बात की जा रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गाइडलाइन में सुधार करके यदि हम एमपीलैड स्कीम से दे सकें तो अच्छी तरह सैनीटेशन का काम हो सकेगा।...(व्यवधान) स्वजल धारा में गटर के काम को जोड़ने की आवश्यकता है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Thank you very much.

Hon. Members, I wish to express my gratitude to all the hon. Members. We had a very useful and a comprehensive debate for seven hours, instead of the allotted four hours. It is three hours more. Let us now hear the hon. Minister who is waiting very patiently and hearing all of us. He writes also regularly; but nobody responds unfortunately.

Hon. Minister to reply now.

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार मानता हूं। मैं बिजनैस एडवाइजरी कमेटी और पूरे सदन का भी आभार मानता हूं कि जबकि चार-पांच मंत्रालयों पर ही बहस मंजूर की गई है, आपने बड़ी कृपा की है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों पर बहस करने की स्वीकृति दी। इस विषय पर चार घंटे के बजाए सात घंटे से अधिक बहस हुई। हम माननीय सदस्यों की रूचि देख रहे हैं। माननीय सदस्य इस विषय पर एक दिन की बहस चाहते थे लेकिन समय की लाचारी है। इसमें कुल 40 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और मैं समझता हूं कि एक-आध दर्जन सदस्यों ने लिखित भाषण भी दिया। हम अनुमान लगाते हैं कि इसमें 50 माननीय सदस्यों ने रूचिपूर्वक भाग लिया। मैं आज सबसे ज्यादा प्रसन्न हूं और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। मैं करीब 10-12 वर्षों से सदन की बहस देख रहा हूं। मैं ग्रामीण विकास की बहस में भाग लेते, सुनते और देखते आया हूं। लेकिन आज हमने सदस्यों की जो रूचि देखी है, सर-जमीन की जानकारी और उनका उत्साह देखा, उससे इतना उत्साहवर्धन हो रहा है कि मैं मानता हूं कि देश के माथे पर गरीबी और बेरोजगारी का जो कलंक है, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ जो जंग है, उस जंग में हमारी विजय होगी, यह देश बेरोजगारी और गरीबी से मुक्ति पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।...(व्यवधान)

मुझे उस समय बहुत खुशी हुई जब पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री काशीराम राणा और राज्य मंत्री श्री सुभाष महरिया ने भी बहस की शुरूआत बड़ी उचित की। हमारे दोनों राज्य मंत्री भी सुनने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए मुस्तैद रहे। श्रीमती करूणा शुक्ला जी चली गई, काशी राम राणा जी ने भी बजट की खोज की, चर्चा की, जिज्ञासा की है। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि इस देश की जो दसवीं योजना बनी, उसमें ग्रामीण विकास पर 76 हजार करोड़ रुपये का आउटले निर्धारित किया गया, लेकिन इनके कार्यकाल में दो वर्ष की अवधि और बाकी तीन वर्षों की अवधि यूपीए गठबंधन के कार्यकाल में हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि 76 हजार करोड़ रुपये के आउटले के बदले एक लाख 14 हजार करोड़ 48 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई और उसे हमने खर्च किया। इससे साफ जाहिर होता है कि ग्रामीण विकास पर यूपीए गठबंधन का कितना जोड़ है और नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसकी यूएनओ ने भी प्रशंसा की है, उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के 15 सूत्र हैं। हमने 15 सूत्रों पर सौ फीसदी कामयाबी हासिल की है।

बजट का हिसाब अलग से बताते हैं। वर्ष 1998 से 2004 तक छ: साल के शासनकाल में इन्होंने क्या खर्च किया। इन्होंने 67 हजार करोड़ खर्च किए।[N78]

हमने अभी चार वित्तीय वर्ष पूरे किये हैं। इन चार वर्षों में हमने 1 लाख 11 हजार रुपये खर्च किये हैं। हम इनका छः वर्षों का हिसाब देखते हैं, तो इन्होंने लगभग 11 हजार रुपये सालाना खर्च किये हैं। हमने चार वर्ष में इनसे ढाई-तीन गुणा अधिक खर्च किया। ...(व्यवधान) लोगों ने हमें यह बताने के लिए कहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी योजना के समय में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई, यह ठीक बात है। लेकिन उस समय बजट उपबंध क्या था? वह बजट 2400-2500 करोड़ रुपये था, जो कि खर्च भी नहीं होता था। हमने भारत निर्माण करने का संकल्प लिया। उसमें हमारा मेनडेट है कि चार वर्षों में हम 48 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इन्होंने एक वर्ष में ढाई हजार करोड़ रुपये खर्च किये जबकि हमने चार वर्षों में 48 हजार करोड़ रुपये खर्च किये यानी हमने इनसे पांच गुणा अधिक खर्च किया। यह जो एक साल में खर्च कर रहे थे, हम पांच गुणा अधिक खर्च कर रहे हैं। हमने बजट का जो प्रावधान किया है, उसके हिसाब से हमने वर्ष 2005-06 में 4200 करोड़ रुपये, वर्ष 2006-07 में 8 हजार करोड़ रुपये और वर्ष 2007-08 में 11 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया है। अब हमें 24 हजार करोड़ रुपये और खर्च करने हैं। एक हजार की आबादी जो समतल में है और 500 की आबादी जो ट्राइबल और हिली एरियाज में हैं, उनको हमें कनेक्टिविटी देनी है। अब भारत निर्माण टाइम बाउंड टारगेटिड प्रोग्राम है। लेकिन प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का मेनडेट हमारा बचा हुआ है जिसमें 500 तक की आबादी और 250 ट्राइबल और हिली एरिया की आबादी को भी कनेक्टिविटी देने के लिए हम संकल्पित हैं। मैं अनुमान लगाता हूं कि वर्ष 2015 तक यह काम भी पूरा हो सकेगा। ...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : क्या यह सरकार वर्ष 2015 तक रहेगी?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या आप दोबारा उसी का उपाय लगा रहे हैं। ...(व्यवधान) अब ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो चुकी है। हम उसका एक वर्ष बीता चुके हैं। अभी उसका दूसरा वर्ष चल रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में क्या हुआ? वर्ष 2004-05 में यूपीए हुकूमत आई। वर्ष 2004-05 में 16 हजार करोड़ रुपये, वर्ष 2005-06 में 24 हजार करोड़ रुपये, वर्ष 2006-07 में 31 हजार करोड़ रुपये और वर्ष 2007-08 में जहां 40 हजार करोड़ रुपये का बजट उपबंध था वहां 42 हजार करोड़ रुपये हमने खर्च किये। इस साल हम वर्ष 2008-09 के बजट की बहस हम चला रहे हैं। हमारा 49,400 करोड़ करोड़ रुपये का

बजट प्रावधान हुआ है, लेकिन यह 49,400 करोड़ रुपये पर यह खत्म नहीं होगा। लगभग 60 हजार करोड़ रुपये इसमें खर्च होंगे, ऐसी मैं घोषणा करता हूं क्योंकि एनआरईजीएस पर लोगों ने सवाल उठाया है। एनआरईजीएस पर हमारा शुरू में बजट उपबंध 11 हजार करोड़ रुपये का था। हमने 8 हजार 600 करोड़ रुपये खर्च किये। दूसरे वर्ष में बजट प्रावधान 12 हजार करोड़ रुपये का था जबकि हमने 12 हजार 800 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। तीसरे वर्ष में 16 हजार करोड़ रुपये जरूर कम है। हम इस पर अड़ गये थे लेकिन जब प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी आदि सभी लोगों ने कहा कि यह डिमांडिड है यानी जितना खर्च किया जायेगा उतना दिया जायेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में केटेगोरिकली कहा कि हालांकि बजट प्रावधान 16 हजार करोड़ रुपये का हुआ है, लेकिन इसमें जितना वे खर्च करेंगे उतना हम देंगे। इसलिए हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि 16 हजार करोड़ रुपये से नहीं 20 हजार और 25 हजार करोड़ रुपये पर खत्म होगा। इसी कारण मैं कहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : मंत्री जी, चार-चार महीने तक मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। ...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं उस बारे में भी बताता हूं। महोदय, एनआरईजीएस और फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने गहराई से और सरजमीं की बात की है। उन्होंने कमियों की बात गिनायी हैं। जहां-तहां त्रुटियां असंगतियां, विसंगतियां और अनियमितताएं हो रही हैं, लोगों ने हमें उस बारे में बताया है। हम उस बारे में अवगत भी हैं और उसके लिए हमने निश्चिंत नहीं हैं। हम अभी चैन से नहीं बैठे हैं। हमारा यह लक्ष्य है कि इसमें पांच सूत्री कार्यक्रम, लोगों ने कहा है कि अवेयरनैंस की कमी है। हम स्वीकार करते हैं कि कर्मचारियों, अधिकारियों, माननीय सदस्य पंचायती राज और आम जनता जो अनपढ़ है, असली मेहनत कश मजदूर है, उनको जानकारी नहीं होती। मैं इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं।[MSOffice79] अवेयरनेस, पीपुल्स पार्टीशेपेशन, पारदर्शिता, स्ट्रिक्ट एण्ड विजिलेंट मॉनीटरिंग और एकाउण्टिबिल्टी, यह पांच सूत्रीय कार्यक्रम मैं चला रहा हूं। इसमें राज्य सरकारों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स, IIMs, IITs और रूरल डेवलपमेंट की पढ़ाई से जुडे हुए सभी संस्थानों की भागीदारी हमनें इसमें सुनिश्चित की है, सभी से प्रार्थन की है कि सभी लोग इसमें लगें। हम सभी विद्वानों की एक बैठक करने जा रहे हैं, सभी इसे जानें, समझें और इसे मुस्तैदी से कराएं। जब हमने 2 फरवरी, 2006 को इसे शुरू किया था तो उस समय देश के 200 जिलों में इसे शुरू किया था, एक साल बीतने पर इससे एक करोड़ दो लाख परिवारों को रोजगार मिला। जब दूसरे चरण में इसमें 130 जिले और जोड़े गए तो 31 मार्च तक लगभग 3 करोड़ 20 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने कहा कि इसे पांच साल में लागू किया जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि इसे एक अप्रैल से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। पांच वर्षों में लागू करने के लिए कानून पास हुआ था, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे तीन साल में ही पूरे देश में लागू किया है। यूपीए का मजबूत इरादा गरीबोन्मुखी, ग्रामोन्मुखी है। यह कायाकल्पीय योजना है। इसमें गरीब के लिए फूड सिक्योरिटी की बात है। उसे भोजन मिले, भुखमरी न हो, डिस्ट्रेस पलायन न हो, उसके लिए यह योजना है। एनआरईजीए में इसे 5 वर्षों में लागू करने की बात कही थी, लेकिन हमने इसे 3 वर्षों में ही लागू किया है। दो वर्षों मेमं 3 करोड़ 20 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। पिछले वर्ष में 90 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए थे। 31 मार्च तक 132 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं जिसमें से एससी की भागीदारी 27 प्रतिशत, एसटी की भागीदारी 30 प्रतिशत और महिलाओं के लिए हमारा एक-तिहाई का लक्ष्य था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भागीदारी 42 प्रतिशत रही है। एसटी का परसेंटेज बढ़ेगा क्योंकि एसटी पापुलेशन वाले जिले ले लिए गए हैं, इसलिए उनका परसेंटेज कुछ ज्यादा है। अभी तक हमने 11,600 करोड़ रूपए में से 8,640 करोड़ रूपए प्रथम वर्ष में खर्च किए हैं, दूसरे वर्ष में 12,610 करोड़ रूपए खर्च हुए और अब हमारा बजट 16,000 करोड़ रूपए का है, लेकिन यह और बढ़ेगा। सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है, प्रसन्न आचार्य जी ने कहा कि पानी की कमी होने वाली है, तीसरा विश्वयुद्ध पानी के लिए होगा। रोजगार गारंटी योजना का कमाल है कि तीन वर्षों में लोग इसके परिणाम देखेंगे। मैं राजस्थान में डूंगरपुर गया था। वहां पहले ग्राउण्ड वाटर लेवल बहुत नीचा हो गया था, ट्यूबवेल और हैण्डपम्प्स बेकार हो गए थे, वहां एक नदी में 12 किलोमीटर में 6 चेक डैम रोजगार गारंटी योजना से बने तो वहां पानी का खजाना बन गया। अगल-बगल में सिंचाई की व्यवस्था हो गयी और जल स्तर में सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश में भी वाटर कंजरवेशन की वजह से ग्राउण्ड वाटर ऊपर आया है। वाटर कंजरवेशन में 48 फीसदी काम हुआ है। 7 लाख 99 हजार योजनाओं को लिया गया है। प्रॉविजन ऑफ इरीगेशन फेसीलिटीज में 15 फीसदी, रूरल कनेक्टिविटी में 17 फीसदी, लैण्ड डेवलपमेंट, ट्राइबल और शिडयुल्ड कास्ट लोगों की जमीन डेवलपमेंट का प्रावधान इसमें हुआ है, में 16 फीसदी काम हुआ है। इसमें उनकी जमीन का विकास करना, उसे समतल करने का काम हुआ है। झारखण्ड में आदिवासी बोलता है कि हमारी जमीन का समतलीकरण करा दीजिए, गुमला के बार्डर से लगे हुए छत्तीसगढ़ के जसपुर इलाके में आदिवासी कहता है कि हमारी जमीन का समतलीकरण करा दीजिए, गांव का आदिवासी ऐसा कहता है। इसलिए इसमें काम हुआ है। लोगों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि इसमें गड़बड़ियां और हेराफेरी हो रही है। यह संभावित है क्योंकि 2 लाख 38 हजार, पंचायत, 6,000 प्रखण्ड, 600 जिले, उनमें जितने लोग कार्यरत हैं, सभी को कोई कैसे यह मान सकता है कि वे सत्य हरिश्चन्द्र हो गए हैं, महात्मा गांधी हो गए हैं, महात्मा गांधी के शिष्य हो गए हैं।[R80]

नहीं, हम नहीं मानकर चलते, जैसे अनारकिस्ट्स की थ्योरी फेल हो गई थी कि सभी मनुष्यों को विवेकशील मान लिया। वैसे ही हम सभी मनुष्यों को, सभी लागू करने वाले लोगों को मान लें कि ठीक है, ऐसा नहीं है। इसलिए हमने पांच सूत्री कार्यक्रम चलाया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि 100 प्रतिशत भुगतान एकाउंट से होगा। अभी तक 3 करोड़ 20 लाख रुपयों में से 1 करोड़ 45 लाख रुपए हमने बैंकों में और पोस्ट ऑफिसेज़ में खाता खोलकर जमा कराए हैं। हम राज्य सरकारों, बैंकों और पोस्ट ऑफिसेज़ के साथ सम्पर्क में हैं कि सभी को भुगतान उसी एकाउंट से होना चाहिए। यह फर्जीगिरी करके, मस्टर रोल खत्म हो जाए, इसलिए हमने इस तकनीक से काम लिया है। इसमें और कहीं गड़बड़ की सम्भावना हो सकती है, यह भी ठीक है। चोर विद्या सभी विद्याओं से आगे है इसलिए चोर विद्या को रोकने का हमने इस पांच सूत्री कार्यक्रम में पर्याप्त प्रबंध किया है।

अध्यक्ष महोदय: चोरी को बंद करना चाहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: आंध्र प्रदेश में 100 प्रतिशत, झारखंड में 50 प्रतिशत से ज्यादा और दूसरे राज्यों में भी इसकी शुरूआत हो गई है कि खाते से भुगतान किया जाए। इसलिए अलग-अलग जगह पर हम काफी मुस्तैद हैं।

जहां तक स्टाफिंग की बात है, ब्लाक पदाधिकारी नहीं थे। ग्राम सेवक भी नहीं थे। राज्य सरकारों के सहारे हमें काम करना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकारों की कमजोरियां दूर करने के लिए हमने प्रावधान किया है और स्टाफिंग में उनकी सहायता की है। हमने कहा है कि प्रत्येक गांव पंचायत में एक रोजगार सेवक होगा। अभी तक 79249 रोजगार सेवक बहार किए गए हैं। कई राज्य इसमें आगे हैं और कई पीछे हैं, क्योंकि हमें राज्यों पर निर्भर रहना है इसलिए हम यह काम कर रहे हैं। यह फुल टाइम प्रोग्राम है। A Full-Time Programme Officer not below the rank of BDO per Block, one Technical Assistant per five

Panchayats; two Data Entry Operators per Block, have been appointed. 1685 Programme Officers, 11,464 Technical Assistants, 2578 Computer Operators, 75,131 Accountants have been appointed. States are in the process of completing deployment of personnel in Phase-3 Districts. इसलिए राज्य सरकारों पर हम निर्भर हैं, उन्हें प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देना और उनकी सहायता करना हमारा दायित्व है। मैं महीने में चार पत्र मुख्यमंत्रियों को लिखता हूं। One-time expenditure in infrastructure, इस तरह एक प्रकार की और सहायता हमने एक मुश्त दी है, वह क्या है, Preparation for five years perspective plan, प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपए प्रोसपेक्टिव प्लान के लिए दिए हैं। प्रिंटिंग आफ जॉब कार्ड और फोटोग्राफ के लिए हम सारा खर्च दिया है। कहीं-कहीं इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि वहां भी मजदूरों से इसके लिए पैसा लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: हां लेते हैं और बोगस जॉब कार्ड्स भी बनाते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: जी महोदय। At the Block and District level computer connectivity,

रूरल डवलपमेंट में सुनने से लगता है कि ई-गवर्नेंस का उल्टा व्यवहार हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में सारे विभागों से ई-गर्वनेंस के मामले में हम आगे हैं और हमारा यह मैनडेट है। हम मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम की इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसमें सबसे आगे हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को मन्थली ई-मेल पर प्रोग्रेस रिपोर्ट भेज रहा हूं। अभ तक 385 सांसदों का कनेक्शन मिला है, उन्हें हम यह भेज रहे हैं और बाकी को भेजने का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई देखता भी है?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: कुछ लोग तो जरूर देखते हैं। आज के भाषण सुनने के बाद मैं काफी प्रोत्साहित हुआ हूं कि सरजमीन की जानकारी जो पहले सुनता था, अब जो सुनता हूं, उससे मैं काफी प्रोत्साहित हूं। मुझे खुशी है कि माननी सदस्यों ने रुचि ली है और जानकारी ले रहे हैं। मेरे पास जिन लोगों का पता था, उन्हें मैंने ई-गवर्नेंस की जानकारी दी है, बहुत से लोग हो सकता है कि कम्प्यूटर के मामले में इल्लीट्रेट हों और सीख रहे हों। इसलिए मुझे विश्वास है कि वे जरूर सीख जाएंगे और इसमें हमारा सहयोग करें। Almirahs and personal furniture at Gram Panchayat, Block, District level और कई लोग मांग कर रहे थे कि पंचायत भवन हो। हर गांव में पंचायत भवन बनाना है और उसे कम्प्यूटर से सुसज्जित करना है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि फलां चीज भी होनी चाहिए। जब ऐसी मांग होती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी की कल्पना ग्राम स्वराज, डा. लोहिया जी की कल्पना - चौखम्भा राज, उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। धीरे-धीरे यह सब होगा और वे लोग जानेंगे। इसलिए हम विकेन्द्रीत व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। इसी सदन में हम लोगों ने पंचायती राज के महत्व को देखते हुए संविधान में 73वां संशोधन पारित किया था। यह पहले से ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी में था। लेकिन संविधान के नौवें अध्याय में ग्राम पंचायत के लिए हमने संविधान में 73वां संशोधन जोड़ा था।[R81] इसीलिए अभी तक एक Comprehensive waste management scheme has been implemented which places everything under public domain. सभी जगह ट्रंसपेरेंसी है। 2 करोड़ 56 लाख 74 हजार 292 जॉब कार्ड्स एंड 35 लाख 36 हजार 54 Muster rolls have been placed on the website, जिससे सभी लोग जान सकें, उसकी छानबीन कर सकें। इस सिस्टम से रोजगार गारंटी में कमियां, त्रुटियां, कमजोरियां, जानकारी की कमी, नीयत की भी कमी की जानकारी हो सकती है, इसे मैं यहां स्वीकार करता हूं। लेकिन हम zero tolerance towards corruption की ओर चल रहे हैं। तीसरा वर्ष बीतते-बीतते स्वर आयेगा कि यह सबसे सफल योजना है और इसी से देश का कायाकल्प और गरीबों को फूड सिक्योरिटी मिलेगी।

उसके बाद भारत निर्माण का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 6 खंडों में है। शुरू में लोगों ने सोचा था कि इस पर 1 लाख 74 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा और इसके 6 खंडों में से 3 खंडों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय का 85 हजार करोड़ रुपया चार वर्षों में खर्च होना है। उसमें एक है प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसकी संक्षेप में हमने जानकारी आपको दे दी है। उसमें भी उपलब्धियां हैं और हम सफलता की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमें आशंका है कि एक साल के लिए इसमें जरूर स्पिल होगा क्योंकि अभी तक हम 24 हजार करोड़ रुपये इसमें खर्च कर चुके हैं तथा 24 हजार करोड़ रुपये हमें अभी और खर्च करने हैं। यह कार्यक्रम एक साल के लिए स्पिल कर सकता है। 31 मार्च 2009 वित्तीय साल होता है लेकिन 2009 के दिसम्बर या मार्च 2010 तक भी यह जा सकते हैं, ऐसी मैं आशंका करता हूं। बहुत कठिनाइयां हैं, क्योंकि राज्यों से ढाई हजार करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है और अभी हम 11000 करोड़ पर पहुंचे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता राज्यों की कंज्यूमिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। कंट्रेक्टर्स की कमी है, मैटीरियल की कमी है और कहीं-कहीं लॉ एंड आर्डर की समस्या है, नक्सली लोग, रंगदारी आदि सभी से हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। भारत निर्माण में महोदय Habitation to be connected –

59 हजार 461, Road length to be constructed – एक लाख 46 हजार 185 किलोमीटर कनैक्टिविटी के लिए। लेकिन अपग्रेडेशन भी हमने नया जोड़ा है क्योंकि पहले यह नहीं था जब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत हुई थी। राज्यों ने मांग की और हमने महसूस किया कि कनैक्टिविटी में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर विकनी सड़क हो और 10-20 किलोमीटर लम्बी चौपट सड़क हो तो जनता को लाभ नहीं पहुंचेगा, तो हमने पुरानी राज्य सरकारों की सड़कें भी जो मेंटेन्ड नहीं थीं, उनको भी हमने अपग्रेकडेशन में लिभ है। उसमें हमारा लक्ष्य 1 लाख 94 हजार 130 किलोमीटर का है, जिसमें अभी 31 मार्च तक 13 हजार 8 सौ 31 गांवों को कनैक्टिविटी मिल गयी, Habitation likely to be connected in 2007-08 is 12,100 villages. Balance habitation to be covered during 2009-2010 is 15,430 villages. इस प्रकार 59461 गांवों को कनैक्टिविटी मिलेगी। इसमें क्वालिटी का सवाल लोगों ने उठाया है। क्वालिटी में थ्री टीयर सिस्टम में से दो टीयर सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट के पास और एक टीयर हमारे पास है। इसमें उनको भी हमने जिम्मेदार ठहराया है, उसमें मॉनिटरिंग होती है, उनसे हम एक्शन-टेकन रिपोर्ट लेते हैं व उसकी भी वैबसाइट पर सारी चीजें हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की योजना आयोग ने प्रशंसा की है कि इस तरह से ट्रंसपेरेंसी रहनी चाहिए और एमआईएस सिस्टम उसमें भी काम कर रहा है और उसी की नकल सब लोग कर रहे हैं। हमने यह भी कहा है कि माननीय सदस्यों को वहां का एसी इन्वाइट करेगा, सड़क का जाइंट इंस्पेक्शन होगा और माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वे आग्रह करके जरूर समय मांगे और समय उनको देना चाहिए।

दूसरा, शिलान्यास का सवाल उठा। शिलान्यास का इस सदन में ऐलान किया और सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को हमने पत्र लिखा। लेकिन फैडरेशन है, फैडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग कार्यक्रम चलता है। माननीय ब्रिजेश पाठक जी नहीं हैं, उन्हीं की पार्टी के सदस्य बोल रहे थे कि अब राज्य सरकार उनको नहीं पूछती है, उनकी पार्टी की हुकूमत भी हमारे एमपी को नहीं पूछती है।[r82] वहां से कह दिया कि रुपए नहीं हैं। महोदय, 5000 रुपए शिलान्यास उद्घाटन के लिए मंजूर किए, उसकी चिट्ठी श्री हरिकेवल को नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय : आप इतना रुपया शिलान्यास के लिए क्यों देते हैं?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मुझसे देखा नहीं जा रहा था। जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, तब दुश्मन की तरह हम पर अटैक कर रहे थे। हम सदस्यों के साथ हैं कि इनकी मजबूती बढ़े, इनका सम्मान बढ़े, इनकी ताकत बढ़े। पूरे देश में हमारा माननीय सदस्यों के अलावा कोई नहीं है इसलिए मैं माननीय सदस्यों पर भरोसा करके, उनका सहयोग लेने-देने के लिए तैयार हूं, ताकि गरीबों को लाभ मिल सके। माननीय सदस्य को चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन वह चिट्ठी मुझे मिल गई है। माननीय सदस्य को भी चिट्ठी मिल जाएगी, क्योंकि अभी वह चिट्ठी रास्ते में होगी। हमने कहा है कि माननीय सदस्यों के द्वारा अनुशंसित योजनाओं को लेना है। अगर उन योजनाओं को नहीं लेते, तो उन्हें कारण बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं ले रहे हैं। हमारी अपेक्षा है, प्रार्थना है, सदन से तथा माननीय सदस्यों से भी कि आप जरूर रुचि लें।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और भारत निर्माण योजना है। उसके लिए राजस्थान के लोग कह रहे थे कि और पैसा दीजिए। उनके राज्य के लिए जितना पैसा था, उससे दस गुना पैसा हम दे चुके हैं। हम राज्यों को यह भी कह रहे हैं कि हम जितना पैसा दे रहे हैं, उसे आप खर्च कीजिए। लक्ष्मण सिंह जी कह रहे थे कि तीन चार राज्य पिछड़ गए हैं। पन्द्रह राज्य पिछड़ गए थे, लेकिन सभी राज्यों ने प्रगति की है। परफोर्मेंस रिव्यू कमेटी की पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहे थे। सभी राज्यों ने इपूव किया है। महाराष्ट्र के माननीय सदस्यों का भाषण भी सुना कि बहुत पीछे थे। महाराष्ट्र ने भी तरक्की की है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि कई राज्य पीछे थे।

MR. SPEAKER: Every honourable Member of Parliament should ask his or her conscience.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सड़क निर्माण के बारे में कहना चाहता हूं। इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट है कि एक करोड़ रुपया यदि एक सड़क के लिए लगाते हैं, तो उस एरिया के 1640 परिवार बीपीएल से एपीएल हो जाते हैं। पढ़ाई में वृद्धि, अस्पताल आने-जाने की सुविधा, किसानों को आने जाने की सुविधा, उनको फसल की अच्छी कीमत मिलती है। सड़क से बहुत ज्यादा विकास हो सकता है। यूएनओ ने कहा है कि सैवन टाइम्स ग्रोथ बढ़ जाती है, यदि सड़क बन जाती है। हम नाली में पैसा नहीं डाल रहे हैं। इससे रूरल इंडिया की इक्नोमी पर अच्छा असर पड़ रहा है और अच्छा असर दिख रहा है।

दूसरा बिंदू भारत निर्माण में इंदिरा आवास योजना का है। शुरू में जहां 85 हजार करोड़ रुपयों का हमारा तीन खंडों के लिए लक्ष्य था, उसमें 12 हजार करोड़ रुपया इंदिरा आवास योजना के लिए था। हमने इसमें बढ़ोतरी की है। इससे पहले 12000 रुपए इस योजना के तहत दिए जाते थे, बाद में बढ़ा कर 20000 हुआ, उसके बाद 25000 हुआ और अब बढ़ कर 35000 रुपए कर दिया है। हिली एरिया में 38500 रुपए किया गया है। कुछ राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी पैसा दे रही हैं। इतना ही नहीं, बजट भाषण में फैसला हुआ, हम केबिनेट में भी इस बात को ले गए और मंजूरी मिल गई। एक अप्रैल से उसे लागू कर दिया कि अगर कोई अच्छा मकान बनाना चाहता है, तो 15000 से 20000 रुपए वह 4 परसेंट इंटरेस्ट पर लोन ले सकता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने निदेश दे दिया कि वह 35000 के बदले ऋण लकर 50000 रुपए तक खर्च करके अपना घर बना सकता है, यह भी प्रावधान किया गया है और राज्य सरकारें अपनी तरफ से इसमें जोड़ रही हैं। हमने भारत निर्माण योजना में चार वर्षों में 60 हजार मकानों का लक्ष्य रखा था, लेकिन तीन वर्षों में ही हमने 45,83,000 मकान बना दिए हैं। चौथे वर्ष में इस साल 21 लाख मकान और बनाने हैं। 7,48,000 मकान निर्माणाधीन हैं। लक्ष्य से हम आगे चल रहे हैं और हम आगे जाएंगे भी। इस साल 21 लाख मकान बनाने का हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत निर्माण में सफलता से हम आगे हैं।[R83]

20.00 hrs.

देश में ऐसे गरीब परिवार हैं जिन के पास एक इंच जमीन रहने के लिए नहीं है। वे सड़क किनारे, मंदिर के मकान में और स्कूल में डेरा डाल कर रहते हैं। इन्दिरा आवास की मंजूरी के बाद भी उनके लिए मकान नहीं बनता था क्योंकि जमीन नहीं थी। इतिहास में प्रथम बार हम सौ करोड़ रुपए खर्च करके होम स्टेट लैंडलैस के लिए जमीन खरीद कर इन्दिरा आवास के अधीन मकान बनाएंगे, हमने उसके लिए प्रावधान किया है।..(व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि इसके लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जिस के पास एक इंच जमीन नहीं है, वह गाना गा रहा है कि "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" जिस के पास एक इंच जमीन नहीं वह भी कह रहा है "हिन्दोस्तां हमारा" हम इन विसंगतियों को दूर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकारों और माननीय सदस्यों के सहयोग की जरूरत है।

पानी पर बहुत चर्चा हुई है। पानी में तीन समस्याएं हैं - availability of water, sustainability of water and quality of water. शुरू में जो आंकड़े मिले थे कि जहां 5920 गांव कवर्ड नहीं हुए हैं, जहां drinking water availability is less than 10 litres per capita हो, उसे नॉट कवर्ड कहते हैं। 10 लीटर से 40 लीटर के बीच को पार्शली कवर्ड कहते हैं। नॉट कवर्ड कितना था 5920 और पार्शली कवर्ड कितने थे - 69 हजार। हमने 74 हजार गांवों के लिए भारत निर्माण में लक्ष्य रखा है लेकिन इधर लक्ष्य रखा, उधर स्लिप बैक हो गया। स्लिप बैक की भी बीमारी है। इस प्रकार दोनों मिला कर भारत निर्माण में लक्ष्य रखा है और हम उसे पूरा करने जा रहे हैं। इसमें अभी तक क्या हुआ है? 2003-04 में 2565 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2008-09 में 7300 करोड़ रुपए खर्च होंगे यानी तीन गुना खर्च होंगे। 6 वर्षों में 11 हजार 820 करोड़ रुपए और चार वर्ष में 18 हजार 30 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सब को पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। गरीब आदमी को जो पानी मिलता है, वह उसे पी लेता है और उससे बीमार होता है। 50 परसेंट बीमारियां अशुद्ध पानी और सफाई नहीं रहने के कारण गरीबों को होती हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य उस काम को करने का है। 11वीं योजना में 49,490 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है लेकिन यह 50 हजार करोड़ रुपए तक जाएगा, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : कुंए की खुदाई के बारे में क्या योजना है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कुंए की खुदाई एनआरईजी में मंजूर है। सस्टेनेबिलिटी के लिए इस बार सौ परसेंट प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की कठिनाई है क्योंकि उनके सामने रिसोर्स कंस्ट्रेंट है। इसलिए हमारा सस्टेनेबिलिटी पर जोर है। क्वालिटी ऑफ वाटर के मामले में 2 लाख 16 हजार हैबिटेशन्स में अशुद्ध पानी है। पश्चिम बंगाल, बिहार जो गंगा जी के किनारे हैं, वहां जहरीला पानी है। आंध्र प्रदेश में नालगोंडा इलाके में, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में भी यही समस्या है। ...(व्यवधान) राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन में सबमिशन केवल क्वालिटी ऑफ वाटर के लिए था लेकिन इन लोगों ने उसे खत्म कर दिया था। हमने उसे पुनर्जीवित किया है। हमने कहा कि उसके लिए अलग से पैसा देकर मंजूर करेंगे और जो भी पैसे लगेंगे, देंगे। हम जानबूझ कर जहरीला पानी गरीब आदमी को पीने नहीं देंगे।

एक-आध सवाल माननीय सदस्यों ने उठाया कि पानी की जांच होनी चाहिए। उसके लिए क्वालिटी एंड सर्वेलेंस प्रोग्राम के तहत प्रत्येक पंचायत में वहीं के पांच

व्यक्तियों का चयन करके और ट्रेनिंग देकर, किट्स का प्रावधान करेंगे। सभी पानी की जांच अनिवार्य है। राज्य सरकारों को हरेक जिले में पानी की जांच के लिए लैबोरेट्री, स्टेट लैवल पर रैफरल लैबोरेट्री, हाई टैक्नॉलोजी के इक्विमेंट्स के लिए पैसे दे दिए हैं। कोई आगे और कोई पीछे काम कर रहे हैं। हरेक पंचायत में वहां के पांच आदमी ट्रेंड होंगे।

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): इन सब के लिए ज्यादा राशि का प्रावधान करिए।[a84]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उसके लिए भी प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय: जो किया है उसका ठीक तरह से इस्तेमाल होना चाहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: 12वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पंचायतों के लिए पीने के पानी और सेनिटेशन को टॉप प्रियारिटी दी है और पांच वर्षों में बीस हजार करोड़ रुपए पंचायतों में जा रहे हैं। हम इस पर खर्च करने की जानकारी माननीय सदस्यों को दे रहे हैं जिससे मॉनिटरिंग और विजिलेंस करने में सहूलियत होगी।

जब भाषण हो रहा था तब माननीय उपाध्यक्ष महोदय आसन पर थे, उन्होंने स्कूल में सेनिटेशन और पानी की व्यवस्था के लिए चिंता व्यक्त की। हमने जो भी खर्च होना है, सभी राज्यों को पैसे दे दिए लेकिन कुछ राज्य आगे-पीछे डेट बढ़ा रहे हैं, पहले 31 दिसंबर, 2007 थी फिर बढ़ाकर 31 मार्च की गई अब लगता है और बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन हम इसमें भी सफलता की ओर जा रहे हैं। प्रत्येक स्कूल में पानी और पखाना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और करनी पड़ेगी। अभी हाल में बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया "A new programme will be started to provide safe drinking water in rural schools affected with water quality problems Rs. 200 crore in the year 2008-09." इस वर्ष जहां जिस विद्यालय में पानी की क्वालिटी प्रॉब्लम है उसके लिए 200 करोड़ अलग से दिए गए। इस तरह से स्कूल में केवल पानी के लिए यह किया गया है और पखाना के लिए पैसा अलग से भेज चुके हैं। All Scheduled Caste and Scheduled Tribe habitations even with less than 100 population to be provided with drinking water facilities under ARWSP scheme.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Have you provided anything for Solid Waste Management?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सॉलिड वेस्ट मैनेजेमेंट के बारे में बाद में बताएंगे क्योंकि यह सेनिटेशन के विषय में आता है। हमने पानी के संबंध में संक्षेप में बता दिया है। गांधी जी ने कहा था "sanitation is more important than Independence." आजादी की लड़ाई के समय में गांधी जी ने जो कहा था हम उसे भुला गए थे। सन् 1981 में देहाती इलाकों में एक प्रतिशत शौचालय थे, 1991 में 11 प्रतिशत हो गए, 2001 में 21.9 प्रतिशत यानी लगभग 22 प्रतिशत हुए लेकिन 2001 के बाद इन तीन-चार वर्षों में 50 परसेंट से ज्यादा शौचालय हो गए हैं। हमने निर्मल हिन्दुस्तान, निर्मल भारत का लक्ष्य रखा है कि दस फीसदी, एक करोड़ शौचालय हर साल बनाएंगे। शौचालय के लिए पैसे छः सौ रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किए लेकिन अब माननीय सदस्यों की मांग हो रही है कि पैसा बढ़ाइए। हम उनकी मांगों से सहमत हैं, हम तुंत इस विषय को कैबिनेट में ले जा रहे हैं। माननीय सदस्यों की मांग इसमें मंजूर हो जाएगी तो पखाना बनाने की पर यूनिट कास्ट बढ़ जाएगी। सेनिटेशन में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रतियोगिता की भावना के लिए शुरू किया गया। इसका नाम उन्होंने रखा लेकिन कार्यान्वयन हमने किया। वर्ष 2005 में 40 पंचायतों से यह कार्यक्रम शुरू किया गया, वर्ष 2006 में बीस गुना बढ़ोत्तरी हुई यानी 770 और तीसरे साल 2007 में 4945 लगभग 5000 पंचायतों में शुरू हुआ। इस साल 30,000 पंचायतों और बारह जिलों को मिला है जबकि पहले यह कुछ ब्लॉकों को मिला था। अब इस कार्यक्रम ने अद्भुत टेक ऑफ किया है। माननीय जवाहर लाल नेहरू जी ने भी कहा था कि हम इकनॉमिकल इंडीकेटर का कुछ मतलब नहीं समझते जब तक हर घर में पानी और पखाना की व्यवस्था नहीं होगी, सारे इकनॉमिकल इंडीकेटर बेमाने हो जाते हैं इसलिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मिलिनियम डेवलपमेंट में यूएनओ ने पढ़ालिखी की कि वर्ष 2015 तक 50 फीसदी कीजिए।[r85] हमने कहा नहीं, 2012 तक पचास फीसदी नहीं, हम सौ फीसदी करेंगे, इसलिए मिलेनियम डैवलपमैन्ट गोल से हम आगे चल रहे हैं।

महोदय, गांवों में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमैन्ट का काम चल रहा है। गांवों में कूड़ा-कचरा सारी सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर पड़ा रहता हैं। नाली-नाली में पानी जमा रहता है, चापाकल चलते हैं, जिनके कारण सड़कों पर पानी जमा रहता है, चारों तरफ गंदगी सड़ती है, जिसके कारण मक्खियों भिनकती हैं, कीटाणु फैलते हैं और बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए टोटल सेनिटेशन कैम्पेन का 15 फीसदी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमैन्ट पर खर्च करने के लिए हमने कहा है और उसकी शुरूआत भी जहां-तहां हुई है।

जिस तरह से निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना है, उसी तरह से जल वाली योजना भी हमने पुरस्कार के लिए स्वीकार कर ली है कि जो गांव जल के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन को टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है। वर्षा के बूंद-बूंद पानी को एकत्र किया जाए, जिससे ग्राउंड वाटर और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर की सभी तरह की समस्या हल हो जायेगी। हमने इसका भी प्रावधान किया है। हम वर्ष 2008 में बहस कर रहे हैं, जबकि वर्ष 2008 में यू.एन.ओ. ने इंटरनेशनल सेनिटेशन ईयर भी रखा है। इसलिए इसमें भी हम अद्भुत विकास और उसकी सफलता की ओर जा रहे हैं। इसलिए हमारे ग्रामीण विकास से संबंधित जो तीन खंड हैं, वे इसमें होने जा रहे हैं। इसके अलावा तीन खंड और हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण के अधीन सभी गांवों का, हर टोले का वर्ष 2009 तक विद्युतीकरण, 2012 तक प्रत्येक परिवार में विद्युतीकरण, बी.पी.एल., गरीब आदमी शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स घरों में मुफ्त में बिजली कनैक्शन, राजीव गांधी विद्युतीकरण का यह मैनडेट है। इसके बाद लोगों ने जनरेशन के बारे में कहा था। जनरेशन का काम पिछले वर्षों में पीछे चला था। लेकिन अब जनरेशन में पानी, पनबिजली की फुल पोटेन्शियलिटी का हम इस्तेमाल करेंगे और कोयले वाली ताप बिजली का भी इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम लोग परमाणु बिजली भी चाहते हैं, लेकिन वामपंथी पार्टी के नेता लोग उसमें अगर-मगर कर रहे हैं। फिर भी बिजली की आत्मनिर्भरता के लिए इन सभी स्रोतों से हमें बिजली चाहिए, जिससे घर-घर बिजली, 24 घंटे बिजली हम पहुंचा सके। इसलिए विद्युतीकरण की योजना का भी उसमे समावेश हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, वेज इम्पलायमैन्ट प्रोग्राम के बारे में बता दिया। लेकिन गरीबी कैसे हटेगी? गरीबी तब तक नहीं हटेगी, जब तक बेरोजगारी नहीं हटेगी। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार लगभग पांच से छः करोड़ होंगे। इन पांच-छः करोड़ परिवारों में कम से कम प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, यदि नौकरी नहीं तो रोजगार, स्वरोजगार, सैल्फ इम्पलॉयमैन्ट अथवा प्रोटक्टिव सैल्फ इम्पलायमैन्ट के अधीन हमें उन्हें लाना है। हमने यह लक्ष्य रखा है। हमने सात साला योजना तैयार की है। सात वर्षों में गरीबी की रेखा से नीचे वाले प्रत्येक परिवार को हमें रोजगार अथवा स्वरोजगार वर्ष 2015 तक देना है। जिसमें हर बीपीएल परिवार में कम से कम तीन हजार रुपये की एडीशनल इंकम की बढ़ोतरी हो जाए। उसमें ज्यादा नहीं कम से कम तीन हजार, चार हजार, पांच हजार या आठ हजार हो जाए

तो और अच्छा है। इसीलिए हमने लक्ष्य रखा है कि 11वीं योजना के अंत तक प्रत्येक परिवार में कम से कम एक स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो जाए। सैल्फ हैल्प ग्रुप मूवमैन्ट चले। विभिन्न माननीय सदस्यों ने चर्चा की, पहले मुझे आशंका थी कि हमारे सदस्यगण सैल्फ इम्पलायमैन्ट प्रोग्राम, एस.जी.एस.वाई., सैल्फ हैल्प ग्रुप के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि और विश्वास भी बढ़ रहा है कि सैल्फ हैल्प ग्रुप मूवमैन्ट भी अभी तक 29 लाख स्वयं सहायता समूह का सदस्य हुआ है और 29 लाख सैल्फ हैल्प ग्रुप का गठन हो जायेगा। प्रत्येक परिवार में एक स्वयं सहायता समूह को हमने अनिवार्य किया है।

इसके अलावा उनके बैंकों में खाते खुलेंगे। बैंकों की सहायता के बिना गरीबी नहीं हट सकती, इसलिए बैंकों की सहायता अनिवार्य है। जहां-तहां बैंकों के द्वारा नॉन-कोऑपरेशन है, असहयोग है, लेकिन हम उससे भी निपट रहे हैं। इसीलिए टोटल स्वरोजगारी असिस्टेड 99 लाख और इसमें 52 लाख वूमैन हैं। लोग चाहते हैं कि महिलाओं को यहां एक-तिहाई आरक्षण दे दीजिए। वह रियल वूमैन इम्पावरमैन्ट नहीं है। रियल वूमैन इम्पावरमैन्ट स्वयं सहायता समूह में है[b86]। 7 फीसदी महिलाएं जब झुंड बांधकर चलती हैं, अकेली महिला ब्लॉक में जाती है कि भागो, भागो, बैंक में भागो, भागो, और जब स्वयं सहायता, ग्रुप रियल वूमैन एमपॉवरमेंट होगा, उनका जब मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा, बैंक में खाता खुलेगा और उनको भी लगेगा कि हम देश के मजबूत नागरिक हैं तो रियल वूमैन एमपॉवरमेंट वहां पर है। इसीलिए हमने एक और काम किया है कि देश और दुनिया में डिमांड का पता लगाया जाए कि कैसे लोगों की मांग, उस तरह की क्वालिटी वाली ट्रेनिंग और स्किल डैवलपमेंट और मस्ट प्लेसमेंट यह प्रयोग शुरु किया है। Fifteen per cent of the Central allocation is provided to special projects for creating new alternative models of employment generation. परिवार का बीपीएल यूथ हो, लड़का हो या लड़की हो, उसे ट्रेनिंग देकर जैसे अभी तक 9 प्रोजेक्ट्स मंजूर किये हैं। Rural BPL youths have been taken up under skill development and placement at a total cost of Rs. 117 crore. बड़े कम खर्चे में वे बीपीएल और एपीएल में हो जाता है। Till date 35,000 rural youths have been given placement in various industries and services. 27000 लोग 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जिन्हें 3000, 5000, 8000 और 9000 रु. महीना मिल रहा है। उस कश्मीर के लड़के ने भाषण दिया कि हम आतंकवाद में जाते हैं लेकिन अब मैं जी लूंगा और अंधेरा अब नहीं रहेगा और अपने परिवार को भी मैं खींच ले चलूंगा। इस तरह का आत्मविश्वास हमने नौजवानों में देखा। इसीलिए स्वयं सहायता समूह आंदोलन और स्वरोजगार प्रत्येक परिवार को वर्ष 2015 तक इकॉनोमिकल एक्टिविटीज ग्रेड I, ग्रेड II उनके लिए बहुत सदस्यों ने मार्केटिंग का सवाल उठाया। ये हमारी गरीब महिलाएं और गांव में बसने वाले आर्टिसन्स, रंग-बिरंगे सामान, कपड़े, कागज, पत्थर, मिट्टी, लोहा, तांबा और पीतल के सभी तरह के फूड आइटम्स बनाते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं है। हमने प्रीतमपुरा, प्रगति मैदान और राजीव गांधी भवन में जसोला में भारत सरकार की ओर से मार्केटिंग के लिए सभी राज्यों से कहा है कि राजधानी में जिले में आप जमीन दीजिए, दुकान का पैसा हम देते हैं, 13 राज्य आगे आये हैं कि मार्केटिंग ऑफ रूरल प्रोडक्ट में जो गांव के गरीब आदमी द्वारा बना हुआ सामान दिल्ली, पटना, कलकत्ता और विदेश के बाजारों में जब बिकेगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। इसलिए मार्केटिंग ऑफ रूरल प्रोडक्ट, उसका भी उनको ट्रेनिंग, उनकी पैकेजिंग, उनका डिजाइनिंग, उनका ब्रांडिंग ये सभी मार्केटिंग के आयाम किये जाएं तो इस तरह से हमने सैल्फ एम्पलॉयमेंट प्लानिंग का काम किया है। इसीलिए जमीन का जो सवाल है और लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट भी और हमारे वामपंथी नेता, उनके लोग बड़े चिंतित होते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स का क्या हुआ, उनकी जमीन का क्या हुआ? उनका सवाल वाजिब है और हमारा भी अधिकार उनको जानकारी देने का बनता है कि कैसे हो रहा है। इसीलिए हमने एरिया डैवलपमेंट प्रोग्राम, वेस्ट लैंड डैवलपमेंट, इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डैवलपमेंट प्रोग्राम, डैजर्ट डैवलपमेंट प्रोग्राम और ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स इत्यादि सभी प्रोग्राम्स चलाए। 1227 Projects completed against the target of 966. टार्गेट 966 था और 1227 प्रोजेक्ट्स पूरे किये। लोगों ने पूछा कि कितना एरिया किया? 9.22 यानी 9 लाख 22 हजार हेक्टेअर में किया। सेन्ट्रल शेअर रिलीज 1164 करोड़। एलोकेशन-1164 करोड़। पाई-पाई खर्च किया। कॉमन गाइडलाइन्स तैयार की है। अभी प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को लालकिले से ऐलान किया था, नेशनल रेनफैड एरिया ऑथोरिटी, कॉमन गाइडलाइन, इरीगेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर- जो लागू कर रहे हैं और हम मेजर रूप में लागू कर रहे हैं। इसलिए हमारी कॉमन गाइडलाइन्स तैयार हो गई हैं और उसकी मंजूरी हो गई है। Plan for implementation of the common guidelines 2008 has been circulated to all the States. सभी राज्यों को दे दिया है और उसका सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। Zonal meetings of the detailed reviews have been scheduled. Professional support, scheme for IEC has been framed and capacity building institutions have been identified. Diploma and certificate course for capacity building and training by Indira Gandhi National Open University to be rolled out.

MIS for State/District/Watershed levels being developed under Integrated Wasteland Management Progamme.

Demand for Grants 2008-09 Rs. 1825 crore for Integrated Wasteland Management Programme.

अब लैन्ड रिफार्म्स की बात सुनी जाए। The National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007. श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सवाल उठाया था कि भारत के संविधान की धारा 73 के मुताबिक स्टैटुटरी दर्जा दे दिया, कानून लागू हो गया, फिर भी उसका एनैक्टमैंट करने के लिए आपके अधीन स्टैन्डिंग कमेटी में है। हन्नाम मोल्लाह साहब से हमने प्रार्थना की है कि जल्दी रिपोर्ट दे दी जाए। उससे संबंधित लैन्ड एक्वीज़ीशन अमैन्डमैंट बिल, जो क्रांतिकारी है, देश भर के कंसलटेशन से बनाया। सब लोगों ने प्रशंसा की है। स्टैन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हम उसे पारित कराने को तैयार हैं। हालांकि रीहैबिलिटेशन पॉलिसी को कानूनी दर्जा दे दिया है। Under the Centrally Sponsored Scheme of Computerisation of Land Records (CLR), 582 districts, 4484 tehsils/taluks/blocks/anchals and 1045 Sub-divisions have been covered and Rs. 581.61 crore has been provided to States/UTs.

Under the scheme of Strengthening of Revenue Administration and Updating of Land Records, उसमें 475 करोड़ रुपये राज्यों को दे दिये हैं और वे स्टेट शेयर के साथ खर्च करेंगे। उसके बाद एक नयी स्कीम हम बनाने जा रहे हैं - National Land Records Modernization Programme, जिसमें खाता खतियान सब अद्यतन हैं। सर्वे, डिजिटल और रिमोट सैंसिंग टैक्नोलाजी का इस्तेमाल करके यह कर रहे हैं। टोडरमल के समय से यह शुरू हुआ और अभी तक हल नहीं हुआ। छः-सात वर्षों में हमने लक्ष्य रखा है हरेक ज़मीन का जहां सर्वे नहीं हुआ, अद्यतन लैन्ड रिकार्ड्ज़ नहीं हैं, खाता खतियान देखने के लिए किसान जाता है तो आठ दिन तक रिकार्ड नहीं मिलता। Providing citizen services, अब तुंत एक हाथ से पैसा डालेंगे, दस रुपये में रिकार्ड ऑफ राइट्स मिलेगा। लैन्ड रिफार्म्स के लिए Committee on State Agrarian Relations and the Unfinished Tasks in Land Reforms गठित हो गई, हमारी अध्यक्षता में बैठक हो गई, 8 को सब-कमेटी बना दी, वह कार्यरत है। देश भर के ज़मीन के विशेषज्ञों को उसमें लगाया गया है। National Council for Land Reforms प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित हो गई है और हम काम शुरू करने जा रहे हैं। The first meeting of the Committee has been held and seven Sub-Groups have been set up for in-depth review/studies. उसमें आप लोगों के सुझाव, आपकी भागीदारी और आपकी जानकारी की हमें अपेक्षा है और हमें सहायता चाहिए। फिर बायो-डीज़ल का लोगों ने सवाल उठाया है। National Mission on Bio-Diesel तैयार है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में वह पड़ा हुआ है लेकिन दो वर्षों में 50-50 करोड़ रुपये हमने राज्यों की सहायता की है कि वह जैट्रोफा और पुंगामिया का सीडलिंग्ज़ और प्लांट्स तैयार करने के लिए

पांच वर्षों में पांच लाख हैक्टेयर वेस्टलैन्ड में उसको लगाया जाए जिससे तेल की कमी का कुछ मुकाबला उससे भी हो सके। दुनिया के मुल्क इस क्षेत्र में काफी बढ़ रहे हैं।

इसलिए ये सभी सवाल जो हमारे विभाग ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल डैवलपमैंट और ड्रिंकिंग वाटर एंड लैन्ड रिसोर्स है, उसका मोटा मोटा आकलन और जानकारी हमने माननीय सदन के सदस्यों को दी है। लगभग 40 सदस्यों ने इनडिविजुअल विभिन्न किस्म की रुचि से उत्साहपूर्वक जानकारी के बाद सवाल उठाए हैं। उनको भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी देना हमें आवश्यक है। श्री काशीराम राणा जी, जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट है एनआरईजीए में। सामान्यतः सीएजी तीन-चार साल के बाद पोस्टमार्टम करती है। हमने सीएजी को आग्रह किया कि आप शुरू में जाइए और जांच करके बताइए, जो कमी है, उसको हम दूर करेंगे और राज्य सरकारों से दूर कराएंगे। [b87]

इसलिए जहां-जहां इन्होंने कमियां गिनाई हैं, उन्हें हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना फेल होने वाली है। फार्मर रूरल डेवेलपमेंट मिनिस्टर ऐसा कह दें, इससे बहुत तकलीफ हुई है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि शुरु में कठिनाईयां होती हैं और जानकारी के अभाव में गड़बड़ियां भी होती हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी में कम काम मिला है। श्री नीतीश कुमार जी ने बयान दिया था और आपने भी इंटरनेशनल कांफ्रेंस में जिक्र किया था। एक करोड़ 13 लाख बीपीएल है, सन् 2001 की जनगणना के हिसाब से वहां कुल रूरल हाउस होल्ड देहात के परिवारों की संख्या एक करोड़ 26 लाख है और वे कह रहे हैं हैं कि एक करोड़ 13 लाख बीपीएल हैं। बिहार में 95 फीसदी बीपीएल हैं, इस तरह से हिसाब होता है और कांफ्रेंस में ये सब बातें होती है। मैं एक करोड़ 13 लाख मान लेता हूं, लेकिन उन्होंने अभी तक जॉब कार्ड केवल 64 लाख बांटे हैं। इन्होंने बीपीएल वालों को भी जॉब कार्ड नहीं दिया और अगर जॉब कार्ड नहीं दिया है तो काम कहां से देंगे, जब कि बीपीएल और एपीएल का भेद नहीं है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वहां ए टू जैड सब परिवारों में कागज बांट दिए। कलेक्टर और ज्वाइंट सैक्रेट्री के घर में भी जॉब कार्ड भेज दिया और यह बात अखबारों में छपी। सैक्रेट्री से पूछा कि आपने कलेक्टर के घर में भी जॉब कार्ड भेज दिया तो उसने कहा कि साहब, गलती हो गई। मांग करने से देना है, लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या कलेक्टर को कोई जॉब मिला, जॉब नहीं मिला तो पैसा मिल गया होगा?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: उसमें यह है कि काम की मांग करना, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो काम की मांग नहीं करेगा, जिन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन कोई यह नहीं कहेगा कि हमें जॉब कार्ड नहीं मिला। लेकिन बिहार और यूपी में गरीब लोगों को जॉब कार्ड भी नहीं मिला। इस बात के लिए बार-बार लिखा-पढ़ी की गई। वहां पहले श्री मुलायम सिंह जी थे और अब मायावती जी हैं। अभी उनकी पार्टी के लोग यहां बैठे नहीं हैं, नहीं तो हम उन्हें इस बारे में बताते। ...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : एनआरईजीपी का हालत भी यही होगा।...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: नहीं होगा।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Let us not encourage theft and misuse of funds.

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं आपको इस बारे में बता रहा हूं कि उसमें सोशल ऑडिट का प्रावधान है। कोस्टल एरिया में सेलिनिटी बढ़ी है और उन्होंने इस बात को मंजूर किया था। उन्होंने कहा कि हमने इसे रोक दिया है। ये गलत कह रहे हैं। सन् 2004 में 85 लाख रुपया मिला, मार्च 2007 में 29 लाख रुपए दिए और जून 2007 में दो करोड़ 78 लाख रुपए दिए। इस प्रकार से कुल मिला कर उन्हें तीन करोड़ 93 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इसका किसी ने ठीक से खर्च नहीं किया। इसका किसी ने कोई हिसाब नहीं दिया। इसके लिए किसी ने कुछ पूछा नहीं और न ही एक्सटेंशन मांगा तो हम क्या करें। सन् 2004, मार्च 2007 और जून 2007 में तीन करोड़ 93 लाख रुपए दे दिए। दूसरी योजना में उन्होंने जनवरी में 76 लाख का जिक्र किया था और फरवरी, 2007 में दो करोड़ 91 लाख दिया, कुल तीन करोड़ 68 लाख रुपए दिए। हमने उन्हें इसके लिए रोका नहीं, लेकिन उनकी एजेंसी ने काम नहीं किया, उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया। वे ये सब चीजें देख कर बताएं, इसके लिए हमने उन्हें सूचना दी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर वे हिसाब नहीं देते तब भी उन्हें पैसे देते हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: तब हम उन्हें पैसे नहीं देते हैं। उन्होंने पीने के पानी की समस्या का जिक्र किया, लेकिन यह बताया गया कि उन्होंने जो खर्च किया था, जब मंत्री थे, उसका हम तीन-चार गुना खर्च कर रहे हैं। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी यहां नहीं हैं, उन्होंने बड़ा ही अध्ययन करके, जानकारी और मजबूती के साथ सभी योजनाओं का वर्णन किया है। आईएवाई की कीमत में 35 हजार की वृद्धि हुई है, उसे उन्होंने मेंशन नहीं किया है। एनआरईजीपी सभी जिलों में लागू हो गया, उनकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं।[s88]

अध्यक्ष महोदय, [r89]श्री हन्नान मोल्लाह साहब ने सभी योजनाओं के बारे में बताया। एन.आर.जी.पी. कानून बनाने के वक्त से पास कराने और लागू कराने में सभी वामपंथी नेताओं का बड़ा भारी योगदान रहा है और हन्नान मोल्लाह साहब तो मंत्रालय की स्टेंडिंग कमेटी के एक्टिव मैम्बर हैं। इसलिए ज्यादा मुस्तैदी से इस काम को देखते रहे हैं।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने बी.पी.एल. सूची में गड़बड़ी का जिक्र किया है। उसे जानना जरूरी है। बी.पी.एल. में शुरू से, पुराने जमाने से, पहले आई.आर.डी.पी. प्रोग्राम होता था, तब से यह चला आ रहा है। यह आठवीं और नौवीं योजना के समय की बात है। उस समय एक वर्ष में 12 हजार रुपए प्रति व्यक्ति आमदनी का हिसाब था। यदि उससे कम हो, तो वे बी.पी.एल. में आएंगे। उसके बाद 12 हजार रुपए से बढ़ाकर उसे 20 हजार रुपए कर दिया गया। एक लाकड़ावाला कमेटी थी। उसमें फॉरेन से इकनॉमिस्ट आए हुए थे। वे कैलोरी की बात करते थे। अब यह कैलोरी क्या है। अगर 1800 और 2200 कैलोरी से कम है, तो उसे बी.पी.एल. में मानेंगे। विदेशों में तो 4000 कैलोरी को मानते हैं। अब कैलोरी कितनी है, कहां से उसका कैलकुलेशन होगा और कैसे उसकी हिसाब लगाएंगे। उसकी कुछ आमदनी तो है ही नहीं। वर्ष 2002 में, दसवीं योजना के लिए, बी.पी.एल. के सर्वे करने के लिए एक्सपर्ट्स बैठे थे, उन्होंने यह बनाया है और अब वही लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। जो कर्ता-धर्ता ते, अब वही इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी थी। हमने

प्रार्थना की कि हमें ट्रांसपेरेंसी लानी है और इस बारे में पूरा ब्यौरा दीवाल पर टांगना है, जिससे गरीब आदमी जान जाए कि पूअरैस्ट ऑफ दि पूअर का मार्किंग के हिसाब से सबसे ऊपर नाम रहेगा। इसे कुछ राज्यों ने टांगा और कुछ राज्यों ने नहीं टांगा। इसी कारण से इंदिरा गांधी आवास योजना में हेरा-फेरी की शिकायत आ रही है और कहा जा रहा है कि चार या पांच हजार रुपए घूसखोरी की जा रही है। हम सब राज्यों से निवेदन कर रहे हैं कि उसे सार्वजनिक स्थान पर टांगिए।

महोदय, उसमें 13 पैरामीटर्स थे और 13 को 4 से गुणा करने पर 52 बनता है और 52 नंबरों में से जिन्हें जीरो नंबर मिलेगा, उसे पूअरैस्ट ऑफ दि पूअर माना जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं, मकान नहीं, देह पर कपड़ा नहीं, भोजन की भी व्यवस्था नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। घर में एक सूप, बर्नी, चौकी और खटिया तक नहीं, तो उन्हें शून्य नंबर मिलेगा। अगर उसके पास कुछ है, तो उसे उसी के अनुसार 1, 2, 3 या 4 नंबर और इस प्रकार 52 नंबर तक मिलेंगे। किसी राज्य में 12, किसी में 13 और किसी में 14 नंबर वाला जो परिवार है, उसे बी.पी.एल. में माना गया है। योजना आयोग ने नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के द्वारा सभी राज्यों के बी.पी.एल. के परिवारों की संख्या को निर्धारित कर दिया है। अब राज्य के लोग कफ्रंट कर रहे हैं। हम योजना आयोग से कह रहे हैं कि आप इस बात को साफ करिए, हमें मानने में कोई हर्ज नहीं है। अब उन्होंने श्री सुरेश तेन्दुलक जो अर्थशास्त्री हैं और बहुत विद्वान हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है जो फिर से बी.पी.एल. को ठीक करेगी। उस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, उसे हम देखेंगे। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि आप भी अपने सुझाव उन्हें दें और यदि हमें देंगे, तो हम आपके सुझावों को उस कमेटी को पहुंचा देंगे। वह पहले से वर्ष 2002 से बी.पी.एल. सर्वे था। वह बहुत एक्युरेट नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वह एक्युरेसी के बहुत निकट है। हरेक परिवार का वैबसाइट पर नाम है, ताकि जांच की जा सके। यदि कहीं कोई गड़बड़ी है, तो हमने कहा है कि ब्लॉक लैवल पर अपील करे या फिर जिले या तहसील में अपील करे, तो उसका सुधार हो जाएगा। यू.पी. आपका राज्य है, यदि कोई ग़ड़बड़ी है, तो वहां से उसे ठीक करा लीजिए और उन्हें पूछिए कि क्यों गरीब का नाम कट गया, क्यों बड़े आदमी का नाम डाला गया? हेराफेरी हो सकती है और हुई होगी। उसके सुधार के लिए हमने प्रावधान रखा है।

महोदय, उन्होंने बजट की चिन्ता की थी। हमने एन.आर.जी.ए. का बता दिया। वित्त मंत्री के बजट भाषण में है कि यह डिमांड ड्रिविन है, जो भी खर्चा होगा, उतना खर्चा दिया जाएगा। 16 हजार करोड़ रुपए में से हम 12 हजार करोड़ रुपए खर्च कर लेंगे, तो फिर हम दावा करेंगे और इसी हाउस से सप्लीमेंट्री बजट पास कराएंगे। एम्पलायमेंट गारंटी फंड बनाने के बारे में और फंड फ्लो के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। इसमें प्रावधान है कि स्टेट एम्पलायमेंट गारंटी फंड बनाया जाए। उसके लिए जिले में पैसे जाने में सही मायने में कुछ दिक्कतें आई हैं। हम जिले को पैसे दे देते थे। जिले वाले सभी पंचायतों को पैसा बांट देते थे। हमने दिया 7 करोड़, उन्होंने सारी पंचायतों में बांट दिया। कुछ पंचायतों ने 100 प्रतिशत खर्च कर दिया। इस प्रकार 30 करोड़ खर्च हो गया। 25, 30 या 40 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। वहां से हमारे यहां मांग आती है, लेकिन यहां फायनेंस डिपार्टमेंट कहता कि 60 परसेंट से ज्यादा खर्च नहीं हुआ। वहां कुछ पंचायतों ने 100 परसेंट खर्च किया, कुछ ने नहीं किया कुछ जगह फंड डम्प हो गया और कुछ जगह ड्राई हो गया। इसलिए हमने स्टेट एम्पलायमेंट गारंटी फंड के लिए कानून बना लिया है। अब हम राज्य को ही पैसा दे देंगे, वे अपने जिलों में बांटेंगे। हम उसके लिए यहां पैसा नहीं रखेंगे, फॉर दि टाइम बीइंग यह चल रहा है।

श्री हन्नान मोल्लाह साहब ने एक सवाल उठाया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र नहीं देता है। वह जॉब कार्ड के बाद काम मांगता है। यह जागरूकता में कमी के कारण हो रहा है। इसे हमने नोट किया है और हम इस बारे में काम कर रहे हैं।

मिनिमम वेजिज पहले नागालैंड में 25 रुपए था। नार्थ ईस्ट में 40 रुपए से कम था। केरल में 125 रुपए प्रति दिन था, लेकिन इस क्रांतिकारी कदम से मिनिमम वेज के कारण मजदूरों की बारगेनिंग कैपेसिटी बढ़ी। गुजरात के लिए मिनिमम वेज 50 रुपए है, लेकिन जितना एक दिन में काम किया जाता है, उससे आधा करते हैं। अगर ठीक हिसाब किया जाए तो वह 100 रुपए बनता है, लेकिन देखने में वह 50 रुपए लगता है। एक्ट में प्रावधान है कि स्टेट का मिनिमम वेज, जो भिन्न-भिन्न है, एग्रीकल्चर वेज है, वही एनआरईजी प्रोग्राम का भी वेज रहेगा, जब तक सैंट्रल गवर्नमेंट अपना मिनिमम वेज न डिक्लेयर कर दे। विभिन्न किस्म का शेडयूल आफ रेट जिलों में है, इसलिए हमने अभी उनमें अभी कुछ नहीं किया है। लेकिन उस बारे में हमारी दो चिंताएं हैं कि किसान का अहित न हो। किसानों की खेती अभी मकैनिकल नहीं हुई है, खेती अभी भी मजदूरों पर आधारित है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, जिससे रोजगार गारंटी के चलते किसानों को मजदूर न मिलें। हम गांव में गए थे, तब एक किसान ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया है कि मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी योजना चलाई है। लेकिन हमारे लिए भी मजदूर गारंटी योजना चलाइए, क्योंकि हमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं। यह संतुलित रखना पड़ेगा कि किसानों का भी अहित न हो। लेबर कम्पोनेंट भारत सरकार देती है, तो राज्य सरकारें क्रांतिकारी बनने लगीं, लेकिन किसानों का क्या होगा? किसानों के खेत में अगर मजदूर नहीं जाएंगे, तो खेती कैसे होगी, इसलिए हमने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि जब मजदूरों को काम न मिले और उनके पलायन की नौबत आ जाए, तो उन्हें सौ दिन का काम मुहैया कराया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि दो सौ दिन का रोजगार दे दीजिए, कुछ कहते हैं कि पूरे साल काम क्यों नहीं मुहैया कराते हैं। यह हमने इसलिए किया है कि खेती पर भी कुप्रभाव नहीं डलना चाहिए। खाद्य पदार्थ इम्पोर्ट करने की स्थिति पैदा हो गई है, हम इससे और ज्यादा हालत खराब नहीं होने देंगे। इस कारण संतुलित और सम्यक विचार होना चाहिए कि किसानों का भी हित हो और मजदूरों का भी शोषण न हो। मजदूरों को भी उचित मजदूरी मिले।

एक माननीय सदस्य ने स्कूल में शौचालय में पानी न होने का सवाल उठाया था, उसके बारे में बता दिया, फंड्स के बारे में भी बता दिया। नौ घंटे काम करने के लिए हमने लेबर विभाग से राइट लिया है। नौ घंटों में से एक घंटा हमने बीच में आराम दिया है, मजदूर खैनी वगैरह खाएगा, खाना खाएगा, आराम करेगा, इसलिए आठ घंटे काम और एक घंटा आराम के लिए रखा है।

हमने मौटे तौर पर कार्यों की सूची रखी है। वॉटर कंजर्वेशन, फ्लड प्रूफिंग, माइनर इरिगेशन, ड्राउट प्रूफिंग और रूरल कनेक्टिविटी को हमने टाप प्राथमिकता में रखा है, लेकिन किसी खास राज्य में, किसी खास जिले में किसी अन्य कार्य के लिए, राज्यों के साथ परामर्श करके नया काम भी उसमें जोड़ सकते हैं, ऐसा हमने प्रावधान किया है और आपने उस कानून को पास किया है। एकाउंट्स से भुगतान का सवाल उठा है, उस बारे में हम कदम उठा रहे हैं। सैनिटेशन की अचीवमेंट के बारे में मैंने बता दिया है। लैंड रिफार्म्स के विषय में बता दिया है। आईडब्ल्युडीपीएल के बारे में भी बता दिया है, आप सभी उत्तरों से शायद संतुष्ट होंगे।

माननीय सदस्य ने पीएमजीएसवाई के बजट में वृद्धि का सवाल उठाया है। हमने इतना बजट दिया है कि वह पूरा खर्च नहीं हो पाता है। बहुत से सदस्य जो भाषण दे रहे थे, वे सदन से चले गए हैं, उनका नाम जब आएगा, तो मैं बताऊंगा। उद्घाटन का अधिकार दे दिया है और चीफ मिनिस्टर को लिख दिया है। पत्र का प्रावधान पहले से कर दिया है, चिट्ठी भी मिल जाएगी। सांसदों के सुझावों की अवमानना नहीं करनी है। हमने कहा है कि सांसद जो कहेंगे, उनकी बात को मानना है। अगर नहीं मानना है, तो उसका कारण बताना पड़ेगा। एनआरईजीपी से पलायन रुका है। ट्रेक्टर से अगर कहीं काम हो रहा है, तो बताइए। छानबीन करके उचित कार्यवाही

की जाएगी।

आग के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा था।[R90] आग लगने के संबंध में हमने यह देखा कि देश में ऐसे पच्चीस, तीस से चालीस हजार गरीबों के मकान हैं, जबकि देश भर में हम इक्कीस लाख मकान बनाते हैं। कुछ हजार मकान जिनका प्राकृतिक आपदा से, आग लगने से नुकसान हो जाए, तो हमने कलेक्टर को इसके लिए अधिकार दे दिया है कि तुंत उनका घर बना दो। घर बनाकर उनके लिए इंदिरा आवास मंजूर कर दो, उसे पैसे दे दो और हमसे पैसे वसूल लो। वे नाम भेजते थे, तो इसमें महीना-दो महीना लग जाता था, तब तक गरीब टेंपरेरी मैनेजमेंट कर लेता है। इसीलिए हमने कहा कि इसे तुंत करो। कुछ लागों ने इसे लागू किया, जबकि कुछ लोगों की समझ का फेर है, उन्होंने नहीं किया।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : इसमें धारा 4 में जो कहा गया है ...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उस क्लॉज को हटा दिया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको जवाब देने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने सवाल उठा दिया, तो मैं बताता हूं। महोदय, जब आग लगती है, तो देश भर में यह कानून है कि एक सप्ताह का अनाज, कपड़े के लिए कहीं पांच सौ या बर्तन के लिए एक हजार रूपए राशि तुंत दी जाती है। कहीं-कहीं इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। इसलिए ऐसा किया गया कि घर के लिए यदि अलग से पैसे न मिले हों, तो उनको हम इंदिरा आवास दे दें। कहीं कन्फ्यूजन है, तो हम उसे स्पष्ट कर देंगे। हमारा पक्का इरादा है और हम उस पर कायम हैं कि अगर घर जले तो तुंत उसको इंदिरा आवास दें। यह सिर्फ बीपीएल के लिए है, एपीएल के लिए नहीं है। इंदिरा आवास का लाभ केवल बीपीएल को मिल सकता है। इसे हम देखेंगे, अगर उसमें कोई क्लॉज है, तो उसे दुरूस्त करेंगे और उस बात पर हम कायम हैं। हमें खुशी है कि माननीय सदस्य रूचि लेते हैं। अगर गरीब का घर जल जाए, तो वहां मुस्तैद होकर तुंत कलेक्टर से कहा कि तुमने क्यों इंदिरा आवास मंजूर नहीं किया? इसमें देरी होती है, तो इसके लिए अपने यहां के कई कलेक्टरों को हमने स्वयं फोन किया। उनसे कहा कि आपने क्यों कागज नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा कि कागज नहीं मिला, कागज भेज दिया जाए। इसके बाद वह कागज भी भेज दिया। इसके बाद वह बना कि नहीं, वह भी हम देखेंगे।

पीने के पानी के संबंध में आप कह रहे थे कि सांसद की अनुशंसा पर हैंडपाइप का प्रावधान हो। आपने भाषण दिया, लेकिन किसी ने मेज भी नहीं थपथपायी। आपने सवाल उठा दिया है, तो हम भी कहेंगे कि माननीय सदस्य की मांग है, इनकी हम कद्र करना चाहते हैं और कद्र करते हैं। बीपीएल के लिए पंचायत भवन की व्यवस्था का काम हो रहा है। पंचायती राज मंत्रालय भी काम कर रहा है। स्कूल में पानी-पखाने के बारे में मैंने बता दिया। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के बारे में बता दिया। श्री राम कृपाल यादव चले गए। भारत निर्माण योजना और बंजर भूमि के विकास का हिसाब बता दिया। एसईजेड, बंजर भूमि, नेशनल रिहैबिलिटेशन सेटलमेंट पालिसी है, एसईजेड का सारा विवाद उससे खत्म हो जाएगा। रिहैबिलिटेशन बिफोर डिस्प्लेसमेंट उसकी खूबी है। उसमें यह भी है कि वाल्युंट्री डिस्प्लेसमेंट हो। एक योजना बनती, विकास के लिए दस हजार करोड़ रूपए खर्च करते हैं, लेकिन रिहैबिलिटेशन के लिए कोई योजना ही नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि रिहैबिलिटेशन के लिए अलग से योजना हो। जैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी तरह से रिहैबिलिटेशन की भी योजना बने। इससे डिस्प्लेसमेंट स्वतः होगा, ऐसा प्रावधान उसमें किया गया है। एनआरईजी के जाब कार्ड नहीं बंटे, क्योंकि इंदिरा आवास में वितरण में गड़बड़ी की बात आयी। वहां अभी दीवार पर सूची टांगी ही नहीं। हमने सन् 2005 में नीतीश कुमार जी को लिखा था कि हम पैसे नहीं देंगे, यदि आप सूची को दीवार पर नहीं टांगेंगे और बीपीएल सूची ठीक नहीं करेंगे। हमें उन्होंने इस संबंध में लिखा और दो महीने का समय मांगा। इसके बाद फिर समय छः महीने का मांगा, लेकिन वह काम अभी तक नहीं हुआ। वहां हेराफेरी हुयी है, हमारी जानकारी में बातें आ रही हैं।

महोदय, जहां तक वृद्धावस्था पेंशन की बात है, नेशनल सोशल एसिस्टेंस प्रोग्राम सन् 1995 में शुरू हुआ। इसमें 75 रूपए भारत सरकार और 25 रूपए राज्य सरकार देगी। एक सौ रूपए बीपीएल के लिए दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : आप अभी पांचवें नंबर मेंबर पर आए हैं, चालीस मेंबर्स ने भाषण दिया। राम कृपाल जी पांचवें नंबर पर थे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं अब संक्षेप में कहता हूं। बहुत से लोगों का जवाब हम दे चुके हैं। वृद्धावस्था पेंशन जिसे पहले कहा गया डेस्टीच्यूट, नःसहाय, उसकी कोई परिभाषा नहीं थी। जिस बूढ़ा-बूढ़ी ने इधर-उधर घूस दे दी या एमएलए-एमपी से पैरवी करा दी, तो उनको मिल गया। गांव में जो बूढ़ा-बूढ़ी थे, उनको नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : वही असली बात है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बीपीएल सूची के प्रत्येक 65 वर्ष के बूढ़ा-बूढ़ी को अनिवार्य रूप से इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, 19 नवंबर से हमने लागू की है। अब तक यह 87 लाख लोगों को मिलती थी, जो अब एक करोड़ सत्तावन लाख को मिली है। कुछ राज्य इसमें पीछे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसने इसका फार्म ही नहीं भरा है। हम इस काम में लगे हुए हैं। इसमें दो सौ रूपए प्रतिमाह भारत सरकार देगी और हमने राज्य सरकारों से भी कहा है कि दो सौ रूपए आप भी दें, जिससे उन्हें चार सौ रूपए मिलें। उत्तरांचल, तमिलनाडु, राजस्थान और कई राज्यों ने इसे लागू किया, लेकिन कई राज्यों ने इसे लागू नहीं किया। कई राज्य पच्चीस रूपए, पचास रूपए कोई एक सौ रूपए ही इसके लिए दे रहे हैं। [p91]

अध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने कहा कि हम भाषण देने के लिए बैठे हैं, वे मुझे सुनने के लिए यहां नहीं हैं।

श्री खारबेल स्वाई : मैं जानना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पैंशन को कब तक लागू करेंगे, क्या ऐसी कोई डेट है? हमसे गांव में सब लोग पूछ रहे हैं कि सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन वह कब लागू होगी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : वह 19 नवम्बर से लागू है। जो राज्य सरकार फार्म भरकर पैसा नहीं दे रही है। उन्हें भारत सरकार से मिला हुआ पैसा गरीबों को नहीं दे रही है, वे राज्य सरकारें अपमान कर रही हैं।

श्री खारबेल स्वाई : क्या आपने पैसे भेज दिए हैं?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जी हां, भेज दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप वहां जाकर पकड़िए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने 19 नवम्बर से लागू किया है। आप उन्हें पकड़िए कि क्यों नहीं लागू किया। हम माननीय सदस्यों को इसलिए जानकारी दे रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन ने कुछ सवाल उठाए थे, जहां गड़बड़ी है, हेराफेरी है, उन सबको हम ट्रंसपेरैंसी और जनजागरण से दूर करना चाहते हैं।

श्री के.सी. पल्लानी शामी ने तमिलनाडु के बारे में कहा। डा.कलिंगर करूणानिधि नेता और श्री स्टालिन, जो मंत्री है, हरेक ने लिखा है कि जो पैसे दिए गए हैं, वे आपने खर्च नहीं किए हैं। आप और खर्च कीजिए, हम और देंगे, जितना खर्च करेंगे, उतना देंगे। उन्होंने कहा कि उदारता बरतिए। उदारता नहीं, हम मुस्तैदी बरत रहे हैं कि तमिलनाडु में भी अच्छा काम हो। उनका सैल्फ हैल्प ग्रुप का काम अच्छा है, हम देश भर में उसी तरह का काम चाहते हैं। आंगनवाड़ी की मेनटेनैंस, आईएवाई यूनिट कॉस्ट में वृद्धि, आईटी डैवलपमैंट हम कर रहे हैं। श्री ताहिर खान अभी नहीं हैं। ...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदय : सुनने के लिए नहीं हैं, जो माननीय सदस्य अभी उपस्थित नहीं हैं, उनके सवालों के जवाब मत दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पैसे देते हैं लेकिन वे खर्च नहीं कर पाते हैं। फिर भी हम उन्हें मुस्तैद होकर खर्च दे रहे हैं। वे कहते हैं कि बिहार को ज्यादा दे दिया। प्लानिंग कमीशन ने क्राइटीरिया सैट किया है, हम मालिक नहीं हैं कि किस राज्य को कितना मिलेगा, प्लानिंग कमीशन से तय होता है। 75 प्रतिशत वेटेज, जिन राज्यों में जो लोग हाउसलैस हैं और 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे वहां जितने लोग हैं, उसी के अनुसार वहां जो तय हुआ और जिस फार्मूले के हिसाब से पैसे आए हैं, उसके हिसाब से बिहार में 2001 जनगणना में जो लिखा गया है और उसमें कहा गया है, उसके हिसाब से यह किया गया है। इस बात को कहना जरूरी है क्योंकि उन्होंने आरोप लगा दिया है। भले ही कहीं किसी दूसरी पार्टी का भी राज हो,लेकिन वे यह नहीं कह सकते, बीजेपी राज्य के जितने मुख्य मंत्री हैं, वे बताएं कि जब यहां उनका अपना एनडीए का राज था, उसके बदले हम अभी उन्हें उनके राज के मुकाबले में पांच गुना अधिक पैसे दे रहे हैं या नहीं। उन्होंने कह दिया कि बिहार को ज्यादा दे दिया। क्या हम बिहार के बारे में तय करते हैं, हम बिहार के बारे में तय नहीं करते।...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदय : आप बोलपुर में भेज दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने एलीगेशन लगा दिया है।

It says:

> "For the sake of uniformity, for determining the State-wise allocation, the data of rural housing shortage provided by the Office of the Registrar General of India based on Census 2001 is taken into account. As per the information furnished by RGI, the rural housing shortage in U.P. is 13,24,000 only, whereas the housing shortage in Bihar is 42,10,000. â€¦."

13 लाख उनकी शार्टेज है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सैन्सज में लिखा है, उसमें हमारा कहां कसूर है। हम उसकी संख्या तय नहीं करते। बिहार में 42 लाख लिखा और उस पर 75 प्रतिशत वेटेज है।

It further says:

> "That is why, the share of Bihar is more than Uttar Pradesh, in so far as IAY is concerned. During 2007-08, Bihar has the Central allocation â€¦."

इसलिए माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है। सरकार ने वह कागज छापा है। एनआरईजीपी में पैसा मांगा। हमने राज्यों को दिया लेकिन उन्होंने खर्च नहीं किया। हम बार-बार लिख रहे हैं। मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने कह दिया कि यह फालतू योजना है। मायावती जी, मुख्य मंत्री ने बोल दिया कि यह तो फालतु योजना है, हम प्रधान मंत्री होंगे, हालांकि मौका आएगा या नहीं, कह दिया कि हम कैंसल कर देंगे। इसमें भिखमंगी है, जो पिटीशन पर था, उसे भिखमंगी बोल दिया। अब उसका क्या असर पड़ेगा। मैंने उस राज्यमें योजना के अधिकारियों के साथ बैठक की, 70 जिले के सारे आला पदाधिकारी थे।[N92] सभी ने कहा कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन दो-तीन महीने में हमारा एक नम्बर का राज हो जायेगा। अब मुख्यमंत्री का उलटा बयान आ जाता है। इसे पोलीटिसाइज करने, कहासुनी और कांट-छांट करने से गरीबों की योजना का बहुत अहित होता है। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कोई राज्य नहीं कह सकता कि हमने भेदभाव किया है। हम ज्यादा दे रहे हैं। एनआरईजीपी मे कोई राज्य नहीं कह सकता कि हमने जो मांग की, वह हम नहीं दे रहे हैं। हम उन्हें देने के लिए मुस्तैद हैं। श्री ताहिर खान की बातों का हमने उत्तर दे दिया है। यह कहा गया कि एमपी का अपमान होता है, हम एमपी का अपमान नहीं होने देंगे। हम सभी एमपीज के साथ हैं। हम किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदय: एमपी खाली शिलान्यास करने जाना चाहते हैं। वे और कुछ नहीं करना चाहते।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री ब्रह्मानंद पांडा ट्राइबल और बॉर्डर एरिया के बारे मे कह रहे थे। हम ट्राइबल के लिए दे रहे हैं। 500 तक की आबादी के गांव को हम दे रहे हैं। आप वहां के गांव या टोले का नाम बताइये। हम सबको सड़क से जोड़ेंगे। आप कहते हैं कि बिहार उड़ीसा 1937 से एक साथ था, इसलिए उड़ीसा के लिए हम मुस्तैद हैं। लेकिन हम पैसे दे रहे हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने पीने के पानी का सवाल उठाया है कि खर्च नहीं हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश में नहीं बिहार में नहीं, हमको किसी न किसी हिसाब से उनको सहायता करनी होती है। श्री चन्द्रकांत खैरे जी ने कहा ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप नौ नम्बर में पहुंचे हैं। अभी 40 मैंम्बर्स के नाम और हैं।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम संक्षेप में अपनी बात कर रहे हैं। पब्लिसिटी के बारे में कहा गया कि पब्लिसिटी हमारी कमजोरी है। वह कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर लोग कोआपरेट नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारे ऑफिसर्स 24 घंटे मुस्तैद होकर काम कर रहे हैं। हमारे मंत्रालय में 40 अफसर हैं और 600 जिले हैं। एक ऑफिसर पर 15 जिले पड़ते हैं लेकिन हमारे अधिकारी गरीबों के प्रति समर्पित और मुस्तैद हैं। वे निष्ठा से काम कर रहे हैं, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है। अब पब्लिसिटी में हमारा भरोसा कम है। हमारा काम बोलता है। हर घर में, हर गांव में हमारा काम होगा। हमें अखबार में कोई छापे या न छापे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉ. लोहिया कहते थे कि काम बोलेगा, कागज लिखेगा चाहे नहीं लिखेगा, हमारा गरीब आदमी अखबार भी नहीं पढ़ता है। वह फोटो भी नहीं देखता है। उसके घर में पाखाना, पानी, सड़क बिजली आदि सभी होंगे। हमारा काम बोलेगा लेकिन पब्लिसिटी का युग है। हमने कहा है कि उसमें भी सुधार हो। अब कहा जाता है कि राज्यों में खर्च नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि रिपोर्ट पुरानी है। हम 31 मार्च तक देखते हैं लेकिन कुछ राज्यों में जब तक खर्च का हिसाब नहीं होता तब तक वह खर्चे नहीं लिखा जाता। पंचायत में पैसा चला गया और वहां से जब तक हिसाब नहीं आता तब तक वह खर्चे में नहीं लिखा जाता, इसलिए लगता है कि पैसा खर्च नहीं हुआ। अब ऐसी बात नहीं है। पीएमजीएसवाई के उद्घाटन का भाषण कर दिया। एनआरईजीपी के कार्य और बारहवें वित्त आयोग का भी हिसाब हमने बता दिया। टीएसई में एपीएल को आप पैसा देने के लिए कहते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने एपीएल को भी दिया है, भले ही राज्य सरकारें दें, लेकिन आपने सवाल उठाया है, इसलिए हम इसे भी देखेंगे। श्री प्रभुनाथ सिंह सदन से चले गये हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उनके प्रश्न का जवाब नहीं देना है। आप श्री प्रबोध पांडा के प्रश्न का जवाब दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री प्रबोध पांडा जी ने बीपीएल की सूची में ...(व्यवधान)

कमेटी बैठ गयी। अब बजट का जवाब दे दिया, मिनिमम वेजेज का हमने जवाब दे दिया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लक्ष्मण सिंह के प्रश्न का जवाब दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: चन्द्रकांत जी, आपका जवाब हो गया है। आधा घंटे की जगह इस तरह घंटा लग जायेगा।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: भूमि सुधार का जवाब हमने दे दिया। एसजीएसवाई, भूमि का अधिग्रहण, आईडब्ल्यूडीपी सभी का जवाब हमने दे दिया है। श्री सुभाष महरिया सदन में नहीं हैं इसलिए मैं उनके प्रश्न को छोड़ देता हूं। श्री जयप्रकाश और पोन्नुस्वामी जी सदन में मौजूद नहीं हैं। श्री लक्ष्मण सिंह सदन में मौजूद हैं, इसलिए मैं उनके प्रश्न का जवाब दे देता हूं। एआरडब्ल्यूएसपी, आईआरडीपी और इंदिरा आवास में कुछ राज्य पीछे हैं। पीएमजीएसवाई का जवाब हम पहले दे चुके हैं। तुषार चौधरी जी के प्रश्न का जवाब हमने दे दिया है। ...(व्यवधान) श्री अबु अयीश मंडल जी सदन में मौजूद हैं। उनके प्रश्न का जवाब मैं दे चुका हैं। इलियाज आजमी जी सदन में नहीं हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आजमी जी, सदन में नहीं हैं इसलिए आप आगे चलिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री निहाल चंद सदन में नहीं हैं। मानवेन्द्र सिंह जी राधा-कृष्ण जी की भूमिका के बारे में सवाल उठाते रहते हैं। इनके सब प्रश्न का हमने उत्तर दे दिया है। ...(व्यवधान) इन्होंने स्कूल का सवाल उठाया था। वह जवाब हमने दे दिया है। यह ड्रिंकिंग वाटर का सवाल उठाते रहते हैं। उनका मथुरा में पीने के पानी का सवाल है। वहां खारा पानी है इसलिए उन्होंने कहा है कि वहां पानी का इंतजाम हो जाये। पीएमजीएसवाई में क्वांटिटी और मॉनीटरिंग का सवाल जो माननीय सदस्यों ने उठाया है, लगभग 24 बैठकें 12 महीने में होनी चाहिए जिसमें अभी ...(व्यवधान) कहीं-कहीं स्टेट लैवल पर बैठकें नहीं होती हैं।[MSOffice93]

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा में लगभग साढ़े आठ घंटे का समय हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सीताराम सिंह जी, चन्द्रभूषण सिंह जी और प्रो0 महादेव राव शिवनकर जी नहीं हैं। रविचन्द्रन जी चले गए हैं। बैंकों के सहयोग के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है, हमें बैंकों का सहयोग अवश्य चाहिए। श्रीमती करूणा शुक्ला जी नहीं। श्री थंगाबालू जी ने कहा है कि मजदूरी कम है, पेयजल की कमी, एआईजीएसवाई, पीएमजीएसवाई के बारे में जो कहा है, उसको हम मान्य करते हैं। श्री मुंशीराम जी ने छोटे-छोटे टोलों में सड़क निर्माण की बात कही है, उसको भी हम इसमें जोड़ेंगे। शौचालय निर्माण पर पैसा बढ़ाने पर विचार हम कर रहे हैं। श्रीमती सुजाता ने पीएमजीएसवाई में चौड़ाई कम करने की बात कह रही हैं, हम उसको कम कर देंगे और केरल को हम मदद देंगे। ...(व्यवधान) प्रसन्न आचार्य जी ने भू-अर्जन में पैसे के बारे में कहा है। पीएमजीएसवाई में राज्य सरकार भू-अर्जन करती है, यह उनकी जिम्मेदारी है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: They have no interest. वे चले गए हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री रामदास आठवले ने हमें समर्थन दिया है और कहा है कि इन कामों को मजबूती से कीजिए। श्री गणेश सिंह, डा. राम लखन सिंह और श्री बी.के. देव जी चले गए हैं। डॉ. वल्लभभाई कथीरिया ने पानी के बारे में कहा था, वे भी सदन से चले गए हैं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। हमें पूरा विश्वास है कि जितनी रुचि है लोगों की, तमन्ना और मजबूत इरादा है, उससे वर्ष 2015 तक देश से बेरोजगारी, गरीबी हटेगी, गांवों का विकास होगा और वर्ष 2020 तक हिंदुस्तान को दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में जाने से कोई रोक नहीं सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं सदन का आभार व्यक्त करता हूं और जो माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, अगर वे बाद में भी पूछेंगे तो हम उन्हें लिखित उत्तर भेज देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार मानते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

ग्रामीण विकास जिन्दाबाद। ग्रामीण समृद्धि जिन्दाबाद।

MR. SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Rural Development to the vote of the House.

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the Fourth column of the Order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2009, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos.80 to 82 relating to the Ministry of Rural Development."

The motion was adopted.

The House stands adjourned to meet tomorrow, the 24th April, 2008 at 11.00 a.m.

20.58 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, April 24, 2008/Vaisakha 4, 1930 (Saka). [r94]

[R1]Fld by o1

Cd by p1 [MSOffice2]

cd. by q1.h [R3]

[r4]ctd by r

Fd. By s1 [H5]

Contd by t1.e [r6]

LEAVE SPACE FOR 377 MATTERS

Cd by w1 [r8]

(cd. by x1)

Cd by Kashiram Rana

[r10]

Fd by y

Cd by z1

[b12]

A2cd

[s13]

[r14](Cd. by Shri Kashi Ram Rana)

[r15](Cd. by b2)

[r16]Cd by c2

Cont by d2.h [p17]

Pratibha singh cd

[N18]

Cd by e2

[MSOffice20] Cd byf2

cd. by g2.h

[R21]

cd.by h2 [R22]

Cd by J2 [r23]

[R24]cd.

Cd by m2 [r25]

Cd by o2

[r26]

Cd by p2

[b27]

Q2cd

[s28]

[r29](Cd.by r2)

Cd by s2 [r30]

Cont by t2.h [p31]

Cd by u2 [N32]

Cd by w2 [MSOffice33]

cd. by y2 [R34]

[r35]Cd by Z2

(cd. by d3) [b36]

Cd by e3

[r37]

G3cd

[s38]

[r39](Cd. by Shri Chandra Kant Kahaire)

[r40](Cd . by h3)

[p41]cont by k3.h

Cd by l3

Cd by m3 [MSOffice43]

Cotd by o3 [MSOffice44]

[R45](Cd. by p3)

[r46]panda ctd

[r47]ctd by l

Cd by s3 [r48]

(cd. by t3) [b49]

Ctd by Jaiprakash

[r50]

cd.. by w3 [r51]

Cd by x3.e [r52]

[KMR53]Cd by y3

[r54]Fd by z3

Cont by a4.h [p55]

Cd by b4

[N56]

[R57]contd. by c4.e

cd, by d4 [R58]

Cd by F4 [r59]

Cd by j4 [r60]

N4fd

[s61]

[r62](Cd. by o54)

[r63]Cd by p4

Cd by r4

[N64]

Cd by s4 [MSOffice65]

Contd. By w4.e [R66]

cd. by x4 [MSOffice67]

cd. by z4.e [a68]

(cd. by a5) [b69]

Followed by b5 [MSOffice70]

[R71](Cd. by c5)

[r72]acharya ctd

d5cd

[s73]

Mr. Speaker contd. After Hindi [H74]

Fd. By e5 [H75]

[r76]Cd by f5

Cont by g5.h [p77]

Cd by h5

[N78]

[MSOffice79] Cd by j5

[R80]

[R81]cd.by l5

Cd by M5 [r82]

[R83]cd.

[a84]Fd by o5

Cd by p5 [r85]

(cd. by q5) [b86]

Cd by s5

[b87]

[s88]T5cd

[r89]l(Cd.by Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

cd. [R90]

Fld by x5.h [p91]

Cd by y5

[N92]

Cd by z5 [MSOffice93]

[r94] Friday, March 10, 2000/Phalguna 20, 1921 (Saka).